भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव

पीएच.डी. शोध प्रबंध

(डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत)

विषय:
राजनीति विज्ञान

कला संकाय के अंतर्गत

प्रस्तुतकर्ता:
कुमार अभयादित्य शुभम
(*नामांकन संख्या:* 161510217556)

निर्देशन में:
डॉ. बलराम सिंह
प्रोफेसर

पी.के. विश्वविद्यालय

2026

पी.के. विश्वविद्यालय

एन.एच.-27, ग्राम थानरा, (पोस्ट: दिनारा)

शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत – 473665

www.pkuniversity.edu.in

प्रमाण-पत्र (पर्यवेक्षक का प्रमाण-पत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि "**भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव**" विषय पर प्रस्तुत यह शोध कार्य **कुमार अभयादित्य शुभम** द्वारा मेरे मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में **सामाजिक विज्ञान संकाय (राजनीति विज्ञान), पी.के. विश्वविद्यालय (म.प्र.), भारत** से **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.)** की उपाधि की प्राप्ति हेतु किया गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि शोधार्थी ने मेरे साथ **240** दिनों से अधिक की उपस्थिति दर्ज की है। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह शोध प्रबंध:

I. – शोधार्थी का स्वयं का मौलिक कार्य है।

II. – विधिवत पूर्ण किया गया है।

III. – विश्वविद्यालय के पी.एच.डी. उपाधि से संबंधित अध्यादेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक: .....

घोषणा (शोधार्थी द्वारा)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि "**भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव**" विषय पर प्रस्तुत यह शोध प्रबंध मेरा स्वयं का मौलिक कार्य है, जिसे मैंने डॉ. बलराम सिंह के मार्गदर्शन में पी.के. विश्वविद्यालय (म.प्र.), भारत में, शोध उपाधि समिति द्वारा अनुमोदित विषय के अंतर्गत पूर्ण किया है। मैंने अपने पर्यवेक्षक के साथ केंद्र पर 240 दिनों से अधिक की उपस्थिति भी दर्ज की है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार इस शोध प्रबंध का कोई भी भाग किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी डिग्री/उपाधि की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, और जहाँ भी अन्य स्रोतों का उपयोग किया गया है, वहाँ उचित संदर्भ दिया गया है।

शोधार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक: .....

स्थान: .....

संस्थानाध्यक्ष द्वारा अग्रेषण पत्र

"**भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव**" विषय पर **कुमार अभयादित्य शुभम** द्वारा प्रस्तुत पी.एच.डी. शोध प्रबंध की छह प्रतियाँ विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जा रही हैं। शोधार्थी द्वारा आवश्यक शुल्क जमा कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई बकाया शेष नहीं है।

नाम: .....

मुहर (Seal): .....

दिनांक: .....

स्थान: .....

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक: .....

पता: .....

स्थान: .....

कॉपीराइट हस्तांतरण प्रमाण-पत्र

शोध प्रबंध का शीर्षक: "भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव"

शोधार्थी का नाम: कुमार अभयादित्य शुभम

कॉपीराइट हस्तांतरण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त पी.एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध के समस्त कॉपीराइट, जो इस शोध कार्य से संबंधित हैं, **पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी** को हस्तांतरित किए जाते हैं।

दिनांक: .....

(कुमार अभयादित्य शुभम)

आभार

किसी भी शोध कार्य का आभार व्यक्त करना उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होता है, जिन्होंने प्रेरणा, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर ज्ञान की इस यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अत्यंत विनम्रता एवं गर्व के साथ मैं उन सभी प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों को स्मरण करता/करती हूँ, जिन्होंने मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाई। उनके अटूट सहयोग, समर्पण एवं मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ।

सर्वप्रथम, मैं परमपिता परमेश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु धैर्य, साहस एवं शक्ति प्रदान की।

मैं अपने आदरणीय मार्गदर्शक प्रो. (डॉ.) बलराम सिंह, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता/करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन, निरंतर सहयोग, स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा अनुकूल कार्य वातावरण के बिना यह शोध कार्य संभव नहीं हो पाता। उनके उत्कृष्ट निर्देशन ने मुझमें उत्कृष्टता की निरंतर खोज, ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित की।

मैं प्रो. (डॉ.) श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, कुलाधिपति, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) का आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। साथ ही, मैं प्रो. (डॉ.)

योगेश चंद्र दुबे, कुलपति, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) का भी आभारी/आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य के दौरान निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं प्रो. (डॉ.) जितेंद्र कुमार मिश्रा, निदेशक, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के प्रति भी अपनी गहरी श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने निरंतर प्रोत्साहन एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कर इस शोध कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मैं प्रो. (डॉ.) भास्कर नल्ला, शोध अधिष्ठाता एवं पीएच.डी. प्रकोष्ठ प्रभारी, पी.के. विश्वविद्यालय, तथा प्रो. (डॉ.) जितेंद्र कुमार मलिक, अधिष्ठाता, पी.के. विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य के दौरान अमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं प्रो. (डॉ.) दीपेश नामदेव, कुलसचिव, पी.के. विश्वविद्यालय का विशेष रूप से आभारी/आभारी हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं धैर्य के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता/करती हूँ।

मैं प्रो. डॉ. ऐमन फातिमा, अधिष्ठाता, एवं प्रो. डॉ. जी. पवन कुमार, परीक्षा नियंत्रक, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता/करती हूँ।

मैं राजनीति विज्ञान विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता/करती हूँ, विशेष रूप से विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) बलवीर सिंह, प्रो. रेनू, प्रो. मेघा (सहायक प्रोफेसर) एवं समस्त अशैक्षणिक कर्मचारियों का, जिनके सहयोग के बिना यह शोध कार्य पूर्ण करना कठिन था।

मैं विश्वविद्यालय की पुस्तकालयाध्यक्ष सुश्री निशा यादव, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री आनंद कुमार तथा पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों का भी आभारी/आभारी हूँ। साथ ही, आई.टी. प्रकोष्ठ के श्री कमलेश यादव एवं श्री आलोक खरे का भी धन्यवाद करता/करती हूँ।

मैं अपने प्रिय माता-पिता, भाई-बहनों तथा अपने जीवनसाथी श्री मिलिंद साल्वे का विशेष रूप से आभारी/आभारी हूँ, जिनके प्रेम, सहयोग एवं निरंतर प्रोत्साहन ने मुझे इस शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सक्षम बनाया।

मैं अपने सहपाठियों का भी हृदय से धन्यवाद करता/करती हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य के सुचारु संचालन में सहयोग प्रदान किया।

अंततः, मैं पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) का आभारी/आभारी हूँ, जिसने मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का यह अमूल्य अवसर प्रदान किया। यह संस्था मेरे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है।

मैं अपने पुत्र अंश एम. साल्वे के प्रति भी स्नेह एवं आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिनके प्रेम एवं समझ ने मेरे शोध काल के दौरान मुझे प्रेरित किया। अंत में,

मैं पुनः ईश्वर का धन्यवाद करता/करती हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने हेतु शक्ति प्रदान की।

दिनांक: .....

स्थान: .....

(कुमार अभयादित्य शुभम)

सार

प्रस्तुत शोध का शीर्षक "भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव" है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वैश्वीकरण ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, राज्य की संप्रभुता, नीति-निर्माण प्रक्रिया, आर्थिक उदारीकरण, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक परिवेश को किस प्रकार प्रभावित किया है। शोध में वैश्वीकरण को केवल आर्थिक प्रक्रिया न मानकर एक व्यापक राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जिसने शासन प्रणाली, सार्वजनिक नीतियों तथा राज्य और नागरिकों के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं।

अध्ययन में वैश्वीकरण की अवधारणा, उसके स्वरूप, विशेषताओं, कारणों तथा भारत में उसके विकास का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीति में आए परिवर्तनों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध में यह दर्शाया गया है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत की आर्थिक संरचना को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, व्यापार विस्तार, तकनीकी विकास तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन परिवर्तनों का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित न रहकर राजनीतिक निर्णय-निर्माण, शासन व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी पड़ा।

शोध में भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं, युवाओं, परिवार, शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यों पर वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन यह इंगित करता है कि वैश्वीकरण ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है तथा युवाओं के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आधुनिक तकनीक एवं नए रोजगार क्षेत्रों के द्वार खोले हैं। दूसरी ओर उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक परिवर्तन, पारिवारिक संरचना में बदलाव, सामाजिक असमानताओं तथा पारंपरिक मूल्यों के क्षरण

जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। शोध में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वैश्वीकरण की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है, जिससे वैश्विक परस्पर निर्भरता एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी वैश्वीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संप्रभुता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों तथा उनके समाधान का विवेचन किया गया है। शोध में यह प्रतिपादित किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका ने राष्ट्रीय नीति-निर्माण को प्रभावित किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय राज्य ने इन वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, आयोगों की रिपोर्टों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशनों तथा अन्य प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति को अपनाते हुए वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों का समग्र एवं आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। उपलब्ध साहित्य एवं तथ्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

शोध के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति एवं शासन प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया है। एक ओर इसने आर्थिक विकास, निवेश, तकनीकी प्रगति, प्रशासनिक दक्षता, वैश्विक सहयोग तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक समरूपीकरण, नीति-निर्माण में बाह्य प्रभाव तथा राज्य की संप्रभुता पर दबाव जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। अतः वैश्वीकरण को पूर्णतः लाभकारी अथवा हानिकारक नहीं कहा जा सकता; इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय सरकारें वैश्विक अवसरों का उपयोग करते

हुए राष्ट्रीय हितों, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार करती हैं।

यह शोध भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण की भूमिका को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है तथा नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं राजनीतिक विश्लेषकों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भारत के सतत एवं समावेशी विकास के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लाभों का अधिकतम उपयोग करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक विविधता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखें।

अनुक्रमणिका तालिका

संख्या	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	परिचय	1 - 49
	1.1 अवलोकन	1
	1.2 भारत में वैश्वीकरण के पहलू:	9
	1.3 वैश्वीकरण की अवधारणा:	10
	1.4 वैश्वीकरण से भारत को लाभ/लाभ:	10
	1.5 भारत में वैश्वीकरण के नुकसान	13
	1.6 भारत में पहचान की राजनीति	16
	1.7 वैश्वीकरण का प्रभाव	18
	1.8 राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव	21
	1.9 वैश्वीकरण का प्रभाव: वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है	22

	1.10 वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति	23
	1.11 वैश्वीकरण और राजनीति	30
	1.12 वैश्वीकरण के कारण	31
	1.13 वैश्वीकरण के परिणाम	37
	1.14 अध्ययन का उद्देश्य	49
अध्याय 2	साहित्य की समीक्षा	50 - 105
अध्याय 3	भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव	106 - 137
	3.1 परिचय	106
	3.1.1 संस्कृति का समरूपीकरण बनाम वैश्वीकरण	107
	3.1.2 संस्कृति का पुनरुद्धार	108
	3.2 भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव	109
	3.3 भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव	112

	3.4 परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव	114
	3.5 कोविड-19 के संदर्भ में वैश्वीकरण	117
अध्याय 4	राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव	138 - 187
	4.1 परिचय	138
	4.1.1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	140
	4.1.2. आर्थिक वैश्वीकरण	142
	4.1.3. राजनीतिक वैश्वीकरण	144
	4.1.4. सांस्कृतिक वैश्वीकरण	146
	4.1.5. तकनीकी वैश्वीकरण	149
	4.1.6. राज्य संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ	150
	4.1.7. प्रतिक्रियाएँ और अनुकूलन	152
	4.1.8. मामले का अध्ययन	155
	4.2 वैश्वीकरण के तहत भारतीय राज्य	158
अध्याय 5	निष्कर्ष	188 – 195

	संदर्भ	196 - 204

चित्र तालिका

	चित्र	पृष्ठ संख्या
	चित्र 3.1: 2020 **में (एलएमआईसी) को धन प्रेषण प्रवाह में गिरावट की उम्मीद है**	124

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 अवलोकन

वैश्वीकरण के प्रभाव दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देंगे। भारत उन देशों में से एक है जहाँ वैश्वीकरण के आगमन के बाद प्रतिस्पर्धा में बहुत वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को बेहतर और समय पर परिणाम देने के लिए नई व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया। वैश्वीकरण ने भारत को 1990 में प्रभावित किया, उस समय श्री मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तब से, देश आर्थिक मोर्चे पर अच्छा कर रहा है और दुनिया के भीतर एक मजबूत और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के लिए खुली नहीं थी क्योंकि यह देश के भीतर व्यापार और निवेश उदारीकरण की बाधाओं से विवश थी। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गंभीर संकट के बाद, इसने सभी बाधाओं को हटा दिया और वैश्वीकरण को सकारात्मक धक्का मिलने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया।

भारतीय सरकार ने 1990 के दशक में वैश्वीकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या में कमी, निजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत और एकाधिकार में संशोधन उनमें से कुछ हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र खुल गए हैं। दूरसंचार, हवाई अड्डे, बीमा आदि जैसे अन्य नए क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत कर रहे हैं।



हम वैश्वीकरण को दुनिया भर के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आर्थिक शब्दों में, वैश्वीकरण को अक्सर विभिन्न देशों की अपनी सीमाओं से परे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परस्पर निर्भरता के रूप में वर्णित किया जाता है। वैश्वीकरण एक प्रतिस्थापन अवधारणा नहीं है। प्राचीन समय में भी व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करते थे। लेकिन उस समय पूरी प्रक्रिया लंबी और जोखिम भरी होती थी और अब कनेक्टिविटी ने देशों के लिए एक मंच पर वापस आना और अपनी तकनीकों और सेवाओं का आदान-प्रदान करना आसान बना दिया है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और नियमों का पालन करने वाले देश वैश्वीकरण के एक समुदाय हैं। वैश्वीकरण ने देशों को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने और विदेशी कंपनियों को इसमें निवेश करने की अनुमति दी। वैश्वीकरण का प्रभाव अक्सर न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि देशों और उनके नागरिकों की संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक जीवन शैली पर भी देखा जाता है। वैश्वीकरण न केवल कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं को प्रभावित करता है बल्कि यह विभिन्न देशों की संस्कृति को भी प्रभावित करता है। वैश्वीकरण के सभी परिणामों में से, वित्तीय एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी देशों की अर्थव्यवस्था पैसे पर चलती है।

वैश्वीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाएँ और समाज

एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत हो जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रुझानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए, शब्द "वैश्वीकरण" समकालीन राजनीतिक और शैक्षणिक बहस के सबसे फैशनेबल चर्चाओं में से एक बन गया है। लोकप्रिय चर्चा में, वैश्वीकरण अक्सर निम्नलिखित घटनाओं में से एक या अधिक के लिए एक पर्यायवाची के रूप में कार्य करता है: विश्व अर्थव्यवस्था में शास्त्रीय उदार नीतियों का अनुसरण, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के पश्चिमी रूपों का बढ़ता प्रभुत्व, नई सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रसार, साथ ही यह धारणा कि मानवता एक एकीकृत समुदाय को साकार करने की दहलीज पर खड़ी है जिसमें सामाजिक संघर्ष के प्रमुख स्रोत गायब हो गए हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में दुनिया को एक वैश्विक गाँव कहा जाता है।

अनादि काल से ही मनुष्य को या तो पहचान विरासत में मिली है या फिर उसे अपनाना पड़ता है। भारत जैसे बहुजातीय देशों के इतिहास और विकास में भाषा और धर्म आधारित जातीय पहचान प्रमुख मुद्दे रहे हैं। हाल के दशकों में विश्व स्तर पर दो समानांतर प्रक्रियाएँ सह-अस्तित्व में रही हैं: एक ओर वैश्वीकरण और दूसरी ओर विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों की पुनः पुष्टि। दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता जो आमतौर पर वैश्वीकरण से जुड़ी होती है, उसमें स्थानीय संस्कृतियों और विशिष्ट पहचानों के लिए खतरा शामिल होता है। इस प्रकार लोगों को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक संदर्भों को खोने का डर पैदा होता है और इसलिए स्थानीय या क्षेत्रीय पहचानों के इर्द-गिर्द संघर्ष और माँगें होती हैं। कई देशों में, पिछली शताब्दी में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहचानों को बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए गए हैं, तब भी जब वे पहचानें पहले महत्वहीन थीं।

उत्तर-औपनिवेशिक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, स्वतंत्रता से पहले के दशकों में नवजात राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच राजनीतिक महत्व में तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसमें बड़े और छोटे समूहों ने संगठन बनाए, सरकारी निकायों से याचिकाएँ कीं और प्रचार-प्रसार किया, यह सब उन समूहों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में किया गया

जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। जातीय चेतना में सामान्य वृद्धि से भी अधिक दिलचस्प बात यह थी कि समूहों में इसका असमान वितरण था, जिसमें कई अभिजात वर्ग के सदस्य वर्ग, धर्म या राष्ट्र की व्यापक बयानबाजी के पक्ष में संकीर्ण जातीय अपीलों का तिरस्कार करते थे।

वैश्वीकरण को अधिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों और घटनाओं के तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विश्व दृष्टिकोण, उत्पादों, विचारों और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है। भारतीय उद्योग में वैश्वीकरण के विभिन्न लाभकारी प्रभाव यह हैं कि इसने उद्योग में विशेष रूप से बीपीओ, दवा, पेट्रोलियम और विनिर्माण उद्योगों में भारी मात्रा में विदेशी निवेश लाया। चूंकि भारतीय उद्योग में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आ रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया।

भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का लाभ यह है कि कई विदेशी कंपनियों ने भारत में उद्योग स्थापित किए, खासकर फार्मास्यूटिकल, बीपीओ, पेट्रोलियम, विनिर्माण और रासायनिक क्षेत्रों में और इससे देश में कई लोगों को रोजगार मिलने में मदद मिली। इससे देश में बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। साथ ही भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का लाभ यह है कि विदेशी कंपनियां अपने साथ अत्यधिक उन्नत तकनीक लेकर आईं और इससे भारतीय उद्योग को तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत बनाने में मदद मिली।

भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के विभिन्न नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि इसने भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी। विदेशी सामान भारतीय सामान से बेहतर होने के कारण उपभोक्ता विदेशी सामान खरीदना पसंद करते हैं। इससे भारतीय उद्योग कंपनियों के लाभ की मात्रा कम हो गई। यह मुख्य रूप से दवा, विनिर्माण,

रसायन और इस्पात उद्योगों में हुआ। भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि प्रौद्योगिकी के आने के साथ आवश्यक श्रमिकों की संख्या कम हो गई और इसके परिणामस्वरूप कई लोगों को अपनी नौकरियों से हटा दिया गया। यह मुख्य रूप से दवा, रसायन, विनिर्माण और सीमेंट उद्योगों में हुआ। भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों साबित हुए हैं। भारत सरकार को भारतीय उद्योग के वैश्वीकरण के संबंध में ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो फायदेमंद हों न कि हानिकारक।

वैश्वीकरण के धर्मनिरपेक्ष और चक्रीय दोनों पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए, वैश्वीकरण की जड़ें तकनीकी परिवर्तनों में हैं, जैसे संचार और परिवहन की लागत में कमी, जो लोगों, विचारों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की आवाजाही को तेज़ और कम खर्चीला बनाती है। ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं और अक्सर समय के साथ बढ़ते हैं। जबकि देश और उनकी सरकारें ऐसे परिवर्तनों के खिलाफ अवरोध लगाने की कोशिश कर सकती हैं, उनके लिए वैश्वीकरण के दबावों को सफलतापूर्वक रोकना बहुत मुश्किल है। इस दृष्टिकोण से, वैश्वीकरण समय के साथ लगातार बढ़ रहा है क्योंकि तकनीकी परिवर्तन दुनिया को और भी छोटा बनाता है। कभी-कभी तकनीकी परिवर्तन को बहिर्जात माना जाता है - यानी, इसके देशों की नीतियों या वैश्विक एकीकरण के अलावा अन्य स्रोत होते हैं। अन्य बार, वैश्वीकरण को, विशेष रूप से पूंजी प्रवाह के व्यापार के माध्यम से, प्रौद्योगिकी पर प्रभाव डालने के रूप में देखा जाता है; इसे आमतौर पर नवाचार को प्रेरित करने और दुनिया भर में इसके हस्तांतरण को गति देने में मदद करने के रूप में माना जाता है। वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन तब एक साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए।

दूसरी ओर, वैश्वीकरण को चक्रीय माना जाता है; हाल के इतिहास में दो अलग-अलग अवधियों के साथ वैश्विक एकीकरण के उच्च स्तर जुड़े हुए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था उभरी, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटिशों ने सैन्य

शक्ति और आर्थिक नीति दोनों का उपयोग करके एक खुली अर्थव्यवस्था बनाई। दुनिया भर में उपनिवेशों का विकास और यूरोपीय व्यापार, पूंजी, मूल्यों और राजनीतिक शक्ति का विस्तार वैश्वीकरण के इस दौर का आधार बना। 19वीं शताब्दी के अंत में, विश्व अर्थव्यवस्था ने खुलेपन के ऐसे स्तर प्राप्त किए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। श्रम की आवाजाही जैसे कुछ क्षेत्रों में, एकीकरण के ऐसे स्तर कभी हासिल नहीं किए गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दो विश्व युद्धों और महामंदी के साथ यह खुली अर्थव्यवस्था ढह गई। 1914 से 1945 तक, वैश्वीकरण पीछे हट रहा था। कई देशों के लिए संरक्षणवाद प्रमुख व्यापार नीति बन गया; व्यापार और मुद्रा ब्लॉक क्षेत्रीय रूप से बने, अक्सर एक शक्तिशाली देश के इर्द-गिर्द, और सैन्य संघर्ष प्रचलित था। राष्ट्रवाद, अलगाववाद और क्षेत्रवाद ने इस 30-वर्षीय अवधि को चिह्नित किया। इस अवधि के दौरान वैश्वीकरण में गिरावट आई।

हालांकि, 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटिशों से यह पदभार ग्रहण किया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, एक खुली आर्थिक नीति और एक अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के निर्माण के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करना शुरू किया। हालाँकि, वैश्विक प्रणाली कम से कम दो ब्लॉकों में विभाजित थी, जिसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ भूतपूर्व सोवियत संघ था; इसलिए, इस शीत युद्ध प्रणाली में वैश्वीकरण हमेशा सीमित रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक खुली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संगठन के साथ आगे बढ़े। इसने कुछ क्षेत्रों में लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने और फिर इस एकीकरण प्रक्रिया में लोकतंत्रों को शामिल करने के लिए काम किया। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के निर्माण और यूरोपीय समुदाय के बाद के विकास ने विकसित देशों के बीच व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक द्वारा समर्थित ब्रेटन वुड्स मौद्रिक प्रणाली ने देशों को मुद्रा परिवर्तनीयता और डॉलर पर आधारित एक काफी स्थिर विश्व मौद्रिक प्रणाली स्थापित करने में मदद की। इस स्थिरता ने निजी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास के लिए

परिस्थितियाँ प्रदान कीं, और समय के साथ ये बाजार वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों से छोटे हो गए। ब्रेटन वुड्स निश्चित-विनिमय दर प्रणाली की समाप्ति के बाद, 1970 और 1980 के दशक में कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी नियंत्रण हटा दिए जाने से ये अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक बाजारों के लिए और भी अधिक खुल गईं।

जबकि श्रम प्रवाह कभी भी पूंजी और वस्तुओं की तरह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं हुआ, मुख्य रूप से विकसित दुनिया में आव्रजन प्रतिबंधों के कारण, श्रम की अधिक गतिशीलता में कुछ हद तक वापसी हुई जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उच्च वैश्वीकरण की अवधि में प्रचलित थी। यूरोपीय संघ (ईयू) का नए देशों और नए मुद्दों के लिए विस्तार भी इस एकीकरण आंदोलन की विशेषता थी। 1980 के दशक तक, पूर्व सोवियत संघ और उसके उपग्रहों को छोड़कर, अधिकांश उन्नत औद्योगिक दुनिया विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई थी। इस अवधि में वैश्वीकरण केवल आंशिक था।

1980 के दशक के बाद से, दुनिया के बाकी देशों ने अपने बाज़ार और सीमाएँ और भी ज़्यादा खोलनी शुरू कर दीं और विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए। शीत युद्ध की समाप्ति, भूतपूर्व सोवियत संघ का पतन और चीन में आर्थिक सुधार आंदोलन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति दी, क्योंकि भूतपूर्व साम्यवादी देशों और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना शुरू कर दिया। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में, दुनिया के विकासशील देश बड़ी संख्या में इस विश्व अर्थव्यवस्था और इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शामिल होने लगे। दुनिया के अधिकांश देश अब विश्व व्यापार संगठन (WTO), IMF और विश्व बैंक के सदस्य हैं। इस समय दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोकतंत्र भी फैल रहा था।

देशों ने भी तेजी से कई तरह के अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संधि प्रणालियों में शामिल होने का विकल्प चुना। श्रम मानकों, मानवाधिकारों, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अन्य क्षेत्रों पर

सम्मेलनों को दुनिया भर के देशों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया। 2009 तक, दुनिया के अधिकांश देश एक वैश्विक प्रणाली का हिस्सा बन गए थे जो कई मुद्दों को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों और मूल्यों की एक श्रृंखला के आसपास तेजी से संगठित हो गई थी। आर्थिक झटके, जैसे कि 1998 का एशियाई वित्तीय संकट और 2008 का संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ वित्तीय संकट, दुनिया भर में तेजी से फैल गया। वैश्वीकरण का दूसरा दौर आ गया था। एक बड़ा मुद्दा यह है कि किस हद तक वैश्वीकरण को जानबूझकर बनाया गया था, न कि अनजाने में महसूस किया गया। वैश्वीकरण को उलटा किया जा सकता है या नहीं, यह भी मुद्दा है।

वैश्वीकरण का अध्ययन दो सामान्य दृष्टिकोणों से किया गया है। एक ओर, वैश्वीकरण के कारणों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया भर में राज्यों और लोगों के बीच संपर्क और बातचीत बढ़ाने की दिशा में एक आंदोलन क्यों हुआ है? ऐसा कुछ समय में दूसरों की तुलना में अधिक क्यों हुआ है? कुछ क्षेत्र या लोग इस प्रक्रिया में दूसरों की तुलना में अधिक क्यों शामिल रहे हैं? वैश्वीकरण के कुछ पहलू जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दूसरों की तुलना में तेज़ी से क्यों आगे बढ़े हैं? वैश्वीकरण के परिणाम के रूप में कई सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें अपने आप में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। दूसरी ओर, वैश्वीकरण के प्रभाव ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया है। राज्यों और लोगों के बीच संपर्क और बातचीत बढ़ाने की इस प्रक्रिया का अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ये प्रभाव बड़े या छोटे हैं? नकारात्मक या सकारात्मक? वैश्वीकरण के असंख्य प्रभावों को रेखांकित करना और उनके लिए साक्ष्य विकसित करना साहित्य का केंद्र बिंदु रहा है। एक बार जब हम वैश्वीकरण के बारे में अधिक समझ जाते हैं, तो हम इस सवाल का समाधान कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया और इसके प्रभावों को कैसे प्रबंधित किया जाए।

1.2 भारत में वैश्वीकरण के पहलू:

क्रॉस कंट्री निगमन के कई पहलू हैं और ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और/या आर्थिक हो सकते हैं, जो सभी वैश्वीकरण के बराबर हैं। फिर भी, वित्तीय एकीकरण सबसे आम पहलू है। आर्थिक एकीकरण में एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में विकसित करना शामिल है। युद्ध I और II के बाद वैश्वीकरण के पहले रुझान पूरे ग्रह में कम हो गए, जिसका कारण कई बाधाएं थीं, जिन्होंने उत्पादों और सेवाओं की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था। वास्तव में, सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण भी काफी आर्थिक एकीकरण है। वैश्वीकरण कंपनी स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है, जो कंपनी प्रबंधन और सरकारों को उत्पादकता, गुणवत्ता और नवाचार के संबंध में श्रम प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

आम तौर पर, वैश्वीकरण में ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ शामिल होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुलती हैं जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी के खिलाफ़ भेदभाव नहीं करती हैं। नतीजतन, वैश्वीकरण आमतौर पर बाजारों के उदारीकरण और इसलिए उत्पादक संपत्तियों के निजीकरण के बीच होता है। लेकिन वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगारी, आकस्मिक रोजगार में वृद्धि और श्रम आंदोलन कमजोर होते हैं। सैद्धांतिक साहित्य दर्शाता है कि वैश्वीकरण ने देशों को यह समझा दिया है कि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक आदान-प्रदान को व्यापार के विपणन और प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के लिए साझा करेंगे। वैश्वीकरण के उत्साह ने सरकारों को विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की खूबियों के प्रति जागरूक होने के लिए भी मजबूर किया है।

प्रबंधन अध्ययनों ने वैश्वीकरण की विधि को परिभाषित किया है। फ्रेजर (2007) ने स्पष्ट किया कि वैश्वीकरण आजकल हर टिप्पणीकार के होठों पर एक शब्द हो सकता है, लेकिन इसे संतोषजनक ढंग से परिभाषित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह आर्थिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जैसे कई अलग-अलग संदर्भों में उत्पन्न होता है।

अक्तेरुज्जमां.एमडी, 2006 ने कहा कि वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में देशों और क्षेत्रों का परस्पर जुड़ाव है, विशेष रूप से, व्यापार वित्तीय प्रवाह और बहुराष्ट्रीय निगम।

1.3 वैश्वीकरण की अवधारणा:

वैश्वीकरण की अवधारणा का अर्थ है कि ग्रह छोटा होने के साथ-साथ बड़ा भी हो रहा है। अक्तेरुज्जमां.एमडी, 2006 ने बताया कि वैश्वीकरण फर्मों की सीमा पार गतिविधियों के पैटर्न को विकसित करने में योगदान दे सकता है, जिसमें विकास, उत्पादन, सोर्सिंग और विपणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश, व्यापार और रणनीतिक गठबंधन शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ कंपनियों को नए बाजारों में प्रवेश करने, उनके तकनीकी और संगठनात्मक लाभों का लाभ उठाने और व्यावसायिक लागतों और जोखिमों को कम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अन्य सिद्धांतकारों ने कहा कि वैश्वीकरण एक सामाजिक घटना हो सकती है जो कई अलग-अलग मुद्दों के संदर्भ में भौगोलिक सीमा को परिभाषित करती है। ब्रिंकमैन, 2002 के अनुसार, वैश्वीकरण एक विजयवाद प्रकाश के रूप में, क्योंकि पूंजीवाद ग्रह के हर कोने में प्रवेश कर रहा है, जिससे दुनिया की सभी आबादी के लिए श्रम और मुक्त उद्यम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के फलों में भाग लेने की संभावना है।

एएलआई, 2015 ने वैश्वीकरण को देशों के बीच तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में समझाया। यह जुड़ाव व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह के उदारीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति आत्मसात करने के दबाव से प्रेरित है। वैश्वीकरण ने देशों के बीच बाधाओं को कम कर दिया है, जिससे राष्ट्रों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा मजबूत हुई है, उन्नत प्रबंधन प्रथाओं और नए प्रकार के कार्य संगठन का प्रसार हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत श्रम मानकों को साझा किया गया है।

1.4 वैश्वीकरण से भारत को लाभ/लाभ:

बहुराष्ट्रीय निगमों का वैश्वीकरण भारत के गंतव्य शहरों जैसे हैदराबाद, बैंगलोर आदि में कई

नई नौकरियां ला रहा है। भारत के लिए वैश्वीकरण के लाभों को अक्सर निम्नानुसार संक्षेपित किया जाता है:

1) रोजगार में वृद्धि:

नई नौकरियाँ स्वाभाविक रूप से अधिक रोजगार और रोजगार पैदा कर रही हैं। देश भर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) आदि पाए जाते हैं जहाँ बहुत से लोगों को काम पर रखा जाता है। चूँकि भारत में श्रम उचित है, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित पश्चिमी देश अपना काम भारतीय कंपनियों को आउटसोर्स करते हैं। इससे क्रमिक रूप से अधिक रोजगार पैदा होता है।

2) मुआवजे में वृद्धि:

वैश्वीकरण के बाद से, पारिश्रमिक की राशि उस राशि से अधिक है जो घरेलू फर्म पेशेवर अनुभव और योग्यता के समान स्तर पर प्रदान करती हैं। व्हार्टन (2011) के ज्ञान के अनुसार, वैश्वीकरण के कारण विलय और अधिग्रहण में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन संरचना में बदलाव होता है। प्रबंधन पुनर्गठन के दौरान कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए वेतन वृद्धि के साथ उन्हें शांत किया जाता है।

3) जीवन स्तर में सुधार और क्रय शक्ति में वृद्धि:

इन शहरों में भारी मात्रा में धन सृजन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों और शहरों का विकास हो रहा है, साथ ही विदेशी संगठनों के साथ काम करने वालों के लिए उच्च क्रय शक्ति भी विकसित हो रही है। यहां तक कि घरेलू संगठनों को भी अपने कर्मचारियों को उच्च पारिश्रमिक देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन को मापने में मदद करते हैं (हेल्ड, 1999)। इस प्रकार ये शहर बेहतर जीवन स्तर और शहर के भीतर आर्थिक प्रक्रिया के अलावा व्यवसाय में भी विकास देख रहे हैं।

4) भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण:

युवा पेशेवरों के बीच वैश्विक संगठनों में काम करने का गौरव बढ़ रहा है, जिसने 20 के दशक की शुरुआत में ही उनके उत्कृष्ट आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में आश्चर्यजनक काम किया है, जो अन्य आयु वर्ग में नहीं देखा गया। यह अक्सर इन गंतव्य शहरों में एक अच्छा सकारात्मक तथ्य है और यह विकास के अन्य केंद्रों में युवा पेशेवरों के लिए भी बढ़ रहा है।

व्यावसायिकता के साथ यह सकारात्मक घटना भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत प्रेरणा दे सकती है। आर्थिक और आवास भूमि उद्योग के विकास में काफी विस्तार हुआ है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने व्यक्तियों की सामान्य आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है क्योंकि भारतीय राष्ट्र, एक पूरे के रूप में।

5) सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वास का विस्तार:

वैश्वीकरण दुनिया भर के बाज़ार में विभिन्न व्यवसाय, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का विस्तार है। वैश्वीकरण एक उल्लेखनीय कारक हो सकता है जो दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वास को वैश्विक स्तर पर संगठित करता है। यह आपको अपने देश की सीमाओं से परे व्यापार करने की अनुमति देता है।

6) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

वैश्वीकरण विकसित देशों से भारत जैसे अल्प-विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह अर्थव्यवस्था और भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में थोड़ी मात्रा में निवेश करने की अनुमति देती है।

इसलिए भारतीय कंपनियाँ तकनीकी उन्नयन के लिए विकसित देशों की विदेशी कंपनियों से संपर्क करती हैं। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियाँ विकसित देशों से उन्नत तकनीक प्राप्त करती हैं और उच्च उत्पादकता का कारण बनती हैं जो वाणिज्यिक विकास की बेहतर

दर का संकेत देती है। इसलिए हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विकसित देशों से विकासशील देशों में तकनीक के वाहक के रूप में देखेंगे।

7) गरीबी कम करना:

वैश्वीकरण ने भारत में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने एक देश के रूप में बहुत विकास किया है लेकिन गरीबी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ने और अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धा देने में मदद की।

बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ गरीबी रेखा बेहतर होती जाती है। हालांकि, अभी भी भारत को देश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाने हैं, लेकिन गरीबी पर अब तक के वैश्वीकरण के प्रभाव की सराहना की जानी चाहिए।

8) शिक्षा:

वैश्वीकरण ने उन लोगों के लिए यह आसान बना दिया है जो बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीमा पार जाना चाहते हैं। अविकसित देशों के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकसित देशों में जाने लगे हैं। शिक्षा के लिए यह प्रवास संस्कृतियों के मिश्रण के लिए नए द्वार खोलता है।

1.5 भारत में वैश्वीकरण के नुकसान

वैश्वीकरण के लाभों को पढ़ने के बाद यदि आप इसे मानव की भलाई के लिए पृथ्वी पर घटित एक उत्कृष्ट चीज के रूप में पाते हैं, तो आपको इसके नुकसानों पर भी विचार करना चाहिए।

1) बेरोजगारी:

वैश्वीकरण ने नौकरी और व्यापार के मामले में कई नए अवसर पैदा किए हैं लेकिन दूसरी ओर, यह बेरोजगारी का एक बड़ा कारण बन गया है। जब कोई देश अपनी सेवाओं को

आउटसोर्स करता है तो वह वास्तव में अपने नागरिकों से अवसर छीन लेता है और अधिक लाभ कमाने के लिए इसे दूसरे देश के लोगों को देता है और वैश्वीकरण के कारण अब यही हो रहा है।

2) प्रमुख वैश्विक ब्रांड:

वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच गई है और ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में छोटे उद्योगों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया है। प्रमुख वैश्विक ब्रांड छोटे उद्योगों को बढ़ने नहीं देते। बेहतर तकनीकें बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं और नए और छोटे उद्योगों के लिए बाजार पर ईमानदार पकड़ बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है।

3) चूहा दौड़:

अधिक आवक निवेश को आकर्षित करने के लिए, राज्य अपने करों को कम कर देता है जो राष्ट्रों के बीच एक दिनचर्या की शुरुआत करता है। सभी देशों को कम करों की स्थिति में भी बचत करने की आवश्यकता है। ताकि उन्हें मूल्य में कटौती करने की आवश्यकता हो जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी सुरक्षा की कमी और कर्मचारियों के साथ अन्य समस्याएं हुईं।

4) असमानता:

वैश्वीकरण को आय और संपत्ति में बढ़ती असमानताओं से जोड़ा गया है। इसका प्रमाण अक्सर चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ता ग्रामीण-शहरी विभाजन है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक और सामाजिक तनाव और वित्तीय अस्थिरता होती है जो विकास को बाधित करेगी। दुनिया के कई सबसे गरीब लोगों के पास बुनियादी तकनीकों और सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच नहीं है। उन्हें लाभों से वंचित रखा गया है।

5) मुद्रा स्फ़ीति:

खाद्यान्न और ऊर्जा की तीव्र मांग के कारण वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

खाद्यान्न मूल्य मुद्रास्फीति ने दुनिया के कई सबसे गरीब लोगों को भारी जोखिम में डाल दिया है।

6) विश्वव्यापी कॉमन्स के लिए खतरे:

पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति, भूमि क्षरण, वनों की कटाई, जैव-विविधता की हानि तथा जल की स्थायी कमी की आशंकाओं ने विश्व के सर्वाधिक असुरक्षित लोगों को प्रभावित किया है।

7) व्यापार असंतुलन:

वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई है, लेकिन व्यापार असंतुलन भी बढ़ा है। कुछ देश बड़े व्यापार अधिशेष पर चल रहे हैं और ये असंतुलन नए प्रकार के आयात नियंत्रण जैसी संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने के लिए तनाव और दबाव पैदा कर रहे हैं। कई विकासशील देश उन्नत देशों के उत्पादकों द्वारा निर्यात डंपिंग के शिकार हो रहे हैं (डंपिंग का मतलब है आपूर्ति की लागत से कम कीमत पर अतिरिक्त उत्पादन बेचना।)

8) मानकीकरण:

वैश्वीकरण के कुछ आलोचक आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के नुकसान की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि विशाल कंपनियां और वैश्विक बहुराष्ट्रीय ब्रांड कई देशों के घरेलू बाजारों पर हावी हो रहे हैं।

9) प्रमुख वैश्विक ब्रांड:

यदि प्रमुख ब्रांडों और बेहतर प्रौद्योगिकियों के साथ वैश्विक व्यवसाय प्रमुख बाजारों पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे वह दूरसंचार हो, ऑटोमोबाइल हो, तो वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है।

1.6 भारत में पहचान की राजनीति

दक्षिण एशिया के अधिकांश विकासशील 5 देशों की तरह भारत भी बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज है। भारतीय समाज जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि की दृष्टि से एक बहुलवादी समाज है। भारत जैसे देश में जहां जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और समुदाय के आधार पर व्यापक विविधताएं हैं और कई तरह के सामाजिक उत्पीड़न हैं, पहचान की राजनीति उपजाऊ जमीन पाती है। भारत दुनिया के सर्वाधिक विविध समाजों में से एक है। कहा जाता है कि भारत के लोगों की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से निरंतर चली आ रही है। इसमें दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग रहते हैं - हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। हिंदुओं की आबादी लगभग 82 प्रतिशत है, लेकिन भारत में दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है, जो अनुमानित 149 मिलियन है।

2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार, कुल 122 भाषाएँ और 234 मातृभाषाएँ हैं। यहाँ कई जातीय समूह और समुदाय रहते हैं। मुख्य जातीय समूह इंडो-आर्यन (72%), द्रविड़ (25%), मंगोलॉयड और अन्य (3%) हैं। उत्तरी भारत के लोग इंडो-आर्यन समूहों से संबंधित हैं, जो उन आर्यों के वंशज थे जिन्होंने पहली बार 1500 ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। देश के उत्तर-पूर्व के लोग आमतौर पर मंगोलॉयड समूहों से हैं और दक्षिण भारतीय, विशेष रूप से दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के लोग आमतौर पर द्रविड़ मूल के हैं, जो शायद इस भूमि के सबसे पुराने निवासियों में से हैं। भारत में कई आदिवासी समुदाय भी हैं जिन्हें आदिवासी के रूप में जाना जाता है - इस प्राचीन देश के मूल निवासी। वे अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी समुदाय पाए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर में खासी, मिज़ो, नागा और त्रिपुरी जैसी जनजातियाँ हैं। मध्य भारत में सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समूह हैं। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे मुख्य भूमि से दूर द्वीपों में भी अपने आदिवासी

समूह हैं। जबकि राष्ट्रीय जनगणना नस्लीय या जातीय समूहों को मान्यता नहीं देती है, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2,000 से अधिक जातीय 7 समूह हैं। हिंदू, बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय, एक जाति व्यवस्था का पालन करते हैं जो कि चार वर्णों में वर्गीकरण है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों को आगे कई जातियों में विभाजित किया गया है जिनमें से कई अक्सर केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जाति एक पहचान है जिसके आधार पर भारत में पहचान की राजनीति फलती-फूलती है।

चूंकि समाज में जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव है, इसलिए उत्पीड़न से पीड़ित ऐसे समुदायों और जातियों के लोगों को उनकी पहचान और कथित उत्पीड़न के आधार पर लामबंद करने की कोशिश की जाती है। दलित समूह, ओबीसी आंदोलन जो आरक्षण के सवाल पर उभरे हैं, वे आरक्षण, संसाधनों के आवंटन, भेदभाव के खिलाफ़ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में लिप्त हैं। हालाँकि, ऐसे समूह बुनियादी सामाजिक संरचना और वर्ग शोषण को बदलने के संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाते हैं और न ही वे अन्य उत्पीड़ित समूहों के साथ मिलकर एक संयुक्त आंदोलन बनाने में रुचि रखते हैं। भारत में हमें बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक संगठन मिलते हैं जिनका दृष्टिकोण पहचान की राजनीति पर आधारित है जो दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के बीच काम कर रहे हैं। पहचान की राजनीति का प्रसार और इसका प्रभाव विभिन्न राजनीतिक दलों और संरचनाओं में देखा जाता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण बहुजन समाज पार्टी है। दूसरा उदाहरण उन कई पार्टियों का है जो ओबीसी समुदाय की अपील पर आधारित हैं।

इस तरह की पहचान की राजनीति सिर्फ़ दलित और पिछड़े वर्ग के संगठनों तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्रमुख जाति और उच्च जाति समूह भी पहचान की राजनीति का सहारा लेते हैं। पार्टियाँ समर्थन जुटाने और अपनी चुनावी ताकत बढ़ाने के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, यूपी में भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसी सभी पार्टियाँ समर्थन जुटाने के लिए जाति और उपजाति सम्मेलन करती हैं। वे पहचान की राजनीति

को बढ़ावा देते हैं और जाति विखंडन की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया अनुसूचित जातियों की उप-श्रेणियों के भीतर विकसित होने वाली प्रतिस्पर्धा और संघर्षों में देखी जा सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश में माला-मडिगा संघर्ष। दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के मामले में नई पहचानों का उदय भी देखा जा सकता है। अब जबकि हमने भारत में पहचान की राजनीति के बारे में अपनी समझ को रेखांकित कर लिया है। आइए हम इस सवाल पर वापस आते हैं कि वैश्वीकरण से इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

1.7 वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोग के पैटर्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत की पहचान और राजनीति में बदलाव के बुनियादी निर्धारक काफी हद तक घरेलू ही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान शताब्दी में पहचान की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय विकास से प्रभावित होती है। एक बहुलवादी या बहुसांस्कृतिक समाज में पहचान की राजनीति को कैसे समझा जाए और 21वीं सदी में भारत की पहचान की राजनीति की स्थायी विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करना बिल्कुल उपयुक्त है। वृहद स्तर पर भारत में पहचान की राजनीति काफी हद तक भारत के अंदर की बहस बनी हुई है, जिसमें अनिवासी भारतीय समुदाय (एनआरआई) का सीमित प्रभाव है। भारत में पहचान की राजनीति दुनिया के अन्य हिस्सों में पहचान की राजनीति की तरह आगे नहीं बढ़ रही है। यह उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामी कट्टरवाद और लैटिन अमेरिका या फिलीपींस में ईसाई कट्टरवाद से काफी अलग है।

भारत में धार्मिक रूप से प्रेरित राजनीति (हिंदू और मुस्लिम दोनों) ने लैंगिक भूमिका, विवाह, तलाक आदि जैसे सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत की लोकप्रिय राजनीति ने समूह की पहचान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है न कि आर्थिक विकास के सवाल पर। पहचान की राजनीति में वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने का एक और तरीका भारत में विकासात्मक राज्य की वापसी के निहितार्थ का विश्लेषण करना है। वैश्वीकृत युग में, भारत

में राजनीतिक दिमाग के स्थान के लिए दो तरह के एकात्मक राष्ट्रवाद ने प्रतिस्पर्धा की। एक ओर, 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' थे, जो हमेशा हिंदू विश्व दृष्टिकोण को भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति के मूल में रखना चाहते थे। यह तर्क दिया गया कि भारत की एकता हिंदू धर्म की मजबूत शक्ति से प्राप्त हुई है। उन्होंने समान नागरिक संहिता और भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए आक्रामक रूप से दबाव डाला है। भारत में, वैश्वीकरण ने दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रचारित हिंदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसका उद्देश्य एक एकीकृत और समरूप हिंदू राजनीतिक इकाई बनाना है। हिंदू राष्ट्रवादियों का मानना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में बहुसंख्यक समुदाय की बात दूसरों पर हावी होनी चाहिए। आगे विस्तार से बताने के लिए, सावरकर जैसे औपनिवेशिक विचारक और आरएसएस जैसे दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य मानते हैं कि हिंदू धर्म सहिष्णुता का धर्म है और अल्पसंख्यक समूहों को पनपने की अनुमति देता है और इसलिए, यह भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में, देश की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी, भाजपा, अपने चुनाव घोषणापत्र में भारत की 'अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता' का उल्लेख करती है, जिसे वह हज़ारों वर्षों के साझा जीवन द्वारा एक बड़े ताने-बाने में बुनने के लिए आवश्यक मानती है।

गुरप्रीत महाजन के अनुसार, हिंदू बहुसंख्यकवाद दो बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है: (i) वे इस विश्वास पर काम करते हैं कि राष्ट्र-राज्यों का निर्माण तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब एक साझा सांस्कृतिक पहचान हो। (ii) हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। इस प्रकार, हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाकर, राष्ट्रवादी दावा करते हैं कि यह पूरी आबादी की साझा पहचान है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदू राष्ट्रवाद के एक कट्टरपंथी रूप का उदय सीधे तौर पर उत्पादन और उपभोग की वैश्विक प्रणालियों में भारत के एकीकरण के साथ हुआ। प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद के विध्वंस

ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के एक महत्वपूर्ण प्रतीक को मिटा दिया। हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए, यह विविधता आधुनिक दुनिया में भारत के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज दुनिया भर के अधिकांश लोगों के लिए आधुनिकता का विचार शक्ति, आर्थिक समृद्धि और "पूर्ण सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान" की धारणाओं से जुड़ा हुआ है।

भारत में आर्थिक उदारीकरण के कारण अत्यधिक धन और गरीबी एक साथ अस्तित्व में आई। निस्संदेह इसने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने धार्मिक विभाजन को मजबूत किया। हालाँकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन देश में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी है। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रवचन में, मुसलमानों को विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है, भले ही ऐतिहासिक रूप से, मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा निचली जाति के हिंदू पृष्ठभूमि से धर्मांतरित हुआ है। राज्य प्रायोजित धर्मनिरपेक्षता के पाँच दशकों के बाद भी, अल्पसंख्यक समुदायों का राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, 2014 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में, निचले सदन में केवल 22 मुसलमान चुने गए थे। वास्तव में, वे निरक्षरता, बेरोजगारी और गरीबी के मामले में आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालांकि इस बात से सहमत होना होगा कि भारत में अनुपातहीन संपत्ति हमेशा से ही चिंता का विषय रही है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद इस समस्या में उतनी सुधार नहीं हुआ, जितनी उम्मीद थी। हालांकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि ने रोजगार सृजन को दर्शाया, खासकर आईटी क्षेत्र में, लेकिन यह आबादी को गरीबी से ऊपर उठाने के मामले में पर्याप्त प्रतिनिधित्व साबित नहीं हुआ। यह इस तथ्य से साबित हो सकता है कि भारतीय आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा कुल राजस्व में योगदान दे रहा था। एक लोकप्रिय बिजनेस चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट (2013) के अनुसार, देश का केवल 3 प्रतिशत (लगभग 36 मिलियन) लोग ही टैक्स देते हैं। इसलिए, आम लोगों में असंतोष की भावना बढ़ने लगी।

हिंदुत्व 14 विचारधारा ने भारत में एक-सांस्कृतिक समाज को प्रोत्साहित करने के लिए इन भावनाओं का लाभ उठाया। हालाँकि, इन सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों की संख्या नेहरूवादी ढाँचे के आर्थिक राष्ट्रवादियों से बहुत अधिक थी, जो एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक वातावरण को प्राथमिकता देते थे, लेकिन फिर भी वे अपने आर्थिक और तकनीकी विकास की पूर्व शर्त के रूप में एक 'अच्छी तरह से एकीकृत' भारत का निर्माण करना चाहते थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक पहचान के दावे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, जबकि आर्थिक राष्ट्रवादी उनकी आत्म-अभिव्यक्ति की आवश्यकता के प्रति असंवेदनशील थे। वैश्वीकरण और हिंदुत्व दोनों ही बहिष्कारवादी हैं, लेकिन 15 वे अलग-अलग तरह के बहिष्कार पैदा करते हैं।

1.8 राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ी है।

- वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने से विदेशी व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ गई है। इससे भारत की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ा है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में देश की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इससे भारत को वैश्विक मामलों में अधिक आवाज़ मिलती है।
- दूसरी ओर, इससे राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण भी हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (WTO)

और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में अधिक शक्ति प्राप्त हुई है।

• वैश्वीकरण के कारण नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन भी उभरे हैं। ये संगठन सरकारी नीतियों और कार्यों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की वकालत कर रहे हैं।

• हालाँकि, वैश्वीकरण के लाभों के असमान वितरण के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है

1.9 वैश्वीकरण का प्रभाव: वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है

- **अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव**

वैश्वीकरण विदेशी निवेश को सुगम बनाकर किसी देश की आर्थिक वृद्धि को गति देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कौशल का उन्नयन होता है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार आदि में विकास और निरंतर वृद्धि जैसे तकनीकी विकास और नवाचार को भी प्रभावित करता है। हालाँकि, अर्थव्यवस्था का समतावादी विकास और असमानता अभी भी एक चुनौती है जो वैश्वीकरण के कारण कहीं अधिक प्रचलित है। विकासशील देशों में वस्तुओं और सेवाओं की अप्रतिबंधित आपूर्ति के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी ओर, विकसित वस्तुएं और सेवाएं समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए वहनीय नहीं हैं।

- **राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव**

20वीं और 21वीं सदी में वैश्वीकरण ने राज्यों की भूमिका को नगण्य बना दिया है क्योंकि यह मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य से प्रभावित है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

कोष (IMF), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (WTO) आदि भू-राजनीतिक रूप से राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। IMF, विश्व बैंक और WTO द्वारा बनाए गए नियम अपने सदस्य राज्यों पर अपनी आर्थिक नीति को तर्कसंगत बनाने, वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार और टैरिफ पर प्रतिबंध को कम करने का नैतिक दायित्व डालते हैं जिससे राज्यों की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है।

- **समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव**

वैश्वीकरण एक राष्ट्र की सीमा के पार सूचना के मुक्त और सहज प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे विदेशी संस्कृति का तेजी से आयात होता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और तेज संचार प्रणाली के माध्यम से दुनिया के एक छोर के लोग दूसरे छोर के लोगों के समाज और संस्कृति से आसानी से परिचित हो सकते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं जैसे पोशाक, मशीनें, फिल्में, गीत आदि के व्यापार को सुगम बनाता है, जिसके माध्यम से विदेशी संस्कृति का भी तेजी से आयात किया जा सकता है। हालाँकि, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की आसान पहुँच समाज की लोक और क्षेत्रीय संस्कृति और फैशन के लिए खतरा है।

1.10 वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति

एक निश्चित, महत्वपूर्ण अर्थ में, वर्तमान मानव दुनिया इतिहास के किसी भी पहले के बिंदु की तुलना में अधिक मजबूती से एकीकृत है। जेट विमान और सैटेलाइट डिश के युग में, वैश्विक पूंजीवाद के युग में, सर्वव्यापी बाजारों और वैश्विक जनसंचार माध्यमों के युग में, विभिन्न टिप्पणीकारों ने दावा किया है कि दुनिया तेजी से एक ही जगह बनती जा रही है। हालाँकि इस थोड़े अतिरंजित वर्णन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन शीत युद्ध के बाद की दुनिया का शायद इससे भी अधिक चौंकाने वाला पहलू पहचान की राजनीति का उभरना है - ऐसा लगता है कि हर जगह - जिसका स्पष्ट उद्देश्य जड़ परंपरा, धार्मिक उत्साह और/या जातीय या राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की बहाली है। यह निस्संदेह सच है कि

वैश्वीकरण एक व्यापक प्रवृत्ति है जो हर जगह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है - अमेज़न वर्षावन से लेकर जापानी शहरों तक।

यह अवधारणा हाल ही में एक फैशन बन गई है, और परिणामस्वरूप, इसका अर्थ अस्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए, मैं वैश्वीकरण को उन सभी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के रूप में देखने का प्रस्ताव दूंगा जो दूरी को अप्रासंगिक बनाने में योगदान करती हैं। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम हैं, साथ ही साथ नैतिक निहितार्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में वैश्विक प्रक्रियाएं विशेष इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थितियों को प्रभावित करती हैं, जिससे नए अवसर और भेद्यता के नए रूप बनते हैं। परमाणु बम और संभावित पारिस्थितिक आपदाओं के युग में जोखिम वैश्विक रूप से साझा किए जाते हैं। इसी तरह, विशेष इलाकों में आर्थिक स्थितियां अक्सर (कुछ लोग हमेशा कहेंगे) वैश्विक प्रणाली में कहीं और होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। यदि ताइवान में औद्योगिक उछाल है, तो अंग्रेजी मिडलैंड्स के शहर प्रभावित होंगे। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि तेल निर्यात करने वाली त्रिनिदाद की अर्थव्यवस्था के लिए मुक्ति और तेल आयात करने वाली बारबेडियन अर्थव्यवस्था के लिए आपदा।

उपभोग के पैटर्न भी कुछ मामलों में एक दूसरे से मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं; लगभग हर जगह लोग सेलुलर फोन से लेकर रेडीमेड कपड़ों तक एक जैसे सामान चाहते हैं। अब, स्वाभाविक रूप से ऐसा होने के लिए एक पूर्व शर्त आधुनिकता के कुछ संस्थागत आयामों का कमोबेश सफल कार्यान्वयन है, विशेष रूप से मौद्रिक अर्थव्यवस्था का - भले ही जरूरी न हो कि मजदूरी और साक्षरता हो। वस्तुओं का लगातार बढ़ता हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, चाहे वे भौतिक हों या अभौतिक, एक समान सांस्कृतिक विभाजक का समूह बनाता प्रतीत होता है जो स्थानीय भेदभाव को मिटाने की धमकी देता है। हॉट-डॉग (हलाल या नहीं, जैसा भी मामला हो), पिज्जा और हैमबर्गर (या, भारत में, लैम्बर्गर) वास्तव में विश्व व्यंजनों का हिस्सा हैं; कोस्टा रिका और थाईलैंड में समान डिस्कोथेक में समान पॉप गाने बजाए जाते हैं; दुनिया भर के सिनेमाघरों

में न्यूनतम स्थानीय बदलावों के साथ एक ही कोका-कोला विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इत्यादि।

निवेश पूंजी, सैन्य शक्ति और विश्व साहित्य भी इसी तरह स्थान की सीमाओं से मुक्त हो रहे हैं; वे अब किसी विशेष इलाके से संबंधित नहीं हैं। जेट विमान, सैटेलाइट डिश और हाल ही में इंटरनेट के विकास के साथ, दूरी अब प्रभाव, निवेश और सांस्कृतिक अर्थ के प्रवाह के लिए एक सीमित कारक नहीं लगती। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण केवल बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम नहीं है। यह सच है कि यह काफी हद तक प्रौद्योगिकी और आर्थिक हितों द्वारा संचालित है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं जो अपने आप में तकनीकी या आर्थिक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों के विमर्श को लें: बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान, मानवाधिकारों से जुड़े विचार और मूल्य दुनिया भर के शिक्षित अभिजात वर्ग से (और न केवल, जैसा कि कुछ लोग गलत तरीके से मानते हैं, पश्चिम में) दूरदराज के इलाकों में ग्रामीणों और किसानों तक फैल गए हैं। मानवाधिकारों के विचारों का तेजी से प्रसार शायद वैश्वीकरण की सबसे शानदार सफलताओं में से एक है।

साथ ही, हमने हाल के वर्षों में सभी महाद्वीपों के बहुत से समाजों में, ऐसे राजनीतिक आंदोलनों का विकास देखा है जो विशिष्टता की सामूहिक भावना को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्सर वैश्वीकरण प्रक्रियाओं को लक्षित करते हैं, जिन्हें स्थानीय विशिष्टता और आत्मनिर्णय के लिए खतरा माना जाता है। दुखद परिणामों वाला एक यूरोपीय उदाहरण क्रोएशिया और सर्बिया में जातीय राष्ट्रवाद का हालिया उदय है, लेकिन अधिक समृद्ध और स्थिर यूरोपीय संघ में भी, 1990 के दशक के दौरान मजबूत जातीय और राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़े हैं, जिनमें स्कॉटिश अलगाववाद से लेकर फ्रांस में आव्रजन विरोधी फ्रंट नेशनल तक शामिल हैं। एशिया में, हाल ही के दो सबसे शक्तिशाली उदाहरण अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में आना और भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी, "भारतीय लोगों की पार्टी") की जबरदस्त सफलता है; और कई अफ्रीकी देशों ने भी पिछले दशक के दौरान

अपनी राजनीति का एक मजबूत जातीयकरण देखा है, साथ ही उत्तर में राजनीतिक इस्लाम का उदय भी हुआ है।

अमेरिका में, स्वदेशी समूहों से लेकर अफ्रीकी अमेरिकियों तक, विभिन्न अल्पसंख्यक आंदोलनों ने बढ़ती सफलता के साथ सांस्कृतिक मान्यता और समान अधिकारों की मांग की है। संक्षेप में, 1990 के दशक की राजनीति का मतलब काफी हद तक पहचान की राजनीति है। यह नया राजनीतिक परिदृश्य, जिसे पुराने वाम-दक्षिण विभाजन में फिट करना मुश्किल है, उन कई शिक्षाविदों और पत्रकारों द्वारा बहुत अलग तरीकों से व्याख्या किया जाता है जिन्होंने उनका अध्ययन किया है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि पहचान की राजनीति कई तरह की होती है: कुछ अलगाववादी राष्ट्रवादी आंदोलन हैं; कुछ ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समान अधिकारों की मांग करते हैं; कुछ प्रमुख समूह हैं जो अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं; कुछ धार्मिक हैं, कुछ जातीय हैं, और कुछ क्षेत्रीय हैं।

कई लेखक पहचान की राजनीति को सामान्य रूप से वैश्वीकरण द्वारा सन्निहित व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के प्रति आधुनिकता विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ कमजोरों की रक्षा के रूप में या आधुनिकीकरण की एक छिपी हुई रणनीति के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग पहचान की राजनीति के मनोवैज्ञानिक आयाम पर जोर देते हैं, इसे तेजी से बदलते युग में गरिमा और जड़ता की भावना को बनाए रखने के उदासीन प्रयासों के रूप में देखते हैं; अन्य लोग समूहों के बीच दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करते हैं; कुछ लोग पहचान की राजनीति को बहिष्कार की रणनीति और घृणा की विचारधारा के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे समाजवाद के सच्चे जन्मे बच्चे के रूप में देखते हैं, जो वंचितों के सामूहिक प्रयासों की अभिव्यक्ति है।

इनमें से कोई भी व्याख्या और निर्णय पूरी कहानी नहीं बताते हैं, क्योंकि विचाराधीन ठोस

आंदोलन अलग-अलग हैं और क्योंकि पहचान की राजनीति की घटना इतनी जटिल है कि एक सरल व्याख्या पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की केन्द्रापसारक या एकीकृत ताकतें और पहचान की राजनीति की केन्द्रापसारक या विखंडनकारी ताकतें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो पूरक प्रवृत्तियाँ जिन्हें सहस्राब्दी के मोड़ पर वैश्विक परिदृश्य को समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से समझना चाहिए।

विभिन्न कारणों से, वैश्वीकरण स्थानीयकरण के लिए परिस्थितियाँ बनाता है, अर्थात सीमित इकाईयाँ बनाने के विभिन्न प्रकार के प्रयास - देश (राष्ट्रवाद या अलगाववाद), आस्था प्रणालियाँ (धार्मिक पुनरोद्धार), संस्कृतियाँ (भाषाई या सांस्कृतिक आंदोलन) या हित समूह (जातीयता)। इस कारण से, समाजशास्त्री रोलांड रॉबर्टसन द्वारा गढ़ा गया एक अधिक उपयुक्त शब्द ग्लोकलाइज़ेशन हो सकता है। अब मैं कुछ ऐसी विशेषताएँ प्रस्तुत करूँगा जो सहस्राब्दी के अंत के "ग्लोकल" पहचान आंदोलनों में समान प्रतीत होती हैं। सबसे पहले, पहचान की राजनीति में हमेशा दुर्लभ संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा शामिल होती है।

सामूहिक पहचान के आधार पर सफल लामबंदी के लिए यह व्यापक मान्यता आवश्यक है कि संसाधन समूह रेखाओं के अनुसार असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। "संसाधनों" की व्याख्या यथासंभव व्यापक अर्थ में की जानी चाहिए, और सिद्धांत रूप में इसका अर्थ आर्थिक संपदा या राजनीतिक शक्ति, मान्यता या प्रतीकात्मक शक्ति माना जा सकता है - हालाँकि आमतौर पर मुख्य रूप से आर्थिक या राजनीतिक संसाधन ही दांव पर लगे होते हैं। दूसरे, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण मतभेदों को वास्तविक बनाते हैं और संघर्ष को जन्म देते हैं। जब पहले अलग-अलग समूहों को साझा आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में एकीकृत किया जाता है, तो असमानताएँ स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि समूहों के बीच सीधी तुलना संभव हो जाती है।

एक निश्चित अर्थ में, जातीयता को सांस्कृतिक अंतरों को तुलनीय बनाने की प्रक्रिया के रूप

में वर्णित किया जा सकता है, और उस सीमा तक, यह वैश्वीकरण द्वारा तीव्र संपर्क द्वारा बढ़ावा दिया गया एक आधुनिक परिघटना है। यदि आप अपने पड़ोसी के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं, तो आप उससे ईर्ष्या नहीं करते। तीसरा, समानता वैचारिक रूप से समानता को मात देती है। जातीय राष्ट्रवाद, राजनीतिक धर्म और स्वदेशी आंदोलन सभी समूह को समरूप, "एक ही तरह के" लोगों के रूप में चित्रित करते हैं। आंतरिक मतभेदों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और इस कारण से, अक्सर यह तर्क दिया जा सकता है कि पहचान की राजनीति समूह के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हितों की सेवा करती है, भले ही समूह समग्र रूप से वंचित हो, क्योंकि यह आंतरिक वर्ग मतभेदों को छुपाता है। चौथा, अतीत की पीड़ा और अन्याय की छवियों का आह्वान किया जाता है।

कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं: सर्ब 1389 में कोसोवो में तुर्कों के हाथों हार का शोक मनाते हैं; हिंदू भाजपा के नेताओं ने 1500 के दशक से भारत में मुगल (मुस्लिम) शासन को खूनी और निरंकुश के रूप में चित्रित करने के लिए बहुत मेहनत की है; और अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन गुलामी के इतिहास पर व्यापक रूप से आधारित है। यहां तक कि पश्चिमी यूरोप में आप्रवासी विरोधी राजनेताओं जैसे स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के प्रवक्ता भी इसी तरह तर्क दे सकते हैं। पांचवां, राजनीतिक प्रतीकवाद और बयानबाजी व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर करती है।

यह शायद सामान्य रूप से पहचान की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक विशेषता है। अपने समर्थकों को संबोधित करने में मिथकों, सांस्कृतिक प्रतीकों और रिश्तेदारी शब्दावली का उपयोग करते हुए, पहचान की राजनीति के प्रवर्तक व्यक्तिगत अनुभवों और समूह के इतिहास के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह, एक सर्ब के लिए कोसोवो की पौराणिक लड़ाई के बारे में पहले व्यक्ति ("हम 1389 में हार गए") में बात करना पूरी तरह से समझदारी भरा है, और बदला लेने के तर्क को रूपक रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाता है, कई मामलों में लाखों लोग। स्थानीयता और परिवार से जुड़े अंतरंग अनुभवों

को इस तरह राष्ट्रीय स्क्रीन पर पेश किया जाता है।

छठी बात, पहले आने वालों की तुलना आक्रमणकारियों से की जाती है। हालाँकि यह वैचारिक विशेषता किसी भी तरह से पहचान की राजनीति में सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन जब भी संभव हो, इसका आह्वान किया जाता है और इस प्रक्रिया में, ऐतिहासिक तथ्यों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। अंत में, समाज में वास्तविक सामाजिक जटिलता को सरल विरोधाभासों के एक सेट में घटा दिया जाता है। जैसा कि एडॉल्फ हिटलर ने पहले ही मीन काम्फ में लिखा था, सच्चा राष्ट्रीय नेता अपने लोगों का ध्यान उस समय एक दुश्मन पर केंद्रित करता है। चूँकि क्रॉस-कटिंग संबंध हिंसक संघर्ष की संभावनाओं को कम करते हैं, इसलिए सामूहिक पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट मानदंडों (जैसे स्थान, धर्म, मातृभाषा, रिश्तेदारी) पर आधारित होनी चाहिए। फिर से, अक्सर शैतानी दूसरे की ओर सीमाओं को चित्रित करने के कार्य में आंतरिक मतभेदों को कम करके आंका जाता है। * * * पहचान की राजनीति को अक्सर उस समय से एक कालभ्रमित अस्तित्व के रूप में खारिज कर दिया जाता है जब रिश्तेदारी ("रक्त संबंध"), धर्म या स्थानीय संबंध राजनीति का आधार बनते थे। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध, कई बार यह तर्क दिया गया है, जो हमेशा सही रहा है, कि हालांकि पहचान की राजनीति पारंपरिक वेश में होती है, परंतु सतह के नीचे यह आधुनिकता का उत्पाद है।

किसी परंपरा, संस्कृति या धर्म से जुड़ी प्रबल भावनाएं तब तक सक्रिय नहीं हो सकतीं, जब तक लोगों को यह महसूस न हो कि यह घेरे में है। इसे रूपकात्मक रूप से कहें तो: एक मछली को तब तक पानी के बारे में कुछ नहीं पता होता, जब तक वह पानी से घिरी रहती है, लेकिन जैसे ही उसे हवा में खींचा जाता है, उसमें पानी के प्रति गहरी दिलचस्पी और उसके प्रति उदासीनता विकसित हो जाती है। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि मछली को पानी तभी पता चलता है, जब उसे पानी से दूर किया जाता है। इस तरह से देखा जाए, तो सामूहिक भावनाएं, जिन पर पहचान की राजनीति निर्भर करती है, खुद को तेजी से बदलते हालात में अनुभव किए जाने वाले नुकसान की भावना से जुड़ी हुई गहरी आधुनिक भावनाएं बताती हैं।

जातीय राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यक आंदोलन और राजनीतिक धर्म केक का एक बड़ा हिस्सा और साथ ही खुद के बारे में सकारात्मक भावना प्रदान करते हैं, और चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, ये आंदोलन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में तब तक प्रभावशाली बने रहेंगे, जब तक कि कुछ बेहतर नहीं आता।

1.11 वैश्वीकरण और राजनीति

राजनीति विज्ञान में वैश्वीकरण का अर्थ अलग-अलग राष्ट्रों, क्षेत्रों या यहाँ तक कि व्यक्तियों का एक व्यापक वैश्विक व्यवस्था में एकीकरण है। इसकी विशेषता लोगों और देशों के बीच संबंधों और जुड़ावों में वृद्धि और इन अंतःक्रियाओं के बारे में बढ़ती जानकारी है। यह एकीकरण प्रक्रिया अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज या संस्कृति को प्रभावित कर सकती है; यानी, प्रक्रिया की परिभाषा बहुत सामान्य है और यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक एकीकरण को संदर्भित कर सकती है। किसका एकीकरण किया जा रहा है, यह सवाल भी खुला छोड़ दिया गया है, हालाँकि राजनीति विज्ञान में यह ज़्यादातर देश ही होते हैं जो मुद्दे पर होते हैं। इस तरह के एकीकरण का संचालन करने का तरीका भी परिवर्तनशील है। साहित्य में वैश्वीकरण का सबसे आम रूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एकीकरण शामिल है, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी प्रवाह, श्रम आंदोलनों और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के माध्यम से।

कुछ लेखकों के लिए, इसका अर्थ है वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में देशों का एकीकरण - यानी, निजी संपत्ति, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और आर्थिक मूल्य आवंटित करने के लिए बाजारों के उपयोग पर आधारित व्यवस्था। कुछ लोग इसे नवउदारवादी वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के आगे बढ़ने के साथ ही पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी समूह और नवउदारवादी प्रथाएँ पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। देशों और व्यक्तियों के लिए यह अच्छा है या बुरा, यह काफी हद तक विद्वान के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ लोग वैश्वीकरण को अलग-अलग समूहों

के समरूपीकरण से जोड़ते हैं; इसका एक उदाहरण कई स्थानीय भाषाओं का लुप्त होना और अंग्रेजी के उपयोग का बढ़ता प्रसार है। अन्य इसे अमेरिकी (या एंग्लो-अमेरिकन) मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं के वर्चस्व से जोड़ते हैं। उदार लोकतंत्र की ओर वैश्विक मोड़ को अक्सर एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस बिंदु पर वैश्वीकरण पूरा नहीं हुआ है। देशों के पास विश्व व्यवस्था में एकीकरण के विभिन्न स्तर हैं। एक वास्तविक वैश्विक व्यवस्था - चाहे वह आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक हो - किस हद तक मौजूद है, यह बहस का विषय है। वैश्वीकरण के कारणों और परिणामों पर भी बहस होती है।

1.12 वैश्वीकरण के कारण

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैश्वीकरण कैसे विकसित हुआ है, और यह जिस तरह से विकसित हुआ है, वह क्यों हुआ है। यदि कोई वैश्वीकरण के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाता है, तो इसकी प्रगति को इस बात से समझाया जा सकता है कि तकनीकी परिवर्तन कितनी तेज़ी से होता है और फैलता है। ऐसे समय में जब ऐसा परिवर्तन बहुत तेज़ होता है और जब नए विचारों और तकनीकों को अपनाना तेज़ होता है, वैश्वीकरण तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कई लोगों को लगता है कि 19वीं सदी के मध्य और अंत में ऐसा ही हुआ था, जब भाप की शक्ति, रेलमार्ग और टेलीग्राफ जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों ने दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदल दिया था। सैन्य प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवादी नियंत्रण द्वारा आंशिक रूप से फैली इन तकनीकों ने दुनिया के दूरदराज के क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद की।

युद्ध के बीच की अवधि में तकनीकी परिवर्तन नहीं रुका, जब वैश्वीकरण पीछे हट रहा था; वास्तव में, युद्ध ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस अवधि में ऐसी तकनीकों का प्रसार बहुत सीमित था क्योंकि कई सीमाएँ बंद थीं और देश अपने नए रहस्यों की रक्षा कर रहे थे, जो अक्सर युद्ध लड़ने से जुड़े होते थे। परमाणु हथियारों का विकास इसका एक उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि को फिर से एक ऐसे दौर के रूप में देखा

जाता है जब सरकारों द्वारा तेजी से तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया था, जब नई प्रक्रियाओं और उत्पादों का प्रसार बिना किसी बाधा के हुआ था, और जब कम से कम गैर-साम्यवादी देशों में नवाचारों को अपनाने को राज्यों द्वारा अपनाया गया था। इस प्रकार 1950 के बाद वैश्वीकरण में तेजी आई क्योंकि तकनीकी परिवर्तन में तेजी आई।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी परिवर्तन केवल अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है; ऐसे परिवर्तनों का समाज, संस्कृति और राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिजली, टेलीफोन (मोबाइल फोन का उल्लेख नहीं), रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटेड शिपिंग कंटेनर, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और अब इंटरनेट - पिछली डेढ़ सदी के प्रमुख नवाचारों में से कुछ का नाम लेने के लिए - ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन सभी ने दुनिया भर में व्यक्तियों के बीच परिवहन और संचार की लागत को कम करके वैश्वीकरण में योगदान दिया है। वैश्विक एकीकरण की इस धर्मनिरपेक्ष कहानी में, देश नवाचार को बाधित करने और इसके प्रसार को धीमा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे अंततः ऐसे परिवर्तन को रोक नहीं सकते। जिस हद तक तकनीक परिवहन और संचार लागत को कम करती है, तकनीकी नवाचार वैश्वीकरण के लिए एक अदम्य शक्ति प्रदान करता है। वैश्वीकरण की गति प्रभावित हो सकती है लेकिन इसकी आगे की गति नहीं।

वैश्वीकरण के चक्रीय दृष्टिकोण में, अन्य कारकों को अक्सर उन परिवर्तनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है जो हम देखते हैं। एक सिद्धांत वैश्वीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व एक देश के होने की प्रमुखता पर ध्यान केंद्रित करता है। 1970 और 1980 के दशक में विकसित हेगेमोनिक स्थिरता सिद्धांत (एचएसटी) ने तर्क दिया कि एक खुली, स्थिर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक एकल विश्व नेता आवश्यक था। ऐसे नेता के बिना, तकनीकी परिवर्तन भी वैश्वीकरण नहीं ला पाएगा। इस सिद्धांत के दो संस्करण मौजूद हैं। एक में, हेगेमॉन, जिसके पास अन्य देशों के सापेक्ष सभी क्षेत्रों में जबरदस्त क्षमताएं हैं, ऐसी खुलेपन और स्थिरता की लागत का भुगतान करके और उसे व्यवस्थित करके दुनिया के बाकी हिस्सों पर एक सौम्य

प्रभाव डालता है। यह नेता की भूमिका निभाता है और अन्य इसके प्रयासों से लाभान्वित होते हैं। यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमशः 19वीं सदी के मध्य से अंत तक और 20वीं सदी के मध्य से अंत तक इसके दो उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। ब्रिटिश नेतृत्व क्षमता का ह्रास और युद्ध के बीच की अवधि में नेतृत्व करने में संयुक्त राज्य अमेरिका की विफलता को उस अवधि के बंद होने और उथल-पुथल के प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया। ऐसे सौम्य नेतृत्व के बिना, दुनिया एकीकृत नहीं हो पाएगी और देश अपने पड़ोसियों को भिखारी बनाने की कोशिश में अलगाववादी रुख अपनाए रहेंगे।

हेजमॉन छोटे देशों के लिए विश्वास और प्रतिस्पर्धा की समस्या को हल करता है और इस प्रकार वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के अपने प्रावधान के माध्यम से सभी को बेहतर स्थिति में उभरने की अनुमति देता है। यह अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और कठिन आर्थिक समय में एक खुला बाजार प्रदान करने का प्रयास करता है। कठिन समय में देशों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण करके, हेजमॉन स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकता है और अपने सौम्य उद्देश्यों के बारे में अन्य देशों को आश्वस्त करने के लिए खुद को बाध्य कर सकता है। वैश्वीकरण के लिए दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति से नेतृत्व की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद शक्तिशाली देशों का एक छोटा समूह ऐसा ही नेतृत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन इस समूह के भीतर असहमति या दोष दूसरे पर डालने की चिंताओं ने इस दृष्टिकोण पर संदेह पैदा कर दिया है।

दूसरे दृष्टिकोण में, आधिपत्य की भूमिका निस्वार्थ नहीं देखी जाती है। यहाँ वैश्विक नेता अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करता है और अपने श्रेष्ठ संसाधनों का उपयोग दूसरों को रिश्वत देने और उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर करने के लिए करता है। ब्रिटिश और अमेरिकी आधिपत्य को एक बलपूर्वक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा देश अपनी इच्छा दूसरों पर थोपता है; आधिपत्य प्राप्त करता है, जबकि बाकी सभी लोग अधीन हो जाते हैं। ब्रिटिश मामले में, साम्राज्यवाद ने खुले बाजारों और पाउंड की प्रमुख

भूमिका के साथ मिलकर दूसरों को अपने बाजार खोलने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस अवधि में विकसित अंतर्राष्ट्रीय कानून ने भी वैश्वीकरण को सक्षम करने का काम किया क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने इसका उपयोग उपनिवेशों को खोलने के लिए किया। हालाँकि, जैसे-जैसे अन्य देश बढ़े और प्रतिस्पर्धी बने, ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ती कठिनाई में चला गया। एक बार जब ब्रिटेन विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सका, तो सबसे मजबूत शक्तियों के आसपास क्षेत्रीय ब्लॉक विकसित हुए। ब्रिटेन अब संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी सहित देशों को अपनी पसंदीदा प्रथाओं का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, जैसे कि स्टर्लिंग प्रणाली में शामिल होना या अपने बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना। ब्रिटिश आधिपत्य के पतन के साथ वैश्वीकरण का दौर समाप्त हो गया, क्योंकि शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों ने अपने प्रभाव क्षेत्र विकसित कर लिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी क्षेत्रों में इसके प्रभुत्व ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शासन की एक प्रणाली स्थापित करने में मदद की जिसने 60 से अधिक वर्षों तक अमेरिकी आधिपत्य बनाए रखा है। पहले के ब्रिटिशों के विपरीत, अमेरिकियों ने अमेरिकी वैश्विक व्यवस्था को अंतर्निहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की एक श्रृंखला स्थापित की। GATT/WTO, IMF, विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंक, अन्य के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सीधे ऐसा किए बिना अपना प्रभुत्व चलाने का साधन रहे हैं। इन संस्थानों ने देशों को पूंजीवादी प्रथाओं को अपनाने, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए अपने बाजार खोलने और अन्य आर्थिक मामलों में तथाकथित वाशिंगटन आम सहमति का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। देशों को ऋणी बनने की अनुमति देना या प्रोत्साहित करना और फिर जब वे अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो उन पर शर्तें थोपना, हाल ही में, लोकतंत्रीकरण के लिए दबाव भी इन संस्थाओं की ओर से आया है। इस प्रकार, वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करने का अमेरिकी तरीका ब्रिटिश तरीके से अलग है,

लेकिन इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए दूसरों को मजबूर करना भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में सॉफ्ट पावर का उपयोग शायद अधिक स्पष्ट रहा है। लेकिन दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप भरपूर रहा है, और इस दृष्टिकोण ने इसकी वैश्विक दृष्टि को लागू करने का काम किया है। जबरदस्ती के आधिपत्य के इस दृष्टिकोण में, पहले यूके और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में अपनी उच्च स्थिति से बहुत कुछ हासिल किया; विडंबना यह है कि, दोनों मामलों में उनकी गिरावट उनकी नेतृत्व भूमिका से जुड़ी हुई लगती है। दुर्भावनापूर्ण आधिपत्य का यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए यथार्थवादी और मार्क्सवादी दोनों दृष्टिकोणों से जुड़ा हुआ है। इस बात पर पर्याप्त बहस मौजूद है कि आधिपत्य का जबरदस्ती वाला या सौम्य दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट है। इस बहस में इस बात पर विवाद शामिल है कि इस वैश्वीकरण प्रक्रिया से आधिपत्य के अलावा अन्य देशों को किस हद तक नुकसान हुआ है या मदद मिली है।

वैश्वीकरण प्रक्रिया का अधिक रचनात्मक विवरण इस बात पर केंद्रित होगा कि वैश्विक समुदाय और आधुनिकता के बारे में विचार और मानदंड राज्य के व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। यह पिछले 60 वर्षों के प्रमुख विचारों की पहचान करेगा और यह बताएगा कि इन्हें कैसे वैध बनाया गया और पूरे सिस्टम में फैलाया गया। उदाहरण के लिए, उदार लोकतंत्र, मानवाधिकार, पूंजीवाद और नवउदारवाद में विश्वास दुनिया भर में फैल गए हैं; ये संस्थाएँ और प्रथाएँ वैध हो गई हैं और इन्हें देश को प्रबंधित करने का "आधुनिक" तरीका माना जाता है। इस प्रकार देश वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए उन्हें पेश करने और विकसित करने की आकांक्षा रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इन विचारों को मूर्त रूप देती हैं और फैलाती हैं, जैसा कि वैश्विक नागरिक समाज के मानदंड उद्यमी करते हैं।

हालाँकि, इन विचारों का मुख्य प्रभाव विविधता को कम करना और समरूपता में योगदान देना है। विद्वान अक्सर इस बात पर विभाजित होते हैं कि यह मानक वैश्वीकरण लाभकारी है या नहीं। स्पष्ट रूप से, कुछ विद्वानों द्वारा कुछ विचारों (जैसे, लोकतंत्र और मानवाधिकार) के

प्रसार को दूसरों के प्रसार (जैसे, पूंजीवाद और नवउदारवाद) की तुलना में अधिक सकारात्मक प्रकाश में देखा जाता है। इस बात पर भी बहस होती है कि कुछ विचार कैसे प्रमुख हो जाते हैं। क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश द्वारा दबाव या प्रलोभन के माध्यम से है कि अन्य लोग इन विचारों का समर्थन करते हैं? क्या यह उस समय की भावना है जो कुछ विचारों को स्थिति के अनुकूल बनाती है? या क्या यह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक उद्यमियों का प्रभाव है जो देशों से स्वतंत्र कुछ विचारों को वैधता और नैतिक दबाव देते हैं?

वैश्वीकरण के उदय के लिए दिया गया एक और कारण बहुत कम जानबूझकर दिया गया है। समय के साथ देशों की असमन्वित कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप केवल एक तेजी से खुली और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली बन गई है। कोई भी देश ऐसा परिणाम नहीं चाहता था, लेकिन प्रत्येक देश ने अपने सर्वोत्तम हितों पर काम करते हुए ऐसी नीतियों को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप एक वैश्वीकृत दुनिया बन गई। इस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है क्योंकि वैश्वीकरण के लिए कई देशों के निर्णयों के कारण और अनुक्रम राष्ट्रीय रूप से अलग-अलग थे। उन्नत औद्योगिक देशों ने 1960 से 1980 के दशक में व्यापार और फिर अपने पूंजी बाजारों को उदार बनाया। यूरोपीय संघ इस दिशा में आंदोलन के लिए एक प्रमुख शक्ति था; हालाँकि, यूरोपीय देश वैश्वीकरण के अलावा अन्य कारणों से संघ में शामिल हुए और इसका विस्तार किया, जैसे कि घरेलू राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर चीन ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में आंतरिक कारणों से अपना आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया, और राजनीतिक सुधार आगे नहीं बढ़ पाए।

पूर्व साम्यवादी देश शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद ही अधिक खुली और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, और उनमें से कई के लिए, यूरोपीय संघ में शामिल होने के महत्वपूर्ण घरेलू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य थे। विकासशील देशों में, लोकतंत्रीकरण अक्सर आर्थिक उदारीकरण से पहले हुआ। कई गरीब देशों ने 1990 के दशक के अंत और उसके बाद तक आर्थिक रूप से उदारीकरण नहीं किया। वास्तव

में, सबसे खास बात यह है कि 1970 के दशक के बाद से देशों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। जिस तरह से और जिस हद तक देशों को विश्व प्रणाली में एकीकृत किया गया है, वह उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। जबकि समग्र प्रवृत्ति अधिक संपर्क और खुलेपन की ओर रही है, राज्यों ने इसे कैसे महसूस किया, इसमें पर्याप्त विविधता रही है। उदाहरण के लिए, आज अधिकांश देशों में 30 साल पहले की तुलना में अंग्रेजी बहुत अधिक बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी का प्रसार देश-दर-देश बहुत भिन्न है। इस दृष्टिकोण से, यह असंगठित प्रक्रिया प्रत्येक देश में विभिन्न कारणों से प्रेरित रही है। वैश्वीकरण प्रत्येक के लिए अलग-अलग तरीके से विकसित हुआ है; और वैश्वीकरण का भाग्य देशों के (कुछ हद तक स्वतंत्र) निर्णयों पर निर्भर करता है। 2008 से 2009 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के प्रति प्रतिक्रियाएं इस दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं, क्योंकि सरकारें समन्वय करने में विफल रहीं और इसके बजाय उन्होंने अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की।

1.13 वैश्वीकरण के परिणाम

वैश्वीकरण के कारणों पर बहस के अलावा, इसके परिणामों के बारे में भी बहुत बहस है। साहित्य में कम से कम तीन अलग-अलग दृष्टिकोण हैं: (1) जबकि कुछ लोग इसके परिणामों को सभी पहलुओं में नकारात्मक मानते हैं, (2) अन्य लोग इसके प्रभावों को समग्र रूप से सकारात्मक मानते हैं, और (3) फिर भी अन्य लोग दृढ़ता से बीच में खड़े हैं और इसे लागत और लाभ दोनों के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण के कई अलग-अलग प्रभाव होने की बात कही जाती है। यहाँ दृष्टिकोण उन प्रभावों में से कई को देखना और प्रत्येक पर विद्वानों की अलग-अलग राय को रेखांकित करना है। इस स्तर पर, इसके प्रभावों पर बहुत कम आम सहमति है। इस बारे में पर्याप्त साहित्य मौजूद है कि क्या (और कैसे) वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास दर, गरीबी, असमानता, लोकतंत्र, संघर्ष, राज्य क्षमता, नीति और संस्थागत अभिसरण, सांस्कृतिक विविधता, अस्थिरता और संकटों का प्रसार, और पूंजी और श्रम के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करने का तात्पर्य है कि किसी

को अन्य कारकों को स्थिर रखना चाहिए, जो एक कठिन कार्य है। चूंकि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इन सवालों के निश्चित उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से प्रत्येक परिणाम के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और साक्ष्य मौजूद हैं।

आर्थिक विकास

वैश्वीकरण के आर्थिक विकास पर कई तरह के प्रभाव होने का आरोप है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ता एकीकरण आमतौर पर व्यापार उदारीकरण और विदेशी निवेश की खोज के माध्यम से और कभी-कभी पूंजी बाजार उदारीकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। आर्थिक विकास के लिए इन नीतियों के परिणामों पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ शोध इस विचार का समर्थन करते हैं कि सभी नीतियां विकास को बढ़ाती हैं; संभवतः इस बात के अधिक प्रमाण हैं कि व्यापार और विदेशी निवेश पूंजी बाजार उदारीकरण की तुलना में विकास को बढ़ावा देते हैं। शोध से यह भी पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में वैश्वीकृत हुए देशों की वृद्धि उन देशों की तुलना में अधिक तेज़ी से हुई, जिन्होंने ऐसा नहीं किया। कई लोगों को उम्मीद थी कि विकासशील देशों का विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण आर्थिक अभिसरण को बढ़ावा देगा - यानी, यह सबसे गरीब देशों को तेजी से बढ़ने में मदद करेगा और इसलिए समय के साथ सबसे अमीर देशों के बराबर पहुंच जाएगा।

इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा हुआ है - मुख्य रूप से एशिया में - लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका बहुत समर्थन नहीं है। पिछले कुछ दशकों में उत्तर-दक्षिण विभाजन बहुत कम होता हुआ नहीं दिखता है। आंशिक रूप से, ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर में कुछ विकासशील देशों की तुलना में तेज़ विकास दर है। हालाँकि, कई देशों के लिए, वैश्वीकरण ने तेज़ विकास को बढ़ावा नहीं दिया है। विद्वान बताते हैं कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 1980 के दशक से पहले के दशकों में विकास दर बाद की तुलना

में अधिक थी। कई देशों के लिए विकास पर व्यापार का प्रभाव भी अस्पष्ट रहा है; कुछ, विशेष रूप से एशिया में, इससे लाभ हुआ है। लेकिन कई अन्य, उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, ऐसा नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाहित हुआ है और इसलिए यह तेज़ विकास से जुड़ा है, लेकिन यह कारणात्मक नहीं हो सकता है। अंत में, इस बात पर बहुत संदेह है कि विकासशील देशों के लिए पूंजी बाजार उदारीकरण आर्थिक विकास के लिए अच्छा है या रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं, जैसे असमानता और अस्थिरता, ने इसकी विकास क्षमता को प्रभावित किया है।

गरीबी और असमानता

गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक बड़ी बहस केंद्रित है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर लगभग 2005 तक, वैश्विक स्तर पर गरीबी में कमी आई है। अत्यधिक गरीबों (जो 1.25 डॉलर/दिन से कम पर जीवन यापन करते हैं) की संख्या 1981 में 1.9 बिलियन से घटकर 2005 में 1.4 बिलियन हो गई, जो विकासशील देशों की आबादी के 50% से घटकर 25% हो जाने के बराबर है (विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2009, पृष्ठ 61)। इसके अलावा, उदाहरण के लिए, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में, प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत 1990 में 69% से घटकर 2007 में 25% हो गया। फिर भी, दुनिया में 2.5 बिलियन लोग अभी भी प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं (विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2008, पृष्ठ 14, 34)।

विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता के अन्य मापदंड भी बेहतर हुए हैं: उदाहरण के लिए, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, अधिकांश क्षेत्रों में बेहतर हुई है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ एचआईवी/एड्स ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। क्या यह गिरावट वैश्वीकरण

के कारण हुई? कुछ देशों ने व्यापार बाधाओं को कम किया है और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, जैसे कि चीन, ताइवान और वियतनाम, पिछले दशकों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। हालाँकि, इन देशों के लिए भी, यह स्पष्ट नहीं है कि देश के भीतर असमानता कम हुई है; कई विकासशील देशों में बढ़ता ग्रामीण-शहरी विभाजन बढ़ती असमानता का संकेत देता है। कई अन्य देशों में गरीबी के स्तर में बहुत कम बदलाव देखा गया है, और असमानता या तो काफी हद तक स्थिर रही है या बढ़ी है।

विश्व बैंक अधिक वैश्वीकरण को वृद्धि, घटती गरीबी और घटती असमानता से जोड़ता है - विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर। लेकिन अन्य डेटा इस आशावादी परिदृश्य पर सवाल उठाते हैं। व्यापार के कई अध्ययनों से पता चला है कि विकासशील देशों में इसके उदारीकरण से गरीबी या असमानता कम नहीं होती है। आज व्यापार और विदेशी निवेश से जुड़े तथाकथित कौशल पूर्वाग्रह का मतलब अक्सर यह होता है कि उच्च कुशल श्रमिकों को कम कुशल श्रमिकों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण से अधिक लाभ होता है, जो देश के भीतर असमानता की डिग्री को बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में विकसित देशों में भी असमानता बढ़ी है। यह परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। व्यापार के मानक मॉडल बताते हैं कि अमीर देशों में, उच्च कुशल श्रमिकों को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए और कम कुशल श्रमिकों को नुकसान उठाना चाहिए; यह गरीब देशों में होने वाली घटना के विपरीत है। ऐसा लगता है कि यह कई विकसित देशों में हुआ है, हालांकि यह संभवतः कल्याणकारी राज्य के पुनर्वितरण प्रभावों से कम हो गया है। इस प्रकार कई विकसित देशों में असमानता बढ़ी है।

सबसे चौंकाने वाला परिणाम यह रहा है कि विकासशील देशों में कम कुशल श्रमिकों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। हालाँकि अब इस परिणाम के लिए कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में गरीबी में कमी और समानता के लिए यह एक समस्या है, खासकर तब जब इन देशों में कुल मिलाकर अच्छी तरह से विकसित कल्याणकारी राज्य नहीं हैं। वित्तीय संकटों का प्रभाव और वैश्विक प्रणाली में उनका प्रसार भी गरीबी और असमानता के संबंध में

चिंता का विषय है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैश्वीकृत दुनिया में ऐसे संकट अधिक संभावित, अधिक तीव्र और अधिक व्यापक रूप से फैले हुए हैं। अन्य बताते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय झटके एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं और वास्तव में प्रणाली को अधिक स्थिर बना सकते हैं। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन वित्तीय झटकों का देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एशियाई वित्तीय संकट और हाल ही में वैश्विक वित्तीय संकट ने गरीबी और असमानता को बढ़ाया है। सरकारें अपने देशों में वैश्वीकरण प्रक्रिया को कैसे आकार देती हैं, यह वैश्वीकरण द्वारा गरीबी और असमानता को प्रभावित करने के तरीके को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि वैश्वीकरण के साथ देशों के अनुभव काफी अलग होंगे।

राजनीति और लोकतंत्रीकरण

वैश्वीकरण को राजनीति पर प्रभाव डालने का श्रेय भी दिया जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसने लोकतंत्र को फैलाने में मदद की है और नेताओं पर लोकतंत्रीकरण के लिए दबाव डाला है। 1980 के दशक से निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ा है। लेकिन क्या यह वैश्वीकरण के कारण हुआ है? खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या आदर्श उद्यमियों द्वारा उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से वैश्वीकरण नेताओं को शासन के अधिक लोकतांत्रिक रूपों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि वे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के सदस्य बनना चाहते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत तर्क देते हैं: कई देशों में नीतियों में बदलाव के लिए लोकतंत्रीकरण आवश्यक था जिसके कारण अधिक वैश्वीकरण हुआ।

लोकतंत्रीकरण और वैश्वीकरण के बीच कार्य-कारण संबंध पर बहुत बहस होती है। यह भी एक कठिन प्रश्न है कि क्या लोकतंत्र और वैश्वीकरण संगत हैं। राजनीतिक शासन अपनी सीमाओं के भीतर लोकतंत्र का अभ्यास करते हैं, और जनता अपनी सरकारों को उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों के लिए जिम्मेदार मानती है। लेकिन एक वैश्वीकृत दुनिया में इन

दोनों से समझौता किया जा सकता है। यदि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम वैश्विक ताकतों से उत्पन्न होते हैं और यदि सरकारें इन ताकतों को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यूरोपीय संघ में कथित लोकतांत्रिक घाटा इस समस्या की एक अभिव्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बढ़ती संख्या भी एक संबंधित चिंता का विषय हो सकती है। इनमें से कई संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और देशों को अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीतियों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए स्थापित की गई हैं। लेकिन अगर वे सरकारों से निर्णय लेने की शक्ति छीन लेते हैं, तो वे घरेलू लोकतंत्र और उसमें जनता के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। दूसरों ने तर्क दिया है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा लोकतंत्र को बढ़ाया जा सकता है। लोकतंत्र का प्रसार और वैश्वीकरण की यह लहर एक साथ चली है; समय के साथ देश अत्यधिक वैश्वीकृत दुनिया में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह लोकतंत्र के लिए अनुकूल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

टकराव

वैश्वीकरण का संघर्ष पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विश्व युद्धों के बाद से अंतरराष्ट्रीय युद्धों की आवृत्ति में लगातार कमी आई है, लेकिन हाल ही में गृह युद्धों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कुछ शोध बताते हैं कि वैश्वीकरण के पहलू संघर्ष को कम कर सकते हैं, खासकर अंतरराज्यीय युद्ध। शोध से पता चला है कि देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, विदेशी निवेश में वृद्धि और व्यापार समझौते सभी कम अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से जुड़े हैं। तथाकथित अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी शांति इस तर्क का एक उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच भी ऐसा ही संबंध प्रतीत होता है: कोई देश जितना अधिक उनमें शामिल होता है, सैन्य संघर्षों में शामिल होने की संभावना उतनी ही कम होती है। गृह युद्ध के लिए ऐसा कोई समान संबंध नहीं दिखता है। हालांकि, दूसरी तरफ, जैसे-जैसे देश एक-दूसरे के साथ व्यापार और निवेश करते हैं, उनके बीच व्यापार और निवेश विवाद होने की संभावना अधिक होती है। समय के साथ ये संघर्षों

को बढ़ा सकते हैं, अगर पैदा नहीं करते हैं।

इसके अलावा, जैसे-जैसे दूर के देश और लोग एक-दूसरे के करीब आते हैं, गलतफहमियों और विवादों की संभावना बढ़ती है क्योंकि उनकी अलग-अलग संस्कृतियां, मूल्य और विश्वास आपस में टकराते हैं; सभ्यताओं का तथाकथित टकराव एक अत्यधिक अन्योन्याश्रित दुनिया में अधिक संभावित है। जैसे-जैसे उनकी अन्योन्याश्रितता बढ़ती है, देश दूसरे देशों की कार्रवाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का राजनीतिक लाभ उठाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिलचस्प उदाहरण 2000 के दशक की शुरुआत में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का मामला है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों के विकास के परिणामस्वरूप चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी और व्यापार का बहुत बड़ा और असंतुलित प्रवाह हुआ है; ये आर्थिक संबंध दोनों पक्षों के लिए संभावित राजनीतिक लीवर के रूप में काम कर सकते हैं। संबंध बहुत अधिक जटिल हो गए हैं और राजनीतिक तनाव से भरे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये संबंध सैन्य रूप से संलग्न होने की किसी भी प्रवृत्ति को कम कर देंगे; अन्य उन्हें भविष्य के संघर्ष के लिए संभावित चिंगारी के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण इसे महंगा बनाकर संघर्ष की प्रवृत्ति को कम कर सकता है क्योंकि अगर देश लड़ते हैं तो उन्हें अपने आर्थिक संबंध तोड़ने होंगे; अथवा इससे संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उनमें अधिकाधिक संबंध होते हैं, जिनसे विवाद उत्पन्न हो सकता है।

राज्य की शासन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

वैश्वीकरण के राज्य क्षमता पर प्रभाव के बारे में प्रश्न उठे हैं। यानी, क्या वैश्वीकरण देशों को कमजोर करता है और उनकी शासन करने की क्षमता को नष्ट करता है? राज्यों को अक्सर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रबंधित करने, संकटों का जवाब देने और स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय रक्षा और शिक्षा जैसे सार्वजनिक सामान प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर आंका जाता है। जैसे-जैसे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ते जाते हैं,

राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रबंधित करने की क्षमता खो सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के सापेक्ष राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जितनी छोटी होगी, इस परिणाम की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

देश अन्य देशों की नीतियों के बाहरी प्रभावों का अनुभव करेंगे, लेकिन अक्सर इन नकारात्मक परिणामों को प्रबंधित करने में असमर्थ होंगे। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खोना, खासकर अगर कोई देश अपना पूंजी खाता खोलता है और अपनी मुद्रा को तैरने देता है, इसका एक जाना-माना उदाहरण है। वैश्वीकृत दुनिया में राज्यों के बीच कर प्रतिस्पर्धा एक और चिंता का विषय है, क्योंकि कर सरकारों को सार्वजनिक सामान प्रदान करने के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर वैश्वीकरण से जुड़ी दौड़-से-नीचे की घटना किसी देश के अपनी अर्थव्यवस्था और शायद अपनी राजनीति पर नियंत्रण खोने का संकेत दे सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोकतंत्रों के लिए नियंत्रण का यह नुकसान विशेष रूप से चिंताजनक हो सकता है क्योंकि यह सरकार और समग्र रूप से लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।

दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ वैश्वीकरण से जुड़ी समस्याओं को कम करने में राज्यों की मदद कर सकती हैं। राज्य का व्यवहार दूसरों के लिए नकारात्मक बाह्यताएँ पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्था में भी जो बहुत वैश्वीकृत नहीं है। लेकिन वैश्वीकरण के बिना राज्यों के लिए इन बाह्यताओं को संबोधित करने के लिए सहयोग करना बहुत कठिन हो सकता है। वैश्वीकरण राज्यों को संगठित सहयोग की आवश्यकता के प्रति जागरूक कर सकता है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण को प्रेरित कर सकता है जो राज्यों को इन बाह्यताओं से निपटने में मदद करती हैं और इस प्रकार उन्हें अन्यथा की तुलना में अधिक राजनीतिक क्षमता प्रदान करती हैं। इस प्रकाश में कोई भी EU के बारे में सोच सकता है। EU के भीतर राज्यों के पास अब एक समूह के रूप में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की अधिक क्षमता हो सकती है, जो EU में शामिल होने से पहले उनके

पास नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से वे वैश्वीकरण के दबावों का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक संस्थागत सहकारी व्यवस्था के साथ वे ऐसा करने में बहुत बेहतर हो सकते हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद आइसलैंड जैसे देशों की EU में शामिल होने में हाल ही में रुचि इस तरह के परिणाम का सुझाव देती है। वैश्वीकरण निस्संदेह उन समस्याओं को बनाता है या बढ़ाता है जो राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन इसमें ऐसे दबाव भी हो सकते हैं जो देशों को उन समस्याओं का बेहतर तरीके से जवाब देने की अनुमति देते हैं।

राज्यों के बीच अभिसरण

वैश्वीकरण राज्यों के बीच नीति और संस्थागत अभिसरण से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जैसे-जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलते हैं, वे समान नीतियों और संस्थानों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। यह अभिसरण प्रक्रिया विभिन्न दबावों द्वारा संचालित हो सकती है। कुछ लोग इसे दुनिया के आधिपत्य की शक्ति के लिए जिम्मेदार मानते हैं; कुछ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दबावों के लिए राज्यों की बढ़ती भेद्यता के लिए; कुछ, राज्यों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के लिए; अन्य, देशों द्वारा की जाने वाली सीखने की प्रि या के लिए। कारण जो भी हो, यह अभिसरण आर्थिक नीति और संस्थानों में हुआ प्रतीत होता है।

नवउदारवादी नीतियों या तथाकथित वाशिंगटन सर्वसम्मति को व्यापक रूप से अपनाना 1980 के दशक के उत्तरार्ध से उल्लेखनीय रहा है। अन्य उदाहरण कई देशों द्वारा स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाने और अपनी मुद्राओं को तैरने देने के निर्णय हैं। इस प्रक्रिया को अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मुद्दों से निपटने के लिए नौकरशाही के निर्माण से लेकर लोकतंत्र की ओर रुख करने तक। वैश्वीकरण राज्यों के पास मौजूद विकल्पों को सीमित कर सकता है और उन पर समान संस्थागत रूपों और प्रथाओं को अपनाने का दबाव डाल सकता

है। जिस हद तक ये रूप और प्रथाएँ बेहतर परिणाम देती हैं, इस प्रक्रिया का स्वागत किया जा सकता है। हालाँकि, अगर वे राज्यों के लिए उत्पादक नहीं हैं, तो यह अभिसरण प्रक्रिया हर जगह सरकारों के लिए नकारात्मक हो सकती है।

जब यह अभिसरण दबाव सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन तक फैलता है, तो इसे अक्सर नकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों, जातीय समूहों, भाषाओं और राष्ट्रों से जुड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को खोना वैश्वीकरण का अक्सर उल्लेख किया जाने वाला प्रभाव है। कई भाषाओं का लुप्त होना और अंग्रेजी का बढ़ता उपयोग दो ऐसे उदाहरण हैं। कुछ लोगों के लिए, यह एक लाभ है क्योंकि यदि सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो लेन-देन की लागत बहुत कम हो जाती है, और एक आम वैश्विक भाषा का सपना एक लंबा इतिहास है। देशों या लोगों पर कुछ प्रथाओं और अनुष्ठानों को कम करने का दबाव जो "आधुनिक" या "सभ्य" नहीं माने जाते हैं, भी बढ़ रहा है। इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या देशों को अपनी सीमाओं के भीतर सभी प्रकार की प्रथाओं को माफ करने का अधिकार है या क्या कुछ न्यूनतम मानक मौजूद हैं जिनका सभी देशों को पालन करना चाहिए। और गुलामी जैसी कुछ प्रथाओं के अंत की व्यापक रूप से सराहना की गई है। वैश्वीकृत दुनिया में संचार और लेन-देन की लागत दोनों में कमी ने स्पष्ट रूप से इस तरह के अभिसरण को तेज करने में मदद की है। वैश्विक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए बाहरी दबाव आज पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकते हैं लेकिन ऐसे दबाव हमेशा से मौजूद रहे हैं। आज बल प्रयोग या विजय के माध्यम से इन्हें थोपे जाने की संभावना कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये दबाव कम शक्तिशाली हैं।

विद्वानों को यह भी चिंता है कि वैश्विक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो आपस में तेजी से जुड़ती जा रही है, जहाँ एक देश या क्षेत्र में समस्याएँ कम परस्पर जुड़े वातावरण की तुलना में अधिक तेज़ी से, बलपूर्वक और व्यापक रूप से फैल सकती हैं। उदाहरण के लिए, परिवहन की बढ़ती आसानी बीमारी के प्रसार को बहुत तेज़ और शायद अधिक घातक बनाती है। संचार

क्रांति नए विचारों और सनक के लिए भी ऐसा ही करती है। ऐसी प्रणालियों में सूचना का प्रवाह अधिक होने की संभावना है।

इसका मतलब यह है कि अस्थिरता भी अधिक हो सकती है। सिस्टम में छोटे-छोटे बदलाव सभी दिशाओं में फैलते हैं और बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इस तरह के वैश्वीकृत विश्व में संकट अधिक संभावित और अधिक संक्रामक होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध का एशियाई वित्तीय संकट और 2008 से 2009 का हालिया वैश्विक वित्तीय संकट ऐसे दो उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने 1970 के दशक से "महान नरमी" का अनुभव किया है, जिसमें आंशिक रूप से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जोखिम के कारण व्यापार चक्रों में कमी और मुद्रास्फीति में कमी आई है। अन्य लोग समय के साथ बढ़ती अस्थिरता से घिरी एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि संकट कई गुना बढ़ जाते हैं और फैल जाते हैं। वैश्वीकरण समस्याओं को फैलाकर और प्रतिसंतुलनकारी शक्तियों को लाकर एक प्रणाली को स्थिर कर सकता है, लेकिन यह सभी देशों और सभी क्षेत्रों के बीच संबंधों का एक नेटवर्क बनाकर एक प्रणाली को अस्थिर भी कर सकता है जो समस्याओं को प्रसारित और बढ़ाता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्वीकरण से कौन से देश लाभान्वित होते हैं और कौन से खोते हैं, इस सवाल के अलावा, यह मुद्दा भी है कि कौन से समूह घरेलू स्तर पर लाभान्वित होते हैं और कौन से समूह खोते हैं। कई लोग वैश्वीकरण को पूंजी मालिकों और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के हाथ को मजबूत करने के रूप में देखते हैं, न कि श्रम मालिकों और वामपंथी दलों के। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जहां पूंजी अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है, यह घरेलू स्तर पर लाभप्रद हो जाती है। वैश्वीकरण व्यवसाय और श्रम के बीच शक्ति के घरेलू संतुलन को बदलता है। जब पूंजी के मालिकों को सरकार की नीति पसंद नहीं आती है या उन्हें डर होता है कि श्रम

बहुत मजबूत हो गया है, तो वे अक्सर एक नए राजनीतिक वातावरण में चले जाते हैं जो अधिक अनुकूल होता है। यह प्रक्रिया तब दौड़-से-नीचे दबाव पैदा कर सकती है क्योंकि सरकारें अपने देश में पूंजी को बनाए रखने की कोशिश करती हैं और अधिक व्यापार-अनुकूल नीतियों को अपनाती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वैश्वीकरण ने श्रमिक संघों और श्रम बाजार संगठन के अन्य रूपों को कमजोर करने में मदद की है। यह प्रक्रिया तब राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

यदि दक्षिणपंथी पार्टियाँ व्यावसायिक हितों का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वे वैश्वीकरण द्वारा मजबूत हो सकती हैं। वामपंथी पार्टियाँ और उनके कार्यक्रम अधिकाधिक अनाकर्षक लग सकते हैं क्योंकि वे पूंजी को "डर" देते हैं और शायद विकास को धीमा कर देते हैं। इस प्रभाव के साक्ष्य मिश्रित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वामपंथी पार्टियाँ और सरकारें वास्तव में पूंजी को आकर्षित करने का बेहतर काम करती हैं और इस प्रकार वैश्वीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है; वे दक्षिणपंथी पार्टियों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर भागीदार भी बन सकते हैं। कुछ विद्वान घरेलू राजनीति पर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव नहीं देखते हैं; वे दावा करते हैं कि घरेलू राजनीतिक संस्थाएँ ऐसे बाहरी दबावों को छानती और आकार देती हैं ताकि उनका अंतिम प्रभाव घरेलू राजनीति का एक कार्य हो। पहले से मौजूद घरेलू संस्थाएँ और प्रथाएँ तब यह निर्धारित करती हैं कि वैश्वीकरण आंतरिक राजनीति को प्रभावित करता है या नहीं और कैसे करता है। देशों के भीतर और उनके बीच राजनीतिक शक्ति पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहस का विषय है और भविष्य के शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

1.14 अनुसंधान क्रियाविधि

स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर होगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हुई, जिन्होंने समाज के समाजवादी पैटर्न के माध्यम से

आत्मनिर्भर विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा, जहाँ राज्य न्याय प्रदाता के रूप में उभरा। यह दर्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ संरेखित होगा। नेहरू ने उत्पादन के साधनों में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के उद्यम की अनुमति देते हुए समाजवादी व्यवस्था के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की। यह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास मॉडल की नींव रखेगा।

हालांकि, वैश्वीकरण और राज्य की अवधारणा बनाना समस्याग्रस्त होगा क्योंकि दोनों शब्दों और उनके विभिन्न पहलुओं पर बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध है। यह जांचना आवश्यक होगा कि वैश्वीकरण और राज्य विरोधाभासी हैं या आपस में जुड़े हुए हैं, और यह स्वीकार करना कि अवधारणाएँ खोखली हैं। इस शोध का उद्देश्य वैश्वीकरण और राज्य की अवधारणा बनाना है ताकि उनकी गतिशीलता को समझा जा सके, क्योंकि वे बौद्धिक चिंता के स्थायी विषय बने हुए हैं और महत्वपूर्ण अकादमिक ध्यान आकर्षित करते हैं।

राज्य संप्रभुता रखेगा, जो लैटिन शब्द सुपरनस से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति है। "संप्रभुता" शब्द की शब्दकोश परिभाषा "स्वायत्तता" और "संप्रभुता" की अवधारणाओं को जोड़ती है, जो वैचारिक रूप से अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार में, ये अंतर अक्सर धुंधले हो जाते हैं। इससे जो मुद्दे उठेंगे उनमें शामिल है कि क्या संप्रभुता स्वतंत्रता का पर्याय है और क्या यह स्वायत्तता का पर्याय है।

शिक्षाविदों की पहली श्रेणी इस शब्द के उपयोग के बारे में सैद्धांतिक विवरण प्रदान करेगी, जबकि दूसरी श्रेणी का उद्देश्य एक ऐसी अवधारणा प्रदान करना है जो व्याख्यात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सके। यह आंशिक रूप से इस शब्द के वैचारिक प्रसार में योगदान दे सकता है और इसे एक विवादित अवधारणा बना सकता है। हमें इसकी जड़ों को निर्धारित करने के लिए इस शब्द के लौकिक युग को सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में वापस खोजना होगा।

1.15 केंद्रीय प्रश्न

इस प्रकार, अध्ययन का केंद्रीय प्रश्न इस विचार के इर्द-गिर्द घूमता है कि 'वैश्वीकरण ने संघीय और प्रांतीय स्वास्थ्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन को किस प्रकार और किस हद तक प्रभावित किया है और भारत में चुनौतियों का सामना करने में मदद की है?'

1.16 शोध प्रश्न

इस शोध में जिन प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है, उनमें शामिल हैं:

1. 1990 के दशक से दुनिया भर में बह रही उदारीकरण की बयार की दिशाएँ और अभिव्यक्तियाँ क्या हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया के भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों पर क्या परिणाम होंगे?
2. वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य पर कौन-सी नई बाधाएँ और माँगें थोपी हैं?
3. क्या वैश्वीकरण या उदारीकरण की प्रक्रिया एक विकासशील राज्य की अपनी पूर्व भूमिका में कमी की माँग करती है?
4. क्या बदली हुई परिस्थितियाँ भारतीय राज्य पर नए दायित्व थोपती हैं?
5. क्या उदारीकरण की माँगों के जवाब में राज्य अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका और आर्थिक एवं कल्याणकारी कार्यों से समझौता करेगा, जिन्हें आज़ादी के बाद के पहले कुछ दशकों में अपनाया गया था?
6. क्या बदली हुई परिस्थितियाँ पहले से स्थापित मॉडलों के अनुसार राज्य में सुधार या पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता को इंगित करती हैं, या क्या यह एक नई परिस्थिति के अनुकूल राज्य के एक नए मॉडल की माँग करती है?

1.17 अध्ययन की परिकल्पनाएँ

यह निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है:

1. वैश्वीकरण ने तीसरी दुनिया की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में एक निर्णायक बदलाव लाया है।

2. इस बदलाव ने भारतीय राज्य के सामने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तरों पर विभिन्न चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

3. परिणामस्वरूप, राज्य की भूमिका की पुनर्परिभाषा आवश्यक हो गई है।

4. पुनर्परिभाषित राज्य न तो उदारवादी राज्य का दोहराया हुआ संस्करण है, न ही कल्याणकारी राज्य के मॉडल की प्रतिकृति है और समाजवादी राज्य की प्रतिध्वनि तो बिल्कुल नहीं है; बल्कि यह एक सूक्ष्म राज्य है जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एजेंट के रूप में एक नई भूमिका को मूर्त रूप देता है।

1.18 अध्ययन का उद्देश्य

1. अध्ययन में भारतीय समाज, सतत विकास और अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच की गई है, जिसमें व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक ढांचे और प्रासंगिक द्वितीयक स्रोतों और सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना

3. वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में वैश्वीकरण की कमियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों की सिफारिश करना।

साहित्य की समीक्षा

अध्याय 2

साहित्य की समीक्षा

भट्टाचार्य, सीई डॉ. सुमंता और अन्य। (2022) भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इसका परिवर्तन और भविष्य के पहलू। वैश्वीकरण दुनिया में प्राचीन काल से ही मौजूद है। हालाँकि, समय बीतने के साथ इसका स्वरूप बदल जाता है। आज, वैश्वीकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है क्योंकि यह किसी राष्ट्र की सीमा के पार सूचना के आसान और तेज़ प्रवाह के कारण हमारे दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीति में उनका बढ़ता महत्व नव उदार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है जो साम्यवादी यूएसएसआर के विघटन के बाद और पूंजीवादी यूएसए के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने के बाद और तेज़ हो गया। यह पत्र विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आँकड़ों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के आधुनिक स्वरूप के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसके बाद, राज्यों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीति और आधुनिक सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया गया है ताकि वर्तमान परिदृश्य के तहत विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के आधार पर दोषों को खत्म करने के लिए कुछ कदम सुझाए जा सकें।

रसम, वसंती. (2013).इस शोध पत्र के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत की राजनीतिक संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कृषि की संस्कृति पर भी यही स्थिति साबित करने के लिए सांख्यिकीय डेटा उपलब्ध है, जिसे सार्वजनिक उद्योग के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जो आज की स्थिति में राजनीतिक प्रणाली और सरकार के हस्तक्षेप पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जबकि आज जीएलपी के

राजनीतिक आयामों के संदर्भ में भारत की संप्रभुता, एक राज्य के रूप में अपनी कम होती निर्णय लेने की शक्ति के साथ दांव पर है। लेकिन पहुंच, समता और समानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इस निजीकरण के लाभार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है, जबकि एक बड़ा प्रतिशत नुकसान में है। खतरों को अवसरों में बदलने के लिए, या तो राजनीतिक प्रणाली का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है जो कल्याणकारी दृष्टिकोण और भारतीय राजनीतिक संस्कृति को समायोजित करती है। जबकि हम वैश्वीकरण से पहले मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, इसके अलावा पहुंच और अवसरों के समान प्रावधान और हितधारकों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हैं। अपेक्षित 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' का अभाव है, जिसके कारण वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ भारत में राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए मजबूत नागरिक समाज आंदोलन और विद्रोह तेजी से बढ़ रहे हैं।

साहू, सरबेश्वर. (2013).यह शोधपत्र वैश्वीकरण साहित्य में दो बुनियादी सवालों को संबोधित करता है: (1) क्या वैश्वीकरण एक खतरा है या एक अवसर? और (2) बाजार की गहराई वास्तव में दुनिया में वास्तविक ठोस लोकतंत्र को किस हद तक प्रोत्साहित करती है? कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप असमानता और गरीबों का हाशिए पर जाना बढ़ गया है, जो लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। हालाँकि, भारत के मामले को ध्यान में रखते हुए, यह शोधपत्र तर्क देता है कि कल्याणकारी राज्य के पीछे हटने और विकासवाद के पतन ने वैश्वीकरण के अभिजात्य और शोषणकारी एजेंडे के खिलाफ जनता को लामबंद किया। परिणामस्वरूप, एक प्रति-आधिपत्यवादी जीवंत नागरिक समाज उभरा है, जो अभिजात वर्ग के आधिपत्य को चुनौती देता है और अधीनस्थ समूहों के सशक्तिकरण एजेंडे को आगे बढ़ाता है। अधीनस्थों की यह नई राजनीति सामाजिक न्याय और नागरिकता अधिकारों के विचार पर आधारित है, जो भारतीय राज्य और लोकतंत्र की प्रकृति को फिर से परिभाषित कर रही है।

कुमार, सुरिंदर एट अल. (2012).वैश्वीकरण एक नया शब्द है जो पिछली सदी के नब्बे के दशक से शीत युद्ध की समाप्ति और पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक प्रवृत्ति के साथ दुनिया पर हावी हो गया है। अपने पुराने समय में जिस तरह से वर्तमान में विकसित अर्थव्यवस्थाएँ विस्तारित हुईं और वैश्विक हो गईं, उसके विपरीत भारत में (कई अन्य विकासशील देशों की तरह) मुख्य सुधार पहल राजकोषीय और विदेशी मुद्रा संकट के बाद की गई थीं, जिसने इसे विदेशी ऋणों पर चूक के कगार पर ला दिया था। इस प्रकार, भारतीय वैश्वीकरण भीतर के पतन और बाहर से दबाव का परिणाम है। वैश्वीकरण के बाद के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव विदेशी क्षेत्र-विदेशी मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी पूंजी का प्रवाह आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह पत्र वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रिया की रूपरेखा का पता लगाता है। इस पूरे पत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर अंतर्निहित ध्यान केंद्रित किया गया है।

गोविंदराज, योगानंदम। (2023)।वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल, सेवाएँ, धन और प्रौद्योगिकी को ले जाना संभव है, जो उद्यमों और समाजों का वैश्वीकरण है। सिल्क रोड इसकी सबसे प्रारंभिक अभिव्यक्तियों में से एक है, और यह प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क के दिनों से ही अस्तित्व में है। वैश्विक व्यापार और औद्योगिक क्रांति 15वीं शताब्दी में खोज के युग की शुरुआत में शुरू हुई थी। वैश्वीकरण व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ धन, विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित द्वितीयक स्रोतों और सूचनाओं का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जांच करता है। प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार में प्रगति ने वैश्वीकरण को गति दी है, अर्थव्यवस्थाओं, पार-सांस्कृतिक जुड़ाव और परंपराओं को बदला है, समाज के जीवन को प्रभावित किया है और अस्थिरता या व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ावा दिया है। वैश्विक बाजार, विदेशी निवेश और पार-सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विशेष रूप से पर्यटन उद्योग में, भारतीय अर्थव्यवस्था को

मजबूत किया है। सरकारों को सामाजिक न्याय को सबसे पहले रखना चाहिए क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देती हैं। आर्थिक विस्तार द्वारा प्रदान की गई व्यापार संभावनाएँ, नए बाज़ार, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता उद्यमों और सरकारों को वैश्वीकरण के अनुकूल होने और उससे लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं। वैश्वीकरण आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, जिससे नौकरी छूटती है, उद्योग में गिरावट आती है, आय में असमानता होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। सरकारों और व्यवसायों को विविधता लानी चाहिए, एसएमई में निवेश करना चाहिए और सतत विकास के लिए शिक्षा को निधि देनी चाहिए। वैश्वीकरण भारतीय कृषि, संस्कृति, पहचान और शिक्षा को प्रभावित करता है। उपर्युक्त के बावजूद, इस शोध लेख का मुख्य उद्देश्य लेख के विषय से संबंधित सूचना और सांख्यिकीय डेटा के द्वितीयक स्रोतों की सहायता से एक व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक विश्लेषण में विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की जांच करना है। इस तरह का दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति को एक साथ महत्वपूर्ण और आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक मानता है।

अब्दुनैइमोवा, दिनारा. (2020).इस लेख में वैश्वीकरण की घटना की समीक्षा की गई है, इसके सार, विषय-वस्तु और कारणों का विभिन्न पहलुओं में विश्लेषण किया गया है। सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है, विश्व संस्कृति की विविधता के वितरण और संस्कृति के वैश्वीकरण के कारणों और परिणामों पर समाजशास्त्रियों की राय का विश्लेषण किया गया है। वैश्विक भाषाओं का विषय और विभिन्न राष्ट्रों और लोगों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने की समस्या का भी खुलासा किया गया है।

मन्हास, नीरज सिंह. (2020).भारत का चौथा स्थान पूंजीकरण है। वैश्वीकरण के बाद से कृषि में सुधार नहीं हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17% है। भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी, आत्महत्या करने वाले किसान। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणामों के बावजूद, उभरते भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने और जल्दी विकास की ओर बढ़ने के लिए

प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा से एक त्वरित संदेश यह है कि एक राष्ट्र को जानबूझकर एक नीति संतुलन चुनना चाहिए जो उसे दुर्घटनाओं से बचने के साथ-साथ अवसर को जब्त करने में मदद करे। अमेरिका एक सदी से दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है, लेकिन वैश्विक बाजार में बड़े पैमाने पर बदलाव ने अमेरिका और यूरोप के अमीर देशों से दो एशियाई दिग्गजों-भारत और चीन में बदलाव किया है। आर्थिक विशेषज्ञों और वैश्विक सर्वेक्षणों के अनुसार, 21वीं सदी में भारत और चीन का दबदबा है। भारत, जो वर्तमान में क्रय शक्ति का चौथा सबसे बड़ा माप है, जापान से आगे निकल गया है, जिससे यह 10 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वे यह भी दावा कर सकते हैं कि हमारे आस-पास के रोजमर्रा के जीवन का परिवर्तन वैश्वीकरण का जवाब देता है। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हैं। 1991 के बाद से वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को बढ़ावा देते हुए हमें काफी आगे बढ़ाया है।

हिली, डाल्टन. (2012).वैश्वीकरण की भूमिका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं तथा उनके व्यापक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर इसका प्रभाव। खंड 1 - 2008-2009 की वैश्विक मंदी के बाद से वैश्वीकरण का प्रभाव पश्चिमी देशों और महाद्वीपों में अपनी दीर्घकालिक स्थिति से हटकर मध्य-पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है, क्योंकि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर चीन और भारत ने वैश्विक संकट से कम गंभीर परिणाम देखे हैं। यह 'पूर्वीकरण' प्रभाव है और 1960 के दशक से ही स्पष्ट है। हालांकि ऐसे देश अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थितियों पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह से बच नहीं पाए हैं, इसलिए यह बदलाव अपने आप में पूर्ण नहीं है। खंड 2 - इन देशों और संस्थाओं के बीच विवादों को सुलझाने में लगातार असमर्थता के कारण दोहा दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद, पिछले 12 वर्षों के दौरान चीन और भारत ने कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। आलोचकों का तर्क है कि एफटीए की ये भारी संख्या (वर्तमान में लगभग 50 और 80 रास्ते में हैं) बहुपक्षीय उदारीकरण प्रक्रिया को अस्थिर कर देगी (डब्ल्यूटीओ, 2011)। इसलिए

निम्नलिखित खंड जांच करता है कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और ओईसीडी द्वारा इन एशियाई देशों द्वारा बनाए गए मुक्त व्यापार समझौतों के 'नूडल बाउल' कहे जाने वाले समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। खंड 3 - आज के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों में से तीन हैं; वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट। यह मूल रूप से संसाधनों की बढ़ती कमी, भोजन और पानी के असमान वितरण, दुनिया भर में अनसुलझे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विवादों के कारण युद्ध और अपराध हो रहे हैं, और अनियंत्रित पर्यावरण प्रदूषण धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुनिया की जलवायु को बदल रहे हैं। यह तर्क दिया जा सकता है

आब्दी, उमर एट अल. (2024).वैश्वीकरण का तात्पर्य दुनिया भर के देशों, अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों के बीच बढ़ती परस्पर संबद्धता और अन्योन्याश्रयता की प्रक्रिया से है। वैश्वीकरण की प्रेरक शक्ति प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार में प्रगति है, जिसने लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों को सीमाओं के पार ले जाना आसान बना दिया है। इस परस्पर संबद्धता ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समान रूप से प्रभावित किया है और दुनिया भर में नए दृष्टिकोण और दृष्टिकोण लाए हैं। यह निबंध वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आए बदलाव पर बहस करेगा।

अग्रवाल, अंकुर एवं अन्य (2021).भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक मीडिया शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। भारत में, संचार के सभी रूप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भारत के मीडिया नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नेटवर्क में से एक माना जाता है। इस लेख में, हम वैश्वीकरण और मीडिया प्रबंधन और मीडिया प्रबंधन पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेख के लिए सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं से 40 से अधिक शोध प्रकाशनों को यादृच्छिक रूप से जांचा गया। लेखों को उनके प्रकाशन के वर्ष, विशिष्ट देशों, जिस पत्रिका में वे प्रकाशित हुए थे, उद्योग के प्रकार और शोध तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नतीजतन, इस संदर्भ में प्रकाशनों की अधिक बारीकी से जांच की जाती है।

तुरान, सुएयिप एट अल. (2022).अध्ययन राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रभावों की अभिव्यक्ति की जांच करता है, आधुनिक वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत के साथ, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर, क्योंकि यह प्रमुख सत्यापन योग्य तैयारी का तात्पर्य है, इसके प्रामाणिक पठन के माध्यम से, उन्नत दुनिया के सामाजिक आदेश, विचार ने यह जानने के लिए एक खंड बिंदु के रूप में देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के विषय ने बहुत अधिक चर्चा, विवाद लिया है, और यह मानव सामाजिक व्यवस्था, मध्य पूर्व और सभी मध्य पूर्वी देशों और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव की डिग्री पर इसका प्रभाव हो सकता है, विशेष रूप से राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। हाल के दिनों में, दुनिया ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच विकास, अन्योन्याश्रय, एकीकरण, ओवरलैप और आदान-प्रदान देखा है और जिसे विश्व वैश्वीकरण कहा जाता है, उसके राजनीतिक क्षेत्रों में। वैश्वीकरण की घटना को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं में से एक माना जाता है जो मानव समाजों के विकास के साथ-साथ दुनिया के स्तर पर लगातार बदल रही है, और वैश्वीकरण मुख्य रूप से समकालीन दुनिया में देखी गई वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है, और वैश्वीकरण के आयाम वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम से आगे बढ़कर शीर्ष पर आते हैं, क्योंकि संस्कृति नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को राज्य के भीतर राजनीतिक प्राधिकरण की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है-चाहे वह व्यवहार नकारात्मक हो या सकारात्मक-और वैश्वीकरण ने अरब देशों को विभिन्न पहलुओं और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में प्रभावित किया है। अरब सांस्कृतिक निर्माण पर वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव यह है कि मध्य पूर्व क्षेत्र राजनीति और संस्कृति से प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से अरब समाज वैश्वीकरण के विचार की सामग्री को गहरा करने में एक प्रभावी प्रभाव है, जिसका उद्देश्य दुनिया को वैश्वीकृत करना है और यह दुनिया के लोगों के बीच एकजुट होने और दूरियों को कम करके दुनिया को एक छोटा सा गाँव बनाने के लिए आया था। यह अध्ययन 31 मध्य पूर्व की संस्कृति और राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को

स्पष्ट करने के लिए संदर्भित करता है, विशेष रूप से अरब और इस्लामी देशों में। इस्लामी समुदाय को जिन समस्याओं, चुनौतियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वैश्विक अभिनेताओं ने इन देशों के हितों पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। सांस्कृतिक और राजनीतिक के साथ-साथ शिक्षा की चुनौतियाँ, वर्तमान पीढ़ी, बौद्धिक और सांस्कृतिक आक्रमण और वैश्वीकरण के प्रभाव को जन्म देने वाले परिवार का विघटन इस्लामी पहचान को लगभग नष्ट कर रहा है। राजनीति और संस्कृति में ये सभी परिवर्तन अमेरिकी और यूरोपीय संस्कृतियों, सभ्यताओं और रीति-रिवाजों के अरब दुनिया में प्रवेश की ओर इशारा करते हैं, वैश्वीकरण का लक्ष्य राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण के सरल लक्ष्य के साथ दुनिया को प्रभावित करने वाली घटनाओं और विकास के इर्द-गिर्द घूमता है,जिससे मानव समाज सामाजिक माध्यमों से विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियों और राजनीतिक समाचारों को प्राप्त करता है तथा उसे प्रभावित करता है।

माहेश्वरी, हर्ष आदि। (2023)।वैश्वीकरण और सामाजिक संरचना पर इसका प्रभाव। यह शोध पत्र वैश्वीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों पर केंद्रित है, यह पत्र वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों के बारे में चर्चा करता है। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि यह कैसे सामाजिक समस्या को जन्म देता है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव जैसे वैश्वीकरण और समाज पर इसका प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह कैसे आय असमानताएँ पैदा करता है। यह इस बारे में बात करता है कि यह लोगों की संस्कृति, जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आशावादी बढ़ते वाणिज्य और आर्थिक विस्तार के बीच संबंध पर जोर देते हैं, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यापार फायदेमंद है। विकास गरीबों के लिए अच्छा है (नौकरी सृजन और गरीबी उन्मूलन दोनों के संदर्भ में)। इसके विपरीत, निराशावादी तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण अपने प्रभाव में अत्यधिक असमान है और पहले से संरक्षित उद्योगों पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पूरे हिस्से को हाशिए पर डालता है और देश के भीतर आय असमानता (WCII)

में वृद्धि करता है। इस तरह की राय की विविधता का एक और उदाहरण गरीबी संकेतकों के बारे में चर्चा है: वैश्वीकरण के समर्थक इस वास्तविकता पर जोर देते हैं कि पिछले दो दशकों के दौरान दुनिया भर में निरपेक्ष गरीबी में कमी आई है, फिर भी वैश्वीकरण के आलोचक बताते हैं कि यह परिणाम लगभग पूरी तरह से सांख्यिकीय कलाकृतियों के कारण है, चीन के तेजी से बढ़ने के कारण, जबकि कई डीसी में निरपेक्ष गरीबी बढ़ी है, और अधिकांश देशों में सापेक्ष गरीबी बढ़ी है। यह पत्र वैश्वीकरण विषय के तहत जाति व्यवस्था के प्रभाव और समाज पर इसके प्रभाव पर भी संक्षेप में चर्चा करता है।

खान, एस. (2015).वैश्वीकरण ने दुनिया भर के विकासकर्ताओं के लिए नए और जबरदस्त अवसर खोले हैं। वैश्वीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए, भारत ने आर्थिक नीति में बदलाव किए और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया। इसने दुनिया के देशों के साथ भारत के आर्थिक, व्यापार और निवेश संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डाला है। पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक उपलब्धियों ने भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। यह पत्र शीत युद्ध के बाद के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह सबसे पहले वैश्वीकरण की अवधारणा और इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करता है। यह भारत में वैश्वीकरण के आगमन के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की भी जांच करता है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर भी प्रकाश डालता है।

भट्टाचार्य, एच. एवं अन्य (2015).यह पुस्तक भारतीय राजनीति, इसकी संरचनाओं और प्रक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करती है, और भारत की जटिल और आकर्षक कहानी को उजागर करने के लिए वैश्वीकरण के लिए चुनौतियों की पहचान करती है। 1991 में, भारत ने GATT समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर

पर नव-उदारवादी सुधारों की नीति को अपनाया, जिसने देश, इसके समाज, संस्कृति और संस्थानों को वैश्वीकरण की विभिन्न ताकतों के सामने उजागर किया। वैश्वीकरण भारत के लिए नया नहीं हो सकता है, क्योंकि देश सहस्राब्दियों से बाहरी संस्कृतियों और सभ्यताओं के प्रभाव को अपनाता रहा है, लेकिन 1991 के बाद की सुधार नीति ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण राज्य और एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से मुख्य रूप से बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में बदल गया। विभिन्न अनुशासनात्मक दृष्टिकोणों के माध्यम से, लेखक विश्लेषण करते हैं कि कैसे भारत के धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, सामाजिक न्याय और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के संस्करण पर नई व्यवस्था की ताकतों द्वारा हमला किया गया। पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारत में वैश्वीकरण ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, संघवाद, विकेंद्रीकरण, संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका और संसदीय वामपंथ के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। भारत के वैश्वीकरण के संदर्भ में स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक विषयों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करते हुए, यह पुस्तक दक्षिण एशियाई राजनीति, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए रुचिकर होगी। © 2016 चयन और संपादकीय सामग्री, हरिहर भट्टाचार्य और लायन कोनिग; अलग-अलग अध्याय, योगदानकर्ता। सभी अधिकार सुरक्षित।

साहू, विकास एवं अन्य (2024).वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्थाएँ और समाज इस हद तक एक-दूसरे पर निर्भर, जुड़े और एकीकृत हो जाते हैं कि दुनिया के एक क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के लोगों पर भी असर पड़ता है। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष रूप से क्रॉस कंट्री संस्कृति में स्पष्ट है। राष्ट्र के कई पहलुओं में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला प्राथमिक घटक उसका आर्थिक एकीकरण है।

देश ने कॉर्पोरेट, खुदरा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि देखी है। वैश्वीकरण ने दूरियों को लगभग समाप्त कर दिया है और वस्तुतः दुनिया को एक साथ ला दिया है। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण ने एक विश्वव्यापी तरीका प्रदान किया है जहाँ व्यक्ति, कंपनियाँ और सरकारें जुड़ सकती हैं और एक साथ आ सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन में प्रगति के परिणामस्वरूप हाल ही में वैश्वीकरण में तेजी आई है। बेहतर विश्वव्यापी तालमेल से वैश्विक व्यापार, विचारधाराओं और संस्कृति का विस्तार होता है। इसके परिणामस्वरूप कई लाभ हुए हैं जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, कुछ क्षेत्रों में गंभीर गरीबी में कमी, आर्थिक विकास में वृद्धि और प्रौद्योगिकी और शिक्षा तक आसान पहुँच। वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, जिससे निर्यात, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच संपत्ति में अंतर भी आया है।

पटजोशी, प्रमोद. (2019).वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन। वैश्वीकरण एक नया तत्व है जो पिछली सदी के नब्बे के दशक से दुनिया को निर्देशित करने के लिए आया है। बाजार अर्थव्यवस्था पर बढ़ते आत्मविश्वास और निजी पूंजी और संसाधनों में विश्वास के साथ राष्ट्रीय सीमाओं, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययनों और प्रभावों द्वारा प्रोत्साहित संरचनात्मक समायोजन की एक प्रक्रिया कई विकासशील देशों में शुरू हुई है। वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के लिए नए अवसर लाए हैं। विकसित देश के बाजारों और प्रौद्योगिकी आवंटन में उच्च संगणना और पहुंच संभावित बेहतर उत्पादकता और उच्च जीवन स्तर प्रदान करती है। नब्बे के दशक तक व्यापार और निवेश उदारीकरण की बाधाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से संगठित थी। नब्बे के दशक में शुरू हुए वैश्वीकरण, निवेश और वित्तीय प्रवाह के विकास ने प्रतिस्पर्धा की बाधाओं को कम किया है और वैश्वीकरण की गति को तेज किया है। इसलिए यह शोधपत्र वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन करता है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के कई कारकों को अध्ययन के लिए मापा जाता है।

रघुनाथ, (2017).वैश्वीकरण का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। इसे राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व अर्थव्यवस्था में देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, आर्थिक खुलेपन और बढ़ती आर्थिक निर्भरता को गहरा करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह न केवल सीमा पार आर्थिक लेन-देन के अभूतपूर्व प्रसार और मात्रा से जुड़ा है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के संगठन से भी जुड़ा है जो दुनिया की राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। भारत में वैश्वीकरण को आम तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के साथ एकीकृत करने के रूप में लिया जाता है। इसका अर्थ है कि विदेशी कंपनियों को भारत में आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलना; बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश में बाधाओं और रुकावटों को दूर करना; भारतीय कंपनियों को भारत में विदेशी सहयोग में प्रवेश करने की अनुमति देना और उन्हें विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना; मात्रात्मक प्रतिबंधों से टैरिफ पर स्विच करके बड़े पैमाने पर आयात उदारीकरण कार्यक्रम चलाना और फिर आयात शुल्क के स्तर को काफी कम करना; और निर्यात प्रोत्साहनों की अधिकता के बजाय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनिमय दर समायोजन का विकल्प चुनना। क्या वैश्वीकरण के बीज सुधार-पूर्व काल में बोए गए थे, क्योंकि विदेशी पूंजी को कई रियायतें दी गई थीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिनमें उनका प्रवेश पहले प्रतिबंधित और प्रतिबंधित था। अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

सिन्हा, सुबीर. (2024).वैश्वीकरण अब एक सार्वभौमिक शब्द है जिसे पारंपरिक रूप से पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। यह एक साझा वैश्विक सभ्यता और एकीकृत विश्व का सुझाव देने की कोशिश करता है। वैश्वीकरण ने अपने पंख फैलाए और दुनिया के लगभग हर कोने

को छुआ। हालाँकि, भारत में, इसने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अस्तित्व दिखाया है। वैश्वीकरण के स्पर्श का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और जनसंचार माध्यमों ने इस प्रभाव की गति को बढ़ाया है। वैश्वीकरण विदेशी संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला लाता है और जनसंचार माध्यम भारतीय समाज में उन संस्कृतियों का लगातार प्रचार-प्रसार करते हैं। विदेशी संस्कृतियों के भारतीय संस्कृति के साथ समामेलन के बाद, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और एक संकर संस्कृति विकसित हो रही है। 'वैश्वीकरण, जनसंचार माध्यम और भारत के सामाजिक परिवर्तन' शीर्षक वाला लेख गहन विश्लेषण करता है और दिखाता है कि कैसे वैश्वीकरण ने जनसंचार माध्यमों की मदद से एक संकर संस्कृति विकसित की और कैसे संकर संस्कृतियाँ भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर हावी हो गईं।

फ़िशर, जस्टिना. (2013).वैश्वीकरण और राजनीतिक विश्वास। यह शोधपत्र यह मानता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में किसी देश के एकीकरण से नागरिकों का राजनीतिक विश्वास कम हो सकता है। मेरा तर्क है कि आर्थिक वैश्वीकरण सरकार की व्यवहार्य नीतियों के चयन को बाधित करता है, जिससे औसत मतदाता के प्रति जवाबदेही बाधित होती है। 1981 से 2007 तक व्यक्तिगत स्तर के सर्वेक्षण डेटा का मिलान, 80 देशों के कुल 260'000 व्यक्तियों के बार-बार किए गए क्रॉस-सेक्शन, उसी समय अवधि के लिए किसी देश के आर्थिक वैश्वीकरण की डिग्री के माप के साथ, मुझे पता चलता है कि वैश्वीकरण का विश्वास कम करने वाला प्रभाव है; हालाँकि, इसका परिमाण इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी है या नहीं। वैश्वीकरण के विश्वास कम करने वाले प्रभाव उन लोगों के लिए अधिक हैं जिनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, जो अपने राजनीतिक झुकाव को इंगित करने के लिए तैयार नहीं हैं, या जिनका शैक्षिक स्तर कम है। दो-चरणीय न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन और देश और समय निश्चित प्रभावों का एक सेट एक कारण व्याख्या का समर्थन करता है। जाहिर है, घरेलू सरकार को अपनी नीतियों के लिए जवाबदेह के रूप में देखना आर्थिक वैश्वीकरण और राजनीतिक विश्वास के बीच संबंध के लिए निर्णायक भूमिका निभाता

है। देश के आर्थिक विकास के स्तर, पिछले वैश्वीकरण और विभिन्न समयावधियों के प्रति मजबूती का परीक्षण किया जाता है।

पटजोशी, प्रमोद. (2019).वैश्वीकरण एक नया तत्व है जो पिछली सदी के नब्बे के दशक से दुनिया को निर्देशित करने के लिए आया है। बाजार अर्थव्यवस्था पर बढ़ते आत्मविश्वास और निजी पूंजी और संसाधनों में विश्वास के साथ राष्ट्रीय सीमाओं, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययनों और प्रभावों द्वारा प्रोत्साहित संरचनात्मक समायोजन की एक प्रक्रिया कई विकासशील देशों में शुरू हुई है। वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के लिए नए अवसर लाए हैं। विकसित देश के बाजारों और प्रौद्योगिकी आवंटन के लिए उच्च संगणना और पहुंच संभावित बेहतर उत्पादकता और उच्च जीवन स्तर प्रदान करती है। नब्बे के दशक तक व्यापार और निवेश उदारीकरण की बाधाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से संगठित थी। नब्बे के दशक में शुरू हुए वैश्वीकरण, निवेश और वित्तीय प्रवाह के विकास ने प्रतिस्पर्धा की बाधाओं को कम किया है और वैश्वीकरण की गति को तेज किया है। इसलिए यह शोधपत्र वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन करता है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के कई कारकों को अध्ययन के लिए मापा जाता है।

लाल, मैरी. (2013).मैरी लाल नागरिकता की पश्चिमी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करती हैं क्योंकि यह भारतीय सोच और राजनीतिक स्थान में समाहित हो गई है जो राष्ट्र राज्य की बदलती प्रकृति से जुड़ी हुई है। वह सुझाव देती हैं कि इस अवधारणा को भारत ने उत्तर-औपनिवेशिक बहुसांस्कृतिक और बहु-धार्मिक समाज के स्थानीय संदर्भ में फिट करने के लिए अपनाया है। नागरिकता मूल्यों को मजबूत करने के लिए शिक्षा प्रमुख राजनीतिक उपकरण रही है और भारत की कक्षाएँ प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान की दोनों जुड़ी हुई अवधारणाएँ गढ़ी जाती हैं। जिस तरह वैश्वीकरण राज्य की प्रकृति को बदल रहा है, उसी तरह यह राज्य और नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध की प्रकृति को भी बदल रहा है।

मोंगा, ओ.पी. एट अल. (2016).ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस, जो आधुनिक समाजों के बारे में अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने कहा, "वैश्वीकरण का अर्थ है कि हम सभी एक ही दुनिया में रहते हैं, ताकि व्यक्ति, समूह और राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं।" यह आम तौर पर नव-उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है जो बाजार की प्रधानता और सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार, निजीकरण और आर्थिक गतिविधियों के विनियमन से राज्य की वापसी की वकालत करता है। भारत को अस्सी के दशक की शुरुआत में वैश्वीकरण विरासत में मिला था जब उसने IMF से 5 बिलियन SDR का भारी भरकम ऋण लिया था। लेकिन एक दशक बाद जब भारत ने भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए 1991 में 2.5 बिलियन डॉलर का एक और बड़ा ऋण लिया, तो भारत में वैश्वीकरण वास्तव में शुरू हुआ। नव-उदारवादी दर्शन को अपनाने के साथ, आर्थिक सुधार शुरू हुए और आर्थिक गतिविधियों से हटने, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश करने के अलावा, भारत ने एक उदार व्यापार व्यवस्था के लिए देश के संसाधनों को विदेशी व्यापार समूहों के लिए खोल दिया, जिससे उनका दोहन करना और उन तक आसान पहुँच बनाना आसान हो गया। इस आलेख में एक प्रमुख मुद्दे, वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा पर चर्चा की गई है।

धागे, वृषाली अनिल. (2018).वैश्वीकरण और समकालीन भारतीय कला पर इसका प्रभाव। भारत के संदर्भ में "वैश्विक" शब्द को समझने के प्रयास में वैश्वीकरण की घटना को समझना आवश्यक है। इसने ललित कला के क्षेत्र में एक अलग दृश्य भाषा के निर्माण और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में माध्यमों के विस्तार में भारी योगदान दिया है। इसके अलावा, इसने दृश्य प्रथाओं के समानांतर / समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए तैयार की गई नीतियों का एक हिस्सा था। इसका अध्ययन दोहरी स्थितियों से किया जाना चाहिए - प्रारंभिक आर्थिक घटना और परिणामी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में दृश्य कला के क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव को एक समान दोहरी स्थिति के माध्यम से देखना है - इसका आर्थिक

मॉडल: कला बाजार का बदलता बुनियादी ढांचा और वैश्वीकृत दुनिया की सामाजिक और सांस्कृतिक चिंताओं और मुद्दों की जांच और विश्लेषण करना। ये चिंताएँ दुनिया भर में सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर हुए बदलावों के परिणामस्वरूप उभरी हैं और कलाकारों ने अपने कामों के माध्यम से इन्हें संबोधित किया है।

राठी, अमित एवं अन्य (2011).हाल के वर्षों में सॉफ्टवेयर उद्योग के तेजी से वैश्वीकरण ने भारत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिसका सॉफ्टवेयर उद्योग अब श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ हिस्सा है। हमारे अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य थे: भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की मुख्य विशेषताओं को समझना और उनका वर्णन करना, विशेष रूप से इसकी क्षमता और कमजोरियाँ; और चीन के सॉफ्टवेयर उद्योग और अधिक सामान्य रूप से चीन की अर्थव्यवस्था के साथ इसके संबंधों को समझना। चीन के उद्योग और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, हमारा सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग काफी हद तक चीन के उद्योग का पूरक है। भारतीय फर्म आवश्यक रखरखाव और विकास सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे यू.एस. और चीन की फर्म अपने दुर्लभ इन-हाउस आईटी कर्मचारियों का उपयोग उच्च मूल्य वर्धित कार्य, जैसे कि नए प्रकार के अनुप्रयोगों को डिजाइन और विकसित करने के लिए कर सकती हैं। ऐसा करने में, भारतीय फर्म अक्सर स्थापित चीन और अन्य विकसित देशों जैसे यू.एस. सॉफ्टवेयर सेवा फर्मों और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए उप-ठेकेदारों के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा, इनमें से कई फर्म भारतीय प्रोग्रामर पर निर्भर हैं और उनके भारत आधारित महत्वपूर्ण संचालन हैं। कई फर्म आउटसोर्सिंग, सीधे सहायक कंपनियों की स्थापना और सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना के माध्यम से भारत में अपने व्यावसायिक जुड़ाव को बढ़ाने की संभावना रखते हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के उदय ने अमेरिकी फर्मों, सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स दोनों को काफी लाभ प्रदान किया है। अमेरिकी फर्मों को लाभ होता है क्योंकि भारतीय सॉफ्टवेयर फर्म अनुबंधों के लिए आपस में जमकर प्रतिस्पर्धा करती हैं। नतीजतन, उपयोगकर्ता व्यापार

से होने वाले अधिकांश लाभों का आनंद लेते हैं। वे ऐसे स्रोत का उपयोग कर सकते हैं जो लचीला, लागत प्रभावी हो और सामान्य कार्यों पर काम करने के लिए तैयार हो, जिससे इन-हाउस स्टाफ को अधिक रचनात्मक कार्य के लिए मुक्त किया जा सके।

गोविंदराज, योगानंदम एट अल। (2023)।वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को काफी प्रभावित किया है, उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन और टीवी तक पहुँच रहे हैं। वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने वैश्वीकरण के कारण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। राष्ट्र में प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी सबसे कम है ($2,277)। भारतीय समाज वैश्वीकरण से बहुत प्रभावित हुआ है, जिसने इसकी सामाजिक और औद्योगिक प्रणालियों को बदल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तेजी से विकास के परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का विस्तार हुआ है। भारत सरकार बाधाओं को दूर करना चाहती है और व्यापार विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना चाहती है। भारत को इसकी जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए वैश्वीकरण के लाभों को इसकी कमियों के विरुद्ध तौलना चाहिए। वैश्वीकरण द्वारा भारत को विश्व मंच पर धकेल दिया गया है, जिसमें कई तरीकों से देश के भविष्य को आकार देने की क्षमता है। भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, फिर भी कानून, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दे अभी भी हैं। यह बहुराष्ट्रीय व्यवसायों को विशाल उपभोक्ता और श्रम पूल और रणनीतिक निवेश अवसरों तक पहुँच प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। भारत में दुनिया के कुछ शीर्ष तकनीकी कर्मचारी हैं, इसलिए तकनीकी कंपनियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। भारत में, वैश्वीकरण ने नौकरी के अवसरों और तकनीकी प्रगति का विस्तार किया है, लेकिन इसने समाज, संस्कृति, शासन और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव लाए हैं, जिसमें संसाधनों का गलत आवंटन, साइबर अपराध और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। उपर्युक्त के बावजूद, इस शोध लेख का मुख्य उद्देश्य सूचना के द्वितीयक स्रोतों और लेख के विषय से संबंधित सांख्यिकीय डेटा की मदद से एक व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक विश्लेषण में भारतीय समाज, सतत विकास,

अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर वैश्वीकरण के परिणामों की जांच करना है। इस तरह का दृष्टिकोण वर्तमान स्थिति को एक साथ गंभीर रूप से महत्वपूर्ण और आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक मानता है। लेख का विषय भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के परिणाम: आधुनिकीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा तकनीकी प्रगति और व्यापार ने दुनिया को जोड़ा और परस्पर जोड़ा है। इसमें परिणामी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं। आधुनिक युग में उपभोक्ताओं के सामने वस्तुओं और सेवाओं के लिए ढेर सारे विकल्प हैं। नवीनतम डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन दुनिया भर के प्रमुख निर्माताओं से उपलब्ध हैं। भारतीय राजमार्गों का परिदृश्य वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक मौसम में नए मोटर वाहन मॉडल पेश किए जाते हैं। वैश्वीकरण ने ग्राहक अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव किया है, व्यापार और तकनीकी प्रगति में सुधार के कारण अतिरिक्त विकल्प और बाजार में बदलाव की पेशकश की है, पारंपरिक प्रतिनिधियों और बिचौलियों को प्रतिस्थापित किया है। चाहे आप दुनिया में कहीं भी इस पोस्ट को पढ़ रहे हों, वैश्वीकरण और इसके फायदे दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं।इसने दुनिया भर के लोगों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ना संभव बना दिया है। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसने कंपनियों को ऐसे तरीकों से बढ़ने में सक्षम बनाया है जो पहले स्थानीय स्तर पर संभव नहीं थे। हालाँकि, भारत वह देश है जो वैश्वीकरण की घटना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है और वर्तमान में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ने बहुत तेज़ी से खुद को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जनशक्ति के एक जबरदस्त आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। 2021 में इसका नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद $3.17 ट्रिलियन था, जो लगातार बढ़ रहा है।

डांग, जी पी. (2016).वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया को एक विशाल बाजार में एकीकृत करने की प्रक्रिया से है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार, पूंजी प्रौद्योगिकी, सेवाओं और वस्तुओं के निर्बाध प्रवाह को संदर्भित

करता है। वर्तमान अध्ययन वैश्वीकरण के विभिन्न पक्ष और विपक्षों के साथ-साथ वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करता है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करना है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि हमारे दैनिक जीवन में जो आधुनिकीकरण हम अपने आस-पास देखते हैं, वह वैश्वीकरण का ही योगदान है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए, वैश्वीकरण ने हमें 1991 से एक लंबा सफर तय कराया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की उन्नति हुई है।

मुथुस्वामी, मुरली (2014).श्री वासावी कॉलेज (स्व-वित्त विंग), इरोड के प्रबंधन विभाग ने 2 जनवरी 2014 को "वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी, कॉर्पोरेट अधिकारी, व्यवसाय प्रबंधक और छात्र वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। उन्होंने कुछ नई अवधारणाएँ और विचार सुझाए हैं जो वैश्विक मानकों के अनुसार भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक हैं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत उत्पादों और सेवाओं को भी लॉन्च करना चाहिए। दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों और उद्योगों से लगभग 750 पेपर प्राप्त हुए। उनमें से केवल 89 पेपर को आईएसबीएन नंबर के साथ पुस्तक के प्रकाशन के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, अनुसंधान विद्वानों, कॉर्पोरेट अधिकारियों और छात्रों ने विपणन प्रबंधन और सेवा विपणन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उत्पादन और संचालन, अस्पताल और होटल प्रबंधन, समुद्री प्रबंधन, पत्रकारिता और जनसंचार, वाणिज्य और कॉर्पोरेट सचिव, इतिहास और पर्यटन प्रबंधन, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, आईटी और संचार प्रौद्योगिकी, वैमानिकी और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, अंग्रेजी और शिक्षा, गणित, सांख्यिकी और संचालन अनुसंधान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान,

कृषि और अर्थशास्त्र, भाषा और भाषा विज्ञान (तमिल और अंग्रेजी), पुस्तकालय विज्ञान और सूचना प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव सूचना विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित उप विषयों पर अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं।

अधिकारी, किंग्शुक. (2010).वैश्वीकरण दुनिया के देशों की लगातार बढ़ती आर्थिक निर्भरता की एक प्रक्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं में सीमा पार लेनदेन, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करती है। प्रस्तुत शोधपत्र तीन अलग-अलग खंडों में विभाजित है। खंड 1 एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है, खंड 2 वैश्वीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालता है और खंड 3 में वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत के आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण वर्ग की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। हालाँकि, यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा विश्लेषण अधूरा है और इसका प्रयास कुछ ऐसे मुद्दों को उठाना है जो निश्चित रूप से भविष्य के शोधकर्ताओं द्वारा आगे की जाँच की माँग करते हैं।

पांडे, मनीषा. (2011).वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत में आया और धीरे-धीरे हमारी संस्कृति और आत्म-छवि को बदल रहा है। यह शोधपत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को सैद्धांतिक रूप देने और भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को इसके व्यापक संदर्भ में स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण और एक परियोजना के रूप में वैश्वीकरण के बीच अंतर किया गया है। जबकि 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने विकास को बढ़ावा दिया, प्रत्यक्ष लाभार्थी अधिक समृद्ध शहरी निवासी थे। सामाजिक सुधार आर्थिक सुधार से पिछड़ गया है। भारतीय नियोजन में स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ विकास से नव-उदारवादी विकास की ओर प्रतिमान बदलाव का पता लगाया गया है। यह वैश्वीकरण पर सैद्धांतिक प्रवचनों और भारतीय संदर्भ में उनकी प्रयोज्यता से जुड़ा हुआ है।

गोविंदराज, योगानंदम। (2017)।वैश्वीकरण दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से बहस और चर्चा की जाने वाली घटना है। वैश्वीकरण क्या है और क्या वैश्वीकरण अच्छा है या बुरा, इस पर दुनिया की राय विभाजित है? मुट्ठी भर विद्वानों ने वैश्वीकरण को भूख से मुक्ति और समृद्ध बनाने का एकमात्र तरीका माना है। इसके विपरीत साक्ष्यों से पता चलता है कि जिन देशों में ये नीतियां लागू की गई हैं, वहां गरीबी, निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों तरह की बढ़ी है। विभिन्न विश्व बैंक रिपोर्ट उन साक्ष्यों का समर्थन करती हैं। इसने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया है, विशेष रूप से वर्ष 2015 तक 'अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाने' के पहले लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में। वैश्वीकरण चाहे अच्छा हो या बुरा, लगभग हर राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए बाध्य है। कुछ विचारकों ने इसे 'नई विश्व व्यवस्था' कहा। इस तथाकथित नई विश्व व्यवस्था में, जो आज अपने पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है, कल्याण के आंकड़े क्या होंगे और गरीब कहां जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण ने भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को हिला दिया है। भारत में जाति व्यवस्था मुख्यतः असमानता पर आधारित है, क्या वैश्वीकरण के दौर में ये असमानताएं (सामाजिक और आर्थिक) कम हो जाएंगी या और भी अधिक बढ़ जाएंगी? क्या वे बदलते परिदृश्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं? उनके व्यवसाय का क्या होगा? क्या वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हैं? वैश्वीकरण ने उनकी जीवनशैली में क्या परिवर्तन लाए हैं? क्या उनके पास वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए नए कौशल हैं? क्या वैश्वीकरण के मद्देनजर उनके बीच कोई सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता है या वे स्थिर हैं? आदि सवालों के जवाब देने की आवश्यकता है यदि उन्हें एक वैश्विक समुदाय का नागरिक बनना है - जिसे ज्ञान समाज के रूप में देखा जाता है।

महापात्रा, हितेश (2017).इसने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व दृष्टिकोण और विचारों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर लोगों की जीवनशैली और जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय संस्कृति इस परिवर्तन

प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। वैश्वीकरण के उदय के साथ हमारी गहरी जड़ें वाली परंपराएं और रीति-रिवाजों की पकड़ ढीली पड़ गई है। भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समृद्ध है और इसकी संस्कृति पर गर्व पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वैश्वीकरण ने न केवल भारत में पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ने भी वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव फैलाया है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं उसकी विशिष्टता के संबंध में विशेष महत्व रखती हैं और यही एक भौगोलिक सीमा के भीतर की आबादी को दूसरे से अलग करने वाला कारक है। वैश्वीकरण के कारण यह विशिष्टता अलग-अलग स्तरों पर प्रभावित हुई है। जब भारत जैसे विकासशील देश में इसका प्रभाव पड़ता है तो इसका प्रभाव बहुत अधिक स्पष्ट होता है।

बागची, अमिया. (2019).अध्याय की शुरुआत शास्त्रीय उदारवाद और नवउदारवाद के बीच अंतर से होती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नवउदारवाद मुक्त-व्यापार साम्राज्यवाद का दूसरा नाम है, जिसका पहले ब्रिटेन और फिर अमेरिका ने लगातार अभ्यास किया है। जबकि नवउदारवाद का प्रभाव आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के रूप में हो सकता है, इसने असमानता की डिग्री को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक बढ़ा दिया है। यह आम लोगों के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ है, जिससे वे पहले से कहीं अधिक भूखे रह गए हैं और ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए हैं जिनका आम लोगों के लिए इलाज नहीं किया जाता या खराब तरीके से किया जाता है।

बिष्ट, रमीला एट अल. (2012).वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रियाओं के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं। इस क्षेत्र को समझने में सामाजिक विज्ञान का क्या योगदान है? भारत के लेंस का उपयोग करके प्रासंगिक साहित्य की पहचान करने के लिए एक संरचित स्कोपिंग अभ्यास आयोजित किया गया था - एक 'उभरती हुई शक्ति' जिसकी स्वास्थ्य सेवा अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। यथासंभव व्यापक सामग्री को पकड़ने के लिए पाँच-चरणीय खोज और विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया था।

सामाजिक विज्ञान योगदान के लिए मानदंड को पूरा करने वाले अंग्रेजी में प्रकाशित दस्तावेज़ों को समीक्षा के लिए शामिल किया गया था। भारत में किए गए इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथसूची डेटाबेस, वेबसाइट और हाथ से की गई खोजों के माध्यम से, 113 प्रासंगिक लेख, किताबें और रिपोर्ट की पहचान की गई। इन्हें विषय क्षेत्र, प्रकाशन तिथि, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, शैली और सैद्धांतिक और पद्धतिगत दृष्टिकोणों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। विषय क्षेत्रों की पहचान शुरू में एक प्रेरक दृष्टिकोण के माध्यम से की गई थी, फिर उन्हें सात व्यापक विषयों में युक्तिसंगत बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय खपत; अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यबल; विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं में उत्पादन, खपत और व्यापार, और विचारों और ज्ञान का अंतरराष्ट्रीय प्रसार, सभी ने भारत से संबंधित कार्यों में सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। कम मात्रा में काम करने वाले अन्य विषयों में नए वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन मुद्दे और संरचनाएं शामिल हैं; स्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी और पूंजी का अंतरराष्ट्रीय आंदोलन। हमारी समीक्षा में तेरह विषयों का प्रतिनिधित्व पाया गया, जिसमें सामाजिक नीति स्पष्ट रूप से अग्रणी है, उसके बाद अर्थशास्त्र और प्रबंधन अध्ययन हैं। कुल मिलाकर भारत से संबंधित कार्य का यह सर्वेक्षण एक युवा और विस्तारित साहित्य का सुझाव देता है, हालांकि वैश्विक तुलनात्मक डेटा में अपर्याप्तता और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने में कठिनाइयों से बाधा उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र को विषयों के बीच आगे के क्रॉस-फर्टिलाइजेशन और व्याख्यात्मक सिद्धांत के अधिक से अधिक अनुप्रयोग से लाभ होगा। स्टेम सेल अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के बारे में साहित्य सामाजिक विज्ञान को रोशन करने के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रणालियों के मुद्दों पर भविष्य के शोध एजेंडा में अभिनव अनुभवजन्य कार्य शामिल करने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की गतिशीलता को पकड़ता है और जो सामाजिक जीवन के बारीक अवलोकनों के साथ मैक्रो-स्तरीय परिवर्तन को जोड़ता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रियाओं के साथ तेजी से विकसित हो रही हैं। इस

क्षेत्र की समझ में सामाजिक विज्ञान का क्या योगदान है? भारत के नज़रिए से प्रासंगिक साहित्य की पहचान करने के लिए एक संरचित स्कोपिंग अभ्यास आयोजित किया गया - एक 'उभरती हुई शक्ति' जिसकी स्वास्थ्य सेवा अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। यथासंभव व्यापक सामग्री को पकड़ने के लिए पाँच चरण की खोज और विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया। अंग्रेजी में प्रकाशित दस्तावेज़ जो सामाजिक विज्ञान योगदान के मानदंडों को पूरा करते थे, उन्हें समीक्षा के लिए शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथसूची डेटाबेस, वेबसाइट और भारत में किए गए हाथ से किए गए खोजों के माध्यम से,113 प्रासंगिक लेख, पुस्तकें और रिपोर्ट पहचानी गईं। इन्हें विषय क्षेत्र, प्रकाशन तिथि, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, शैली और सैद्धांतिक तथा पद्धतिगत दृष्टिकोणों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। विषय क्षेत्रों की पहचान शुरू में एक प्रेरक दृष्टिकोण के माध्यम से की गई, फिर उन्हें सात व्यापक विषयों में तर्कसंगत बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय खपत; अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यबल; विशिष्ट स्वास्थ्य-संबंधी वस्तुओं में उत्पादन, खपत और व्यापार, तथा विचारों और ज्ञान का अंतरराष्ट्रीय प्रसार, सभी ने भारत से संबंधित कार्य में सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। कम मात्रा में कार्य वाले अन्य विषयों में नए वैश्विक स्वास्थ्य शासन मुद्दे और संरचनाएं; स्वास्थ्य सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय डिलीवरी और पूंजी का अंतरराष्ट्रीय आंदोलन शामिल हैं। हमारी समीक्षा में तेरह विषयों का प्रतिनिधित्व पाया गया, जिसमें सामाजिक नीति स्पष्ट रूप से अग्रणी रही, उसके बाद अर्थशास्त्र और प्रबंधन अध्ययन रहे। कुल मिलाकर भारत से संबंधित कार्य का यह सर्वेक्षण एक युवा और विस्तारित साहित्य का सुझाव देता है, हालांकि वैश्विक तुलनात्मक डेटा में अपर्याप्तता और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने में कठिनाइयों से बाधित है। इस क्षेत्र को विषयों के बीच आगे के क्रॉस-फर्टिलाइजेशन और व्याख्यात्मक सिद्धांत के अधिक अनुप्रयोग से लाभ होगा। स्टेम सेल अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के बारे में साहित्य सामाजिक विज्ञान को रोशन करने के कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रणालियों के मुद्दों पर भविष्य के शोध एजेंडे में अभिनव

अनुभवजन्य कार्य शामिल करने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की गतिशीलता को पकड़ता है और जो सामाजिक जीवन के सूक्ष्म अवलोकनों के साथ मैक्रो-स्तर के परिवर्तन को जोड़ता है।स्टेम सेल अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के बारे में साहित्य सामाजिक विज्ञान को रोशन करने के कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रणालियों के मुद्दों पर भविष्य के शोध एजेंडे में अभिनव अनुभवजन्य कार्य शामिल करने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की गतिशीलता को पकड़ता है और जो सामाजिक जीवन के सूक्ष्म अवलोकनों के साथ मैक्रो-स्तर के परिवर्तन को जोड़ता है।स्टेम सेल अनुसंधान और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं के बारे में साहित्य सामाजिक विज्ञान को रोशन करने के कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रणालियों के मुद्दों पर भविष्य के शोध एजेंडे में अभिनव अनुभवजन्य कार्य शामिल करने की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की गतिशीलता को पकड़ता है और जो सामाजिक जीवन के सूक्ष्म अवलोकनों के साथ मैक्रो-स्तर के परिवर्तन को जोड़ता है।

उपाध्याय, राजीव (2014).यह शोध पत्र भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण और सारांश प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए, इस शोध पत्र में कई शोध पत्रों की समीक्षा, प्रस्तुति और पुष्टि की गई है। इस शोध पत्र में लैंगिक असमानता, समान अवसर, पारिवारिक संरचना और मूल्य, सामाजिक सुरक्षा जाल, जीवन शैली, प्रशासन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, त्यौहार, भाषा, संगीत, साहित्य, सिनेमा, टेलीविजन और नशीली दवाओं और तस्करी जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर पूर्व शोध कार्यों के आधार पर चर्चा की गई है। उन कार्यों के निष्कर्षों को इस शोध पत्र में संक्षेपित और प्रस्तुत किया गया है।

कक्यापदावु, निज़ार. (2022).इस शोधपत्र में हमने भारत में उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव और वैश्वीकरण के कारण उच्च शिक्षा के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जांच करने का प्रयास किया है। शिक्षा को व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र के समग्र और सतत विकास

की कुंजी माना जाता था। विउपनिवेशीकरण के दौर में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों की तुलना में भारत ने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। फिर भी, शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती मांगों को पूरा करने और व्यवस्था के भीतर कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए बहुत कुछ हासिल करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में, हम अपने देश की उच्च शिक्षा के परिदृश्य तक ही सीमित रहेंगे, अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे और इसके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, खासकर वैश्वीकरण के संदर्भ में। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और यहां तक कि शासन को एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। GATS (सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत अपने उच्च शिक्षा क्षेत्र को विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के लिए खोलने के लिए बाध्य है। संसाधनों की उपलब्धता और वर्तमान शोधपत्र की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, हमने डेटा के द्वितीयक स्रोतों के आधार पर यह शोध अध्ययन तैयार किया है। द्वितीयक डेटा विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध लेखों आदि से एकत्र किया गया है।

सिंह, जगदीप एट अल. (2022).भारतीय इतिहास के दौरान, महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जैसे सामाजिक दबाव, जाति के आधार पर भेदभाव और अन्य प्रकार की सामाजिक बाधाएँ जैसे उत्पादक संसाधनों तक सीमित पहुँच, गरीबी, उन्नति के सीमित अवसर, लाचारी और बहिष्कार, इत्यादि। दूसरी ओर, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए कई तरह की नई परिस्थितियाँ सामने आई हैं, जिनका उनके जीवन के लगभग हर पहलू पर प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन में मीडिया की भूमिका, शिक्षा, सांस्कृतिक पहलुओं, राजनीति और महिलाओं की भूमिका, समाज में महिलाओं की भागीदारी और वैश्वीकरण के अन्य सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में महिलाओं के जीवन पर वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने की कोशिश की गई है।

अंबू, सेइलान. (2020).भारतीय व्यापार और संस्कृति में वैश्वीकरण का प्रभाव। व्यापार का वैश्वीकरण एक व्यापार दर्शन है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यापार को वैश्विक दृष्टिकोण से

देखा जाता है, वैश्विक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ऐसे उत्पादों या सेवाओं की पेशकश की जाती है जो वैश्विक वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संतुष्ट कर सकें, वैश्विक मानकों के अनुपालन में गुणवत्ता बनाए रखें, वैश्विक कॉर्पोरेट नागरिकता की पहचान बनाएं और अंततः एक वैश्विक संगठनात्मक और व्यावसायिक संस्कृति को बढ़ावा दें।

हक, एम. (2018).कॉर्पोरेट वैश्वीकरण और भारत में महिलाओं पर इसका प्रभाव। क्या यह सच है, या कम से कम सैद्धांतिक रूप से संभव है, कि लोगों या राष्ट्र के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब राजनीतिक माहौल की मांग होती है कि हम-यहां तक कि हममें से सबसे परिष्कृत लोग-खुले तौर पर पक्ष लें? मेरा मानना है कि ऐसे समय हमारे सामने हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में, बुद्धिजीवियों और कलाकारों को पक्ष लेने के लिए बुलाया जाएगा, और इस बार, स्वतंत्रता के संघर्ष के विपरीत, हमारे पास 'उपनिवेशवादी दुश्मन' से लड़ने की विलासिता नहीं होगी। हम खुद से लड़ेंगे" (रॉय 198)।

गोंजालेज, बी. (2016).वैश्वीकरण: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे। वैश्वीकरण, एक अंतरराष्ट्रीय घटना के रूप में, नई सहस्राब्दी में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के विकास में योगदान दिया है या सहायता की है। पिछली आधी सदी से, वैश्वीकरण की ताकतें विकासशील और विकसित दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं। जबकि वैश्वीकरण या दुनिया को एक साथ बांधने वाले आर्थिक और सामाजिक संबंधों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, विद्वान और नीति-निर्माता इस बात पर जोरदार असहमत हैं कि क्या वैश्वीकरण अपरिहार्य है; क्या यह संतुलन पर सकारात्मक या नकारात्मक है; कौन, यदि कोई है, तो प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है; वैश्वीकरण द्वारा किए जा रहे मौलिक परिवर्तनों में विजेता और हारने वाले कौन हैं; और वैश्वीकरण के सामने क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिए। यह पुस्तक वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है।

चटर्जी, मिनिया. (2012).दुनिया ने 2011 के वसंत में एक चौंकाने वाली घटना देखी। कई देशों के नागरिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपनी सरकारों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए समान तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने एक-दूसरे से बहुत तेज़ी से सीखा। उन्होंने इस बारे में एक नई समझ साझा की कि सत्ता को कैसे संगठित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए कैसे किया जाना चाहिए, जिससे एक नई राजनीतिक व्यवस्था सामने आई जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार तेज़ी से फैल गई। शहरों में यह घटना कहीं और इतनी स्पष्ट नहीं थी, जो आम तौर पर लोगों, धन और विचारों के सीमा-पार प्रवाह के केंद्र बिंदु होते हैं, और जो बाहरी प्रभावों के संपर्क में आने वाले नागरिकों के एक निश्चित वर्ग का पोषण करते हैं। यह प्रोफ़ाइल दर्शाती है कि वैश्वीकरण नागरिकों के लिए ऐसी स्थितियाँ स्थापित करने में मदद करता है जिससे वे खुद की तुलना दूसरे समूहों से कर सकें और खुद को अपेक्षाकृत वंचित मान सकें। वैश्वीकरण उन कारकों और घटनाओं की सीमा को भी व्यापक बनाता है जो समाज में सामाजिक आंदोलन को गति दे सकते हैं, और विभिन्न देशों में सामाजिक आंदोलनों के अभिनेताओं को नोट्स का आदान-प्रदान करने, सफल रणनीतियों पर नज़र रखने और प्रभावी परिणामों के लिए दूसरों की रणनीतियों को अपने में ढालने की अनुमति देता है। इस तरह, यह प्रोफ़ाइल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार हाल के शहरी सामाजिक आंदोलनों की हस्तांतरणीयता की जांच करती है, विशेष रूप से उन कारकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो मिस्र में 2011 के वसंत में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से कुछ तत्वों को भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उसी समय हुआ था।

वदित्य, वेंकटेश. (2019).वैश्वीकरण का तर्कसंगत आधार यह है कि कोई भी राज्य स्वायत्त नहीं है, बल्कि कुछ संसाधनों के साथ दूसरों पर तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है और इन राज्यों के बीच मुक्त व्यापार पारस्परिक लाभ के लिए काम करेगा, जो आर्थिक वैश्वीकरण प्रक्रिया का सार रहा है। परिणामस्वरूप, यह वकालत की गई कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार की शक्तियों के मुक्त

खेल को बढ़ावा मिलता है। यह तर्क भारत में उच्च शिक्षा के बाजारीकरण का आधार रहा है, जो हाल के दशकों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में, यह पत्र यह समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करता है कि शिक्षा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रवेश राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है। शिक्षा और विशेष रूप से उच्च शिक्षा को उन प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है जो राज्य को एक न्यायपूर्ण समाज प्राप्त करने के संवैधानिक लक्ष्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो समग्र रूप से राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने का एक बड़ा हिस्सा है। हालाँकि, वैश्वीकरण के एक हिस्से के रूप में बाजारीकरण की प्रमुख सोच ने राज्य के भीतर और बाहर गहन वर्ग असमानताओं को ही रहस्यमय बना दिया है। भारत में उच्च शिक्षा अच्छे अर्थशास्त्र की आड़ में बाजारीकरण की ऐसी विचारधारा से अछूती नहीं है। परिणामस्वरूप, "सामाजिक भलाई" के रूप में उच्च शिक्षा तेजी से बाजार में एक मूल्यवान वस्तु बनकर रह गई है। इस प्रक्रिया में, शिक्षा के प्रभावी सामाजिक विकास के उत्प्रेरक होने की भारत की स्वतंत्रता के बाद की दृष्टि धुंधली होती जा रही है।

शर्मा, शिव. (2019).सामवेद की परंपरा का महाउपनिषद प्रतिपादित करता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति परम सत्य को जानते हैं, उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है। प्राचीन भारतीय सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करते थे। जब इन वैदिक सिद्धांतों को धर्म के शाश्वत नियम के साथ पढ़ा जाता है, तो वैदिक भूमण्डलीकरण (वेद के मूल्यों पर आधारित वैश्वीकरण) की अवधारणा विकसित होती है। अंग्रेज दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने सूत्रबद्ध किया, 'अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख'। पश्चिमी 'प्रिमम नॉन नोसेरे' का अर्थ है पहले किसी को नुकसान न पहुँचाना। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जोर दिया कि सत्ता का प्रयोग समाज के किसी भी सदस्य को केवल नुकसान से बचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन एलपीजीसी- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब भ्रष्टाचार के साथ जुड़ जाते हैं, तो कुछ लोगों द्वारा दूसरों के शोषण का रास्ता तैयार हो जाता है। लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर पूंजीवाद 'अधिकतम संख्या के हिस्से को हड़पने के लिए न्यूनतम संख्या के अभिजात वर्ग' के

उपकरण बन गए हैं। समकालीन भौतिकवादी और स्वार्थी दुनिया में उच्च नैतिक मूल्य अपना महत्व खो रहे हैं। धन का संचय न केवल अपने उपयोग के लिए बल्कि लालफीताशाही को बढ़ाने के लिए भी 'आधुनिक जीवनशैली' बन गई है। धन की स्थिति में सुधार करने वाली यह संपत्ति दुनिया के लोगों में खतरनाक रूप से गैरकानूनी गुणों को बढ़ा रही है।

शोटली, जीवंता और अन्य। (2023)।यह खंड भारत की घरेलू राजनीति, संरचनाओं, संस्थानों और नीतियों के लेंस के माध्यम से वैश्वीकरण और शासन के बीच के पेचीदा संबंधों की जांच करता है। इस खंड के योगदानकर्ता वैश्विक और घरेलू प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा करते हुए, यह खंड राज्य-समाज-बाज़ार संबंधों की विकसित होती गतिशीलता को भी पकड़ता है। कागजों का एक अनूठा मिश्रण, संग्रह नीति सुधारों के साथ-साथ संस्थागत परिवर्तन दोनों की दृढ़ता को समझाने में वैश्विक रुझानों, घरेलू राजनीति और शासन चुनौतियों के बीच जटिल अंतरसंबंधों और अंतर्संबंधों को सामने लाता है। इस प्रकाश में, यह खंड घरेलू स्तर पर सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं और प्रमुख अभिनेताओं की भूमिका की जांच करता है; कैसे उन्होंने वैश्विक मानदंडों, दबावों और अवसरों पर बातचीत की है जिसके परिणामस्वरूप टिकाऊ नीतियां और संस्थान बने हैं। COVID-19 महामारी ने एक बार फिर वैश्वीकरण और शासन के महत्व और अंतर्संबंध पर ध्यान केंद्रित किया है रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीयकरण और सुधार की राजनीति; माइक्रो-क्रेडिट की वैश्विक सफलता और इसकी घरेलू अभिव्यक्ति; और वैश्वीकरण को संचालित करने के 'भारतीय मॉडल' की लचीलापन और स्थायित्व। यह पुस्तक मूल रूप से इंडिया रिव्यू के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी।

गुप्ता, शिखा एवं अन्य (2021).भारत वैश्वीकरण के चौथे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम वैश्वीकरण के लाभों को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकते हैं। संरक्षणवाद को अपनाने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्वीकरण का विकास के साथ संबंध बहुत अधिक जटिल है। इस शोधपत्र का उद्देश्य विदेशी कारकों द्वारा बताए गए आर्थिक विकास के हिस्से को पकड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की गति की पहचान करना है। भारत में धीमी गति के

साक्ष्य का सुझाव देने के लिए समय-भिन्न अनुमानों में कारक-प्रेरित घरेलू और विदेशी कारक लोडिंग का उपयोग किया जाता है। स्टोकेस्टिक अस्थिरता के साथ पूरक मॉडल अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों की जांच करने में मदद करते हैं।

चौक्रौने, लीला. (2020).भारतीय वास्तविकताओं को समझने में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अवधारणाओं में से एक 'आधुनिक' की अवधारणा है। आधुनिकता के कई दृष्टिकोण सह-अस्तित्व में हैं। आधुनिकता में संक्रमण की मुख्य विशेषता को आम तौर पर मध्ययुगीन स्थिर और एकात्मक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ एक विच्छेद के रूप में समझा जाता है जिसमें कानून और शक्ति के स्रोत एक निर्विवाद शासक की इच्छा तक सीमित थे और उनकी सांप्रदायिक या धार्मिक विरासत या अन्य लोकप्रिय रीति-रिवाजों से अलग नहीं थे। लेकिन आधुनिकता खुद को, भारत की तरह, कई अन्य रूपों का उपयोग करके भी प्रकट कर सकती है। इस संबंध में, भारतीय कानून कानून और लोकतंत्र के संदर्भ में सार्वभौमिक अपील का एक आकर्षक उदाहरण प्रदान करता है। जबकि उत्तर-औपनिवेशिक विधायक ने एक विकासवादी संवैधानिक परियोजना के रूप में नए भारतीय गणराज्य की राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुकूल मानदंडों का एक मजबूत सेट विकसित करने की कोशिश की थी, इस गतिशील प्रक्रिया को एक जीवंत न्यायपालिका द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जिसने सामाजिक आधुनिकीकरण के इंजन के रूप में विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लिया है। कानून का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है और लोकतंत्र को पालतू बनाया गया है। संविधान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के साथ, भारतीय लोकतंत्र पर आज के प्रश्न यह दर्शाते हैं कि आधुनिकीकरण की यह गतिशील और अपूर्ण प्रक्रिया लगभग अपरिवर्तनीय है।

इस्लाम, रबीउल एट अल. (2019).इस शोधपत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभाव के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। वैश्वीकरण की तेज़ी के साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

व्यवसाय अधिकारियों के बीच एक विषय रहा है और इसने सभी उद्योगों का ध्यान आकर्षित किया है। कार्यप्रणाली: इस अध्ययन के लिए डेटा वैश्वीकरण की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रभाव पर मौजूदा साहित्य से प्राप्त किए गए थे। कार्यप्रणाली इस विषय पर मौजूदा पिछले साहित्य पर निर्भर थी। निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय युग में वैश्वीकरण और देशों के बीच विरोधाभासों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए अवसर और खतरे दोनों हैं। इसलिए, सभी व्यावसायिक संस्थाओं को किसी भी समायोजन और समाधान को निष्पादित करते समय और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संचालन को प्रशासित करते समय वैश्वीकृत व्यावसायिक वातावरण में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखना और नोट करना चाहिए। निहितार्थ: वर्तमान अध्ययन ने बताया कि विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया। किसी फर्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करने, अपने उत्पादन को अन्य देशों में स्थानांतरित करने और संचालन की दक्षता पर विदेशों से ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता। तकनीकी उन्नति, बढ़ती आय, सीमा पार आवागमन के उदारीकरण और राष्ट्रों के बीच सहकारी व्यवस्था के कारण यह बढ़ रहा है।

गोविंदराज, योगानंदम एट अल। (2023)।वैश्वीकरण का शिक्षा और वैश्विक नागरिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फिर भी विविध वैश्विक नागरिक बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। भारतीय उद्योग वैश्वीकरण से जूझ रहे हैं, जिसके कारण श्रम की मांग में कमी आई है, विनिर्माण लागत में कमी आई है और नए बाजारों का उदय हुआ है। यदि वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो उन्हें प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करना होगा और सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाना होगा। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए, व्यवसायों को आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और हितधारकों के साथ गठबंधन करना होगा। विनिर्माण सुविधाएँ वैश्वीकरण से प्रभावित होती हैं, जिसके लिए सहयोग,

प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। विऔद्योगीकरण अपरिहार्य है, और इसमें प्रौद्योगिकी एक प्रमुख कारक है। वैश्वीकरण ने सरकारी भूमिकाओं को बदल दिया है, राज्य के स्वामित्व और विनिर्माण को कम किया है, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा और निजीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे एक अधिक सुसंगत वैश्विक समुदाय, नवउदारवादी दृष्टिकोण और संभावित संघर्ष और संसाधन की कमी हुई है। यह ब्लॉग उच्च उत्पादकता और मजदूरी की मांग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया की जांच करता है। वैश्वीकरण ने राज्य के कार्यों को बदल दिया है, सरकारों को आतंकवाद, पर्यावरण क्षरण और मानवाधिकार उल्लंघनों को विनियमित करने की आवश्यकता है, जो अंतरराज्यीय संबंधों, राजनीति, सार्वजनिक नीति, प्रशासन और संस्थागत अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। उपर्युक्त के बावजूद, इस शोध लेख का मुख्य उद्देश्य भारत के विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला स्थानीयकरण, बाजार की सफलता, कौशल अंतराल, क्षेत्रीय रीति-रिवाजों, नियामक आवश्यकताओं और राज्य कल्याण पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना है, लेख के विषय से संबंधित सूचना और सांख्यिकीय डेटा के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करके एक व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक विश्लेषण में। यह दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि वर्तमान स्थिति अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

बीसन, मार्क. (2017).इक्कीसवीं सदी में नीति निर्माताओं के सामने चुनौती बनने वाले सभी मुद्दों में से कोई भी राज्य के भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार, राज्य राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता के केंद्र में है, और अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता बना हुआ है - या कम से कम कुछ राज्य तो हैं। जैसा कि हम देखेंगे, जबकि सभी राज्य कई तरह की ताकतों के अधीन हैं जिन्हें हम 'वैश्वीकरण' के शीर्षक के तहत आसानी से पैकेज कर सकते हैं, सभी राज्य समान नहीं बनाए गए हैं। इसके विपरीत, समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था (आईपीई) में सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक अधिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक अंतरनिर्भरता

के समय राष्ट्रीय मामलों को प्रबंधित करने की राज्यों की क्षमता के बारे में है। यह केवल एक अकादमिक बहस नहीं है: राष्ट्रीय जीवन स्तर और समग्र सुरक्षा तेजी से व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के साथ राज्य की बातचीत से निर्धारित होती है जिसके भीतर वह अंतर्निहित है।

मुखर्जी, राहुल. (2014).आयात प्रतिस्थापन से आर्थिक वैश्वीकरण की ओर संक्रमण दक्षिण एशिया में बहुत गहरा रहा है। श्रीलंका और मालदीव - दक्षिण एशियाई क्षेत्र के दो अपेक्षाकृत छोटे देश - ने 1970 के दशक में यह परिवर्तन किया। वे आयात प्रतिस्थापन के साथ अपने रिश्ते को लंबे समय तक जारी रखने के लिए बहुत छोटे थे। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मार्ग को पार किया। एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया ने बड़े पैमाने पर आर्थिक वैश्वीकरण को अपनाया है। एशियाई चमत्कार से प्रेरित होकर दक्षिण एशिया के नीति निर्माताओं को यह विश्वास हो गया कि वैश्वीकरण से जरूरी नहीं कि निर्भरता1 पैदा हो और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के रास्ते से वैश्विक परिधि2 से बाहर निकलने के रास्ते हैं। इस नए नीति प्रतिमान ने इस दृष्टिकोण की वैधता को चुनौती दी है कि उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अनिश्चित काल तक घरेलू अर्थव्यवस्था की रक्षा करने की आवश्यकता है।

रॉय, तीर्थंकर. (2019).इतिहास की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समकालीन प्रासंगिकता है। अतीत की तरह, वर्तमान समय में भी, वैश्वीकरण ने पूंजीवादी ऊर्जा के असाधारण स्तरों को मुक्त किया है, जबकि कई आजीविकाएँ खराब, स्थिर और असंतुष्ट हैं। उभरने का यह विरोधाभास भारत में वैश्वीकरण के दो प्रकरणों को एक सदी के अंतराल पर जोड़ता है।

सिंह, डॉ. (2016).वैश्वीकरण एक व्यापक शब्द है जो आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक क्षेत्रों में वैश्विक संपर्क, एकीकरण और अन्योन्याश्रयता को बढ़ाता है। यह एक एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें कई ऐसी उप-प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिन्हें शायद बेहतर तरीके से बढ़ी हुई आर्थिक अन्योन्याश्रयता, बढ़ा हुआ सांस्कृतिक प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी की

तीव्र प्रगति और नवीन शासन और भू-राजनीतिक चुनौतियों के रूप में समझा जा सकता है। उच्च शिक्षा में कुछ कॉलेजिएट स्तर के संस्थान शामिल हैं, जैसे व्यावसायिक स्कूल, ट्रेड स्कूल और कैरियर कॉलेज जो डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण ने सीमा पार शिक्षा में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। अच्छी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना शैक्षिक व्यापार का एक मजबूत आधार रहा है जो दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है। कुछ दशक पहले, कई कारणों से, भारत अपने विश्वविद्यालयों में अच्छी संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में असमर्थ था। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कुछ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। अब, भारतीय विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान वैश्विक बाजार के लिए खुले हैं और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की उम्मीद करते हैं। यह आलेख वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियों के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से विविध विचारों और गुणवत्ता के प्रदर्शन और गुणवत्ता की गारंटी की प्रणालियों को विकसित करने के प्रयासों में, जो इस स्थिति में उपयोगी और टिकाऊ होंगे।

प्रभु, एस. (2020).स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने केन्द्रीकृत नियोजन के सिद्धांत के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। उस समय भारत राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत था। इसलिए, इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को चुना जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में थे। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंच गया और निजी क्षेत्र राज्य केन्द्रीकृत नियोजन तंत्र के सख्त नियंत्रण में था। लाइसेंसिंग और नियंत्रण ने नौकरशाहों और राजनेताओं के हाथों में बहुत अधिक शक्तियाँ दे दी थीं। वर्ष 1948 में पी.वी. नरसिंह राव सरकार ने नेहरूवादी दर्शन से मौलिक रूप से अलग हटकर नई आर्थिक नीति की घोषणा की और उदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के युग की शुरुआत की और सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया और व्यापार, औद्योगिक और स्कैल्प क्षेत्र में

दूरगामी सुधारों की घोषणा की। नई आर्थिक नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण ने कई विभागों में कर्मचारियों की इस ताकत के आधार पर सरकार के आकार को कम करने या सही आकार देने के रूप में सरकार और नौकरशाही की भूमिका को फिर से परिभाषित किया और कुछ कार्यालय बंद कर दिए गए। वैश्वीकरण के संदर्भ में निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है, इसलिए हमारे देश को अमेरिका के स्वतंत्र विनियामक आयोग की तर्ज पर विनियामक नौकरशाही का निर्माण करना होगा। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी वर्तमान नौकरशाही प्रणाली में भारतीय लोक प्रशासन में उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में नए कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए विशेषज्ञता नहीं है, ताकि बेहतर सेवा वितरण दिया जा सके।

गोयल, कमलेश. (2018).वैश्वीकरण मूल रूप से एक सामाजिक-आर्थिक शब्द है, जहाँ लोग स्थानीय रूप से सोचते हैं और वैश्विक रूप से कार्य करते हैं। यह आर्थिक विकास की एक रणनीति को संदर्भित करता है, जहाँ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, वित्त, श्रम, प्रौद्योगिकी, विचारों और सूचनाओं की आवाजाही के लिए देशों की सीमाएँ मायने नहीं रखती हैं। यह रणनीति विश्व अर्थव्यवस्था के देशों के बीच बढ़ते आर्थिक एकीकरण और बढ़ती परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया उत्पन्न करती है। वास्तव में, यह न केवल सीमा पार आर्थिक लेन-देन के प्रसार और मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के एक संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो दुनिया की राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। जुलाई, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बड़े नीतिगत बदलावों का अनुभव किया था। नए आर्थिक सुधारों को लोकप्रिय रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना था। औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के संबंध में सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई है। आर्थिक संक्रमण की इस अवधि का न केवल समग्र आर्थिक विकास पर बल्कि भारतीय लोगों की मानसिकता पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जो पारंपरिक, जिद्दी सोच, अंधविश्वास

और अशिक्षा से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं और यह आलेख वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों तथा सुधारोत्तर अवधि के बाद इसके प्रभावों का विश्लेषण करता है।

टेकबास, मूरत. (2021).इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 1990-2014 की अवधि के लिए पैनल डेटा विश्लेषण विधियों का उपयोग करके ब्रिक्स-टी देशों में आर्थिक विकास और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के बीच दीर्घकालिक संबंधों का विश्लेषण करना है। कॉब-डगलस उत्पादन फ़ंक्शन के आधार पर स्थापित मॉडल के अनुभवजन्य परिणामों के अनुसार, यह देखा गया है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वैश्वीकरण और पूंजी संचय का आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डुमिट्रेस्कु-हर्लिन पैनल ग्रेंजर कॉसैलिटी परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि पूंजी संचय और राजनीतिक वैश्वीकरण और आर्थिक विकास के बीच दो-तरफ़ा कार्य-कारण संबंध है। यह भी पाया गया है कि आर्थिक और सामाजिक वैश्वीकरण से आर्थिक विकास की ओर एकतरफा कार्य-कारण संबंध है।

अरोड़ा, दिव्या. (2020).भारत भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का सामना करने वाले एशियाई और वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। चीन का बाहरी एकीकरण तुलनात्मक रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सफल रहा है जबकि भारत के पास अंतर्मुखी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में 2020 में वैश्वीकरण का नया युग शुरू हुआ है, उचित लॉकडाउन, कुशल और प्रभावी राजकोषीय उपायों और आरबीआई गवर्नर के समय पर सहायता प्राप्त मौद्रिक उपायों ने चीन से वापसी के बाद निवेश आकर्षण के लिए एक मजबूत आधार दिया है। भारत की विदेश नीति दुनिया भर में पाँच व्यापक कारकों द्वारा आकार लेती है। व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक भूगोल और रणनीतिक संस्कृति हैं। सरकार देश में निवेश करने के लिए अप्रैल के महीने में 1000 देशों की कंपनियों तक पहुँचती है। कोविड-19 एक महामारी है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बनकर उभरी है।

के, अश्विनी एट अल. (2020).यह शोधपत्र वैश्वीकरण के परिणामों को बताने का प्रयास करता है जो इसके रिकॉर्ड किए गए सुधार दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इतिहास ने वैश्वीकरण की विभिन्न घटनाओं में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी दी है। इस शोधपत्र में वैश्वीकरण के विभिन्न आकलन भी उपलब्ध हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से वैश्वीकरण को समझने के लिए प्रत्येक आकलन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस शोधपत्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग हाल के सुधारों, आकलनों, रिपोर्टों और मॉडल विश्लेषण से युक्त है जो वैश्वीकरण के भविष्य की कल्पना करने में मदद करते हैं। भविष्य उपलब्ध सत्यापन योग्य डेटा केंद्रों के अधीन तय होता है। निश्चित रूप से, वैश्वीकरण के संभावित पूर्वानुमान पर सभी आदान-प्रदान का स्थगित परिणाम यह है कि यह जीवित रहेगा और किसी भी समय सभी पक्षों के लिए थोड़ा सा हिस्सा बना रहेगा। नवीनीकृत वैश्वीकरण के लिए मंच तैयार है। इस तथ्य के बावजूद कि इसमें रुचि और बोझ के उद्देश्य हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैश्वीकरण के मूल्यवान परिणामों का समर्थन करें, उन्हें बढ़ावा दें और उन्हें सशक्त बनाएँ, साथ ही सीमाओं को प्रबंधित करने या इसके नुकसानों को कम करने के तरीकों की तलाश करें। निर्मित देशों के सबसे बुनियादी हिस्सों में से एक महत्वपूर्ण कारक देश के वैश्वीकरण दर सूचक का मार्कर है। यदि किसी देश का मार्कर अविश्वसनीय या उच्च वैश्वीकरण सूचक है तो यह उस देश के लिए एक सकारात्मक बिंदु है। यह पत्र वैश्वीकरण के कुछ समकालीन मुद्दे और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने का इरादा रखता है। इस पत्र में इस्तेमाल किया गया नमूना आकार 1850 था। इस पत्र में, काई-स्क्वायर, एनोवा और सहसंबंध का उपयोग किया गया है। यह पत्र निष्कर्ष निकालता है कि वैश्वीकरण विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा।

एली, अली एट अल. (2011).एक वैश्विक संस्कृति अब तेजी से उभर रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम बनाई गई है। यह प्रौद्योगिकी केवल एक जगह से आती है - शिक्षा। वैश्वीकरण को स्वीकार करने (या उससे लड़ने) का प्राथमिक तरीका ज्ञान के माध्यम

से है। शिक्षा हर जगह लोगों के लिए बातचीत को सुविधाजनक बनाने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का मुख्य तरीका है।

अवेयर, विवेक. (2019).वैश्वीकरण और राष्ट्र-राज्यों पर इसका प्रभाव। वैश्वीकरण 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है, जिसका दुनिया पर विभिन्न आयामों में महत्वपूर्ण प्रभाव है। राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैश्विक मुद्दों और वैश्विक राजनीति पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और विश्व शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। आतंकवाद, वैश्वीकरण, ऊर्जा, पारिस्थितिकी, आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचलित मुद्दे हैं, जिन्होंने वैश्विक क्षेत्र में बढ़ती प्रासंगिकता प्राप्त की है। वैश्वीकरण, विशेष रूप से, एक बहुआयामी अवधारणा है जो मानव समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, संस्कृति और पर्यावरण को प्रभावित करती है। जबकि इसमें विश्व आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है, यह राष्ट्रों के बीच असमानता के बारे में चिंता भी पैदा करता है। विकासशील देशों को वैश्वीकरण की अवधारणा का अनुपालन करने की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि यह राष्ट्रों के बीच राजनीतिक बाधाओं के बिना एक सीमाहीन दुनिया को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्र-राज्यों के अधिकार और संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इसके संभावित लाभों के बावजूद, वैश्वीकरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है जिसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आगे के विश्लेषण और चर्चा की आवश्यकता है।

वर्मा, एट अल. (2018).वैश्वीकरण किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण के दर्शन को अपनाया; भारत, हालांकि इसमें देर से शामिल हुआ, लेकिन इसने वर्ष 1991 में इसे अपनाया। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा वैश्वीकरण के बारे में वर्तमान धारणा समान नहीं है, जबकि शोधकर्ताओं के एक समूह की राय है कि वैश्वीकरण ने किसी देश के आर्थिक विकास में मदद की है जबकि

शोधकर्ताओं के दूसरे समूह की राय बिल्कुल विपरीत है, इसलिए, हमारे लिए भारत के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका जानना अनिवार्य हो जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र वैश्वीकरण के आठ विभिन्न कारकों अर्थात् आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), निर्यात, आयात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर, सांस्कृतिक निकटता, सूचना प्रवाह, व्यक्तिगत संपर्क और टैरिफ समझौतों की संख्या के भारत के आर्थिक विकास पर प्रभावों का पता लगाने का प्रयास करता है। हमने ओएलएस मॉडल का उपयोग किया है और पाया है कि आठ में से छह कारकों ने सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एफडीआई, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कर, सूचना प्रवाह और टैरिफ समझौतों की संख्या ने भारत के आर्थिक विकास के साथ एक सीधा संबंध दिखाया जबकि आयात ने एक व्युत्क्रम संबंध दिखाया।

कुमार, संजीव. (2023).भारत में वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा। शिक्षा किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसे समय की जरूरतों और दुनिया के बदलते परिदृश्य के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह मानवता के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विश्लेषणात्मक रूप से विचार करने का अवसर प्रदान करता है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अधिक कुशल और शिक्षित समाजों की आवश्यकता है। दुनिया भर में ऐसे कई भारतीय हैं, जो भारत को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने या वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक समृद्ध भागीदार बनने के लिए अपनी क्षमताओं और कौशल के लिए जाने जाते हैं। भारत को अनुसंधान और विकास विंग के साथ सामान्य रूप से शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा को गुणात्मक रूप से मजबूत करना होगा। वैश्वीकरण और उदारीकरण के परिदृश्य में, सरकार उच्च शिक्षा में वृद्धिशील निवेश से पीछे हट रही है और जवाबदेही धीरे-धीरे निजी हितधारकों के पास जा रही है। शैक्षिक सह सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण को समर्थन जारी रखना सरकार के लिए विवेकपूर्ण रूप से आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में गिरावट और निजी संस्थानों में

नामांकन की काफी अधिक संख्या के साथ। यह निम्न-गुणवत्ता वाली शिक्षा और उच्च शिक्षा में निजी निवेश के लिए बड़ी जगह को इंगित करता है।

शोपिना, इरीना एट अल. (2017).लेख का उद्देश्य - विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव के कारणों को उजागर करना और परिणामों का सामान्यीकरण करना। कार्यप्रणाली। वैज्ञानिक अनुसंधान का सैद्धांतिक और पद्धतिगत आधार दुनिया के जाने-माने वैज्ञानिकों का काम है जिन्होंने वैश्वीकरण के विकास के मुद्दों और आर्थिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर इसके प्रभाव, आर्थिक विकास की गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आधिकारिक आंकड़े, स्वयं के शोध परिणामों का अध्ययन किया है। शोध परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया गया: आगमनात्मक और निगमनात्मक - सैद्धांतिक निष्कर्षों के लिए; सामान्यीकरण - विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के प्रभाव पर वैज्ञानिकों के कार्यों की सामग्री का अध्ययन करने में; विश्लेषणात्मक - वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों के अध्ययन के दौरान; कारण-और-प्रभाव - अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए। परिणाम। इस लेख में, विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव के कारणों का खुलासा किया गया है विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव के परिणामों को सामान्यीकृत किया गया है। व्यावहारिक अर्थ। इस अध्ययन के परिणाम रेटिंग एजेंसियों, विश्व बैंक की संरचना, यूक्रेन के यूरोपीय और यूरो-अटलांटिक एकीकरण मंत्रालय के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मूल्य/मौलिकता - विश्व समुदाय के लिए वैश्वीकरण के कारण और आर्थिक परिणाम निर्दिष्ट किए गए हैं। आगे के शोध का उद्देश्य संकट की घटनाओं और प्रक्रियाओं की घटना को रोकना होना चाहिए।

ड्रेसी, परशकेवी और अन्य। (2024)।अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण को उच्च शिक्षा पर 21वीं सदी के प्रभाव की केंद्रीय वास्तविकताओं के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण मिलकर विश्वविद्यालयों की छवि और संगठनात्मक

गतिविधियों को बदलने में प्रभाव डालते हैं। छात्रों को करियर के विकास के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में सक्षम होने के लिए, विश्वविद्यालयों को वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के रुझानों, अवसरों और अनुभवों से अवगत होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के चरित्र और व्यवहार पर वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव कई हालिया अध्ययनों का केंद्रीय विषय बन गया है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वैश्विक विश्वविद्यालयों का एक नया मॉडल तैयार किया है। आज की वास्तविकता का यह सामान्य रुझान हमें किसी देश की संतुलित आर्थिक और वैज्ञानिक क्षमता और मानव पूंजी के निर्माण को बढ़ाने का अवसर देता है जो स्थायी विकास वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है और समाज को ऐसे भविष्य को नेविगेट करने में मदद करना है जिसकी भविष्यवाणी करना अधिक कठिन है। प्राप्त: 25 दिसंबर 2023 / स्वीकृत: 25 फरवरी 2024 / प्रकाशित: 23 अप्रैल 2024

पापानिकोस, ग्रेगरी. (2024).महामंदी और महामारी के हालिया झटके वैश्वीकरण के प्रक्षेप पथ में एक नए युग की शुरुआत करते प्रतीत होते हैं। 1990 और 2000 के दशक के अति वैश्वीकरण से हटकर, दुनिया वैश्वीकरण के चरण में प्रवेश करती दिख रही है। वैश्वीकरण की अवधारणा जटिल और बहुआयामी है। यह शोध वैश्वीकरण के चार पहलुओं पर गहराई से चर्चा करता है: आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। गरीबी उन्मूलन वैश्वीकरण का सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए, जो आर्थिक विकास और लोकतंत्र के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तरार्द्ध उन नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक है जो आर्थिक विकास के लाभों को गरीबी से मुक्ति पाने का प्रयास करने वालों तक पहुंचाती हैं। निष्कर्ष में, यह दावा किया गया है कि लोकतंत्र के साथ मिलकर वैश्वीकरण गरीबी में कमी को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रक्रिया का अंत गरीबी का पूर्ण उन्मूलन है।

बुर्लाकू, सोरिन एट अल. (2018).वैश्वीकरण एक बहुत ही आम अवधारणा है जिसका उपयोग विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे एक घटना के रूप में परिभाषित करने वाले लोग इसे अलग-अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग इसे पूर्ण एकरूपता के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य, इसके विपरीत, सामान्य सिद्धांतों के पालन के आधार पर अनुपातों के विविधीकरण के रूप में देखते हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण की वर्तमान समझ के साथ-साथ वैश्वीकरण के संदर्भ में पर्यावरण में होने वाले बदलावों और जनसांख्यिकीय विकास, जनसंख्या और वैश्विक पर्यावरण पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत करना है। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष को प्रस्तुत करने में निष्पक्षता के लिए इस अवधारणा के दोनों अर्थों पर विचार किया गया है, जैसा कि साहित्य में पाया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संचालन में भी, साथ ही इस घटना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर भी।

विट, माइकल. (2019).वि-वैश्वीकरण, जो अब एक अलग संभावना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आईबी) में देखी जा सकने वाली रणनीतियों, संरचनाओं और व्यवहारों में एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बदलाव लाएगा। इस गुणात्मक बदलाव को समझने के लिए आईबी शोध को राजनीति के अधिक गहन एकीकरण को विकसित करने की आवश्यकता होगी, जो वि-वैश्वीकरण का मुख्य चालक है। इस तरह के एकीकरण का समर्थन करने के लिए, यह पत्र राजनीति विज्ञान, उदारवाद और यथार्थवाद से (वि-)वैश्वीकरण के दो प्रासंगिक सिद्धांतों का परिचय देता है। दोनों वर्तमान परिस्थितियों में वि-वैश्वीकरण की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भविष्य की विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में अलग-अलग उम्मीदें पैदा करते हैं: उदारवाद आर्थिक संबंधों के एक पैचवर्क का सुझाव देता है, जबकि यथार्थवाद प्रमुख देशों के आसपास आर्थिक ब्लॉकों के उद्भव की भविष्यवाणी करता है। यह पत्र आईबी शोध के तीन क्षेत्रों में परिणामी अवसरों पर चर्चा करता है: बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) की राजनीतिक रणनीतियाँ और भूमिकाएँ, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ और राष्ट्रीय संदर्भ की भूमिका। राजनीतिक रणनीतियों और भूमिकाओं के लिए, यह

पता लगाने की आवश्यकता है कि नियमित व्यावसायिक गतिविधियाँ और एमएनई की जानबूझकर राजनीतिक एजेंसी वैश्वीकरण की राजनीतिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती हैं। मूल्य श्रृंखलाओं के लिए, प्रश्नों में उनकी भविष्य की पहुंच और विशेषज्ञता, संगठनात्मक रूपों में परिवर्तन और स्थान निर्णयों पर राजनीतिक विचारों का प्रभाव शामिल है। राष्ट्रीय संदर्भों पर शोध के अवसर वैश्वीकरण को बनाए रखने की उनकी क्षमता और आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ उनके संबंध से संबंधित हैं।

डियाज़, क्रिश्चियन एट अल. (2024).हालाँकि शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकरण को अक्सर एक समान शक्ति माना जाता है, लेकिन विकास के मामले में अलग-अलग देशों में लगातार व्यापक रूप से भिन्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस सैद्धांतिक गुणात्मक शोध अध्ययन का उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव में अंतर और समानता का पता लगाना है, साथ ही उनके पीछे की आधारभूत विशेषताओं की पहचान करना है। इसे पूरा करने के लिए, वर्तमान कार्य एक नए वर्गीकरण दृष्टिकोण का उपयोग करता है, निष्कर्षों को सात आयामों में समूहीकृत करता है जिन पर अलग-अलग चर्चा की जानी है: स्वतंत्रता और वैश्वीकरण, पहचान और सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, शांति निर्माण और संघर्ष समाधान, संधारणीय भविष्य, डिजिटल परिवर्तन और शिक्षा व्यवसाय। निष्कर्ष बताते हैं कि विकासशील देशों को अपने विकसित समकक्षों की तुलना में शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव के मामले में एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, संसाधन (पर्यावरण सहित), भाषा, समाज, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नीतियाँ, इतिहास, धर्म और विशेष रूप से, संस्कृति जैसे कारकों को यह समझने के लिए महत्वपूर्ण माना गया कि इतना उल्लेखनीय अंतर क्यों है। अध्ययन की सीमाएँ ज्यादातर चयनित कार्यप्रणाली, नमूनाकरण और अनुसंधान निष्पादन से जुड़ी हैं, जिसमें चयनित वर्गीकरण दृष्टिकोण भी शामिल है। अनुशंसाओं में यह माना गया है कि सभी के लिए एक ही समाधान प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तथा शिक्षण और सीखने (पाठ्यक्रम सहित) के सांस्कृतिक फोकस

को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें स्थानीय रूप से प्रासंगिक बनाना है, तथा साथ ही, समाज-केंद्रित मार्ग के हिस्से के रूप में समग्र दृष्टिकोण के साथ समन्वयात्मक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। आगे के अध्ययनों में विभिन्न पद्धतियाँ, विशेष रूप से अनुभवजन्य, शामिल हो सकती हैं, ताकि वर्तमान सैद्धांतिक शोध अध्ययन निष्कर्षों को गहरा किया जा सके, त्यागा जा सके या पुष्टि की जा सके।

एमपोलोमोका, डैनियल एट अल. (2024).वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय शासन और विकास को महत्वपूर्ण रूप से नया रूप दिया है, जिसने दुनिया भर में नीति-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित किया है। वैश्विक बाजारों के एकीकरण ने सरकारों पर अधिक प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीतियों को अपनाने, व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का दबाव डाला है। ज्ञान का भंडार: राष्ट्रीय शासन और विकास पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आयाम शामिल हैं। आर्थिक रूप से, वैश्वीकरण व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक रूप से, वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रसार को बढ़ाता है, फिर भी यह सुपरनैशनल संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय निगमों को सत्ता हस्तांतरित करके राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर कर सकता है। सामाजिक रूप से, वैश्वीकरण सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है, जो सामाजिक विकास और नवाचार में योगदान देता है।

वेंकटेश, आर. (2023).वैश्वीकरण का भारत में उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, शिक्षकों और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग का प्रवाह शामिल है। यह शोधपत्र भारत में उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभावों की पड़ताल करता है, जिसमें इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ और अवसर शामिल हैं। शोधपत्र में चर्चा की गई है कि कैसे वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में बदलाव किए हैं, और उच्च शिक्षा संस्थानों को बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने की आवश्यकता है। शोधपत्र

वैश्वीकरण के लाभों पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारों से परिचित होना, और ज्ञान साझा करने और सहयोग की संभावना। शोधपत्र उन तरीकों का सुझाव देकर समाप्त होता है जिनसे भारत वैश्वीकरण द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठा सकता है और इसकी चुनौतियों को कम कर सकता है।

कोएट्जी, डर्क एट अल. (2024).विकासशील राष्ट्र और चौथी औद्योगिक क्रांति: वैश्वीकरण चुनौतियों की तुलना। यह शोधपत्र एक गहन तुलनात्मक अध्ययन है, जो विकासशील देशों और तुलनात्मक रूप से विकसित राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के बीच शोध क्षमताओं में असमानताओं को उजागर करता है, जो उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के बाद कंप्यूटर, विज्ञान, गणित और भौतिकी के क्षेत्रों से संबंधित हैं। यह वैश्वीकरण विशेषताओं और चुनौतियों जैसे राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, असमानता, कुशल प्रवास और अपर्याप्त शैक्षिक सुधारों के प्रभावों के ऐतिहासिक और चल रहे प्रभावों की पड़ताल करता है, जो सभी एक कमजोर शैक्षिक प्रणाली में योगदान करते हैं। मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, यह रिपोर्ट जांच करती है कि कैसे इन कारकों ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक खंडित शिक्षा वातावरण हुआ, जो घरेलू अनुसंधान क्षमताओं को विकसित करने और बढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं था। यह प्रारंभिक शोध कुशल शोधकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण और व्यवस्थित कमी को उजागर करता है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में जो किसी देश को चौथी औद्योगिक क्रांति में भाग लेने और फलने-फूलने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और न्यूरोटेक्नोलॉजी जैसी डिजिटल तकनीकों के विकास और व्यापक कार्यान्वयन पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह इस क्षमता अंतर को पाटने तथा इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

हाफ़िज़, डॉ-नुसरत और अन्य। (2023)।यह अध्ययन वैश्वीकरण और मानवाधिकारों के बीच जटिल अंतर्क्रिया पर केंद्रित है। अध्ययन वैश्वीकरण और मानवाधिकारों के बीच संभावित

ओवरलैप और संघर्षों का विश्लेषण करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करता है ताकि नकारात्मक प्रभावों को कम करने और अच्छे प्रभावों को अधिकतम करने के तरीके खोजे जा सकें। शोध का उद्देश्य विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली विशेष कठिनाइयों को देखते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू करने की कमियों और संभावनाओं की पहचान करना है। अध्ययन कई केस स्टडीज़ के डेटा के साथ-साथ साहित्य की गहन जाँच का उपयोग करके वैश्वीकरण और मानवाधिकारों के बीच जटिल अंतर्क्रियाओं को प्रकट करता है। यह कई महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्रों की पहचान करता है, जैसे श्रम अधिकार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच, पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक समानता और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा। इसके अतिरिक्त, अध्ययन यह मूल्यांकन करता है कि सरकारें, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य हितधारक मानवाधिकारों और सतत विकास पर वैश्वीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कैसे संबोधित कर रहे हैं। यह शोधपत्र कम करने वाले कारकों को उजागर करता है और मानवाधिकारों की रक्षा करने और एसडीजी की प्राप्ति में सहायता करने के लिए कई संयुक्त राष्ट्र हितधारकों के दायित्वों पर जोर देता है। इन मुद्दों को हल करके, विकासशील देश मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए और सतत विकास लक्ष्यों को एसडीजी ढांचे के भीतर आगे बढ़ाते हुए वैश्वीकरण के संभावित लाभों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकते हैं। इस पेपर की प्रमुख सीमाओं में से एक प्राथमिक डेटा प्राप्त करने और अवधारणा के सामान्यीकरण तक पहुंच की कमी है। वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा का एक गहरा और विशिष्ट दायरा है।

सिद्दीकी, कलीम. (2020).यह लेख वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेगा और संक्षेप में कोविड-19 पर इसके प्रभाव का विश्लेषण भी करेगा। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब है आर्थिक और व्यापारिक खुलापन (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में परिभाषित व्यापार) और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ एकीकरण। वैश्वीकरण को अभूतपूर्व आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप, समर्थकों का दावा है

कि दुनिया में गरीब लोगों की संख्या में कमी आई है। 19वीं सदी के मध्य के बाद, तकनीकी विकास और राजनीतिक उदारवाद ने वह गति पकड़ी जिसे हम आज 'वैश्वीकरण की पहली लहर' के रूप में जानते हैं और 1914 में समाप्त हो गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान तक सीमित रहा। सोवियत संघ के पतन के बाद 'वैश्वीकरण की दूसरी लहर' शुरू हुई

यिगिट, पीएच.डी., मेहमत फातिह एट अल। (2013)। लोकतंत्रीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान नागरिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमारे समय में इसे प्राप्त करने के कई प्रभावी तरीके हैं। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग उपकरण राजनीतिक चुनावों और सामाजिक परिवर्तनों को निर्देशित करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक रहे हैं। इस अध्ययन में, शोधकर्ता चर्चा करते हैं कि लोकतंत्रीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सोशल मीडिया उपकरणों का उपयोग कैसे किया गया है, वे पहल कहाँ सफल रहीं, उन्होंने नागरिक और राजनीतिक भागीदारी को कैसे प्रभावित किया, और सोशल मीडिया में किस तरह के चर महत्वपूर्ण हैं और ईरान, सीरिया और मिस्र में लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

भाटिया, श्वेता एवं अन्य (2019).लेख भारत में समकालीन व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करता है। जब 1990 के दशक में भारतीय सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा बाजार को उदार बनाया, तो यह मान लिया गया कि व्यावसायिक स्कूलों के निर्माण से स्वतः ही रोजगार के लिए तैयार व्यक्ति तैयार हो जाएँगे, खासकर प्रबंधकीय भूमिकाओं में। इसके विपरीत, कुछ रुझान बताते हैं कि व्यावसायिक स्कूल उद्योग के लिए कम कुशल व्यक्तियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कौशल-रोजगार योग्यता का अंतर लगातार बढ़ रहा है। लेख इस अंतर के संभावित कारणों पर चर्चा करता है। लेख प्रबंधन शिक्षा ढांचे में

एक प्रमुख व्यवहार कौशल के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) को एकीकृत करने का भी तर्क देता है।

कोचचेवा, लाडा. (2013).वैश्वीकरण, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और समाजों के बीच गहन संपर्क और एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में, आर्थिक विकास और पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरण परिवर्तन और नीति प्रतिक्रियाओं के चरित्र और वैश्विक प्रक्रियाओं और घरेलू पर्यावरण अधिकारों, विचारों और विश्वासों के बीच संबंधों के बीच संतुलन के बारे में उठने वाले कई परस्पर विरोधी तर्कों को तेज कर दिया है। क्या वैश्वीकरण आर्थिक अवसरों और नीति नवाचार में वृद्धि में योगदान देता है, या यह पर्यावरणीय गिरावट और अस्थिरता को बढ़ाता है? कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच असंतुलन को क्यों बढ़ाती हैं जबकि अन्य पर्यावरणीय जिम्मेदारी की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती हैं? थियोडोर पानायोटो के ढांचे पर निर्माण करते हुए, यह लेख वैश्वीकरण और पर्यावरण के बीच मुख्य संबंधों का पता लगाता है और चीन, भारत और ब्राजील में वैश्वीकरण के पाँच प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है: पैमाने के प्रभाव, संस्थागत प्रभाव, प्रौद्योगिकी/उत्पाद प्रभाव, नीति प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। यह तर्क देता है कि वैश्वीकरण इन उभरती शक्तियों में संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन को तेज करता है, जिससे उनकी औद्योगिक और नीति संरचना, संसाधन उपयोग पैटर्न और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरणीय गिरावट के प्रति जागरूकता और प्रतिक्रियाएँ बदल जाती हैं। लेख में यह भी पाया गया है कि वैश्वीकरण बाजार और नीतिगत खामियों को बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति फैल सकती है और बढ़ सकती है, फिर भी यह पर्यावरणीय आंदोलनों से सुधार के लिए दबाव भी उत्पन्न करता है, जिससे अवसर पैदा होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रुचि आकर्षित होती है।

खान, अकबर एट अल. (2019).नए आर्थिक विकास, जो वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण का परिणाम है, ने भारतीय मानव संसाधन कार्यों पर खुद को विकसित करने और फर्म के परिणामों में मूल्य जोड़ने के तरीके पर जबरदस्त दबाव डाला है। प्रस्तुत पत्र नए आर्थिक सुधारों के

आलोक में वैश्वीकरण और भारतीय फर्म के मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं पर इसके प्रभाव पर सटीक रूप से चर्चा करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में लगातार बढ़ते वैश्वीकरण के कारण मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं के पैटर्न में दूरगामी परिवर्तनों की जांच करना है। भारतीय फर्मों के 282 वरिष्ठ मानव संसाधन प्रबंधकों से स्व-विकसित प्रश्नावली के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया था। वैरिमैक्स रोटेशन के साथ प्रमुख घटक विश्लेषण ने पंद्रह मानव संसाधन प्रथाओं से तीन घटक उत्पन्न किए, अर्थात् औपचारिक, प्रेरक और रणनीतिक मानव संसाधन प्रथाएँ। एसपीएसएस एमोस 22 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वैश्वीकरण और मानव संसाधन प्रथाओं के तीन बंडलों के बीच संबंधों को समझने के लिए संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग (एसईएम) तकनीक लागू की गई है।

डेविड, सोलोमन अरुलराज। (2014)।यह अध्ययन उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम पुनर्गठन पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर केंद्रित है। भारत में हाल ही में हुए औद्योगिक विकास, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का व्यापक विकास, और नौकरी बाजार का पाठ्यक्रम पुनर्गठन पर एक मजबूत प्रभाव है। केरल और तमिलनाडु में रुझानों पर एक तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन ऊपर दिए गए तर्कों के अनुरूप किया गया है, जबकि केरल में विकास सावधानी से किया गया है, हालांकि समान दृष्टिकोण स्पष्ट हैं। छह चयनित उच्च शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम पुनर्गठन से अलग तरीके से निपटते हैं, इन विश्वविद्यालयों की शासन, रणनीतियों और प्राथमिकताओं की प्रकृति को देखते हुए

पांडे, अतुल (2024).वैश्वीकरण को वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, साथ ही साथ ज्ञान के आदान-प्रदान से जाति, वर्ग, हीनता और श्रेष्ठता की भावना और व्यापार बाधाओं को भी तोड़ा जा सकता है। वैश्वीकरण का संबंध अहस्तक्षेप की अवधारणा से है। भारत में वैश्वीकरण के आगमन के परिणामस्वरूप विकसित देशों द्वारा विदेश नीतियों में ढील, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों की सिलिकॉन वैली में स्मार्ट वेतन पैकेज; पर्यटन और प्रबंधन अध्ययन को बढ़ावा; पुरातत्व और वैज्ञानिक अन्वेषण में

विभागों और राज्यों की रुचि, उदाहरण के लिए: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और नासा के बीच सहयोग, जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए एक-दूसरे की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली को जानने के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान में राज्यों की रुचि। संयुक्त राज्य अमेरिका में अचानक मंदी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के उद्भव के साथ, वे आर्थिक संकट से निपटने में कामयाब रहे और दुनिया के बाकी देशों ने भी इसका अनुसरण किया। भारत ने भी अपने व्यापार मानदंडों को ढीला कर दिया और परिणाम मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और कई अन्य ब्रांड भारत में आ रहे हैं। यह 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हुआ, जिसे एलपीजी सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चूंकि, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इसी तरह, वैश्वीकरण के भी कुछ गुण और दोष हैं। अगर हम आर्थिक परिदृश्य की उपेक्षा करते हुए मानक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारे भारतीय समाज का सबसे कमजोर वर्ग हमारी वृद्ध आबादी है। "वैश्वीकरण अच्छा है। वैश्वीकरण के बाद से भारतीय लोकतंत्र में सुधार हुआ है।" ii "अगर कोई सबक सीखा जा सकता है, तो वह यह है कि सर्वोत्तम अभ्यास या आदर्श नीति वास्तव में संदर्भ विशिष्ट होती है। यह अफ़सोस की बात है कि नीति को प्रभावित करने की स्थिति में किसी ने भी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने दो दशक पहले संप्रभुता को कमज़ोर करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी।" iii भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को ध्यान में रखते हुए, इसकी अधिकांश आबादी युवा पीढ़ी से समृद्ध है, जो इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में विदेश जाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि विदेशी राज्य आकर्षक पैकेज देते हैं, लेकिन मुश्किल समय में अपने माता-पिता को अकेला छोड़ देते हैं। माता-पिता के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वे स्वयं को वृद्धाश्रम या पालन-पोषण गृह में भर्ती करा लें और जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त धन नहीं होता, वे कष्ट भोगते हैं और अचेत अवस्था में मर जाते हैं।

डॉ.अब्दाल एट अल. (2024).इस लेख का उद्देश्य सामाजिक पूंजी और पति-पत्नी तथा बच्चों के बीच पारिवारिक संबंधों के बीच संबंधों की घटना का वर्णन करना और भारत में सामाजिक पूंजी के सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखना है। भौगोलिक स्थानों ने कुछ समानताओं के साथ-साथ कुछ अंतरों को भी बाधित किया है, जैसे ग्रामीण या शहरी, जाति, वर्ग और स्थिति जहां तक संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का संबंध है। अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के बाद के बदलाव के बाद अभूतपूर्व बदलाव, इस घटना और आधुनिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रियाओं से प्रेरित होकर, पारिवारिक जीवन में कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसने सामाजिक विज्ञान के कई विद्वानों को इस पर यथासंभव गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इस संदर्भ में प्रस्तुत पत्र में कुछ निम्नलिखित उद्देश्य गिनाए गए हैं; सबसे पहले, पति-पत्नी तथा बच्चों के बीच पारिवारिक संबंधों की तुलना में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना दूसरा उद्देश्य यह जानना है कि युवा पीढ़ी अपने परिवारों से अलग/अव्यवस्थित क्यों हो गई, ताकि हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे भारत में सबसे अधिक प्रस्तुत करने योग्य स्थिति के रूप में देख सकें।

शर्मा, श्रीमती एट अल. (2024).जैसा कि हम एक नए युग की शुरुआत में खड़े हैं, पिछले दशक पर विचार करने से हमें सद्भाव और सहयोग के धागों से बुनी गई वैश्विक गतिशीलता की जटिल टेपेस्ट्री को समझने का मौका मिलता है। दुनिया ने असंख्य चुनौतियों और जीतों को देखा है, और इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में G20 है - हमारे सामूहिक भाग्य के पाठ्यक्रम को आकार देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति। यह संपादित खंड, "भविष्य को आकार देने का एक दशक: वैश्विक सद्भाव, सहयोग और G20," पिछले दस वर्षों के दौरान राष्ट्रों, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के बीच उल्लेखनीय परस्पर क्रिया की एक व्यापक खोज के रूप में कार्य करता है। जैसे-जैसे हम इस संकलन के पन्नों में उतरेंगे, पाठक एक विचारोत्तेजक यात्रा पर निकलेंगे जो वैश्विक शासन, कूटनीति और हमारे परस्पर जुड़े विश्व पर G20 के गहन प्रभाव के बहुमुखी आयामों को उजागर करती है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से

मिलकर बना G20 अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए आशा और सहयोग की किरण के रूप में उभरा। आर्थिक संकटों से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों तक, G20 ने संवाद को बढ़ावा देने, आम सहमति बनाने और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक मार्ग तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यायों का यह संग्रह, सावधानीपूर्वक संकलित और संपादित किया गया है, जो अग्रणी विद्वानों, नीति निर्माताओं और विचारकों की अंतर्दृष्टि को एक साथ लाता है, जिन्होंने वैश्विक शासन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए अपनी विशेषज्ञता समर्पित की है। प्रत्येक अध्याय उन प्रमुख विषयों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन और तकनीकी नवाचार से लेकर समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आकार दिया है। इन पृष्ठों के माध्यम से यात्रा कालानुक्रमिक रूप से सामने आती है, जो इस बात की सूक्ष्म समझ प्रदान करती है कि G20 कैसे विकसित हुआ और वैश्विक मामलों के बदलते ज्वार के अनुकूल कैसे हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर, हम इस परिवर्तनकारी दशक को परिभाषित करने वाली विजय और क्लेशों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इस खंड के संपादकों के रूप में, हम उन सम्मानित योगदानकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना ज्ञान, बुद्धि और दृष्टि साझा की है। उनके सामूहिक प्रयासों ने एक ऐसे संग्रह को जन्म दिया है जो न केवल अतीत को दर्शाता है बल्कि भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करने वाले दिशासूचक के रूप में भी काम करता है। हम पाठकों को इन विविध दृष्टिकोणों से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे सीमाओं से परे बातचीत शुरू हो और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिले। "भविष्य को आकार देने का एक दशक" घटनाओं का एक मात्र वृत्तांत नहीं है; यह अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है जो सहयोग, समझ और एक बेहतर दुनिया की निरंतर खोज पर पनपती है। उम्मीद है कि यह पुस्तक वैश्विक सद्भाव, सहयोग और हम सभी के लिए भविष्य को आकार देने में हमारी साझा जिम्मेदारी के आदर्शों के प्रति एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी।

मारलुसिद्दैया, एचएम एट अल. (2015).यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में, भारत के कृषि प्रदर्शन में खुलेपन के बाद लाभ के बहुत कम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हालाँकि, ऐसे लाभ आसानी से हो सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, या अभी तक पहचाने नहीं गए हैं और शायद मापना बहुत कठिन या अमूर्त है। जो भी मामला हो, यह बहुत संभावना है कि वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के पूर्ण प्रभाव का आकलन करना अभी बहुत जल्दी है। निर्यात और व्यापार घरानों के विकास के माध्यम से निर्यात संवर्धन और साथ ही कृषि के लिए निर्यात संवर्धन क्षेत्र योजनाओं को प्रभावी रूप से उदार बनाना हाल ही के उपाय हैं और केवल समय ही बताएगा कि ये उपाय कितने प्रभावी हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि-उद्योग पार्क जैसी अन्य संभावनाएँ भी पाइपलाइन में हैं। निष्कर्ष रूप में, भारत ने वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के जलमार्ग पर सफलतापूर्वक यात्रा की है और आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर भी, भारत को कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लाभों को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक अपना मार्ग निर्देशित करना होगा।

मेन्से, इवान एट अल. (2018).वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा को एक नई दुनिया में धकेल दिया है, जो परिवर्तन, अस्थिरता और अस्पष्टता की दुनिया है, जो तेजी से एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, एक अंतरराष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और उच्च शिक्षा संस्थानों के नियंत्रण से परे अन्य ताकतों द्वारा आकार लेती है। भविष्यवादियों का अनुमान है कि कल की शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणालियों से काफी अलग होगी। वे भविष्यवाणी करते हैं कि शिक्षण और सीखने के लिए नवीन दृष्टिकोण बढ़ेंगे और प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के कारण अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाएंगे। पारंपरिक विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप से मानव पूंजी, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के रूप में ज्ञान के उत्पादक रहे हैं और अब आजीवन सीखने की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने की चुनौती है। उच्च शिक्षा की आवश्यकता और इच्छा बढ़ रही है, लेकिन उच्च शिक्षा को वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की चुनौती है।

देसाई, प्रणव. (2023).हाल के वर्षों में भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई है, जो बढ़ते सांस्कृतिक पदचिह्न, आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक पहुंच से प्रेरित है। बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन और योग अब दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, जबकि भारतीय कंपनियां विदेशों में तेजी से निवेश कर रही हैं। भारत जी20 और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय सॉफ्ट पावर के इस पुनरुत्थान का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है कि भारत को बाकी दुनिया में कैसे देखा जाता है और उसका सम्मान किया जाता है।

सुजंता, जी. एट अल. (2024).वैश्वीकरण, धीरे-धीरे फैलने वाला जोखिम कारक है, जो अपनी पूरी ताकत के साथ लगभग पूरे देश को कवर करता है। साहित्य और साहित्यिक अध्ययन वैश्वीकरण की दुनिया में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विचारों के उद्घोष, प्रचार और व्याख्या के लिए एक स्थान के रूप में विकसित हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय साहित्य ने साहित्यिक लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। आज देश की युवा पीढ़ी एक नई पहचान की तलाश में है और वे व्यक्तित्व, संस्कृति और समाज के चौराहे पर हैं। साहित्य की दुनिया में, कॉल-सेंटर पीढ़ी खुद को भारत के सांस्कृतिक कमिसार के रूप में देखती है, जो भारत को रोशनी और मुक्ति की भूमि के रूप में पेश करती है। युवाओं का प्रमुख सैमसन प्राकृतिक और मानव संसाधनों के असीमित उपभोग के माध्यम से युवाओं की शक्ति में निहित है। सहस्राब्दी के उपन्यास हमें इस मिथक को दूर करने में सहायता करते हैं कि समकालीन लेखन केवल युवा पीढ़ियों के हल्के मनोरंजन के लिए है।

शर्मा, अंशु एट अल. (2019)' यदि आप एक ही पीढ़ी में किसी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे करेंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षित करने के तरीके को बदलेंगे', कैरोल ब्लैक ने समझाया, जिन्होंने स्कूलिंग द वर्ल्ड: द व्हाइट मैन्स लास्ट बर्डन (ब्लैक 2010) नामक डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किया था, जिसमें उन्होंने शिक्षा के मानकों को सुधारने के नाम पर सूक्ष्म उपनिवेशवाद के एक और रूप के रूप में पश्चिमी शिक्षा की भूमिका पर सवाल उठाया

था। यह शोधपत्र सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और इसकी समृद्ध स्वदेशी संस्कृति को छीनने के साधन के रूप में, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, किसी देश की शिक्षा प्रणाली पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इसमें विशेष रूप से शिक्षण के माध्यम, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक परिवर्तन और सीखने के परिणामों पर प्रभाव शामिल है। अतीत में कई विद्वानों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि शिक्षा का उपयोग सामाजिक रूप से देशों पर हावी होने के साधन के रूप में कैसे किया जा सकता है (कार्नोय 1974; बोमन 1976; कूलहान 2001; किंडलर और जॉर्ज 2000)। हालाँकि, कुछ अन्य लोगों ने यह कहते हुए इस दृष्टिकोण की आलोचना की है कि औपनिवेशिक शिक्षा भी प्रबुद्ध पितृसत्तावाद का एक साधन थी (व्हाइटहेड 1995)। फिर भी अन्य लोगों ने पश्चिमी और तीसरी दुनिया के देशों में तुलनात्मक शिक्षा के विकास को समझने के लिए सैद्धांतिक मॉडल बनाए हैं (यांग और गौ 2010)। आलोचनात्मक विश्लेषण इस बात पर कठोर बहस को बढ़ावा देते हैं कि कैसे वैश्वीकरण ने पश्चिमी शिक्षा मॉडल को महिमामंडित किया है और स्थानीय ज्ञान और स्वदेशी शिक्षा मॉडल के मूल्य को कम किया है जो संदर्भ में निहित थे और कहीं अधिक टिकाऊ और समग्र थे। इस प्रकार, अध्याय यह सुझाव देते हुए समाप्त होता है कि शिक्षा के संबंध में वैश्वीकरण की योग्यता तब कम हो जाती है जब स्थानीय/स्वदेशी ज्ञान कमजोर हो जाता है या उसे 'निम्न' करार दिया जाता है। चूंकि संस्कृति और शिक्षा आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं; इसलिए, समग्र विकास के लिए, यह जरूरी है कि स्वदेशी संस्कृति बरकरार रहे। लेखक जागरूकता और अन्य संस्कृतियों से सीखने के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह मूल संस्कृति के कमजोर पड़ने और राष्ट्र के सामूहिक ज्ञान के क्षरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

शोध अंतराल

वैश्वीकरण का भारतीय राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उदारीकरण नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को

दुनिया के लिए खोल दिया है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। हालाँकि, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हाशिए पर भी धकेल दिया है। उदारीकरण की नीतियों के कारण अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर बढ़ गया है। साहित्य समीक्षा भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है। वैश्वीकरण के कारण भारत में नई राजनीतिक ताकतों का उदय हुआ है। मध्यम वर्ग के उदय के कारण मध्यम वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ है।

भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव

अध्याय 3

भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव

3.1 परिच

भूमंडलीकरण यह अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की परस्पर निर्भरता, अंतर्संबंध और एकीकरण को इस हद तक बढ़ाने की प्रक्रिया है कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटना दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोगों को प्रभावित करती है।

वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत दूरगामी है। यह हम सभी को प्रभावित करता है, लेकिन हम पर अलग-अलग तरीके से। इसलिए, जहाँ कुछ लोगों के लिए इसका मतलब नए अवसर हो सकते हैं, वहीं दूसरों के लिए आजीविका का नुकसान।

उदाहरण के लिए, बिहार की महिला रेशम कताई करने वाली और मुड़ने वाली महिलाओं की नौकरियां तब चली गईं जब चीनी और कोरियाई रेशम धागे बाज़ार में आ गए। बुनकर और उपभोक्ता इस धागे को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह कुछ हद तक सस्ता है और इसमें चमक भी है।

भारतीय जल क्षेत्र में बड़े मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रवेश के कारण भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए अवसरों का नुकसान, महिला मछली छांटने वालों, सुखाने वालों, विक्रेताओं आदि की आजीविका का नुकसान।

गुजरात में जूलीफेरा (बावल के पेड़) से गोंद चुनने वाली महिलाएँ सूडान से सस्ते गोंद के आयात के कारण अपना रोज़गार खो बैठीं। भारत के लगभग सभी शहरों में, विकसित देशों से रद्दी कागज़ के आयात के कारण कचरा बीनने वालों का कुछ न कुछ रोज़गार छिन गया।

यह स्पष्ट है कि वैश्वीकरण का सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। हालाँकि, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में इसके प्रभाव के बारे में बहुत ही अलग-अलग विचार हैं। कुछ लोग तर्क देते

हैं कि जबकि अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के कई लोगों को लाभ हो सकता है, पहले से ही वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से की स्थिति खराब हो जाती है। कुछ अन्य लोग तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण बिल्कुल भी नया विकास नहीं है।

वैश्वीकरण कई तरह से संस्कृति को प्रभावित करता है। सदियों से भारत ने सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाया है और इसी वजह से समृद्ध हुआ है। पिछले कुछ दशकों में बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे यह डर पैदा हुआ है कि हमारी स्थानीय संस्कृतियाँ पीछे छूट जाएँगी। इसलिए हमारे समाज में सिर्फ़ राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीत, फ़िल्मों, भाषाओं, शारीरिक भाषा में बदलाव को लेकर भी गरमागरम बहसें होती हैं। यह बहस नई नहीं है और 19वीं सदी के सुधारकों और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने भी संस्कृति और परंपरा पर बहस की थी। आज के मुद्दे कुछ मायनों में वही हैं, कुछ मायनों में अलग। जो शायद अलग है वह है बदलाव का पैमाना और तीव्रता।

3.1.1 संस्कृति का समरूपीकरण बनाम वैश्वीकरण

एक केंद्रीय तर्क यह है कि सभी संस्कृतियाँ समान हो जाएँगी, यानी एकरूप हो जाएँगी। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि संस्कृति के वैश्वीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक को स्थानीय के साथ मिलाना। यह पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त नहीं है। न ही यह वैश्वीकरण के व्यावसायिक हितों से पूरी तरह अलग है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे अक्सर विदेशी कंपनियाँ स्थानीय परंपराओं से निपटते समय अपनी बाज़ार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाती हैं। भारत में, हम पाते हैं कि स्टार, एमटीवी, चैनल वी और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टेलीविज़न चैनल भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड भी भारत में केवल शाकाहारी और चिकन उत्पाद बेचता है, न कि उसके गोमांस उत्पाद, जो विदेशों में लोकप्रिय हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान मैकडॉनल्ड शाकाहारी हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में,

'भांगड़ा पॉप', 'इंडी पॉप', फ्यूजन संगीत और यहाँ तक कि रीमिक्स की लोकप्रियता में वृद्धि देखी जा सकती है।

इससे जुड़ी एक और घटना है जिसे ग्रोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है जिसे रिट्जर (2004) ने गढ़ा है। यह उस चीज को संदर्भित करता है जिसे वह "विकास की अनिवार्यताएं कहते हैं जो संगठनों और राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने और वहां के स्थानीय भूगोल पर खुद को थोपने के लिए प्रेरित करती हैं"। रिट्जर के लिए, वैश्वीकरण 'ग्लोकलाइजेशन' और 'ग्रोबलाइजेशन' का योग है।

3.1.2 संस्कृति का पुनरुद्धार

- **योग का पुनरुद्धार**देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। इसे रविशंकर के 'आर्ट ऑफ लिविंग' कोर्स की लोकप्रियता या फिर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न में देखा जा सकता है।
- देश के साथ-साथ विदेशों में भी आयुर्वेदिक दवाओं का पुनरुत्थान हुआ है।
- बाहरी दुनिया के साथ अंतर्संबंधों के कारण बढ़ती अनिश्चितता के कारण धार्मिक पुनरुत्थानवाद हुआ है। यह मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धर्म के उपयोग या धर्म के आधार पर लोगों को लामबंद करने में प्रकट हो सकता है।
- वैश्विक बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग बढ़ रही है: जैसे चिकनकारी या बांधनी।
- बढ़ते वैश्विक पर्यटन के कारण स्थानीय लोग अपनी विविधता को संरक्षित करने और अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहे हैं।

इन सभी परिवर्तनों के कारण भारतीय संस्कृति में भारी परिवर्तन हुए हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश परिवर्तन शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भी तेजी से इसकी चपेट

में आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रही है, लेकिन यह इसे प्रतिस्थापित नहीं कर रही है, बल्कि दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृति को एक अपरिवर्तनीय निश्चित इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता है जो सामाजिक परिवर्तन का सामना करने पर या तो ढह सकती है या वैसी ही बनी रह सकती है। आज भी यह अधिक संभावना है कि वैश्वीकरण न केवल नई स्थानीय परंपराओं बल्कि वैश्विक परंपराओं के निर्माण की ओर ले जाएगा।

3.2 भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण अलग-अलग जगहों पर महिलाओं के अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है। एक तरफ यह महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अग्रणी बनने के नए अवसर पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह असेंबली लाइन उत्पादन या आउटसोर्सिंग के रूप में सस्ते रास्ते उपलब्ध कराकर नौकरी के अवसरों को छीन सकता है।

वैश्विक संचार नेटवर्क और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आगमन के साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता दिख रहा है, हालांकि यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। वैश्वीकरण ने वास्तव में महिलाओं के लिए समानता के विचारों और मानदंडों को बढ़ावा दिया है, जिससे जागरूकता आई है और समान अधिकारों और अवसरों के लिए उनके संघर्ष में उत्प्रेरक का काम किया है।

हालाँकि, वैश्वीकरण पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ा सकता है, खासकर विकासशील देशों में। आर्थिक क्षेत्र में यह अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में महिलाओं के हाशिए पर जाने या आय के पारंपरिक स्रोतों के नुकसान के कारण गरीबी की ओर ले जा सकता है। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को बढ़ाने में योगदान दिया है।

महिलाओं पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि - व्यापक संचार लाइनें खोली गईं और अधिक कंपनियों के साथ-साथ विभिन्न विश्वव्यापी संगठनों को भारत में लाया गया - इससे महिलाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हुए, जो कार्यबल का बड़ा हिस्सा बन रही हैं

- स्वतंत्रता और आत्मविश्वास - महिलाओं के लिए नई नौकरियों के साथ, उच्च वेतन के अवसर हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और स्वतंत्रता लाता है। इसके अलावा, बढ़ते शहरीकरण के कारण, शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गई हैं। यह अंतर-जातीय विवाह, एकल माताओं, लिव-इन रिलेशनशिप के माध्यम से प्रकट हुआ है।

- उद्यमशीलता के दृष्टिकोण का विकास - निम्न मध्यम वर्ग पारिवारिक संबंधों के तरीके में बदलाव का अनुभव कर रहा है। परंपरागत रूप से महिलाएँ घर पर रहकर घरेलू ज़रूरतों और बच्चों की देखभाल करती थीं। अब ज़्यादातर महिलाएँ जीविकोपार्जन के लिए अपने निजी स्थानों से बाहर निकल रही हैं। उदाहरण के लिए: भारत में स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) उन महिला मज़दूरों का संघ है जो कड़ी मेहनत करने और मिलने वाले किसी भी काम के अवसर को भुनाने के लिए तैयार हैं।

- नारीवादी आंदोलन का प्रसार - वैश्वीकरण के कारण नारीवादी आंदोलन भारत में भी फैल गया है, जिससे महिलाएं अपने विचारों के प्रति अधिक मुखर हो गई हैं। हाल ही में, नारीवाद की चौथी लहर जो कार्यस्थल पर समानता और भेदभाव की रोकथाम की मांग करती है, दुनिया भर में और भारत में "मी टू" अभियान के रूप में प्रकट हुई।

- शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में सुधार - वैश्वीकरण के कारण महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, इससे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिससे MMR और IMR में कमी आई है

- कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण - दुनिया भर से विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों को

भारत लाया गया है। इन संगठनों ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी कौशल प्रदान किए हैं, जैसे साक्षरता और व्यावसायिक कौशल।

- ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव - ग्रामीण परिवेश की महिलाएं मीडिया और गैर-लाभकारी संगठनों जैसे अनेक हस्तक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्वीकरण से प्रभावित हुई हैं, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया है।

- सांस्कृतिक परिवर्तन - महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन - पश्चिमी कपड़ों की अधिक स्वीकार्यता, शहरी क्षेत्रों में डेटिंग आम हो गई है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गर्भनिरोधक का उपयोग बढ़ गया है।

महिलाओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- रोजगार और कार्यस्थल से जुड़े मुद्दे - हालांकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे ज्यादातर कम वेतन वाली नौकरियों में ही व्यस्त हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा भी कम है। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण एक नया मुद्दा बनकर उभरा है

- दोहरी जिम्मेदारी - महिलाओं को दो तरह से कष्ट उठाना पड़ रहा है। विकासशील देशों में महिलाएँ जैसे-जैसे कार्यबल में शामिल होती हैं, उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ कम नहीं होती हैं। महिलाएँ दो पूर्णकालिक नौकरियाँ करती हैं।

- महिलाओं का वस्तुकरण - वैश्वीकरण के साथ भारतीयों की पितृसत्तात्मक मानसिकता कायम रही है, जिसके कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे महिलाओं का वस्तुकरण, महिलाओं को परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि।

- उपभोक्ता के रूप में, महिलाओं को उपभोक्ता संस्कृति का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें वस्तुओं तक सीमित कर देती है और उत्पादक के रूप में, महिलाओं को काम के दौरान

शोषण और व्यावसायिक खतरों का सामना करना पड़ता है

- इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के बावजूद वेश्यावृत्ति, दुर्व्यवहार और दहेज संबंधी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।

3.3 भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण स्पष्ट आर्थिक अवसर और लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही पर्याप्त सामाजिक लागत भी आती है, जो अक्सर युवा लोगों को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि अनिश्चित और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक संदर्भ में उनकी स्थिति संक्रमणकालीन है।

भारत की अधिकांश आबादी युवा है। युवाओं के बीच जनसंख्या वृद्धि वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारतीय युवा वैश्वीकरण के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे वैश्वीकरण को ऐसे तरीके से अपना रहे हैं जिसकी पिछली पीढ़ी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

युवाओं पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- **शिक्षा और उद्यम :**छोटे से छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक के युवा भारतीयों की प्राथमिक महत्वाकांक्षा "अमीर बनना" है। युवा लोग उद्यम और शिक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे सबसे उच्च प्रतिष्ठित करियर उच्च तकनीक और मीडिया में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे हैं।

- **वैश्विक किशोर बनना:** भारत को प्रभावित करने वाली गतिशील, वैश्विक, आर्थिक शक्तियों के अलावा, वैश्वीकरण ने भारत की समृद्ध संस्कृति में भी बदलाव लाया है। युवा खुद को वैश्विक किशोरों के रूप में देखते हैं। वे जिस समुदाय में पैदा हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। युवा पीढ़ी पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति को अपना रही है और इसे

अपनी भारतीय पहचान में शामिल कर रही है। पश्चिमी और भारतीय मूल्यों का एक सूक्ष्म और शक्तिशाली संकरण हो रहा है - जो विशेष रूप से भारतीय युवाओं में स्पष्ट है।

- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** आज के युवा अपनी भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक रूप से अधिक जागरूक विचारों के साथ धीरे-धीरे सादगीपूर्ण तरीकों और प्रतिबंधित पारंपरिक भारतीय बाजारों को त्याग रहे हैं। युवा एक अधिक महानगरीय समाज की मांग करते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूर्ण सदस्य हो।

- **धर्म के प्रति दृष्टिकोण:** युवाओं के लिए ज़्यादातर धार्मिक गतिविधियाँ अप्रासंगिक होती जा रही हैं। वे धर्म में बदलाव देखना चाहते हैं। वे पारंपरिक विचारों को आत्मसात नहीं कर रहे हैं; बल्कि, वे उन्हें सिर्फ़ सहन कर रहे हैं। हालाँकि, उन्हें धर्म में कुछ अप्रत्यक्ष मूल्य ज़रूर मिलते हैं।

युवाओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- **शहरी गरीबी में वृद्धि:**आर्थिक वैश्वीकरण के कारण शहरी गरीबी बढ़ी है क्योंकि लोग अवसर की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरी प्रवासियों में युवा वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन शहरी केंद्रों में युवाओं को उच्च स्तर की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। युवा प्रवासियों को शहरों में धकेला जाता है और खींचा जाता है, लेकिन उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में तनाव का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अभाव में कई युवा दुर्लभ संसाधनों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होते हैं जो अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं। धार्मिक, नागरिक और जातीय संघर्ष भी शहरों में उपलब्ध आर्थिक समृद्धि को कमजोर करते हैं, जिसमें अक्सर युवा लोग सीधे तौर पर शामिल होते हैं।

- **उपभोक्तावादी रवैया:** उपभोक्तावाद ने भारतीय लोगों की पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं में घुसपैठ की है और उन्हें बदल दिया है। पारंपरिक भारतीय पोशाक में कमी आ रही है,

खासकर शहरी युवाओं में, जो पश्चिम के नए फैशन के पक्ष में हैं। नवीनतम कारें, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फैशनेबल कपड़े खरीदना काफी लोकप्रिय हो गया है। युवा गरीब आबादी विशेष रूप से विज्ञापनों में देखे जाने वाले महंगे उत्पादों के आकर्षण के प्रति संवेदनशील है और जब वे इन विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं।

- **परिवार में युवाओं की स्थिति:** वैश्वीकरण के कारण पारिवारिक संस्थाएँ भी बदल रही हैं, और एकल परिवार का चलन बढ़ता जा रहा है। युवा अपने दादा-दादी के उतने करीब नहीं हैं, जितने पिछली पीढ़ियाँ थीं और वे पुरानी पीढ़ी के साथ कम समय बिताते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान का ह्रास हो रहा है।

अवसाद और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि: वैश्वीकरण के कारण युवाओं में अनिश्चितता बढ़ी है; यह अंतर्निहित अस्थिरता उन तनावों और नियंत्रण की कमी को बढ़ा सकती है जो वे दैनिक आधार पर अनुभव करते हैं। अनिश्चितता पारंपरिक मानदंडों के टूटने, परिवार और विवाह जैसे सामाजिक संबंधों के कमजोर होने, बाजार अर्थव्यवस्था के कारण करियर में अनिश्चितता के कारण है। इससे युवाओं में अवसाद और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन मिश्रित रूप में किया जाता है, जो अच्छा और बुरा दोनों है। आर्थिक वैश्वीकरण ने अध्ययन और नौकरी के अवसरों में सुधार किया है और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। लेकिन इसने गरीबों को और भी गरीब बना दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वीकरण से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। युवा आधुनिक, प्रगतिशील होने और समाज का हिस्सा बनने का अवसर पाकर खुश हैं।

3.4 परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव

परंपरागत रूप से भारत में समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज में जीवन के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं

और हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण परिवार धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ रहा है।

परिवार की संरचना

- संयुक्त परिवार का विघटन - नए रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश में युवा पीढ़ी की बढ़ती गतिशीलता ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। इससे संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। संयुक्त/विस्तारित परिवारों से एकल परिवार पैटर्न में पारिवारिक संरचना में धीरे-धीरे बदलाव आया है।

- **परिवार के नए रूप उभर रहे हैं**उदाहरण के लिए एकल अभिभावक वाले परिवार, लिव-इन रिलेशनशिप, महिला मुखिया वाले परिवार, दोहरी नौकरी वाले परिवार (पति और पत्नी दोनों कामकाजी), समान लिंग वाले जोड़े आदि।

परिवार के कार्य

- शारीरिक दूरी के कारण पारिवारिक बंधन और रिश्ते कमजोर पड़ने लगे हैं क्योंकि परिवार के सदस्यों का पहले की तरह एक साथ आना असंभव हो गया है। इससे बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल और पोषण करने वाली इकाई के रूप में 'परिवार' की पहले की आदर्श धारणा प्रभावित हुई है।

- कार्यबल प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण परिवारों में वृद्धों की देखभाल में कमी आई है।

- **साझेदार ढूँढना**युवा पीढ़ी 'शादी डॉट कॉम', भारत मैट्रिमोनी जैसी इंटरनेट विवाह साइटों पर निर्भर होने लगी है। दूल्हा/दुल्हन खोजने में परिवार की भागीदारी कम होती जा रही है। हालाँकि, भारतीय समाज में अरेंज मैरिज की परंपरा अभी भी प्रासंगिक है।

- परंपरागत रूप से परिवार युवा पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने की भूमिका निभाता था।

लेकिन श्रम के बढ़ते विभाजन और कार्य की विशेषज्ञता के कारण यह भूमिका विशिष्ट संस्थानों ने ले ली है।

- हालाँकि, परिवार के कार्यों में परिवर्तन के बावजूद, आज भी कुछ कार्य अभी भी परिवार के लिए विशिष्ट हैं: i) बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, ii) सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी

अंतर-वैयक्तिक संबंध

- **पारंपरिक प्राधिकरण संरचना बदल गई है**परिवार के मुखिया - पिता/दादा, परिवार के कमाने वाले के सामने अपना अधिकार खोने लगे हैं।

- एकल परिवारों में वैवाहिक नियमों और शक्तियों के वितरण में परिवर्तन आया है।

- महिलाओं की पुरुषों के प्रति पूर्ण अधीनता तथा बच्चों के प्रति पिता की कठोर अनुशासनात्मक भूमिका बदल रही है।

- **युवा पीढ़ी में व्यक्तिवाद बढ़ रहा है**उनमें से कई लोग कुल मिलाकर विश्वास नहीं करते हैं

अपने व्यक्तिगत हितों को पारिवारिक हितों के लिए समर्पित करना।

- हालाँकि, प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण दूरदराज के रिश्तेदारों के साथ सम्पर्क में सुधार हुआ है।

पारंपरिक जाति व्यवस्था पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं:

1. पदानुक्रम
2. संपर्क का पृथक्करण
3. श्रम का व्यावसायिक विभाजन

- **जाति व्यवस्था का कमजोर होना**- वैश्वीकरण के कारण आर्थिक अवसरों, शिक्षा और उदार विचारों का विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था कमजोर हुई है।

- **अंतरजातीय विवाह की स्वीकृति**- अंतरजातीय विवाह अधिक आम होते जा रहे हैं और धीरे-धीरे स्वीकार किए जा रहे हैं

- **जाति मुक्त श्रम विभाजन**- औद्योगीकरण के कारण पारंपरिक श्रम विभाजन टूट रहा था, जिसे वैश्वीकरण ने बढ़ावा दिया।

- **जातिवाद की भावना में कमी**- आधुनिक संचार सुविधाओं के बढ़ते उपयोग, विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच बढ़ते संपर्क के कारण जातिवाद की भावना में कमी आई है।

- **धर्मनिरपेक्ष जीवनशैली**- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे धर्मनिरपेक्ष जीवनशैली को बढ़ावा मिला है और इस प्रकार जाति व्यवस्था के "संपर्क पृथक्करण" पहलू पर प्रभाव पड़ा है।

हालाँकि, परिवर्तनों के बावजूद, जाति व्यवस्था ने काफी लचीलापन दिखाया है और अभी भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विद्यमान है।

3.5 कोविड-19 के संदर्भ में वैश्वीकरण

वैश्वीकरण दुनिया को एक वैश्विक गांव में एकीकृत करने की आकांक्षा के रूप में उभरा, और इसके बाद दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयामों को बदल दिया। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के समय में इसे एक गंभीर झटका लगा। कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकृत दुनिया की कमज़ोरियों को उजागर किया। महामारी ने देशों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी निवेश, चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया। इसने संरक्षणवाद, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद की एक नई लहर को जन्म दिया। लेकिन इस संकट से निपटने और कोविड के बाद की दुनिया के लिए खुद को तैयार करने के लिए, एक वैश्वीकृत प्रतिक्रिया ही आगे का रास्ता है।

वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृतियों के पार उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों का प्रसार है। आर्थिक वैश्वीकरण में सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, टैरिफ और व्यापार बाधाओं में कमी, आप्रवासन और सीमाओं से परे प्रौद्योगिकी और ज्ञान का प्रसार शामिल है। इसके उद्भव के बाद से, कई अध्ययनों में घरेलू संसाधनों के प्रभावी आवंटन, प्रौद्योगिकी के प्रसार, कारक उत्पादकता में सुधार और पूंजी के संवर्द्धन के माध्यम से विकास पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पाए गए हैं।

हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान संकट ने "ग्लोबल विलेज" की कुछ कमज़ोरियों को उजागर किया है। पिछले कुछ वर्षों से, वैश्वीकरण के आसन्न पतन का मतलब यह है कि यह प्रणाली पहले से ही टूटने के बिंदु पर पहुँच चुकी है। महामारी से पहले भी, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में आर्थिक असंतोष से प्रेरित लोकलुभावनवाद की बढ़ती लहर ने वैश्वीकरण को चुनौती दी थी। इसके अलावा, महामारी ऐसे समय में आई जब अंतर-राज्यीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार युद्धों में वृद्धि हुई, जिसने वैश्वीकरण के लिए आधार के रूप में काम करने वाले विश्वास को खत्म कर दिया। इस अर्थ में, महामारी वैश्वीकरण के लिए नवीनतम और, जैसा कि तर्क दिया जाता है, अंतिम झटका है। इस संदर्भ में, यह लेख वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों और कोविड-19 महामारी के कारण उनमें होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

संरक्षणवाद

दुनिया का आर्थिक एकीकरण वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, जिसने दुनिया भर में व्यापार, निवेश और व्यावसायिक संस्थाओं के मुक्त प्रवाह पर जोर दिया। 1990 के दशक से, इसके परिणामस्वरूप आपस में जुड़े बाजार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ। हालाँकि, कोविड-19 संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को एकीकरण से संरक्षणवाद की ओर बदल दिया है।

संरक्षणवाद घरेलू उद्योगों को टैरिफ, सब्सिडी, आयात कोटा या अन्य प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने की नीति है। पिछले कुछ वर्षों से संरक्षणवाद बढ़ रहा था, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, कई देशों में सख्त आव्रजन नियम और BREXIT इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में इस संरक्षणवाद को और बल मिला, जब देशों ने सुरक्षात्मक गियर, मास्क, दस्ताने, दवाइयों और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। इसी तरह, खाद्य पदार्थों के व्यापार में गिरावट का रुख देखने को मिलेगा क्योंकि देश खाद्य निर्यात को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ऐसी चिंताएं हैं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा दबाव में आ सकती है।

अप्रैल 2020 में भारत की नई एफडीआई नीति ने अपने पड़ोसी देशों से स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर प्रतिबंध लगा दिए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, यह नीति भारतीय कंपनियों को "मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/अधिग्रहण" से बचाने के लिए है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप और प्रसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। महामारी के फैलने के परिदृश्यों के साथ अल्पकालिक स्थिरीकरण से लेकर पूरे वर्ष जारी रहने तक, एफडीआई पर नीचे की ओर दबाव -पांच प्रतिशत से -15 प्रतिशत होगा (2020-2021 के लिए एफडीआई प्रवृत्ति में मामूली वृद्धि का अनुमान लगाने वाले पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में)।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं ऐसे नेटवर्क हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की सोर्सिंग और आपूर्ति के उद्देश्य से कई महाद्वीपों और देशों में फैले हो सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में दुनिया भर में सूचना, प्रक्रियाओं और संसाधनों का प्रवाह शामिल होता है। कम लागत वाले देश की

सोर्सिंग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है और इसका मतलब है कि उन देशों से उत्पादों और सेवाओं की खरीद करना जहां घरेलू देश की तुलना में कम श्रम दर और कम उत्पादन लागत है।

कोविड-19 संकट का उन निगमों और व्यवसायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा समर्थित आर्थिक अंतर-निर्भरता से लाभ हुआ है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन आधार है और कई आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित है। इस कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से, चीन पर निर्भर होने वाली कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी सबसे कमजोर कड़ी। किसी भी स्तर पर कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, या पैकेजिंग में किसी भी बिंदु पर एक भी चूक मुख्य इकाई के पूरे उत्पादन को बाधित करती है। उदाहरण के लिए, भारत अपने सक्रिय फार्मा अवयवों का लगभग 70 प्रतिशत आयात करता है - जिसे चीन से थोक दवाओं के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी आपूर्ति महामारी के दौरान बंद हो गई थी, और भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने में असमर्थ था, जबकि दुनिया भर में इसकी उच्च मांग थी।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए वैश्विक मंच ट्रेडशिफ्ट के हालिया डेटा से व्यापार और मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की भयावहता का पता चलता है। यह सुझाव देता है कि शुरुआती झटके के प्रभाव आने वाले महीनों तक बने रह सकते हैं। चीन में, फरवरी के मध्य से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में सप्ताह-दर-सप्ताह 56 प्रतिशत की गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप ने भी यही किया, अप्रैल की शुरुआत में संयुक्त रूप से 26 प्रतिशत की गिरावट आई और अप्रैल के अंत में 17 प्रतिशत की गिरावट जारी रही।

इसके अलावा, लॉकडाउन से प्रभावित हर क्षेत्र में व्यापार ठप हो गया है। 9 मार्च से ट्रेडशिफ्ट प्लेटफॉर्म पर कुल साप्ताहिक लेन-देन में लॉकडाउन से पहले के आंकड़ों की तुलना में औसतन

9.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, साथ ही मार्च के अंत से चालान और ऑर्डर में भी स्पष्ट गिरावट आई है।

कोविड-19 ने लीन मैन्युफैक्चरिंग सिद्धांतों पर निर्मित जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया है। चीन के लॉकडाउन के प्रभाव और विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्रों में इसके प्रभुत्व ने आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्या को और उजागर किया है। जब चीनी कारखाने बंद हो गए, तो निर्माताओं को अपने आपूर्तिकर्ता आधार में लचीलेपन की कमी के कारण बदलाव करने में संघर्ष करना पड़ा। एक संभावित परिणाम यह है कि वैश्विक फर्म अब केवल चीन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाएँगी। वियतनाम, मैक्सिको और भारत जैसे विनिर्माण केंद्रों को इस बदलाव से लाभ होने की संभावना है।

उम्मीद है कि कोविड संकट के बाद नीति निर्माता और अधिकारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण पर विचार करेंगे जो स्थानीय आपूर्ति केंद्र से बेहतर तरीके से जुड़ी हुई हैं। अधिक स्थानीय आपूर्ति भी चपलता को बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनियाँ स्थानीय मांग में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। वे बिचौलियों के बजाय सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेच और वितरित कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशों में उत्पादन आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी कंपनियों के दृष्टिकोण में बदलाव पर भी जोर दिया।

इसने स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया है जो सस्ते विदेशी आयात के कारण टिक नहीं पा रहे थे और आवश्यक उत्पादों के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भरता को कम से कम कर रहे थे। घरेलू सुविधाओं के पक्ष में वैश्विक रूप से फैले उत्पादन आधारों से वापस जाने की दिशा में तेज़ रुझान है। देश अब अधिक स्पष्टता के साथ आयात प्रतिस्थापन को देखने के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुन: कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि विदेशी आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता के खतरे और नुकसान स्पष्ट हो गए हैं। देश वैश्वीकरण की तुलना में स्थानीयकरण पर जोर दे रहे हैं। यह भारत के प्रधान मंत्री के भाषण में भारत के आत्मनिर्भर भारत के

दृष्टिकोण और नागरिकों के "स्थानीय के लिए मुखर" होने के रूप में परिलक्षित होता है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का समर्थन और 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडरों के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास

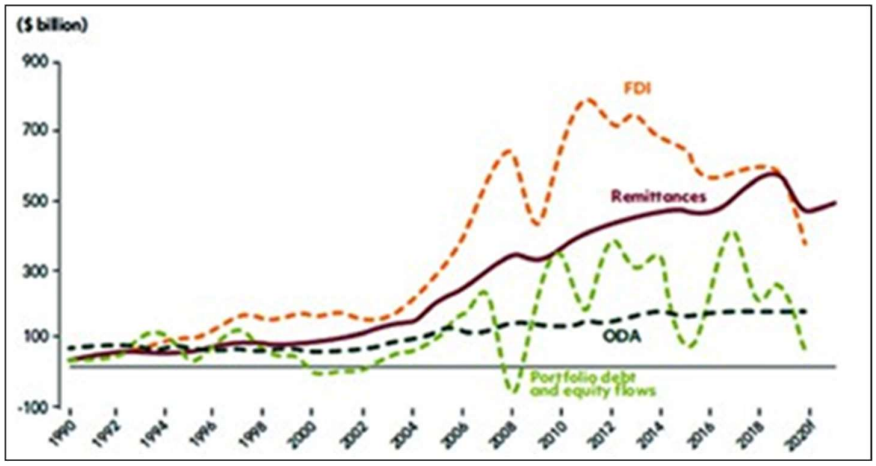
सीमाओं के पार लोगों का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय ने बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में लोगों के इस तरह के आवागमन को और बढ़ावा दिया है। इसने वैश्विक नागरिकों के नए वर्ग को जन्म दिया है। भारत और चीन जैसे विकासशील देश ऐसे प्रवासियों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं। वे न केवल अपने देश में धन वापस लाते हैं बल्कि अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क के रूप में भी काम करते हैं।

हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल अपनी नौकरी खो दी, बल्कि इन देशों में उच्च जीवन-यापन लागत और सामाजिक सुरक्षा जाल की अनुपस्थिति के कारण अस्तित्व के संकट का भी सामना किया। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, देशों ने अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए अपने मिशन भेजे, जिनमें कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक, विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, पर्यटक आदि शामिल थे। 18 जनवरी से 23 मार्च, 2020 के बीच लगभग 15 लाख लोग भारत लौट आए। इसने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित किया है, उनमें से कई कोविड-19 के बाद फिर से विदेश जाने के लिए कम इच्छुक होंगे।

दूसरी ओर, अमेरिका[10] के अलावा कई देशों ने पहले ही विदेशियों के लिए प्रवेश को बंद कर दिया है या बहुत सीमित कर दिया है - और महामारी के सबसे बुरे दौर के बीत जाने के बाद उनमें से कई प्रतिबंध इतनी आसानी से नहीं हटाए जाएँगे। महामारी के फिर से उभरने में योगदान देने वाले अप्रवास की क्षमता के बारे में देश भयभीत होंगे। साथ ही, लंबे लॉकडाउन के

कारण, 1930 के दशक की महामंदी के बाद से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी दर चरम पर है। इस संदर्भ में, विकसित देश निकट भविष्य में अन्य नागरिकों के लिए नौकरी की कमी से बचने के लिए अन्य देशों पर कार्य वीजा प्रतिबंध लगाकर स्थानीय कार्यबल की रोजगार मांग को पूरा करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे।

2020 में, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में धन प्रेषण प्रवाह में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है, जो हाल के इतिहास में सबसे तीव्र गिरावट को दर्शाता है (चित्र 3.1) ।



चित्र 3.1: 2020 में (एलएमआईसी) को धन प्रेषण प्रवाह में गिरावट की उम्मीद है

स्रोत: कोविड-19 संकट प्रवासन के नजरिए से।

संस्कृति

कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के अलावा, इसने उभरती वैश्विक संस्कृति को भी प्रभावित किया है। 1990 के दशक से वैश्वीकरण ने परंपराओं, संस्कृति, खान-पान की आदतों, पहनावे आदि के मामले में विकासशील देशों के समाज को काफी हद तक बदल दिया है। पश्चिमीकरण जो विकासशील देशों का अभिन्न अंग बन गया है, महामारी के दौरान कई लोगों ने इस संकट से निपटने में असमर्थता के लिए इस पर सवाल उठाए हैं।

देश अपने पारंपरिक ज्ञान के ग्रंथों की तलाश में भीतर की ओर देख रहे हैं। भारत के मामले में, "हाथ मिलाने" की जगह "नमस्ते" की प्रशंसा; आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों और च्यवनप्राश के लिए दिशा-निर्देश जारी किए; राष्ट्रीय टीवी पर रामायण के पुनः प्रसारण ने सबसे अधिक टीआरपी रेटिंग दर्ज की, यहाँ तक कि सबसे अधिक देखे जाने वाले मनोरंजन शो को भी पीछे छोड़ दिया; खादी मास्क की बढ़ती मांग और लॉकडाउन के दौरान जिम की तुलना में योग और ध्यान को बढ़ती प्राथमिकता इस बदलाव को दर्शाती है। श्रीलंका, अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों में भी इसी तरह के रुझान देखे जा सकते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण कोविड-19 महामारी में वैश्वीकरण के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। वैश्वीकरण के खिलाफ हाल ही में हुई प्रतिक्रिया कोई नई घटना नहीं है। अतीत में, 2003 में SARS, 2008 में सबप्राइम संकट, 2009 में H1N1 आदि के दौरान वैश्वीकरण पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन यह बच गया। जबकि महामारी वैश्वीकरण के तंत्र को बदल देगी, लेकिन यह वैश्वीकरण की मृत्यु की घंटी नहीं बजाएगी।

भले ही कोविड-19 महामारी ने वैश्वीकृत दुनिया की कमज़ोरियों को उजागर किया है, लेकिन इसका महत्व पहले से कहीं ज़्यादा है। कोविड-19 महामारी के बाद, दुनिया को खाद्य सुरक्षा, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, बहुआयामी गरीबी में वृद्धि, वैश्विक मंदी, हाशिए पर पड़े वर्गों के टीकाकरण आदि के संकट का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, एक एकीकृत वैश्वीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जिसे मज़बूत और सुधारित बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जाए। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी सरकारी प्रतिक्रिया की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सामाजिक वैश्वीकरण पर COVID-19 महामारी के प्रभाव

कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद सीमा बंद होना, सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी उपाय गंभीर रूप से अंतर्राष्ट्रीय और देश के बाहर प्रवास और पर्यटन को प्रतिबंधित कर दिया।

उन्होंने यात्रा के जोखिमों और यात्रा की चिंता की धारणाओं को बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए कोविड-19 महामारी के स्पष्ट प्रभावों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक स्तर पर आगमन की संख्या 2019 में कुल 1465.5 मिलियन आगमन से घटकर 2020 में 405.2 मिलियन आगमन हो गई और 2021 में 426.9 मिलियन आगमन पर अपेक्षाकृत कम रही, जिसके बाद के वर्षों में इसमें सुधार हुआ। इस संदर्भ में, बिकले एट अल ने पाया कि अधिक वैश्विक देशों के मामले में यात्रा प्रतिबंध आम तौर पर अधिक स्पष्ट थे।

विभिन्न राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों के बीच प्रत्यक्ष पारस्परिक संपर्क पर परिणामी सीमाओं ने सामाजिक वैश्वीकरण की सीमा को सीमित कर दिया है। मेजबान देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों और विदेशी श्रमिकों पर असंगत रूप से प्रभाव पड़ा है; इन स्थितियों ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को सीमित करके, नौकरी के नुकसान का कारण बनकर और अपने मूल देशों में लौटने की आवश्यकता के कारण उनके कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा, महामारी ने कई देशों में आव्रजन कार्यक्रमों को बाधित किया है और अन्य देशों को प्रवास के संबंध में प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, सीमा बंद होने से कनाडा के आव्रजन और अस्थायी श्रमिक कार्यक्रम बाधित हुए और प्रवासियों और विदेशी श्रमिकों की आमद प्रभावित हुई। इस बीच, कई (पश्चिमी) यूरोपीय संघ के देशों में स्वास्थ्य उपायों ने पूर्वी यूरोपीय संघ के देशों (जैसे, बुल्गारिया और रोमानिया) से मौसमी श्रमिकों के आवक प्रवास को प्रभावित किया।

कोविड-19 महामारी के दौरान कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रद्द या स्थगित कर दिए गए। उदाहरण के लिए, खेलों में, टोक्यो में 2020 ओलंपिक खेलों को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) ने अपना सत्र रोक दिया, 2020 यूरोपीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप रद्द कर दी गई और 2020 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी लीग दर्शकों के बिना आयोजित की गई। महामारी ने सांस्कृतिक मार्गों तक पहुँच को भी प्रतिबंधित कर दिया और

कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के कार्यक्रमों को विकृत कर दिया। इन प्रतिबंधों को बाद के वर्षों में कम किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की पहुँच और कार्यक्रम को फिर से स्थापित किया गया।

कोविड-19 महामारी ने सामान्य रूप से वैश्वीकरण और विदेशी नागरिकों, आव्रजन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों के बारे में आबादी के कुछ हिस्सों के विकृत विचारों के माध्यम से व्यक्त नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए हैं। इस संदर्भ में, बार्टोस एट अल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेजबान देशों पर महामारी के प्रभाव ने विदेशी विरोधी भावनाओं को कैसे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ज्यादातर कोविड-19 से प्रेरित आर्थिक संकट और राजनीतिक धाराओं और बयानबाजी से प्रेरित हैं जो राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद को बढ़ावा देती हैं। ये प्रवृत्तियाँ अंततः राजनीतिक परिवर्तनों और परिणामों को जन्म दे सकती हैं जो कठोर आव्रजन/यात्रा नीतियों की विशेषता रखती हैं और जो अधिक सांस्कृतिक एकांत और कुछ मामलों में, जातीयतावाद की ओर एक सामान्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं।

सीमा बंद होने, कारावास और सामाजिक दूरी के जवाब के रूप में प्रकोप के साथ आए डिजिटल परिवर्तन ने सामाजिक वैश्वीकरण पर कोविड-19 महामारी के अल्पकालिक नकारात्मक प्रभावों को कम किया है। डिजिटल नवाचार और प्लेटफ़ॉर्म ने मूल रूप से एक वैकल्पिक चैनल का गठन किया है जो अंतर्राष्ट्रीय संचार, सूचना प्रवाह और सांस्कृतिक/सामाजिक संपर्कों की सुरक्षा करता है। ये अनुकूल प्रभाव सामाजिक वैश्वीकरण के कोविड-19 के बाद के पैटर्न को उत्तेजित करने में प्रकोप अवधि को पार करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल परिवर्तन ने पारंपरिक आमने-सामने की बातचीत और जीवनशैली को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि यह शारीरिक अलगाव को बढ़ावा देता है जो महामारी अवधि से परे तक फैल सकता है। ये संशोधन पारस्परिक संपर्क और संचार की शैली में बदलाव के साथ सामाजिक वैश्वीकरण की विशेषताओं को संशोधित कर सकते हैं।

राजनीतिक वैश्वीकरण पर COVID-19 महामारी के प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने शुरू में संरक्षणवादी उपायों, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और विदेशी देशों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दिया, और इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और वैश्विक शासन के लिए चुनौतियां पेश की हैं। पारंपरिक वैश्विक राजनीतिक अंतर्क्रियाओं में बदलाव आया है, और शांति और सुरक्षा बनाए रखने और आर्थिक विकास और व्यापार खुलेपन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र) की भूमिका को चुनौती दी गई है। लेवी [126] ने कहा कि वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को महामारी से पहले महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो लोकलुभावनवाद के उदय और उदारवाद के लुप्त होने से उपजी हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक शासन और राजनीतिक वैश्वीकरण के पाठ्यक्रम को और भी अधिक विचलित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक कोविड-19 संकट को कैसे प्रबंधित किया, इस बारे में आलोचकों की एक विस्तृत श्रृंखला रही है, जिससे सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और अधिक संदेह पैदा हुआ है। इस स्थिति के बीच, कई देशों (जैसे, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन [आसियान] के सदस्य देशों) ने महामारी संकट के प्रबंधन में क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर भरोसा किया, जिससे संभावित रूप से विश्व अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति में और अधिक क्षेत्रीयकरण की दिशा में एक मार्ग शुरू हुआ।

कोविड-19 महामारी ने देशों के बीच राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा दिया है, और इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्य गिरावट को प्रेरित किया है और कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक अशांति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, महामारी को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के कारण चीन और अमेरिका के बीच राजनीतिक मतभेद और व्यापार तनाव बढ़ गया। इसके अलावा, ब्रेक्सिट के शुरुआती निहितार्थ कोविड-19 के कारण यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच सीमा जांच विवादों के कारण बढ़ गए थे।

ऐसे संकेत हैं कि इस महामारी के कारण कई विकासशील देशों में सशस्त्र संघर्षों में वृद्धि हुई है। इन परिणामों का स्वाभाविक रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के लिए दूरगामी और अलग-अलग प्रभाव पड़ता है; वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालते हैं, लोगों और पूंजी की सीमा पार आवाजाही और विचारों और सूचनाओं के वैश्विक प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग और समन्वय को कम करते हैं।

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न किया है और सामाजिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, क्योंकि कई सरकारों ने ऐसे उपाय पेश किए हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं। इस तरह के उपाय सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के साथ प्रतिकूल रूप से जुड़ते हैं और संभावित रूप से व्यावसायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हुए आर्थिक वैश्विक एकीकरण पर सीमाएं लगा सकते हैं और वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अंतर्संबंध को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा, सूचना तक पहुँच पर प्रतिबंध और गिरफ़्तारी/आरोपों, मौखिक/शारीरिक हमलों और सेंसरशिप की घटनाओं में वृद्धि के माध्यम से कई देशों में मीडिया की स्वतंत्रता का लगातार उल्लंघन हुआ है। इन घटनाओं ने लोकतांत्रिक प्रणालियों और संस्थानों के लिए चुनौतियाँ खड़ी की हैं और मानवाधिकारों, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के प्रति उपेक्षा पैदा की है।

वैश्वीकरण के लिए COVID-19 महामारी के दीर्घकालिक निहितार्थ

वैश्वीकरण के पैटर्न और सरकारी प्रतिक्रियाएँ

कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले, वैश्वीकरण की लहरों में कमी के कुछ संकेत थे, जैसा कि राष्ट्रीय संरक्षणवादी नीतियों और सीमा नियंत्रणों के प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण योजनाओं में ठहराव, विदेशी पूंजी प्रवाह में वैश्विक कमी और राष्ट्रवाद और लोकलुभावन आंदोलनों में वृद्धि के माध्यम से व्यक्त किया गया था। कोविड-19 से पहले की ये स्थितियाँ

कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुईं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना (ब्रेक्सिट), और चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक/राजनीतिक तनाव। ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी ने निरंतर/उभरते आर्थिक/राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन और राजनीति और नीतियों में राष्ट्रवाद/लोकलुभावनवाद की और खुराक के साथ इन पैटर्न को बढ़ावा दिया है। इसने स्वास्थ्य, राजनीतिक और आर्थिक उपायों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभाजित करने में और योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य शुरू में वायरस के प्रसार को सीमित करना और राजनीति और समाज में राष्ट्रवादी/लोकलुभावन प्रवृत्तियों के सामान्यीकरण के माध्यम से था। ये स्थितियां वैश्वीकरण के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ दर्शाती हैं, और इस प्रकार, कोविड के बाद वैश्वीकरण का परिमाण संभवतः वैश्वीकरण के उस काल्पनिक स्तर से नीचे हो जाएगा जो महामारी की अनुपस्थिति में हुआ होता।

कई सरकारों ने कोविड-19 महामारी का जवाब अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने की दिशा में अपनी राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों को संशोधित करके, और राष्ट्रीय राजनीतिक संप्रभुता को बढ़ावा देकर और घरेलू उत्पादन की ओर इशारा करके दिया। उन्होंने महामारी के दौरान अपने प्राकृतिक क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया। यह ध्यान अक्सर वैश्विक आर्थिक रुझानों और बहुपक्षीय ढांचे के साथ उनके व्यापक जुड़ाव की कीमत पर आया। अपने तत्काल भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करके, उन्होंने वैश्विक/बहुपक्षीय आर्थिक प्रणालियों से जुड़ी जटिलताओं और साझा प्रतिबद्धताओं से दूर जाने का संकेत दिया, इसके बजाय वैश्विक बहिर्जात झटकों के प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय साझेदारी का पक्ष लिया। इस संदर्भ में, एंडरविक और बकले [35] ने कहा कि महामारी के प्रकोप से पहले ही वैश्वीकरण की सीमा बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, और क्षेत्रीयकरण पर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था एक व्यवहार्य विकल्प होगी। कुछ मामलों में, महामारी के दबाव ने कई सरकारों

को उपायों और नीतियों को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और यूएन) की अवहेलना करने के लिए प्रेरित किया है। ये परिस्थितियाँ मिसाल कायम करेंगी, और वे अंततः भविष्य के बहुपक्षीय समन्वय और सहयोग की सीमा और आर्थिक और राजनीतिक विवादों को निपटाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को चुनौती देंगी। वे उपयुक्त वैश्विक शासन को बनाए रखने के संदर्भ में राजनीतिक वैश्वीकरण के भविष्य और प्रभावी वैश्विक व्यापार प्रणालियों को बनाए रखने और वैश्विक व्यापार उदारीकरण को आगे बढ़ाने के संदर्भ में आर्थिक वैश्वीकरण के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति शृंखलाएँ और बहुराष्ट्रीय उद्यम

कोविड-19 महामारी के बाद एमएनई ने अपनी आपूर्ति शृंखलाओं और व्यावसायिक नेटवर्क के पुनर्गठन को संशोधित किया है, और उन्होंने प्राथमिक और मध्यवर्ती उत्पादों की सोर्सिंग और विदेशी बाजारों तक पहुँचने में विविधीकरण की रणनीतियाँ अपनाई हैं। इस प्रकार, एमएनई ने कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को कम कर दिया और अक्सर भविष्य के झटकों से बचने और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए घरेलू और आस-पास के बाजारों में निवेश को फिर से शुरू किया और निकटवर्ती किया। कोविड-19 के बाद के युग में एफडीआई की भूमिका आर्थिक विकास और विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन पर इस महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। ज्ञान के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी स्पिलओवर और उद्यम व्यवसाय और सामाजिक नेटवर्क को बढ़ावा देकर एमएनई कोविड-19 के बाद की रिकवरी को और सुविधाजनक बना सकते हैं।

इस महामारी ने वैश्विक आर्थिक प्रणाली की कमज़ोरी को उजागर कर दिया है, जिससे उद्यमों और आर्थिक एजेंटों को अप्रत्याशित घटनाओं और झटकों के खिलाफ़ लचीलापन बढ़ाने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए अलग-अलग जोखिम आकलन लागू करने या अलग-अलग जोखिम से बचने के दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए उकसाया गया है। नतीजतन,

संरचनात्मक परिवर्तन जो बफर (बड़े स्टॉक के माध्यम से), उत्पादन लाइनों की सुरक्षा और डिलीवरी गारंटी पर जोर देते हैं, कोविड-19 के बाद के युग में उभर रहे हैं। तदनुसार, उद्यमों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाहरी झटकों और व्यवधानों को कम करने के लिए बफर इन्वेंट्री सुनिश्चित करके पारंपरिक "जस्ट-इन-टाइम" रणनीतियों से हटकर "जस्ट-इन-केस" रणनीतियों की ओर रुख किया है।

व्यापार और निवेश नीतियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में कोविड-19 के बाद के समायोजन उन तरीकों को बदल सकते हैं जिनके द्वारा MNE अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचते हैं, जिससे FDI की तुलना में सीमा पार व्यापार के लाभों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसा कि निकटता-एकाग्रता सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के लिए, बढ़ी हुई संरक्षणवादी नीतियाँ और तार्किक चुनौतियाँ व्यापार-बाधाओं से बचने की रणनीति (जैसे, व्यापार बाधाओं को दरकिनार करने और विदेशी बाजारों की सेवा करने के लिए FDI करना) को और अधिक आकर्षक बना देंगी। साथ ही, विस्तारित बाजार अनिश्चितताएँ दीर्घकालिक विदेशी निवेश को रोकेंगी और अंततः बहुराष्ट्रीय उद्यमों को विदेशी बाजारों तक पहुँचने के लिए निर्यात पर अधिक से अधिक निर्भर रहने के लिए मजबूर करेंगी। MNE अंततः सीमा पार व्यापार और FDI मोड की खूबियों और कमियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और यह तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसे प्रवेश किया जाए।

डिजिटल परिवर्तन

लॉकडाउन, सीमा/यात्रा प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी के उपायों के लिए बाजार समायोजन के साथ, कोविड-19 महामारी ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विस्तार को उत्प्रेरित किया है, ई-कॉमर्स में वैश्विक उछाल को बढ़ावा दिया है, और दूरस्थ कार्य सेटिंग्स की ओर बदलाव के माध्यम से कार्य स्थितियों में परिवर्तन को प्रेरित किया है। इन प्रतिक्रियाओं ने आर्थिक वैश्वीकरण पर महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कुछ हद तक कम किया है और आर्थिक और सामाजिक

वैश्वीकरण को संरक्षित करने के तंत्र के रूप में काम कर सकते हैं।

कोविड-19 से प्रेरित ये दूरगामी डिजिटल परिवर्तन भविष्य के बाहरी झटकों के प्रति उद्यमों की तन्यकता को बढ़ावा देंगे। मोडगिल एट अल के अनुसार, ये परिवर्तन व्यवसाय और बाजार संचालन को अधिक पारदर्शी बनाने, डिलीवरी सुनिश्चित करने, आपूर्ति श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हितधारकों को व्यक्तिगत समाधान प्रदान करने, व्यवधानों के प्रभावों को कम करने और एक उत्तरदायी खरीद रणनीति को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। महामारी से प्रेरित डिजिटल परिवर्तन से जुड़ा एक विशिष्ट लाभ यह है कि दूरस्थ कार्य और आभासी सहयोग को बढ़ाया जाता है, जिससे संगठनों को परिचालन लचीलापन मिलता है और भौगोलिक बाधाओं के निहितार्थ कम होते हैं। दूरस्थ कार्य की ओर सापेक्ष बदलाव ने कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और संगठनों को वैश्विक श्रम बाजार से प्रतिभा और कौशल प्राप्त करने के लिए व्यापक मार्जिन की अनुमति दी है। इसके अलावा, महामारी के बाद के युग में ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान का विकास जारी रहा, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा और छोटे व्यवसायों को विकास के व्यापक अवसर मिले। इन कारकों के अलावा, इन कारकों ने महामारी के बाद की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक अधिक कनेक्टेड, कुशल और लचीली अर्थव्यवस्था का आधार बनाया है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बनाए रखने में सक्षम है।

प्रवासी, यात्रा और पर्यटन

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कोविड-19 महामारी ने प्रवासियों, विदेशी श्रमिकों और अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ा दिया है, जिससे प्रकोप के दौरान सामाजिक असमानताएँ और बढ़ गई हैं। इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों ने अंतर-सांस्कृतिक तनावों को बढ़ा दिया है और ज़ेनोफ़ोबिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है, जबकि साथ ही साथ अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसरों को कम किया है और नए विचारों के लिए खुलेपन को दबा दिया है। इसके अलावा, महामारी के कारण होने वाले व्यवधान ने सीमा पार सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क

की गतिशीलता को बदल दिया है, जिसके संभावित दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। ये कारक ऐसे मानसिक मॉडल बनाने का जोखिम उठाते हैं जो महामारी के बाद के युग में भी बने रह सकते हैं, जिससे सामाजिक वैश्वीकरण के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा हो सकते हैं। इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए, कुछ राजनीतिक समूहों ने विदेशियों/प्रवासियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणालियों पर लक्षित नकारात्मक प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ संदर्भों में संकट का फायदा उठाया है। ये रणनीतिक जोड़-तोड़ चिंताएँ पैदा करते हैं कि इस तरह के राजनीतिक आख्यान वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देंगे और एक स्थायी मिसाल कायम करेंगे, जो कोविड-19 के बाद के युग में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बनाए रखेंगे।

इस महामारी का यात्रा और पर्यटन पर भी स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यात्रा मनोविज्ञान और व्यवहार, साथ ही पर्यटकों और निवासियों के बीच बातचीत, महामारी के दौरान लागू की गई सीमा बंदियों और सामाजिक दूरी के उपायों से बदल गई हो सकती है। ये प्रभाव स्वाभाविक रूप से वैश्विक पारस्परिक और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को कम कर देंगे और इस तरह, COVID-19 के बाद के युग में सामाजिक वैश्वीकरण की सीमा को कम कर देंगे। फिर भी, डिजिटल परिवर्तन का उदय सूचना और संचार के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के साथ-साथ अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए वैकल्पिक चैनल प्रदान करके इन प्रतिकूल प्रवृत्तियों का प्रतिकार कर सकता है।

महामारी के बाद के परिदृश्य और भविष्य की दिशाएँ

वुड्स ने शुरू में कोविड-19 के बाद के दो संभावित परिदृश्यों का प्रस्ताव रखा था। पहला परिदृश्य एक उच्च जोखिम वाली स्थिति है, जिसमें राजनीतिक तनाव और एक खंडित दुनिया की विशेषता है, जो वैश्विक सहयोग और समन्वय को और अधिक कठिन बना देती है, और इससे संघर्ष और घरेलू भेदभाव बढ़ सकता है। उच्च स्तर के ऋण और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करने वाली सरकारें राष्ट्रवादी बयानबाजी और ध्यान भटकाने वाली तकनीकों का सहारा

ले सकती हैं, जबकि अन्य राजनीतिक समूह राजनीति को और अधिक चरम पर पहुंचाने के लिए जनसंख्या असंतोष का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक परिदृश्य एक आशावादी स्थिति है, जिसमें वैश्विक/सामान्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, WHO और WTO) की भूमिका बढ़ाने के लिए सामान्य सहमति शामिल है। समानांतर में, गोरीनिया एट अल ने वैश्वीकरण पर कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में तीन संभावित परिदृश्य बताए: अल्पकालिक अशांत वैश्वीकरण, वि-वैश्वीकरण और पुनर्संतुलित वैश्वीकरण (एक मध्यवर्ती स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है)।

वर्तमान स्थिति इन स्पेक्ट्रा पर अपनी स्थिति के संदर्भ में अनिश्चित बनी हुई है, जो एक जटिल और विकसित परिदृश्य को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, वस्तुओं और सेवाओं, एफडीआई, पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोविड-19 के बाद कुछ सुधार पैटर्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/समन्वय में कुछ विकास हुआ है। ये विकसित हो रहे रुझान वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक प्रणालियों में लचीलेपन और प्रगति की एक हद तक संकेत देते हैं। हालाँकि, महामारी के बाद की दुनिया को और अधिक राजनीतिक विखंडन, व्यापार तनाव और हिंसक संघर्षों से चुनौती मिली है। कई देश अभी भी महामारी के दौरान कई सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक प्रोत्साहन से जुड़ी कोविड-19-प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणामों को झेल रहे हैं। इन परिस्थितियों के साथ राष्ट्रवाद/लोकलुभावनवाद की निरंतर लहरें और संरक्षणवादी नीतियों और सीमा उपायों को व्यवस्थित रूप से अपनाना शामिल है।

कुल मिलाकर, ये स्थितियाँ एक ऐसी दुनिया को दर्शाती हैं जो सुधार और व्यवधान के बीच उलझी हुई है, जो इस मोड़ पर इन स्पेक्ट्रमों के भीतर अपनी स्थिति का एक निश्चित मूल्यांकन जटिल बनाती है। भविष्य का प्रक्षेप-चाहे आशावादी हो या निराशावादी-मुख्य रूप से महामारी के कारण उत्पन्न या तीव्र हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में सरकारों, व्यवसायों और समाजों के निर्णयों और कार्यों द्वारा आकार लेगा। न्यायसंगत नीतियों द्वारा समर्थित सहयोगात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देकर, आर्थिक विभाजन

को कम करके और वैश्विक प्रणालियों में विश्वास का पुनर्निर्माण करके दुनिया को महामारी के बाद अधिक टिकाऊ और समावेशी सुधार की ओर ले जाएगा। वैकल्पिक रूप से, महामारी द्वारा बढ़ाए गए आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक विभाजनों को संबोधित करने में विफलता के साथ एक निराशावादी परिदृश्य सामने आ सकता है। यदि इन चुनौतियों को नजरअंदाज किया जाता है, तो सामाजिक/राजनीतिक असंतोष को बढ़ाने और देशों के भीतर और उनके बीच आर्थिक असमानताओं को गहरा करने का जोखिम उठाकर दीर्घकालिक वैश्विक स्थिरता और प्रगति से समझौता किया जा सकता है।

आईएमएफ की एक प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण संचयी उत्पादन में कुल नुकसान 13.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईएमएफ की निम्नलिखित रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भविष्य में कुछ और घातक वैरिएंट सामने आ सकते हैं। इसलिए, देशों, उद्यमों और लोगों को जोखिमों का प्रबंधन करने और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से दीर्घकालिक रणनीतियों की ओर संक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। देशों और भू-आर्थिक क्षेत्रों ने कोविड-19 महामारी से आर्थिक रूप से कितनी वसूली की, इस मामले में अलग-अलग प्रदर्शन किया। इस तरह के अलग-अलग पैटर्न राष्ट्रवादी हितों पर जोर दे सकते हैं, वैश्विक प्रवृत्ति और जुड़ाव को कमजोर कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तनाव पैदा कर सकते हैं और वैश्विक मुद्दों (जैसे, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सुरक्षा, गरीबी में कमी और सामाजिक सामंजस्य) से निपटने में समन्वय और सहयोग को कम कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया है धनी व्यक्तियों के अपनी नौकरी बचाने और कुछ मामलों में, कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान आर्थिक रूप से लाभ उठाने की अधिक संभावना थी (उदाहरण के लिए, उच्च स्टॉक और घर के मूल्यों के माध्यम से)। इसके विपरीत, कम आय वाले व्यक्ति कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं और परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशील थे। ये स्थितियाँ कोविड-19 के बाद के युग में वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं को और बढ़ाएँगी। नतीजतन, कुछ राजनीतिक समूह राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद को और बढ़ावा देने के लिए

इन भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं, और सरकारें संरक्षणवादी/आत्मनिर्भरता उपायों और प्रतिबंधात्मक सीमा उपायों और आव्रजन नीतियों को अपनाकर जवाब देंगी।

3.6 भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव विश्लेषण

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वैश्वीकरण "उत्पादन और पूँजी के अंतर्राष्ट्रीयकरण, उपभोक्ता रुचियों के मानकीकरण और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से उनके वैधीकरण की एक प्रक्रिया है और इसलिए स्पष्ट रूप से यह प्रक्रिया मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा पर आधारित लेन-देन की एक सीमाहीन व्यवस्था की ओर एक कदम है।" इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है, जो 1980 के दशक से पतन के कगार पर थी और जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्रियों वी.पी. सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा किए गए छोटे-मोटे सुधार उपाय निरर्थक साबित हुए। भारत में रणनीतिक सुधार प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। पी.वी. नरसिम्हा राव की तत्कालीन नई सरकार ने तेजी से कदम उठाए और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के एक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसने भारत में सुधार उपायों की एक श्रृंखला शुरू की। प्रस्तावित नीतिगत ढाँचा, दृष्टिकोण और विषयवस्तु की दृष्टि से, भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतिगत रूपरेखा से मौलिक रूप से भिन्न था।

भारत व्यापक गरीबी से कलंकित रहा है, इसलिए पिछले दशकों में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करना समय की मांग रही है। ये कार्यक्रम "गरीबी हटाओ", स्व-रोज़गार सृजन (SEC), काम के बदले अनाज (FFW), परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम और वेतन रोज़गार सृजन (WEC) कार्यक्रमों के रूप में रहे हैं। आय सीमा के आधार पर, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीब या अत्यंत गरीब परिवारों पर लक्षित थे, जिनमें से अधिकांश आदिवासी समुदायों से हैं। हालाँकि, अधिकांश कार्यक्रमों की एक विशेषता यह है कि इनका वित्तपोषण राज्य द्वारा किया जाता है

और इस प्रकार, समय-समय पर धन की कमी के कारण अक्सर योजनाओं को छोड़ दिया जाता है या उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। हालाँकि, वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ, इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटन वास्तविक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

तालिका 3.1 भारत में विकास कार्यक्रमों के लिए योजनावार निधि आवंटन का विवरण

योजना अवधि	कुल निधि आवंटन	विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन	प्रतिशत दर
1 st Plan (1951-56)	2069.00	13.93	0.06
2 nd Plan (1956-57)	4800.00	49.92	4.08
3 rd Plan (1961-66)	7500.00	50.53	0.60
Annual Plan (1966-67)	2081.54	32.32	0.48
Annual Plan (1967-68)	2246.00	32.32	0.48
Annual Plan (1968-69)	2359.00	32.32	0.48
4 th Plan (1969-74)	15901.47	79.5	0.5
5 th Plan (1974-79)	38853.24	1157.67	3.0
6 th Plan (1980-85)	97500.00	3640.25	3.7
7 th Plan (1985-90)	180000.00	6744.85	3.8
Annual Plan (1990-91)	65714.00	N/A	N/A
Annual Plan (1991-92)	73482.00	N/A	N/A
8 th Plan (1992-97)	434100.00	22409.65	5.2
9 th Plan (1997-2002)	859200.00	32087.26	3.7
10th Plan (2002-07)	1618460.00	1481.00	0.09
11th Plan (2007-12)	3644718.00	3633.00	0.09
12th Plan (2012-17)	3568626.00		

उपर्युक्त आँकड़ा तालिका सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए अब तक सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को दर्शाती है, हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि 1997 के बाद से सामाजिक विकास क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि का कुल प्रतिशत काफी कम हो गया है। वार्षिक बजट 2015-16 की कुछ विशेषताओं पर विचार करने पर यह देखा जा सकता है कि सरकार ने कॉर्पोरेट जगत के लिए संपत्ति कर को समाप्त करके और कॉर्पोरेट कर को कम करके प्रत्यक्ष कर खाते

में लगभग 8,325 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, जबकि अप्रत्यक्ष कर में लगभग तीन गुना वृद्धि करके आम लोगों पर 23,383 करोड़ रुपये का बोझ डाला। आँकड़ों का यह प्रतिबिंब हमें सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव दिखाता है। कल्याणकारी राज्य से कॉर्पोरेट राज्य में परिवर्तन ने निस्संदेह आर्थिक विकास को गति दी जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, हालाँकि, सामाजिक विकास कार्यक्रम स्पष्ट रूप से निधि की कमी और उपलब्ध निधि के दुरुपयोग के कारण ठप हो गए हैं।

3.6.1 भारत में वैश्वीकरण

वैश्वीकरण का प्रभाव पहली बार 1990 के दशक में महसूस किया गया था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्तीय आंदोलन योजना शुरू की थी। आज से लेकर भविष्य तक, भारत दुनिया के वित्तीय दिग्गजों में से एक बना हुआ है। आज, यह लगभग 6-7% की औसत विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी तरह, अर्थव्यवस्था में भी लगभग 10% की कमी आई है।

व्यावसायिक उद्योग का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 54% हिस्सा है, जबकि औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों का क्रमशः लगभग 29% और 17% हिस्सा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण, लागत में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बड़े नीतिगत बदलावों का अनुभव किया है, नया आर्थिक सुधार जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ती और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना था। ये सुधार औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र को सबसे कुशल तरीके से काम करने के लिए विकसित करने पर केंद्रित थे। वर्ष 1991 में, जब आर्थिक सुधार निर्धारित किए गए थे, भारत और इसकी अरबों आबादी के लिए

एक नया अध्याय शुरू हुआ था और इसने देश के समग्र आर्थिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अवधि के दौरान लागू किए गए कुछ प्रमुख उपाय थे: अवमूल्यन, विनिवेश, विघटन, अनिवासी भारतीय योजना आदि। वैश्वीकरण का देश के आर्थिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है और एक तरफ इसने जीडीपी दर में वृद्धि की है यह भी देखा गया है कि कुछ ही लोग अर्थव्यवस्था के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के पास है, इसलिए आय का इस प्रकार का असमान वितरण गरीबी, बेरोजगारी आदि उत्पन्न कर रहा है।

3.6.2 वैश्वीकरण एक वरदान के रूप में

भारत की जीडीपी की विकास दर 5.6% (1980-90) से बढ़कर 7% (1993-2001) हो गई है। इन 10 वर्षों में इसमें 1.4% की वृद्धि हुई है। 2006-07 में यह 9.2% थी। और 2016 के आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 के कॉर्पोरेट बजट के अनुसार, जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार 39 बिलियन डॉलर (2000-01), 107 बिलियन डॉलर (2003-04), 145 बिलियन डॉलर (2005-06) और 2007 में 180 बिलियन डॉलर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 19 फरवरी, 2016 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 351.83 बिलियन डॉलर है। 1991 से 2006 तक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.5 करोड़ रुपये था। 81566 करोड़ ($43.29 बिलियन)। वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पिछली तिमाही के 6.6% से घटकर 5.8% रह गई, जो अनुमान से कम है। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रिकल उपकरण (18%), सेवा क्षेत्र (13%), दूरसंचार (10%), और परिवहन उद्योग (9%) आदि शामिल हैं। 2010 में वैश्विक आउटसोर्सिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत थी।

2005 में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत चौथे स्थान पर था, इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और चीन थे। वर्तमान में भारत नौवें स्थान पर है, जबकि इससे पहले आठ देशों की स्थिति

और भी खराब है, लेकिन तमाम उतार-चढ़ावों के बावजूद यह ट्रिलियन डॉलर के बाजार में शामिल होने में सफल रहा। भारत का बाजार पूंजीकरण 1.6 ट्रिलियन डॉलर है और यह विश्व के पूंजी बाजार में 2.5% का योगदान देता है। 2015 की फोर्ब्स सूची के अनुसार, भारत में 100 अरबपति हैं, जबकि 2007 की फोर्ब्स सूची में केवल 40 अरबपति थे। इन अरबपतियों की संपत्ति भारत सरकार द्वारा 91 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए सामूहिक निवेश से भी अधिक है।

3.6.3 वैश्वीकरण एक अभिशाप

कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल मज़दूर भारत में हैं। गरीबी और सुरक्षा का अभाव बाल श्रम के मुख्य कारण हैं। आर्थिक सुधारों के बाद, एलपीजी नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम होने के कारण भारत में बाल श्रम में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, कॉर्पोरेट कंपनियों ने मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से काम किया। सार्वजनिक निवेश की कमी, किसानों के कर्ज में डूबे होने और विक्रेताओं व खरीदारों के बीच बिचौलियों की मौजूदगी के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा। इस आधुनिक युग में नौकरी और सामाजिक सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों को नौकरी और सुरक्षा के साथ-साथ अन्य लाभ भी मिलते थे। गरीबी और बेरोज़गारी वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों में योगदान देने वाले अन्य कारक हैं। निजी उद्यमों में वृद्धि के कारण ग्रामीण अशिक्षित लोगों के लिए रोज़गार के अवसर कम हुए हैं और इस प्रकार गरीबी बढ़ी है।

3.6.4 विदेशी व्यापार

विदेशी व्यापार का अर्थ है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के पार पूँजी, वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान। आज़ादी के बाद पिछले 70 वर्षों में भारतीय व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई है। सरकारी नीतियों ने देश के आयात-निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव डाला था, लेकिन उदारीकरण के दौर में इसमें सुधार हुआ। अब व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का बोलबाला

है। हाल के दिनों में सेवा क्षेत्र का विभिन्न देशों में तेज़ी से विकास हुआ है। यह देखा गया है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात की दर विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात से अधिक है। और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि होगी।

तालिका 3.2: भारत का विदेशी व्यापार (2000-2019), (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
2000-01	44,560.28	50,536.44	95,016.43	-5976.17
2005-06	103,090.52	129,691.77	232,739.35	-26,601.25
2010-11	249,815.53	369,769.12	619,581.79	-119,95.58
2015-16	262,291.07	381,007.47	642.096.63	-118,716.40
2018-19	330,078.08	514,018,35	844,148.55	-184,000.27

आयात प्रतिस्थापन और निर्यात निराशावाद की नीतियों और प्रमुख विचारों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1970 के दशक में स्थिति में सुधार हुआ और निर्यात अंततः उदारीकरण के बाद के युग में और विशेष रूप से 2002 के बाद बढ़ गया। संरचना के संदर्भ में, अब इसमें विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का प्रभुत्व है। हाल के दिनों में सेवा निर्यात का योगदान तेजी से बढ़ा है। वैश्विक निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा भारतीय विनिर्माण निर्यात के दोगुने से भी अधिक है। दिशा के संदर्भ में, यह अब दुनिया भर में अधिक वितरित है और पूर्वी एशियाई देशों की हिस्सेदारी समग्र व्यापार में बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के बड़े आकार, उच्च विकास दर और विश्व व्यापार में छोटे हिस्से को देखते हुए; आर्थिक सिद्धांतों की मदद से, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय विदेशी व्यापार के

लिए बहुत बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है।

तालिका 2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान भारत के निर्यात में हुई वृद्धि को दर्शाती है। तालिका में बताया गया है कि 2000-01 की अवधि के दौरान शीर्ष 5 निर्यातक देशों को भारत का निर्यात 2005-06 में 44,560.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 103,090.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.3 गुना) हो गया; 2010-11 में 249,815.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 262,291.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.04 गुना) हो गया; और 2015-16 में 262,291.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 330,078.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.25 गुना) हो गया। जबकि 2000-01 की अवधि के दौरान शीर्ष 5 देशों से आयात 2000-01 में 50,536.44 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2005-06 में 129,691.77 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2.5 गुना) हो गया; 2010-11 में 369,769.12 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 381,007.57 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 1.03 गुना) हो गया; 2015-16 में 381,007 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 514,018 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1.34 गुना) हो गया। चूँकि आयात की समग्र वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक है, इसलिए व्यापार घाटा 2000-01 में 5976.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010-11 में -119.95.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और बाद में बढ़कर 184,000.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2010-11 से 2015-16 तक व्यापार घाटे में 92,115.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी वृद्धि देखी गई।

राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव

अध्याय 4

राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण का प्रभाव

4.1 परिचय

नीति विज्ञान में, राज्य संप्रभुता स्थायी सैद्धांतिक और व्यावहारिक चिंता का विषय है। शायद एकमात्र महत्वपूर्ण विकास जिसने हाल के वर्षों में राज्य संप्रभुता की अवधारणा और अभिव्यक्ति को प्रभावित किया है, वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। राज्य संप्रभुता की वर्तमान प्रणाली की प्रकृति और राज्य संप्रभुता के लिए वैश्वीकरण के कुछ संभावित परिणामों के बारे में कई अलग-अलग सिद्धांतों की पहचान करना संभव है। राज्य संप्रभुता की आधारभूत अवधारणा को संक्षेप में रेखांकित करना सार्थक है।

आधुनिक राज्य प्रणाली में संप्रभुता की रूपरेखा: राज्य संप्रभुता के मुद्दे को कई - शायद बहुत अधिक - विषयों के सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा कई तरीकों से परिभाषित किया गया है। हालाँकि, नीति विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली राज्य संप्रभुता की अवधारणा को सकारात्मक और मानक संवेदनाओं द्वारा चित्रित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के कई या अधिकांश कोनों (उदाहरण के लिए इतिहास, कानूनी अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत और समाजशास्त्र) में राज्य संप्रभुता अक्सर दुनिया की मूलभूत मान्यताओं और समझ से जुड़ी होती है - दूसरे शब्दों में, राज्य संप्रभुता का विचार सकारात्मक से ज़्यादा मानक मुद्दा है।

इस अध्ययन का विषय वैश्वीकरण का राज्य संप्रभुता पर प्रभाव है, जिसमें राज्य के विशेष विनियामक सरोकार के क्षेत्र, कल्याणकारी राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे-जैसे आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ा है, अधिकांश राज्यों ने निजी निवेशकों के निवेश को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आकर्षित करने या कम से कम बनाए रखने और अपनी स्वयं की गैर-चलती पूंजी के लिए स्थितियों को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। ये सभी गतिविधियाँ राज्य की कार्रवाई द्वारा विनियमित की गई हैं और उसका परिणाम हैं। फ़र्म और धनी व्यक्ति भी मुनाफ़ा

बढ़ाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए 'अनंत तरह के काम और व्यवहार' में लगे हुए हैं, जिनमें से कई फ़र्म और व्यक्तियों के आर्थिक स्थान की तटस्थता को चुनौती देते हैं। इसका परिणाम राज्य का व्यापक कानूनी और संस्थागत दुरुपयोग रहा है - राज्य का उपयोग राष्ट्र की संपत्ति और व्यक्तियों की संपत्ति दोनों को बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए किया गया है, जबकि इसे एक मजबूत और सुलभ नागरिक समाज बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित रखा गया है।

उदार लोकतंत्रों के अंदर उथल-पुथल बहुत ज़्यादा रही है। आर्थिक वैश्वीकरण के दौर में 'बाजार समर्थक राज्य' के मुख्य आयामों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों और स्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा से संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। इनमें से कई प्रतियोगिताएं कल्याणकारी राज्य के संगठन को आकार देती हैं, जिसके महत्वपूर्ण पुनर्वितरण और आवंटन संबंधी परिणाम होते हैं। इन परिणामों का इस विशेष मुद्दे के फोकस पर सीधा असर पड़ता है; जैसे-जैसे बड़ी सरकार धीरे-धीरे राज्य सत्ता के केंद्र से सामाजिक नियामक एजेंसियों के बिखरे हुए नेटवर्क में स्थानांतरित होती है; नियामक वैधता और न्याय के सवाल लंदन स्कूल को सौंपे जाते हैं। भौतिक और वैचारिक प्रथाओं के इस परदे के माध्यम से, आर्थिक नियतिवाद की लंबी छाया फिर से राष्ट्र राज्यों की राजनीति को कवर करती है, और संस्थाओं को केवल आर्थिक बातचीत के क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। अमेरिकी कल्याणकारी राज्य की राजनीति की पहचान यह है कि गरीबों, मजदूर वर्ग और सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों के हित निजी बाजारों से काफी दूर हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सरकार एक ऐसे क्षेत्र के रूप में कार्य करती है जिसमें धनी, शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े लोगों द्वारा अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए किए गए निजी सौदों की मध्यस्थता की जाती है, और घरेलू और विदेशी निजी पूंजी दोनों की समृद्धि का विकास सरकारी अधिकारियों का प्राथमिक, यदि अनन्य नहीं है, तो लक्ष्य है। स्थिति इतनी गंभीर है कि आरआर ओवरचर में कुछ विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि कल्याणकारी राज्य इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रह सकता है।

राज्य संप्रभुता की परिभाषा

इस थीसिस के दौरान, हम राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इस अवधारणा के विकास और सामग्री का विश्लेषण करना आवश्यक है। सबसे पहले, हम राज्य संप्रभुता की परिभाषा, इसके घटक तत्वों और सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद, हम राज्य संप्रभुता की परिभाषा की "समस्या" और पारंपरिक संप्रभुता के "पतन" और इसलिए इसकी "घटती अवधारणा" के बारे में परिकल्पना का उल्लेख करेंगे। संप्रभुता शब्द, लैटिन सुपर या सुपरम (सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, संक्षेप में) और सुपरस (ऊपर झूठ) के सापेक्ष रूप से, अपने स्वयं के क्षेत्र के संबंध में राज्य की शक्ति की अवधारणा को व्यक्त करता है। संप्रभु शब्द भी, मूल रूप से, स्वतंत्र राज्यों की एक विशेष विशेषता है।

राज्य संप्रभुता के चार घटक तत्व हैं जिन पर बहुत बहस हुई है: क्षेत्र, जनसंख्या, अधिकार और स्वीकृति। स्थायी जनसंख्या को अक्सर संप्रभुता के आधार के रूप में समझा जाता है, एक राज्य के अस्तित्व की नींव, जिसके माध्यम से वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग करता है। वैश्वीकरण द्वारा चिह्नित विश्व संदर्भ में, "राज्य" की अवधारणा को भी खुद को फिर से परिभाषित करना होगा, एक ऐसे विश्व संदर्भ में जहां कई संस्थाएं हैं जो किसी राज्य के कुछ पहलुओं में समान हैं। वैश्वीकरण के दबाव और प्रभाव के तहत "राज्य" और "संप्रभुता" की अवधारणाओं का सार बदल रहा है, जो वैश्विक स्थानों को प्रकट करने वाले लोगों और समाजों के विश्व एकीकरण की आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति दे रहा है। ये प्रक्रियाएँ अपने साथ राज्यों की संप्रभुता, उनके नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ बाकी विश्व समुदाय के प्रति भी समझौता लाती हैं।

4.1.1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक संस्कृति का फिर से उभरना और नई प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमताएं हमारी दुनिया को तेजी से एक ही आम समुदाय की ओर ले जा रही हैं - एक दृष्टिकोण जिसे वैश्वीकरण कहा

जाता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के बावजूद, परिवर्तन सार्वभौमिक है और गति अपरिवर्तनीय है। राज्यों की ओर से संरक्षणवाद, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के पैचवर्क की विफलताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गतिशील विकास और अधिक की ओर रुझान को जन्म दिया है

समेकित, वैश्वीकृत दुनिया। दुनिया भर में प्रवासी एक नई अवधारणा का गठन करते हैं और वैश्विक नेतृत्व के महत्व को बढ़ाते हैं। जो लोग वैश्विक समाज में योगदान करते हैं - सरकारी नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सफल बहुराष्ट्रीय निगम, परोपकारी संगठन, प्रमुख विश्वविद्यालय और कुछ गैर-सरकारी समूह - स्थानीय या प्रांतीय हितों से परे प्रभाव रखते हुए बड़े और बड़े दांव का सामना करेंगे। वास्तव में, वैश्विक समुदाय को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए एक साझा जिम्मेदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में, राज्य मानते हैं कि वैश्वीकरण की कम शासित दुनिया उनकी भूमिका को कम करती है। सरकारें, राष्ट्रवाद की भावना को जगाती हैं, कभी भी संप्रभुता के क्षरण को मंजूरी नहीं देती हैं, और निश्चित रूप से न्यायेतर निकायों द्वारा नहीं।

आर्थिक कार्यों के साथ वैश्वीकरण की निर्विवाद पहचान ब्रेटन वुड्स संगठनों - विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन - को सामान्य रूप से किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रभाव डालने के लिए अधिक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का केंद्र बनाती है। वे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक अधिकार मानकों से प्रभावित लोगों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और इन अधिकारों को साकार करने के लिए प्रवर्तन की अनुपस्थिति के बीच संघर्ष को साबित करते हैं। तब से विकसित हुए तदर्थ न्यायालय अभी भी अधिकार क्षेत्र की एक भ्रूण अंतर्राष्ट्रीय संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वैश्वीकरण में योगदान करने में सक्षम है। सरकारें शक्ति संतुलन बनाए रखने और बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने स्वयं के हित में अपने उद्देश्यों को परिभाषित करने पर बेताब हैं। राज्यों के हितों या नेतृत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव की अनुपस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड भौतिक प्रभावशीलता के बिना हैं और उनके आवेदन की गुंजाइश अत्यधिक संदिग्ध है। धर्म, संस्कृति और भूगोल की दुश्मनी मान्यता प्राप्त मानवता की किसी भी अवधारणा का विरोध करती है। केवल तभी जब दुनिया के लोग आम अच्छे को बढ़ावा देने के लिए साझा चिंता से शासित समुदाय

स्थापित करने के लिए तैयार हों, तभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन अधिक गहराई से निहित हो सकता है और नागरिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तभी वैश्वीकृत विश्व की सम्भावना और आशा प्राप्त हो सकेगी।

4.1.2. आर्थिक वैश्वीकरण

यकीनन, आर्थिक वैश्वीकरण वैश्वीकरण सहित व्यापक वैश्विक प्रक्रिया का सबसे व्यापक और प्रभावशाली हिस्सा है। आर्थिक वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आर्थिक बाधाओं और प्रभावों के संबंध में राष्ट्रीय सीमाओं को कम महत्वपूर्ण बनाती है। परिणामस्वरूप, गैर-घरेलू कारक, जैसे कि बहुराष्ट्रीय उद्यम और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में मदद करने वाली महत्वपूर्ण ताकत बन जाते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को वैश्वीकरण के अन्य भागों के लिए मुख्य भाग और एक शर्त क्या बनाता है? ये इसकी दीर्घायु, दूरगामी प्रभाव और अर्थव्यवस्था जैसे बड़े क्षेत्र तक पहुँच हैं। यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि यह प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई, भले ही यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक वैश्वीकरण प्रक्रिया मध्य युग के अंत से चल रही है।

अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक वैश्वीकरण के महत्व या पहुंच का कोई निश्चित माप नहीं है, लेकिन यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि विदेशों में व्यावसायिक संस्थाओं का निवेश बढ़ रहा है, खासकर 19वीं सदी की शुरुआत से। इस समय सीमा के तहत इस पूंजी की मात्रा भी बढ़ जाती है। आज का महत्वपूर्ण "शराबी आदमी" जो वित्तीय वैश्वीकरण को बदल देता है, क्योंकि वित्तीय पोर्टफोलियो विदेश में निवेश करने के लिए सबसे आसान और सबसे तेज़ होने के कारण अन्य वित्तीय उत्पादों से आगे निकल जाते हैं, वे प्रक्रिया के मुख्य विचार हैं। ये वित्तीय पोर्टफोलियो, पूंजी लगाई जाती है, जो किसी कंपनी या देश में वास्तविक पूंजी प्रदान करती है।

व्यापार

राष्ट्रों के बीच व्यापार, वैश्वीकरण का सबसे पुराना रूप है, यह राष्ट्रों के बीच संपर्क और परस्पर निर्भरता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा है। वैश्विक व्यापार के बढ़ते स्तरों की विशेषता कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से है।

इनमें से पहली घटना हाल के वर्षों में मुक्त व्यापार का प्रसार है। राष्ट्रीय संरक्षणवादी नीतियों, अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण के साथ मिलकर, अधिक सुरक्षित और स्थिर वातावरण की आवश्यकता को बढ़ावा देती है। यदि कोई देश उस समय एक दूसरे पर निर्भर व्यापार व्यवस्था का अनुभव कर रहा है, तो वह इस तरह के संबंध से जुड़े विशाल लाभों के कारण संबंधों को मजबूत करना चाहेगा। इसलिए, परस्पर निर्भर व्यापारिक परिस्थितियों में आधुनिक राष्ट्र क्षेत्रीय मुक्त व्यापार व्यवस्था के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जो कुछ लोगों का सुझाव है कि जल्द ही विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी हो सकते हैं।

दूसरा, अमीर और गरीब देशों के बीच अंतर बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार, टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम करने के कारण व्यापार का उदारीकरण, समर्थकों के अनुसार, इस समस्या के कुछ समाधानों में से एक है। गरीब देशों को व्यापार प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है। इन विकास रणनीतियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और टैरिफ और व्यापार/विश्व व्यापार संगठन पर सामान्य समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं और इन संगठित मुक्त व्यापारियों को आर्थिक और व्यापार वित्तपोषण के वादे शामिल करते हैं।

निवेश

पेट्रो-कॉरपोरेशन द्वारा स्वदेशी गैर-सरकारी संगठनों के साथ सीधे बातचीत के पक्ष में राज्य को दरकिनार करने की बढ़ती प्रवृत्ति कॉर्पोरेट क्षेत्र की शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह प्रत्यक्ष प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (कभी-कभी आचार संहिता में निहित) को प्रसारित करती है जो बहुराष्ट्रीय निगमों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस बीच, सैन्य और तर्क विज्ञान दोनों में "प्रगति" छोटी

और आर्थिक रूप से कमजोर संस्थाओं को बहुत बड़े राज्य विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने और जीतने में सक्षम बनाती है।

बहुराष्ट्रीय निगम (TNC) नियमित रूप से राष्ट्रीय सरकारों को दरकिनार करते हैं, जिससे वेस्टफेलियन प्रणाली के जुड़वाँ स्तंभ और साथ ही इस प्रणाली में एक मास्टर सिद्धांत: संप्रभु राज्य प्राधिकरण, दोनों को दरकिनार कर दिया जाता है और इसलिए उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें तोड़ भी दिया जाता है। TNCs सीधे निहित शक्तियों में राज्यों का सामना करते हैं, चाहे निवेश स्थानों का निर्धारण करने में, राष्ट्रीय कानून को आकार देने में, या राज्य कर लगाने में। उड़ान की रेखा वास्तविक राजनीति की चिंताओं को हित-संवेदनशील गैर सरकारी संगठनों, संगठित प्रतिरोध के लिए स्थगित कर सकती है जिसे प्रदर्शन प्रभाव के संदर्भ में राज्य के हस्तक्षेप के बिना TNCs द्वारा स्वयं प्रेरित और वित्तपोषित किया जा सकता है।

4.1.3. राजनीतिक वैश्वीकरण

वैश्वीकरण और राज्य संप्रभुता की अवधारणाओं पर राजनीतिक वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों द्वारा अक्सर चर्चा की जाती है। प्रारंभ में, 'संप्रभुता' शब्द का अर्थ किसी राज्य द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में रखे गए पूर्ण राजनीतिक और कानूनी अधिकार से था। संप्रभुता की विशेषताओं में कार्रवाई की स्वतंत्रता, अपने क्षेत्र में कानून बनाने और लागू करने की क्षमता और बाहरी हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा शामिल है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं के उदय के साथ, विशिष्ट क्षेत्रों के एकाधिकार प्रशासक के रूप में कार्य करने की राज्य की क्षमता बहुत विवाद का विषय बन गई है।

राज्यों के बीच जटिल अंतर-निर्भरता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रियाओं की सघनता ने शिक्षाविदों को संप्रभुता की ऐतिहासिक समझ की सटीकता पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया है, विशेष रूप से सत्रहवीं शताब्दी में स्वीकार की गई अवधारणा। एक राज्य की धारणा जिसमें एक सख्त और विशेष रूप से परिभाषित क्षेत्र, आंतरिक प्राधिकरण की एक संगठित और समन्वित प्रणाली और

सख्त बाहरी सीमाएँ होती हैं जो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अभिनेताओं को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती हैं, वास्तव में तेजी से वैश्विक परिवर्तनों के युग में पुरानी हो सकती हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री जो वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञता रखते हैं, संप्रभुता शब्द के सबसे करीबी अकादमिक पड़ोसी के रूप में 'राजनीतिक वैश्वीकरण' की अवधारणा का उपयोग करते हैं। इस अवधारणा का उपयोग इस तथ्य के कारण किया जाता है कि तकनीकी प्रगति, विस्तारित संचार और अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक और सामाजिक संपर्क के युग में, राज्य के कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थाओं के साथ बातचीत करने के लिए सीमित धर्मनिरपेक्ष बाधाओं से मुक्त किया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संगठन

वैश्वीकरण के आर्थिक और सुरक्षा पहलुओं को प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन राज्य संप्रभुता के लिए एक वैध खतरा है। साहित्य में दो प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रस्तुत किए गए हैं, अंतर-सरकारी संगठन (IGO) और गैर-सरकारी संगठन (NGO)। IGO में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएँ शामिल हैं। IGO के विपरीत, वे राष्ट्र-राज्यों से मिलकर नहीं बने हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े NGO, जैसे कि ग्रीनपीस या एमनेस्टी इंटरनेशनल, वास्तव में कई छोटे देशों की तुलना में अधिक पैसा खर्च करते हैं।

IGO की ताकत उस विषय, कार्य या उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग होती है जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था। अधिकांश IGO के पास ऐसे नियम होते हैं जो उनके संचालन को नियंत्रित करते हैं। IGO सरकारों और, कुछ मामलों में, संगठनों से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लेते हैं। अपनी आर्थिक, सुरक्षा या तकनीकी सहायता नीतियों की विफलता में, IGO व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकते हैं। संप्रभु राज्यों की तरह, कुछ IGO के पास भी प्रवर्तन उपकरण होते हैं। उनकी शक्ति राज्य प्राधिकरण के उन क्षेत्रों तक भी पहुँचती है जिन्हें आसानी से दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

सिनोट के अनुसार, इन विशेषताओं के कारण, संप्रभु राज्यों से IGO को सशर्त और, कुछ हद तक, प्रत्यायोजित अधिकार का हस्तांतरण संप्रभु राज्यों की सौदेबाजी और अनुनय रणनीतियों को प्रभावित करता है, जो अनुपालन की निगरानी करने, दंड लागू करने और यहाँ तक कि सीधे सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए IGO-आधारित संस्थानों पर निर्भर करते हैं।

4.1.4. सांस्कृतिक वैश्वीकरण

कला और सामाजिक संस्थाओं को, अधिकांशतः, अलग-अलग संस्कृतियों के हिस्से के रूप में देखा और सराहा जाता है। कला, कुछ मामलों में, अलग-अलग संस्कृतियों द्वारा हावी है (जिस तरह से संगीत और फैशन अमेरिकी संस्कृति द्वारा हावी हैं), और एक डर है कि वैश्वीकरण का दुनिया पर एकरूपतापूर्ण प्रभाव पड़ता है, और बड़े खिलाड़ी गलत सूचना, मिथकों, विज्ञान और राजनीति के माध्यम से प्रवाह पर हावी हो जाते हैं। अधिक सामान्य रूप से, वैश्वीकरण के कई आलोचक तर्क देते हैं कि यह घटना राष्ट्रीय पहचानों को कमजोर या समाहित कर सकती है, जिससे एक सांस्कृतिक "बीच में" पैदा हो सकता है, जो एक पहचान, अमेरिकी शैली के उपभोक्ता समाज पर निर्भरता का एक रूप उत्पन्न करता है। मीडिया और उपभोक्ता उत्पादों का वैश्विक विस्तार यकीनन पहचान में बदलाव से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वैश्वीकरण एकरूपता को प्रेरित करता है या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि साझा मूल्यों की उपस्थिति विशेष समुदायों के अभ्यास और दुनिया को समझने के उनके तरीकों के अधीन है।

यह विचार कि वैश्वीकरण का संस्कृतियों पर एकरूपतापूर्ण प्रभाव पड़ता है, पिछले दशकों में कुछ अपील प्राप्त कर चुका है और यह मार्क्सवादी मीडिया सिद्धांतकार जॉर्ज गर्बनर (1930-2005) के नाम से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में, एकरूपता उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा सूचना और मनोरंजन को आपस में जोड़ा गया है, विशेष रूप से हर्बर्ट शिलर द्वारा गढ़ी गई "सांस्कृतिक साम्राज्यवाद" और मैकक्वेल द्वारा विकसित "मीडिया साम्राज्यवाद" जैसी अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को नैतिक और बौद्धिक निर्णय के रूप में

परिभाषित करते हुए, जो आबादी के रीति-रिवाजों, इच्छाओं और मनोविज्ञान की नकल करता है और उन्हें कॉर्पोरेट पूंजीवाद की आवश्यकताओं के प्रति सहमत बनाता है, शिलर ने समझाया कि यह अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों के प्रवाह के व्यावसायिक नेतृत्व को संदर्भित करता है। व्यावसायिक प्रभाव का विस्तार आम तौर पर पूंजीवादी देशों से समाजवादी और अविकसित प्रभुत्व वाले विश्व तक था। वास्तव में, विभिन्न विद्वान यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि उदाहरण के लिए, टेलीनोवेला से निकाले गए विषय काफी क्रांतिकारी रहे हैं। मीडिया साम्राज्यवाद के नाम पर ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक जेम्स कुरेन ने उन तरीकों की ओर इशारा किया जिनके द्वारा टेलीविजन उत्पादन तकनीकें वैश्विक संचार पर नियंत्रण रखने वाले उद्योग का उत्पाद हैं।

यह तर्क सैद्धांतिक या अनुभवजन्य मान्यताओं पर आधारित है। जहाँ पहला मानता है कि सांस्कृतिक व्यापार समग्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था और व्यापार गतिशीलता का परिणाम है, और सांस्कृतिक वस्तुओं के व्यापार के साथ सांस्कृतिक विविधता को गुमराह करता है, वहीं दूसरा अनुभवजन्य ढाँचों पर आधारित है जो उत्पादन, व्यापार और मनोरंजन वस्तुओं की खपत के क्रॉस-कंट्री शोध पर ध्यान केंद्रित करता है। परिणाम यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं की माँग और आपूर्ति को प्रभावित करता है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि सीमांत राजस्व और लागतों में बदलाव, या अविश्वास और विशिष्ट क्षेत्रों में बाजार एकाग्रता की डिग्री से व्याख्याएँ बनाई जाती हैं, सांस्कृतिक विविधता के लिए सांस्कृतिक वस्तुओं के व्यापार के निहितार्थ अलग-अलग हो सकते हैं। एक चल रहे काम में, वैलेंटिना ब्रूनो और जियाकोमो कैलज़ोलारी पूछते हैं कि क्या आर्थिक एकीकरण सांस्कृतिक व्यापार और उत्पाद गंतव्यों के मिलान को प्रभावित करता है, प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक रूप से एकीकृत देशों में एजेंट साझेदार देशों में उत्पादित सांस्कृतिक मनोरंजन को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते हैं। हालाँकि, वैश्वीकरण का यह भी अर्थ है कि स्थानीय उत्पादकों को स्थानीय प्राथमिकताओं पर अधिक कुशलता से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे अधिक सांस्कृतिक विविधता

हो। इसका तात्पर्य यह है कि अधिक वैश्वीकृत विश्व में, सांस्कृतिक वस्तुओं की विशेषता विविधताओं के बढ़ते और घटते प्रतिफल से होती है।

बेशक, तर्क एकमत नहीं हैं, और वास्तव में सांस्कृतिक व्यापार संबंध के संबंध में वैश्वीकरण की गतिशीलता की समझ तुच्छ से बहुत दूर है, क्योंकि प्रासंगिक कारक सांस्कृतिक उत्पादों की आपूर्ति और मांग, और उनके बीच अंतर्संबंधों दोनों के निर्धारक हैं। परिणामस्वरूप, व्यापक मूल्यांकन के लिए नए अनुभवजन्य ढाँचों की आवश्यकता है।

मिडिया

इन विचारधाराओं को प्रसारित करने में सबसे प्रभावशाली कारक मीडिया है। मीडिया हमें दुनिया के विभिन्न स्थानों से समाज और अन्य देशों में होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक होने की अनुमति देता है। मीडिया की यह विशेषता अपने साथ इसका सबसे मजबूत पहलू लेकर आती है: यह उन लोगों के वेतन और वेतन अपेक्षाओं में हेरफेर करने का सबसे व्यावहारिक साधन बन गया है, जिन्होंने बाकी दुनिया के साथ अपने संबंधों को महसूस करना शुरू कर दिया है, समाजों के बीच बातचीत को नियंत्रित करने और उन्हें इच्छानुसार आकार देने के लिए। यह ज्ञात है कि विकसित संकटों के पहले चरण में निर्दिष्ट अपने कार्यों के कारण, इंटरनेट-आधारित जन मीडिया को समाज की आर्थिक संरचना को बदलने में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के सबसे मजबूत हथियारों में शामिल किया गया है।

मीडिया को इतना महत्व क्यों मिलना शुरू हो गया है? सामान्य रूप से वैश्वीकरण के आयाम और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर बढ़ते ध्यान के पीछे कई कारक हैं। पहला घटक सूचना प्रसारित करने में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका है। मीडिया दर्शकों की इकाई के लिए बुनियादी मूल्यों, विश्वासों, संदेशों, कोडों और बिंदुओं को पारित करने की वस्तुनिष्ठ भूमिका भी निभाता है। जैसा कि वैन वोलफेरन बताते हैं: "जो प्रसारित किया जाता है वह एक सामूहिक अनुभव, व्यवहार का एक कोड, एक पसंदीदा मानदंड या किसी प्रकार का रुख होता है जिसे बहुसंख्यक

संजोना पसंद करते हैं, जब आवश्यक हो तो अनदेखा करते हैं या दोहराते हैं।" मीडिया को "चौथे स्तंभ" के रूप में माना जाना इसे सार्वजनिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। स्पष्ट रूप से, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव की यह अंतर्निहित क्षमता मीडिया और विकास के सामान्य मुद्दे को केंद्रीय बनाती है।

4.1.5. तकनीकी वैश्वीकरण

तकनीकी वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के एक हिस्से में विकसित तकनीकें दुनिया में कहीं भी व्यक्तियों या कंपनियों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। नई तकनीकों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक बुनियादी समर्थन माना जाता है। इस घटना के लिए दूरसंचार तकनीकों को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार माना जाता है। सस्ते इंटरनेट कनेक्शन के आगमन के साथ, अब कर्मचारियों के लिए कहीं भी जहाँ टेलीफ़ोन और कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग, टेलीसर्विसिंग या परामर्श गतिविधियों में शामिल होना संभव है, जो उन्हें "नौकरी स्थल" के साथ मानवीय संबंधों में शामिल करते हैं। यह तकनीकी उपलब्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल कार्यों को उनके प्राकृतिक स्थान से हटाने और संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था में अन्य स्थानों पर आउटसोर्स करने की अनुमति देती है। यह भी माना जाता है कि तकनीकी प्रगति श्रमिकों और समुदायों को अधिक असुरक्षित बना सकती है और इस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों का विरोध करने के लिए कम इच्छुक हो सकती है। इस प्रकार तकनीकी प्रगति को बिखरे हुए क्षेत्रों को एक आम विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की शक्ति के रूप में देखा जाता है।

यदि हम पिछले दशक का विश्लेषण करें, तो हम सत्यापित कर सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया दो मुख्य कारकों से प्रभावित हुई है। एक नया तकनीकी वातावरण, सूचना युग, बाहरी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में कई नए मुद्दों की प्रमुखता को बढ़ाता है, जैसे कि सीमा पार डेटा प्रवाह, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार, राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकियों का प्रसार, सूचना के सापेक्ष महत्व में वृद्धि। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि हम सूचना समाज के "उदय" में रह रहे हैं,

जिसकी शुरुआत विशेष रूप से कंप्यूटर के विस्तार और सूचना से संबंधित सभी क्षेत्रों में नेटवर्क के उद्भव से हुई है। वैचारिक बहस अब विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रभाव पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और नीतियों पर प्रकृति से अंतरराष्ट्रीय हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संचार को विनियमित करने के लगभग दो दशकों के प्रयासों के बाद ही वित्तीय बाजारों का वैश्वीकरण संभव हो पाया। वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण को लाने के लिए दूरसंचार में तकनीकी प्रगति की आवश्यकता थी, जैसे कि उच्च क्षमता वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो पश्चिमी यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजों को एकीकृत करते हैं। प्रौद्योगिकीय वैश्विक परिवर्तनों के वर्तमान चरण में, निजी नेटवर्क, जिनका उपयोग 1990 के दशक तक केवल बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ही किया जा सकता था, 21वीं सदी में उच्च क्षमता वाले नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत वैश्विक दोहन की संभावनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

4.1.6. राज्य संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ

राज्य संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के प्रयास में, हमने संप्रभुता के शास्त्रीय दृष्टिकोण को राज्य के क्षेत्र के भीतर सर्वव्यापी माना और कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके इसका विश्लेषण किया, जो इसके सबसे आवश्यक लक्षणों - अंतिम शक्ति और स्वतंत्रता पर केंद्रित था। राज्य के बाहरी संबंधों, आर्थिक जीवन और प्रणालीगत वातावरण के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का संप्रभुता के चिमेरिक लक्षणों पर प्रभाव चर्चा के लिए प्रचलित आधार है। लेकिन इसके महत्व में कमी के बावजूद, संप्रभुता आधुनिक राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है। यह देश के भीतर निर्णय लेने वाली प्रणाली की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है। इसके कमजोर होने के परिणाम भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संप्रभुता वैश्विक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार बनी हुई है, और राष्ट्रीय स्तर पर, यह राज्य की आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों की संभावित दक्षता को कम कर सकती है।

संप्रभुता की क्लासिक परिभाषा इसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में वर्णित करती है, जो अन्य राज्यों की कानूनी प्रणालियों से स्वतंत्र है। राज्य के क्षेत्र के भीतर, राज्य की केंद्रीय शक्ति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह नियम और विनियम जारी करता है, सशस्त्र बल का उपयोग करने का विशेष अधिकार रखता है, बाजारों और बाहरी व्यापार को नियंत्रित करता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवस्था बनाए रखने में इसका एकाधिकार है और यह अप्रत्यक्ष नियंत्रण तंत्र बनाता और लागू करता है। जैसे-जैसे समय बदलता गया, संप्रभुता की अवधारणा में परिवर्तन के दायरे को परिभाषित करने वाले कई दृष्टिकोण सामने आए, जो शर्तों के एक सेट के आधार पर एक नई संप्रभुता के उद्भव की ओर ले जा सकते हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ

पहले से चर्चित सख्त आर्थिक चुनौतियों के विपरीत, जो, हालांकि उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, लेकिन वे काफी हद तक इस विषय पर भिन्नताएं हैं कि कोई राज्य वर्तमान आर्थिक परिवेश में किस तरह से सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, राष्ट्रीय पहचान या समुदायों पर वैश्वीकरण के प्रभाव से राजनीतिक चुनौतियों का एक विशिष्ट वर्ग उत्पन्न होता है। यह मुद्दा पश्चिमी यूरोप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां नागरिकता की परंपरा में सामाजिक अधिकार और भागीदारी अधिकार दोनों शामिल हैं, और जहां अंतरराष्ट्रीय एकजुटता काफी हद तक यूरोपीय संस्थानों की छायादार दुनिया तक ही सीमित है। यहां, राष्ट्र-राज्य के पहलुओं पर हमला, जिसे राष्ट्रीय पहचान का आवश्यक भंडार माना जाता है, ने कई तरह की संरक्षणवादी भावनाओं को जन्म दिया है, जो वाम और दक्षिणपंथी दोनों के चरमपंथियों के जुनून को उत्तेजित करती हैं। उनके अनुसार, वैश्विक बाजार के कहर के खिलाफ आर्थिक राष्ट्रवाद की रक्षा लंबे समय से आम सहमति का विषय रही है।

राजनीतिक चुनौतियाँ

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र-राज्य निर्णय लेने की शक्ति को छोड़ देते हैं। राज्य की एक मानक परिभाषा "कुछ प्रकार के निर्णय लेने (या कार्रवाई करने) की इसकी अत्यधिक विशिष्ट

क्षमता और कुछ निर्दिष्ट नीति क्षेत्रों में कार्य करने या निर्णय लेने में अन्य आधिकारिक अभिनेताओं पर हावी होने की प्रशंसनीय उम्मीदों का आनंद लेने पर जोर देती है। इसके विपरीत, "वैश्वीकरण एक ऐसा तरीका सुझाता है जिसमें कुछ प्रकार के राज्यों की क्षमता या अधिकार कम हो सकते हैं, या कम से कम कम विशिष्ट हो सकते हैं।" यह राज्य के पतन को नहीं दर्शाता है, बल्कि राज्य की कार्रवाई और अधिकार के क्षेत्र में बदलाव को दर्शाता है। "वैश्विक शासन के विकसित होते रूप नीति के क्षेत्रों और कुछ हिस्सों में बदलाव लाते हैं

राज्य हमेशा राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए केंद्रीय नहीं होता। खास तौर पर राज्य के प्रशासनिक तंत्र के गैर-मुख्य कार्यों में।"

वैश्वीकरण और राज्य का दर्जा विपरीत रूप से संबंधित नहीं होना चाहिए। कैट्ज़नेलसन ने विश्लेषण के केंद्र को आपूर्ति से निर्णय लेने की प्रक्रिया के मांग पक्ष में बदलने का सुझाव दिया है। वह मतदाताओं की राष्ट्र-राज्य के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीतिक समुदाय की मांग बनाम वैश्वीकृत उत्पादन, वितरण और उपभोग की ओर बाजार-संचालित गति को देखने का सुझाव देते हैं। एक "अर्थव्यवस्था जो अपनी कई विशेषताओं में राज्यों से स्वायत्त और विनियमन की उनकी क्षमता से परे प्रतीत होती है" में वैश्विक आर्थिक परिवर्तन बाजार-राज्य अक्ष के पुनर्निर्माण को प्रभावित करता है "जिस तरह से राष्ट्र-राज्य शक्ति, पहचान और वैधता के कई मुख्य आयामों को चुनौती देता है और उन्हें फिर से परिभाषित करता है।"

4.1.7. प्रतिक्रियाएँ और अनुकूलन

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की दुनिया में राज्यों के लिए चुनौतियाँ कई गुना बढ़ जाएँगी। हम कई तरह की प्रतिक्रियाओं को देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से कुछ में नई चुनौतियों के लिए अनुकूलन शामिल है, जबकि अन्य में शासन के रूप में समायोजन शामिल है। अधिक मौलिक विकासवादी अर्थ में, हम कुछ राज्यों की "आनुवंशिक संरचना" में परिवर्तन देख सकते हैं। सभी राज्य अनुकूलन, समायोजन या परिवर्तन नहीं करेंगे। जो विफल होते

हैं, वे पाएंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग चीजें हैं। इसके परिणाम सभी राज्यों के लिए समान नहीं हैं, या समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कई राज्यों ने पहले से ही "संरक्षक" गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, अपनी प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं की रक्षा के लिए नीतियों के सेट को अपनाते हुए, जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। इन नीतियों का प्रभाव वैश्वीकरण के क्षरण और "खोखलापन" या "धुंधलापन" प्रभावों को रोकना है। इनमें से कुछ कार्य स्पष्ट और आक्रामक हैं - पोर्नोग्राफ़ी के आयात को नियंत्रित करने, सांस्कृतिक आयात को खत्म करने, इंटरनेट को सेंसर करने, चुनिंदा रूप से व्यापार और निवेश को बाधित करने, सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों को प्रतिबंधित या विनियमित करने और मीडिया क्षेत्र को नियंत्रित करने के प्रयासों पर विचार करें - राज्य की शक्ति को लागू करने के प्रयास। इज़राइल की समाचारों की सेंसरशिप, दक्षिण कोरिया की वेबसाइटों की सेंसरशिप और चीन का वैश्विक बाजारों में गहरा लेकिन आंशिक एकीकरण इसके कुछ उदाहरण हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप देशों के बीच परस्पर निर्भरता का स्तर इस परस्पर निर्भरता को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्तर से कहीं आगे निकल गया है। वैश्वीकरण के आलोचक अक्सर दावा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर सुधार की प्रक्रिया को अमीर और शक्तिशाली देशों ने रोक दिया है। यह निश्चित रूप से सच है कि अमीर देशों में पाए जाने वाले औद्योगिक शुल्कों के उच्च स्तर का मतलब है कि गरीब देशों ने अपने लगभग सभी औद्योगिक शुल्कों को उदार बना दिया है। इस प्रकार गरीब देशों ने टैरिफ और व्यापार (GATT) या नए विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पारस्परिक प्रकृति के किसी भी वाणिज्यिक लाभ को कभी प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, यह भी सच है कि अमीर देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली के लगभग सभी अन्य घटकों का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन खर्च किए हैं, जिसमें अब अंदरूनी और बाहरी लोगों के बीच भेदभाव शामिल नहीं है।

वास्तव में, अमीर देश, कुछ अर्थों में, व्यापारिक साझेदारों के बीच गैर-भेदभाव के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) नियम के विभिन्न भागों को बनाने में इतने सफल रहे हैं कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का अधिकांश हिस्सा कानून के अंतर्राष्ट्रीय नियम के निर्माण के लिए समर्पित है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एक दो-चरणीय प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, जिनका उपयोग नियमों पर बातचीत करने और समितियों को बनाने के लिए किया जाता है, जिनके पास वार्ताकारों द्वारा लिखे गए नियमों की देखरेख करने का अधिकार होगा, आमतौर पर कमज़ोर निकाय होते हैं। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में संगठित है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की क्षमता इसके विपरीत लगभग पूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह अंतर्दृष्टि देकर नैतिक उच्च भूमि दी गई है कि यह सभी के हितों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करती है, दुनिया को याद दिलाती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून वेस्टफेलिया की संधि का निर्माण बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन हमेशा अपने साथ यह अनुवांशिक सिद्धांत लेकर चलता है कि अंतिम राष्ट्रीय संप्रभुता वैश्विक मंच से जुड़ी नहीं हो सकती।

क्षेत्रीय एकता

कुछ क्षेत्रों में राज्य संप्रभुता में कमी, स्वतंत्र कार्यकारी शाखाओं वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या में वृद्धि, तथा वाणिज्यिक संबंधों के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यह पूछना उचित है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में प्रगति की वर्तमान दिशा इन शक्तियों के वांछनीय प्रसार के बजाय इनका पूर्णतया अवांछित संकेन्द्रण उत्पन्न नहीं कर रही है।

इस निबंध में यह तर्क दिया गया है कि इन विशिष्ट स्थितियों का अफ्रीकी समुदायों की संप्रभुता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं और इन स्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के निर्माण और आधुनिक प्रादेशिक राज्य के निर्माण के सह-विकास के उपोत्पाद के रूप में समझा जा सकता

है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के प्रति संघर्ष कम हो रहा है और कई क्षेत्रीय राज्यों की शक्ति नहीं तो अखंडता वैश्वीकरण के अनुशासन में खिसक रही है, जो किसी भी तरह से यह नहीं मानता है कि उत्तरार्द्ध पूर्व के लिए एक संतोषजनक विकल्प है।

इस समस्या का समाधान स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम परिकल्पना पर काम नहीं करते, जो यह है कि एक परिपक्व वैश्विक प्रणाली का लोकतांत्रिक निर्माण पारस्परिक निर्भरता का विविधीकरण नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिक संकेन्द्रण है। ऐसे समय में, हम शहरी सुपरक्रॉट्स और अफ्रीकी समुदायों दोनों की पृथक आबादी की नज़र में उस स्रोत की वैधता के पुनर्गठन की उम्मीद कर सकते हैं। तभी वैश्वीकरण के अधिकांश किनारों पर सीमांत आबादी के लिए उच्चायुक्त और समकालीन राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं।

4.1.8. मामले का अध्ययन

यह भाग यूरोपीय संघ में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के प्रभावों पर दो केस स्टडी प्रस्तुत करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूरोपीय संघ की तुलना में राज्यों के साथ अपने संबंधों में एक संघ के अधिक शुद्ध रूप को दर्शाता है, की तुलना संघीय पहलुओं में यूरोपीय संघ से की जाएगी। सदस्य राज्य अपनी पूर्ण संप्रभुता और पूर्ण स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं जबकि सीमित क्षमताएँ एक आम सभा को सौंपते हैं। यह निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का मामला नहीं है, जहाँ कानूनी प्रणाली की एकता या क्षमता सूची के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है।

ओईसीडी यह भी कहता है कि इस तरह के असमान संबंध की विशेषता संघ के व्यक्तित्व की कमी और एक विशेष प्रशासन की उपस्थिति है जो इसकी गतिविधियों का समर्थन करता है। इसलिए, यह आकलन करना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसी कोई इकाई, जिसका नाम अब यूरोपीय संघ रखा गया है, 80 के दशक से साहित्य से उभरी आर्थिक वैश्वीकरण प्रतिमान है, जिसने एक ऐसी दुनिया को दर्शाया है जहाँ राज्य को अपनी नियंत्रण शक्तियाँ खोते हुए या, कुछ अधिक निराशावादी राय में,

गायब होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है जबकि आर्थिक पहल सीमा पार गतिविधियों में शामिल बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा की जाएगी।

यूरोपीय संघ

1950 के दशक से, यूरोपीय संघ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, राज्य संप्रभुता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों में एक अद्वितीय प्रयोग के रूप में उभरा है। अपने आप में, यूरोपीय संघ राज्य शक्ति और राज्य सीमाओं के बीच पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध को चुनौती देता है। एकीकरण के संदर्भ में यूरोपीय संघ की पहली उल्लेखनीय उपलब्धि समुदाय के मूल सदस्य राज्यों के बीच युद्ध को बेहद असंभव बनाना है। यह उन देशों के लिए ऐतिहासिक रूप से असामान्य है। शांति को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया क्षेत्रीय सहयोग एक केंद्रीय प्राधिकरण को संप्रभुता का एक उपाय प्रदान करने का परिणाम है - इस मामले में, यूरोपीय संघ। अपनी स्थापना के समय से ही, EU कुछ क्षेत्रों में वैश्विक एकीकरण के सकारात्मक पक्ष का एक अत्याधुनिक उदाहरण रहा है। टैरिफ और पर्यावरण पर समझौते करके और प्रभावित निजी पक्षों को कानूनी उपाय प्रदान करके, EU वैश्वीकरण के प्रबंधन में यथासंभव प्रमुख भूमिका निभाने का प्रयास करता है, जिसमें न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि अन्य देशों में भी मानवाधिकारों, राजनीतिक लोकतंत्रीकरण और कानून के शासन को बढ़ावा देना शामिल है। हाल ही में, इसके सदस्य देशों ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक एकल यूरो-मुद्रा क्षेत्र का गठन किया है। यह भी गहन आर्थिक एकीकरण का एक ऐतिहासिक प्रयास है, जिसे संप्रभुता के एक बड़े पूल के माध्यम से हासिल किया गया है। लिस्बन की संधि ने आर्थिक और मौद्रिक नीति पर नियंत्रण बढ़ाया है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। यूरो-मुद्रा का अनुभव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, क्षेत्रीय स्तर पर भी राजनीतिक एकीकरण के वर्तमान प्रयासों के लिए एक करीबी मिसाल है। नकारात्मक पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वर से बोलने में EU की अक्षमता है, यह देखते हुए कि विदेश नीति के फैसले सदस्य देशों द्वारा लगभग सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं।

उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा)

1990 की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त आदान-प्रदान के लिए बातचीत की। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) ने अमेरिकी वस्तुओं पर मैक्सिकन टैरिफ को कम कर दिया। यह व्यापार समझौता विवादास्पद था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप से प्रमुख भागीदार था। कई अन्य देश अमेरिकी बाजार तक पहुंच चाहते थे और एक ऐसा व्यापार समझौता चाहते थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसा असंतुलित लाभ न दे। ये देश NAFTA के आलोचक थे। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा द्वारा टैरिफ में कमी को मेक्सिको के बढ़ते टैरिफ-संरक्षित बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक गणना की गई लागत के रूप में देखा। यदि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यक्तिगत रूप से मूल्यवान कुछ देने जा रहे थे, तो वे एक क्विड प्रो क्वो चाहते थे। वे पर्यावरण और श्रम प्रावधानों के भी आलोचक थे, उनका तर्क था कि NAFTA प्रक्रिया ने राष्ट्रीय संप्रभुता को कम कर दिया, जिससे अमेरिकी हित समूहों (पर्यावरण और श्रम संगठनों) को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया के बाहर घरेलू नियमों को प्रभावित करने की अनुमति मिल गई।

उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंताएँ पैदा कीं। कुछ लोगों ने NAFTA को मैक्सिकन यूनियनों को कमज़ोर करने और इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी मज़दूरी दरों को कम करने का एक तंत्र प्रदान करने के रूप में देखा। श्रम और पर्यावरण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये प्रावधान विवादास्पद थे। क्या इन प्रावधानों से अमेरिकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचने वाला था?

अमेरिकी पर्यावरणविदों ने मेक्सिको के लिए वायु और जल उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव रखा था जो अमेरिकी मानकों के समान थे। जवाब में, मेक्सिको के व्यापारिक समुदाय ने सामूहिक रूप से विरोध किया। व्यवसाय की चिंताओं को दूर करने के लिए, क्लिंटन प्रशासन को मैक्सिकन मैकिलाडोरस से रियो ग्रांडे की रक्षा के लिए प्रस्तावित विनियमन को छोड़ने के लिए मजबूर होना

पड़ा। हालाँकि ये फ़र्म वास्तव में मेक्सिको में सस्ते श्रम का शोषण कर रही थीं, लेकिन उनके उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वे जो प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे थे, वे अत्यधिक संदिग्ध मूल्य के थे। चूँकि NAFTA को संधि के बजाय एक कार्यकारी समझौते के रूप में आगे बढ़ाया गया था, इसलिए प्रशासन के पास ये नीतिगत परिवर्तन करने का अधिकार था। अनुमोदन के लिए सीनेट में वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे मुद्दों पर खुली बहस से बचा जा सके।

4.2 वैश्वीकरण के तहत भारतीय राज्य

कैसे क्या वैश्वीकरण ने भारतीय राज्य को प्रभावित किया?

1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद भारत में बहुत कुछ बदल गया था। निर्यात को बढ़ावा देने और भारत की वृद्धि की प्रक्रिया में विदेशी पूंजी को भाग लेने की अनुमति देने के बारे में भारतीय नीतियाँ अधिक सकारात्मक हो गईं। एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए था वह यह था कि क्या ये संकट से प्रेरित थे, या नीति अभिजात वर्ग के भीतर वैचारिक परिवर्तन, या दोनों? क्या संस्थागत इतिहास भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और दक्षता के पक्ष में नीति परिवर्तन को संस्थागत परिवर्तनों में बदलने में सापेक्ष सफलता या विफलता को समझाने में मायने रखता है? विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण शोध एजेंडा बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका थी, और, भारतीय नीति अभिजात वर्ग के भीतर तकनीकी बदलाव, 1991 के बाद से नीति प्रक्षेपवक्र में विशिष्ट व्यापार-उन्मुख बदलाव को समझाने में।

ये परिवर्तन क्या थे? टैरिफ कम कर दिए गए; विदेशी मुद्रा नियंत्रण में ढील दी गई; बिजली, दूरसंचार और एयरलाइंस जैसे पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व वाले बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा शुरू की गई; औद्योगिक लाइसेंसिंग को लगभग समाप्त कर दिया गया; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी निगमों को बेच दिया गया; विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया; बौद्धिक संपदा व्यवस्था को सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजाय बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के पक्ष में बदल दिया गया और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार

में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। श्रम, कृषि और राजकोषीय घाटे की निरंतर वृद्धि पर नीति जैसे अन्य क्षेत्र थे, जहाँ वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में भारत के कदमों के बावजूद भारतीय नीतियों में पर्याप्त बदलाव नहीं हुआ था। अध्ययन अंतिम खंड में इन मुद्दों को उठाएगा जब चर्चा की जाएगी कि विकास लाने के लिए राज्य को सामाजिक अभिनेताओं पर कैसे काम करने की आवश्यकता है।

क्या भारत ने व्यापार और दक्षता-उन्मुख नीतिगत परिवर्तनों को इस तरह से क्रियान्वित किया कि वह अपनी प्राथमिकताओं और राजनीतिक शैली को प्रतिबिंबित करता हो? यह तर्क दिया गया है कि क्रमिकता भारत के उदारीकरण की विशेषता रही है। नीति और संस्थागत परिवर्तन को प्रभावित करने के इस तरीके में, एक व्यापक नीतिगत दृष्टि प्रदान की जाती है, लेकिन नीतिगत परिवर्तन की बारीकियों को निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी बारीकियों को हित समूहों और राजनीतिक अवसरवाद के समायोजन को ध्यान में रखना चाहिए। क्रमिकता आम सहमति बनाने में मदद करती है, जबकि साथ ही यह वैश्वीकरण की अनिवार्यताओं के साथ समायोजन की प्रक्रिया में देरी भी करती है।

एक उदाहरण देने के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, जिसके विकास के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता थी। दूरसंचार को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया, विशेष रूप से भारत के बढ़ते सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में एक इनपुट के रूप में। भारत में कुछ रणनीतियों का पालन किया जा सकता था। एक रणनीति निजी प्रवेश को आमंत्रित करने से पहले सरकारी सेवा प्रदाताओं को अधिक कुशल बनाना हो सकता है, जैसा कि ब्रिटिश टेलीकॉम के मामले में था। इसके लिए कार्य नैतिकता और खरीद नीति को प्रभावित करने वाले बड़े संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता होती, क्योंकि सरकारी स्वामित्व से संबंधित बहुत सी सुस्ती को दूर करने की आवश्यकता थी। ऐसे उपायों के लिए भारत के सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार क्षेत्र से निकलने वाले नौकरशाही और ट्रेड यूनियन के दबाव से बहुत अधिक अलगाव की आवश्यकता होती।

भारत में ऐसे साहसिक निर्णय संभव नहीं थे। दूरसंचार सेवा विभाग का निगमीकरण 2002 में ही हो सका, जबकि सेलुलर क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवेश की अनुमति 1992 में ही दे दी गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को निगमित करने का कारण यह था कि निजी पूंजी सरकारी एकाधिकार पर इतना प्रतिस्पर्धी दबाव डाल रही थी कि विनियामक विशेषाधिकारों के बावजूद, सरकार को एहसास हुआ कि दूरसंचार विभाग तभी सफल हो सकता है जब इसके निगमित स्वरूप, बीएसएनएल को सरकारी स्वामित्व वाले लेकिन स्वायत्त निगम के रूप में काम करने दिया जाए। चूँकि भारत अपने अकुशल निगमों का सार्थक रूप से विनिवेश या निगमीकरण आरंभिक चरण में नहीं कर सकता था, इसलिए निजी खिलाड़ियों को व्यवसाय में अनुमति देकर पिछले दरवाज़े से प्रतिस्पर्धा को मजबूर किया गया।

सुधारों के माध्यम से क्रमिकता और उलझन का एक और उदाहरण भारत के दूरसंचार क्षेत्र में विनियमन की शुरूआत का तरीका था। नियामक को निजी पूंजी के लिए एक समान खेल का मैदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य और निजी पूंजी के बीच रेफरी की भूमिका निभानी थी। निजीकरण को पहले नियामक की अनुपस्थिति में पेश किया गया था क्योंकि दूरसंचार विभाग आसानी से अपने नियामक विशेषाधिकारों को नहीं छोड़ेगा। 1997 में नियामक की शुरुआती अभिव्यक्ति और उसके बाद 2000 में मजबूती, भारत में अनियमित निजी निवेश के कारण पैदा हुए कई निवेश संकटों का परिणाम थी। विनियमन की आवश्यकता के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश मार्च 1991 की शुरुआत में ही उपलब्ध थे। नियामक विकास की प्रक्रिया अव्यवस्थित थी और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर तकनीकी अभिविन्यास की उपस्थिति में नौकरशाही और वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखना था, जो निजी निवेश के लिए एक समान खेल के मैदान का पक्षधर था।

दूरसंचार विनियमन की राजनीति में गड़बड़ जारी रही। दूरसंचार नियामक को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और नीति-निर्माण शक्तियों की आवश्यकता थी। दूरसंचार विभाग ने इन शक्तियों को आसानी से त्यागा नहीं। ऐसे क्षेत्र में विनियामक विकास की राजनीतिक गतिशीलता क्या हो

सकती है, जहां निजी खिलाड़ियों ने अब सरकारी शोषण की जगह अपने स्वयं के शोषणकारी व्यवहार को अपना लिया है?

भारत का व्यापार-उन्मुख व्यवस्था के प्रति समायोजन किस हद तक घरेलू था, न कि ऊपर से निर्देशित, यह एक कुशल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सफलता का निर्धारक हो सकता है। दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के बावजूद, दूरसंचार क्षेत्र में विनियामक विकास, जो अधिक घरेलू था, अधिक सफल भी रहा। विद्युत अधिनियम 2003 ने दूरसंचार क्षेत्र में सफल विनियमन के कुछ सबक को शामिल करने का प्रयास किया।

दूसरा, भारत ने पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर वाशिंगटन सर्वसम्मति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, एक नीतिगत उपाय जिसने पूर्वी एशियाई देशों के लिए दुख लाया था। पूर्वी एशियाई संकट के आगमन से पहले स्वतंत्र आर्थिक नीति सोच के लिए भारतीय नीति-निर्माताओं को श्रेय दिया जाना चाहिए। 1991 के संकट के बाद अपनाई गई व्यापार-उन्मुख नीतियों के बारे में उल्लेखनीय बात यह थी कि अवमूल्यन, आयात उदारीकरण और चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता ने भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया। लेकिन पूंजी खाता प्रतिबंधों ने कीमती विदेशी मुद्रा भंडार के आसान बहिर्वाह को रोकने में मदद की।

भारत लगातार उभरती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठा रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रचलित बौद्धिक संपदा व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहा था, जहां इसने दावा किया कि नवोन्मेषकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। जैसे-जैसे दवा उद्योग सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण से निजी (अक्सर बहुराष्ट्रीय) स्वामित्व की ओर बढ़ा और सरकारी भागीदारी कम हुई, विजेताओं, हारने वालों की राजनीति और विकासात्मक विचारों की भूमिका को स्पष्ट रूप से विस्तार से समझने की आवश्यकता थी।

दूसरा, भारत ने संरक्षणवादी कोटा संचालित बहु-फाइबर समझौते से वस्त्र उद्योग को मुक्त

करने के लिए तर्क दिया था। क्या देश चीन की चुनौती का सामना करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि श्रम-समृद्ध देश 2005 के बाद अप्रतिबंधित विश्व बाजारों में परिधान बेचने के लिए खुद को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? आयात प्रतिस्थापन के दशकों में भारत की वस्त्र क्षमता में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण भारतीय नीतियों द्वारा उत्पन्न निर्यात निराशावाद है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियां और संस्थान औद्योगिक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में कैसे बदलेंगे जो भारत को निर्यात के निर्माता के रूप में बढ़ावा दे? वस्त्रों के लिए जो प्रश्न पूछा जा सकता है, वही प्रश्न अन्य विनिर्माण क्षेत्रों और वाणिज्यिक निर्यात उन्मुख कृषि की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए भी पूछा जा सकता है।

क्या घरेलू और क्रमिक समायोजन, उन समायोजनों की तुलना में निष्पादित करना आसान है जो तेजी से और ऊपर से थोपे जाते हैं। समायोजन के लिए अक्सर संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे परिवर्तन आसान नहीं होते क्योंकि वे संगठित समूहों को प्रभावित करते हैं जो यथास्थिति से लाभान्वित होते हैं। फिर दक्षता के पक्ष में संस्थागत परिवर्तन लाने में सफलता या विफलता की क्या व्याख्या है? क्या नीतियाँ और संस्थाएँ बदलती हैं, जब परिवर्तन के पक्षधर तकनीकी विचारों ने नीति स्थापना पर कब्ज़ा कर लिया है? ये विचार क्यों बदलते हैं? क्या क्रमिकता और उसके साथ-साथ जाँच और संतुलन सफल समायोजन की दिशा में आम सहमति और अधिक सुनिश्चित आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं? क्रमिक समायोजन के युग में राजनीतिक अवसरवाद और किराया मांगने के क्या नुकसान हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

मनोहनअंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग के साथ

वैश्वीकरण के तहत भारतीय राज्य पर शोध की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास के बारे में परीक्षण योग्य प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण से उत्पन्न होने वाली संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय

प्रणाली में राज्यों के बीच वितरण कैसे होता है। उदाहरण के लिए, एक विशेष बौद्धिक संपदा व्यवस्था गरीब देशों में दवा कंपनियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच लाभ के संतुलन को बदल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर नियमों को बदलने से अमीर देशों की कर लगाने की शक्ति बढ़ सकती है। एजेंडा सेटिंग के क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसी बहुपक्षीय संस्थागत सेटिंग्स से हटाकर क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में स्थानांतरित करना, वितरण संबंधी परिणामों से भरा हुआ था।

वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहे भारत को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समन्वय के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों से निपटने की जरूरत है, जबकि उस समय आर्थिक स्वतंत्रता भारत की आर्थिक नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत थी। भारत में नीति-संबंधित सामाजिक विज्ञान को अंतरराष्ट्रीय मानदंड गतिशीलता को नियंत्रित करने वाले कारणात्मक तंत्रों का पता लगाने की जरूरत है। क्या मानक केवल शक्ति के वैश्विक वितरण को दर्शाते हैं; या, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सकारात्मक योग स्थितियों पर आधारित किसी प्रकार की तर्कसंगत सहमति; या, ऐसे वैध अधिकार में निहित जवाबदेही के साथ एक वैध सामाजिक उद्देश्य?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारी बातचीत लागत शामिल होगी। यदि प्रक्रिया के अंत में सभी को लाभ मिल सकता है, तो कई राज्य इन लागतों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरे तरीके से कहा जाए तो, औद्योगिक हड़तालें अक्सर विफल हो जाती हैं क्योंकि हड़ताली श्रमिकों द्वारा भुगतान की गई कीमत से ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिनका गैर-हड़ताली श्रमिक भी समान रूप से आनंद ले सकते हैं।

शोध की पहेली यह थी कि वैध अधिराष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुपस्थिति में वैश्विक शासन तंत्र कैसे उभरेगा? क्या वे विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ शक्तिशाली राज्यों के विषम लाभों के कारण उभरेंगे; या सकारात्मक योग स्थितियों को साकार करने के लिए जहां सभी को लाभ होगा; या, उचित तर्क के आधार पर उपयुक्तता के किसी तर्क के कारण?

यथार्थवादीकारणात्मक तंत्र

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को समझाने के लिए एक प्रस्ताव यह हो सकता है कि नियम शक्ति के वैश्विक वितरण को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्तिशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य राज्यों के संबंध में अपनी सापेक्ष शक्ति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियम किसी वैध सामाजिक उद्देश्य के बजाय शक्तिशाली लोगों के हितों को दर्शाते हैं।

यथार्थवादी और नव-यथार्थवादी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य वैध सुपरनैशनल अथॉरिटी की अनुपस्थिति में काम करते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जिसे हॉब्स ने अराजकता के रूप में वर्णित किया है। राज्य जीवित रहने के लिए केवल खुद पर निर्भर हो सकते हैं और शत्रुतापूर्ण दुनिया में खुद का बचाव करने के लिए अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का निर्माण करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में समान रूप से स्थित राज्यों के संबंध में सापेक्ष लाभ के उद्देश्य का पीछा किया, और अक्सर अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य उद्देश्यों और इसके विपरीत में परिवर्तित कर दिया। हॉब्सियन रूपक इस प्रस्ताव का एक शक्तिशाली औचित्य था कि अंतर्राष्ट्रीय नियम शक्ति के वितरण को दर्शाते हैं।

एक उदाहरण देते हुए, यदि किसी मुद्दे पर विकासशील देशों की शक्ति बहुत अधिक है, तो कोई उम्मीद कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ही विचार-विमर्श का स्थल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि महासभा में एक देश-एक वोट प्रणाली ने विकासशील देशों को अधिक शक्ति प्रदान की। दूसरी ओर, यदि कुछ अमीर देशों का प्रभाव बहुत अधिक है, तो संभवतः स्थान विश्व बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ में स्थानांतरित हो जाएगा। ये ऐसे संगठन थे जहां अमीर देशों का संयुक्त राष्ट्र से अधिक प्रभाव था। जगदीश भगवती ने तर्क दिया है कि डब्ल्यूटीओ की एक देश-एक वोट प्रणाली इसे विश्व बैंक या आईएमएफ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक बनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े कई मुद्दों में ताकत ही सही है। राज्य की सीमाओं के पार रेडियो

सिग्नल प्रसारित करने के अधिकार पर कोई समझौता नहीं होने का कारण यह था कि औद्योगिक देश इसे चाहते थे, और विकासशील देश इसे रोक नहीं सकते थे। चूँकि औद्योगिक देशों ने बिना किसी सहयोग के अपना रास्ता बना लिया, इसलिए विकासशील देशों के साथ सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं थी।

सत्ता द्वारा संचालित नियमों का एक और क्लासिक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन व्यवस्था है। एयरलाइन मार्गों के राष्ट्रीय नियंत्रण द्वारा संचालित बरमूडा व्यवस्था, जिसने एकाधिकार को मजबूत किया, 1946 में काफी हद तक ब्रिटेन के हितों को दर्शाती थी। ब्रिटेन, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एयरलाइन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता का नुकसान झेला था, प्रतिस्पर्धा-आधारित रणनीति के पक्ष में नहीं था। इसके बाद, उपनिवेशवाद के उन्मूलन और जेट प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने ब्रिटेन की धरती पर अमेरिका की लैंडिंग अधिकारों की आवश्यकता को कम कर दिया। जब ब्रिटेन अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हुआ, तो अमेरिका ने सफलतापूर्वक नीदरलैंड में यातायात मोड़ने की धमकी दी। ब्रिटेन ने अंततः अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, जो अमेरिकी शक्ति और हितों को दर्शाता था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति की गतिशीलता को समझने में असमर्थता के कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापार वार्ता का उरुग्वे दौर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने दौर की शुरुआत से लेकर नए दौर में सेवाओं और बौद्धिक संपदा संरक्षण को शामिल करने तक हर चीज का विरोध किया। यह वार्ता से बाहर रहा और इसने कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई, जो डब्ल्यूटीओ के भीतर इसके हितों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती थी। 10 विकासशील देशों का समूह, जिसमें भारत, मिस्र और ब्राजील शामिल थे, बहुत जल्दी बिखर गया, जिससे भारत को बहुत निराशा हुई। भारत ने खुद को बिना किसी दोस्त के अकेला पाया। अंत में इसने अन्य व्यापारिक देशों द्वारा किए गए सौदों को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने अपने हितों के लिए अधिक सार्थक बातचीत की थी।

भारत ने व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के संरक्षण के लिए वार्ता का विरोध किया। सबसे पहले, भारत का अपनी बौद्धिक संपदा के बेहतर संरक्षण का पूर्ण विरोध, व्यापार अभिविन्यास की कमी की धारणा पर आधारित था। यह नीतिगत स्थिति सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अपने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की ठोस समझ पर आधारित नहीं थी, जिन्हें बौद्धिक संपदा संरक्षण की आवश्यकता होगी। भारत का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम), जो कुछ ही वर्षों में एक महत्वपूर्ण लॉबी के रूप में उभरा, भारत की बौद्धिक संपदा के संरक्षण का पक्षधर था। अनुसंधान और विकास सेवाएँ, एक उभरता हुआ महत्व का क्षेत्र जहाँ इंटेल, ड्यू पॉन्ट और जीई जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में भारी निवेश किया था, को भी बौद्धिक संपदा संरक्षण की आवश्यकता थी। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, अगर भारत में बौद्धिक संपदा को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं किया गया, तो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास गहन निवेश की संभावना नहीं थी।

बौद्धिक संपदा व्यवस्था, जिसे भारत ने बिना उचित बातचीत के स्वीकार कर लिया, वह अमेरिका के दवा क्षेत्र के हितों के लिए काफी हद तक अनुकूल थी। जगदीश भगवती ने तर्क दिया कि डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के परिणामस्वरूप नवप्रवर्तकों की सुरक्षा के मामले में अतिशयोक्ति हुई, जब उत्पाद पेटेंट पर 20 साल का एकाधिकार नवप्रवर्तकों को दिया गया। नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट को नवप्रवर्तकों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता थी। भगवती ने तर्क दिया कि प्रतिस्पर्धा को दबाने वाले ऐसे अनन्य एकाधिकार अधिकारों को तकनीकी प्रगति के इतिहास में कभी भी नवप्रवर्तन के लिए आवश्यक नहीं माना गया। इस एजेंडे को विश्व बैंक ने डब्ल्यूटीओ से दूर कर दिया, जो अमेरिकी दवा लॉबी के हितों से अधिक सीधे तौर पर प्रेरित था। अगर भारत ने एक व्यापारिक व्यवस्था के भीतर अपने हितों को समझा होता, तो वह उन देशों के पक्ष में तराजू को झुका सकता था, जो अधिक सीमित बौद्धिक संपदा संरक्षण के पक्ष में थे।

दूसरा, भारत ने शुरू में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते पर किसी भी बातचीत का

विरोध किया था, जब उसकी सेवाएँ निर्यात आय का एक प्रमुख स्रोत बनने वाली थीं। अगर भारत ने इस संभावना को समझा होता, तो वह बौद्धिक संपदा संरक्षण जैसे अन्य क्षेत्रों में कुछ रियायतों के बदले में सेवा वार्ता में अमेरिका का पक्ष ले सकता था।

भारत को GATS के भीतर प्राकृतिक व्यक्तियों की अधिक मुक्त आवाजाही के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत के निर्यात की सेवा करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को उन स्थानों पर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की आवश्यकता है जहाँ भारतीय कंपनियाँ विदेशी स्थानों पर सॉफ़्टवेयर सेवाएँ प्रदान करती हैं। फिर भी, इस क्षेत्र में विकसित देशों की रियायतें पर्याप्त नहीं रही हैं। भारत को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि वह अपने हितों की रक्षा के बदले में अन्य देशों को क्या पेशकश कर सकता है।

बहुपक्षीय व्यापार जगत में, जहाँ नए वाणिज्यिक नियमों को घरेलू कानूनों में शामिल किया जा रहा था, भारत को रियायतें देने और लाभ प्राप्त करने के लागत और लाभ को तौलना था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत को सत्ता हितों की राजनीति को समझने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में समान विचारधारा वाले राज्यों के गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता थी।

कई बार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय घरेलू लॉबी को विकासशील देशों में समान रूप से रुचि रखने वाले दलों के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत के नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) को अमेरिका में आउटसोर्सिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए भारतीय राज्य की सहायता करनी थी, तो उसे अमेरिका में वित्तीय और औद्योगिक हितों के साथ प्रभावी ढंग से लॉबी करनी होगी, जिनके हित NASSCOM के समान थे। इसे अमेरिका में ट्रेड यूनियनों के खिलाफ प्रभावी ढंग से युद्ध छेड़ना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के हितों को आगे बढ़ाने से घरेलू लॉबी के साथ-साथ राज्य को भी एक अंतरराष्ट्रीय भूमिका मिली। सामाजिक विज्ञान

साहित्य वैश्विक स्तर पर एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य और घरेलू गठबंधन के स्तर पर हितों के संरेखण की ओर इशारा कर सकता है।

कभी-कभी, एक विशेष प्रकार की घरेलू संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद मानकों को निर्धारित करने में अधिक आवाज़ उठाने में सक्षम बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (आईईसी) दो प्रासंगिक उदाहरण हैं। एक अच्छी तरह से शोध किए गए अध्ययन के अनुसार, उत्पाद संबंधी मानकों को निर्धारित करने के क्षेत्र में यूरोपीय मानक सेटिंग संस्थान, अमेरिकी संस्थानों की तुलना में अपनी प्राथमिकताओं को आवाज़ देने के लिए बहुत बेहतर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरोपीय मानक सेटिंग, जिसे सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, बेहतर संस्थागत और पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित थी। बेहतर संस्थागतकरण ने हितों की अभिव्यक्ति में अधिक विविधता की अनुमति दी। हितों के पदानुक्रमिक क्रम का मतलब था कि प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर का मानक सेटिंग संगठन एक आवाज़ में बोलता था।

अमेरिका में, मानक स्थापित करने वाले संगठनों का संगठन निजी विखंडित हितों द्वारा अधिक संचालित था, ऐसे माहौल में जहाँ सूचना न तो स्वतंत्र रूप से साझा की जाती थी, न ही एक स्वर से प्रसारित की जाती थी। दोषपूर्ण संस्थागत व्यवस्था के कारण अमेरिकी मानक स्थापित करने में पिछड़ रहे थे।

उत्पाद मानक व्यापार में एक महत्वपूर्ण बाधा या सुविधाकर्ता हो सकते हैं। भारत को अपने निर्यात-उन्मुख क्षेत्र के हितों को सुरक्षित करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मानकों को निर्धारित करने में उसकी भी कुछ भूमिका हो। व्यापार योग्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने की राजनीतिक अर्थव्यवस्था इस बात पर प्रकाश डाल सकती है कि भारत के व्यापार को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है।

क्षेत्रवाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बन रहा था। यूरोपीय संघ एक बड़े

आंतरिक बाजार में फैल गया था। अमेरिका ने रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से क्षेत्रवाद की ओर कदम बढ़ाया। इसने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग पहल (APEC) के माध्यम से एशिया में अपने विकल्प भी खुले रखे। अमेरिका का मुक्त व्यापार क्षेत्र भी एक संभावना थी। एशिया में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक मजबूत व्यापार क्षेत्र बन रहा था, जिसमें आसियान प्लस 3 के माध्यम से विस्तारित एकीकरण था, जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। पूर्वी एशियाई क्षेत्रवाद का अधिकांश हिस्सा, जिसे औपचारिक रूप नहीं दिया गया था, व्यापार सहायक निवेश पैटर्न के माध्यम से हुआ।

भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान के साथ क्षेत्रीय स्तर पर जुड़ना शुरू कर दिया है। बहुपक्षीय शासन तंत्र के बजाय क्षेत्रीय में भाग लेने के भारत के क्या लाभ और लागतें थीं? दूसरा, पूर्वी एशिया जैसे भौगोलिक रूप से समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ भारत के एकीकरण की राजनीतिक गतिशीलता क्या थी? क्या भारत के वैश्विक बनने के बाद व्यापारिक हितों और बाजारों के विस्तार की आवश्यकता ने इस तरह के क्षेत्रीय एकीकरण को सुगम बनाया?

भारत बहुपक्षीय स्तर पर साझा चिंता के अनेक व्यापारिक मुद्दों, जैसे व्यापार और पर्यावरण, व्यापार और श्रम, तथा बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं पर दक्षिण एशियाई एकजुटता का माध्यम कैसे बन सकता है? इन सभी मुद्दों में, दक्षिण एशिया के अधिकांश देश गरीब और पूंजी की कमी के कारण उन अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रतिकूल थे जो उनके व्यापार के प्रति संरक्षणवादी हो सकते हैं। क्या बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर दक्षिण एशियाई एकजुटता के कोई अन्य क्षेत्र थे? क्या बहुपक्षीय स्तर पर दक्षिण एशियाई एकजुटता की राजनीति को कार्यान्वित करने का कोई प्रशंसनीय तरीका हो सकता है?

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय सहयोग को किस तरह सुगम बनाया जा सकता है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के सामने जो समस्या

है, उसे यथार्थवादी प्रतिमान के भीतर समझा जा सकता है। दक्षिण एशिया के छोटे देशों को डर लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार और विविधता उन्हें भारत के संबंध में कमज़ोर बना देगी, भले ही भारत के साथ व्यापार करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो। प्रतिबंधों या सैन्य संघर्षों की स्थिति में ऐसी कमज़ोरी इन अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकती है। क्या अराजकता और सत्ता से परे ऐसे कारण हो सकते हैं जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बड़े और छोटे देशों के बीच वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए प्रशंसनीय तंत्र का सुझाव देते हैं?

तर्कसंगत स्व-हित पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि राज्य किस तरह से तर्कसंगत स्वार्थी कारणों से कुछ मानदंड विकसित करके अपने हितों को साकार कर सकते हैं। पारस्परिकता जैसे मानदंड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह से विकसित हो सकते हैं, जिससे सभी के लाभ को बढ़ावा मिले। ऊपर वर्णित यथार्थवादी दुनिया के विपरीत, यह एक सकारात्मक योग खेल का माहौल था, जहाँ संस्थाएँ ऐसे लाभों को साकार करने में मदद कर सकती थीं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुपस्थिति ने उप-इष्टतम परिणामों को जन्म दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में तर्कसंगतता आधारित तर्क अक्सर कैदी की दुविधा (पीडी) खेल से एक सादृश्य लेते हैं। पीडी खेल में, इस तथ्य से सहयोग बाधित होता था कि दो कैदियों के बीच कोई संवाद नहीं था। इस खेल में, दो कैदियों को एक छोटे से अपराध के लिए पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस को एक बड़े अपराध का संदेह था। अगर कैदी बड़े अपराध के बारे में चिल्लाते या चुपके से बताते, तो उन्हें तीन साल की जेल हो जाती। अगर दोनों ने सहयोग किया और चिल्लाया नहीं, तो उन्हें दो साल तक जेल में रहना पड़ता। अगर एक चिल्लाता लेकिन दूसरा नहीं, तो सहयोग करने वाले को इनाम के तौर पर एक साल की सजा मिलेगी लेकिन जो चिल्लाता, उसे चार साल की जेल होगी। संवाद की कमी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दोनों कैदी चिल्लाने के कारण तीन साल की जेल में चले गए, जबकि अगर दोनों ने सहयोग किया होता, तो उन्हें दो साल की सजा मिल सकती थी।

रॉबर्ट एक्सलरोड ने पाया कि अगर प्रोटोटाइप कैदियों को अनंत संख्या में पीडी गेम खेलने की अनुमति दी जाए तो कैदियों के बीच संचार विकसित हो सकता है। मिशिगन विश्वविद्यालय में आयोजित कंप्यूटर टूर्नामेंट में, एक्सलरोड ने पाया कि पारस्परिकता की रणनीति ने पीडी गेम के बाद दो लगातार कंप्यूटर टूर्नामेंट जीते। इस रणनीति का उपयोग खेल को सहयोग करके शुरू करने और उसके बाद, सहयोग के साथ एक सहयोगी चाल को पुरस्कृत करने और, दलबदल (या चीख़ने) को दलबदल से दंडित करके किया गया था। इस तरह, पारस्परिकता के लगातार उपयोग से सहयोग हुआ। कैदियों ने चीखना बंद कर दिया और पारस्परिकता के मानदंड को विकसित करके एक-दूसरे के साथ रहना सीख लिया।

एक्सेलरोड ने पाया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वास्तविक जीवन में खाई युद्ध एक सहयोग खेल के रूप में खेला गया था, क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिकों ने समय के साथ एक दूसरे के साथ रहना सीखा था। जर्मन और फ्रांसीसी सेनाओं ने हवा में अपने शॉट फायर करना सीखा, यह दिखावा करते हुए कि वे लड़ रहे थे, ताकि उनके कमांडरों को पता न चले कि वे वास्तव में नहीं लड़ रहे थे। इस मामले में, अगर सैनिकों ने हवा में गोली चलाई और वरिष्ठों को इसके बारे में पता नहीं चला, तो सैनिक बच सकते थे। अगर, दूसरी ओर, वे एक दूसरे को मारते रहे, तो कई और सैनिक अपनी जान गंवा देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के छात्रों के लिए तर्कसंगत स्वार्थ पर आधारित पीडी खेल में सहयोग से क्या सबक मिलते हैं? संस्थाएँ दो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। वे बार-बार पार्टियों को सौदेबाजी की मेज पर लाने में मदद कर सकती हैं, ताकि पारस्परिकता एक रणनीति के रूप में विकसित हो सके। खेल सिद्धांत के शब्दों में, वे एक शॉट वाले पीडी गेम को ऐसे खेल में बदल सकते हैं जिसमें अनंत संख्या में खेल शामिल हों। दूसरा, वे संबंधित पक्षों को इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि कौन सा राज्य सहयोग कर रहा था और कौन सा दलबदल कर रहा था। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषता ऐसी स्थितियों से होती है जहाँ सहयोग को दलबदल से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ राज्यों के

व्यवहार की निगरानी कर सकती हैं और क्लब के अन्य सदस्यों के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को सार्वजनिक कर सकती हैं। यदि राज्यों को पता हो कि उन्हें बार-बार सौदेबाजी की मेज पर मिलना होगा

व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता (GATT) कई व्यापार दौरों में शुल्कों को कम करने में सफल रहा। सबसे पहले, GATT द्वारा सुगम बनाए गए व्यापार वार्ताओं के बार-बार दौरों ने बार-बार पार्टियों को सौदेबाजी की मेज पर लाकर एक अधिक संस्थागत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के जन्म को जन्म दिया हो सकता है। दूसरा, WTO जैसी संस्थाओं ने राज्यों के व्यवहार की निगरानी इस तरह से की जिससे अन्य राज्यों को सहयोग और दलबदल में अंतर करने में मदद मिली। व्यापार के खेल में सकारात्मक राशि को व्यापार वार्ता के विभिन्न दौरों में संस्थागत बनाया गया। इस तरह के तंत्रों ने विश्व अर्थव्यवस्था में कमजोर खिलाड़ियों के आराम के स्तर को बढ़ाया। यह एक कारण हो सकता है कि चीन ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के बजाय WTO को प्राथमिकता दी।

व्यापार सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया तथा विवाद निपटान तंत्र के रूप में न्यायिक तंत्र स्थापित किए गए। जब अमेरिकी लॉबी ने भारत के झींगा निर्यात को रोकने के लिए कछुओं के लिए पर्यावरण संबंधी चिंता का बहाना बनाया, तो WTO का विवाद निपटान तंत्र भारतीय झींगा निर्यातकों की सहायता के लिए आया। WTO के विवाद निपटान तंत्र के नियमों के आगे झुकते हुए, अमेरिका ने WTO के फैसले का सम्मान किया तथा भारतीय झींगा निर्यातकों को टैरिफ की धमकी नहीं दी। WTO के जन्म के बाद से अमेरिका ने अपने विवाद निपटान तंत्र के साथ व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग बंद कर दिया है।

WTO कानून घरेलू राष्ट्रीय स्तर के विधानों में अंतर्निहित था। ऐसे कानूनों का इस्तेमाल विदेशी गंतव्यों में भारतीय बौद्धिक संपदा के शोषण को रोकने के लिए किया जा सकता है। घरेलू न्यायालयों के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के वैधीकरण का अध्ययन करने की आवश्यकता

थी। बौद्धिक संपदा मानदंडों के घरेलू वैधीकरण को एक आसान हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए, वंदना शिवा, लिंडा बुलार्ड और मैग्डा अल्वोएट ने अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) और यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में डब्ल्यू.आर. ग्रेस (10 मई, 2000)। उन्होंने दिखाया कि यूएसडीए और ग्रेस ने नीम के पेड़ के उपयोगी अनुप्रयोगों का पेटेंट कराकर भारत के पारंपरिक ज्ञान को चुराया है। बासमती पेटेंट, जो भारत की पारंपरिक बौद्धिक संपदा की इसी तरह की चोरी थी, को भी इसी तरह चुनौती दी जानी चाहिए।

क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय सहयोग के मामले में व्यापार संबंधों के निर्माण के लिए तर्कसंगत पारस्परिकता आधारित तकनीक विकसित हो सकती है? भारत और श्रीलंका ने वर्षों के संदेह के बाद एक सफल मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? नेपाल ने भारत के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था क्यों की, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध इतने सौहार्दपूर्ण नहीं थे?

क्या पारस्परिकता की रणनीति भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका की तरह, जबरदस्त व्यापार क्षमता रखते हैं, जिसे वर्तमान में भारी मात्रा में सीमा पार तस्करी के माध्यम से साकार किया जा रहा है। बांग्लादेश को चिंता है कि भारत पर व्यापार निर्भरता एक बड़े और आधिपत्य वाले पड़ोसी के संबंध में उसकी भेद्यता को बढ़ाएगी। क्या भारत आधिपत्यपूर्ण इरादे की कमी का संकेत देने और बांग्लादेश के संबंध में पारस्परिकता का खेल शुरू करने के लिए सही कदम उठा सकता है? क्या भारत-लंका मुक्त व्यापार समझौते की कहानी से कोई सबक सीखा जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा अपनाई गई पारस्परिकता-आधारित रणनीतियों ने दक्षिण एशियाई सहयोग में वांछित परिणाम उत्पन्न किए?

वैध सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित अंतर्राष्ट्रीय मानदंड

तीसरा, अपेक्षाकृत कम अध्ययन किया जाने वाला क्षेत्र, जो तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहा

है, वह है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मानदंडों की भूमिका। क्या ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले तर्कसंगत स्वार्थ से कहीं अधिक किसी चीज से प्रेरित हों? ऐसा हो सकता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ अनुनय, अनुकरण और आंतरिककरण के माध्यम से अपना स्वयं का जीवन विकसित करती हैं। जब कोई मानदंड वैधता प्राप्त कर लेता है, तो मानदंड की औचित्य में विश्वास अच्छा माना जाता है। जब कोई मानदंड अभी तक स्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्रेरक तर्क देने की आवश्यकता होती है, और, मानदंड उद्यमियों को ऐसे तर्कों का प्रचार करने की आवश्यकता होती है।

संप्रभु समानता, मानवाधिकार, उदार लोकतंत्र, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक पूंजी और इसी तरह के अन्य मुद्दों के पक्ष में तर्कों को पहले सुना जाना चाहिए और फिर उन्हें आत्मसात किया जाना चाहिए। तर्क बनाने, उन्हें फैलाने और फिर ऐसे तर्कों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंड गतिशीलता के जीवन चक्र का गठन किया। तर्क-वितर्क के शुरुआती चरणों में अधिकांश लोग मानदंड की अनुपयुक्तता के बारे में आश्वस्त होंगे। एक बार आत्मसात हो जाने के बाद, अधिकांश लोग सोचेंगे कि मानदंड से प्रेरित व्यवहार के अलावा कुछ भी उचित नहीं है।

कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्थाएं विद्वान समुदायों के काम से निकले वैज्ञानिक ज्ञान के परिणामस्वरूप पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, भूमध्य सागर को साफ करने की योजना भूमध्य सागर में प्रदूषण की अस्थिरता पर वैज्ञानिक सहमति से उभरी। 1977 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने नीति परिवर्तन का नेतृत्व किया। विशेषज्ञ ज्ञान नौकरशाही के भीतर समाहित हो गया जिसने भूमध्य सागर को साफ करने का बीड़ा उठा लिया। इसी तरह, ओजोन परत पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैज्ञानिकों के बीच इस आम सहमति से सुगम हुआ कि ओजोन को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल की ओजोन परत के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

विश्व व्यवस्था सिद्धांतकारों ने ऐसे विचारों पर आधारित संवैधानिक ढांचे के लिए तर्क दिया है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संरचित करने में मदद करते हैं। अंतर्निहित उदारवाद के कीनेसियन समझौते के बारे में तर्क दिए गए हैं, जिसके बारे में तर्क दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैक्स अमेरिकाना के परिणामस्वरूप बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों के पीछे यही भावना थी। पैक्स ब्रिटानिका की विशेषता वाली अहस्तक्षेप की भावना को अंतर्निहित उदारवाद के मानदंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अंतर्निहित उदारवाद एक ऐसा मानदंड था जो सामाजिक लोकतांत्रिक अपवादों के साथ बाजार उन्मुखीकरण की अनुमति देता था। पश्चिम में कई पूंजीवादी राज्य, जो लोकतंत्र भी थे, को इस संभावना के साथ रहना पड़ा कि राज्य के हस्तक्षेप से रहित अनियमित बाजार मंदी, अवसाद और चुनावी हार पैदा कर सकते हैं। इसलिए, अमेरिका के लिए यूरोप के हितों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण था, जिनके विचारों को जॉन मेनार्ड कीन्स ने अमेरिकी प्रतिनिधि हैरी डेक्सटर व्हाइट के साथ अपनी बहस में कुशलता से व्यक्त किया था।

भारत को प्रेरक तर्क के क्षेत्र में अपना उचित स्थान लेने की आवश्यकता है। संप्रभु समानता, लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय जैसे विचारों को बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शक्तिशाली लोगों की शिकारी प्रकृति को उजागर करने वाले अनुभवजन्य केस स्टडीज, ठोस अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर, प्रेरक तर्क उत्पन्न कर सकते हैं जो इस तरह के अन्याय से लड़ सकते हैं।

इस तरह के अध्ययन मौजूदा विषम स्थिति से निपटने के लिए मानक विचारों को आगे बढ़ा सकते हैंवैश्विक अर्थव्यवस्था में.

शक्ति, तर्कसंगतता और सामाजिक उद्देश्य

यह अनुभाग एक केस स्टडी के माध्यम से प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार विशेष अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर व्यवस्था में विचार-विमर्श का वर्णन करके राजस्व के वैश्विक

वितरण को प्रभावित कर सकते हैं।

इसी तरह के मुद्दों-क्षेत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्न थे: क) अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण के पीछे कारणात्मक तंत्र; तथा, ख) अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्माण की गतिशीलता को देखते हुए भारत किस तरह हस्तक्षेप कर सकता है। आईएमएफ के भीतर शर्तों पर आम सहमति; विश्व बैंक के भीतर संरचनात्मक समायोजन; म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश के अनुकूल गंतव्यों को नियंत्रित करने वाले मानदंड; तथा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश से जुड़ी शर्तें; अन्य व्यवस्थाएं हैं जिनकी भारत द्वारा बारीकी से जांच करने तथा उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जब भारत का विकास तेजी से अंतरराष्ट्रीय पूंजी पर निर्भर होता जा रहा था।

अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कराधान को नियंत्रित करने वाले नियम अमीर या गरीब देशों को लाभ पहुंचा सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। इन नियमों की विषय-वस्तु भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उस तरह के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में संलग्न था, जिसे नए नियमों में शामिल किया जाएगा। मौजूदा सिद्धांत, जो देशों के बीच एक हजार से अधिक द्विपक्षीय संधियों में अंतर्निहित थे, की समीक्षा इस तथ्य के मद्देनजर की जा रही थी कि द्विपक्षीय सेटिंग्स के भीतर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को नियंत्रित करना कठिन होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम, जिन पर OECD के भीतर विचार-विमर्श किया जा रहा था, अब विश्व बैंक, IMF और OECD के बीच चर्चा के रूप में समन्वित किए जा रहे थे।

डिजिटलीकरण ने कॉर्पोरेट कराधान के लिए चुनौती पेश की। "निवास" के आधार पर कराधान अमेरिका के लिए अनुकूल था। "निवास" वह जगह थी जहाँ बंडल उत्पाद के लिए सबसे केंद्रीय फर्म ने अपने सबसे मजबूत संबंध बनाए रखे। Microsoft और Intel भारत में महत्वपूर्ण मूल्य बना रहे हो सकते हैं, लेकिन वे अमेरिका में रह सकते हैं। अमेरिकी निवासी आय वैश्विक रूप

से प्राप्त की गई थी। दूसरी ओर, "स्रोत" वह स्थान था जहाँ मूल्य बनाया जा रहा था। Microsoft बैंगलोर में अपनी सहायक कंपनी में मूल्य बना सकता था, हालाँकि इसका मुख्यालय सिएटल में था।

अमेरिका द्वारा प्रस्तावित निवास-आधारित कराधान के सिद्धांत पर विकासशील देशों की आपत्तियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं। यदि स्रोत आधारित कराधान मार्गदर्शक सिद्धांत होता, तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए मूल्य पर भारत में कर लगाया जाता, और अमेरिका में बनाए गए मूल्य पर अमेरिका में कर लगाया जाता।2 हालाँकि, यदि "निवास" कराधान का सिद्धांत होता, तो कुल मूल्य सृजन पर अमेरिका में कर लगाया जाता। निवास आधारित कराधान पूंजी की कमी वाले उन देशों के हितों के विपरीत था, जिन्होंने मूल्य का सृजन किया, लेकिन जहाँ डिजिटल मार्ग से व्यापार करने वाली प्रमुख फर्मों का मुख्यालय नहीं था। दूसरा, निवास-आधारित कराधान से कर पनाहगाहों या कम कर वाले स्थानों का प्रसार भी हो सकता है। यदि कराधान का स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म कहाँ शामिल है, न कि जहाँ मूल्य सृजन हो रहा है, तो कौन सी बात फॉर्मों को कम कर वाले स्थानों पर खुद को पंजीकृत करने और मूल्य-निर्माण गतिविधियों को अन्य स्थानों पर आउटसोर्स करने से रोकेगी?

वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कराधान जैसी समस्याएं सामान्य प्रकृति की थीं। वैश्वीकरण ने अधिक हद तक जवाबदेह, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक शासन की मांग की। सबसे शक्तिशाली के शोषण के खिलाफ जांच और संतुलन के साथ नियम निर्माण में वैधता और जवाबदेही की डिग्री जितनी अधिक होगी, ये नियम उतने ही अधिक स्थायी और विकास के अनुकूल होने की संभावना थी। दूसरी ओर, इसका मतलब यह होगा कि शक्तिशाली को जांच और संतुलन के साथ अधिक स्थायी संवैधानिक संरचना के पक्ष में अपने अल्पकालिक हितों का त्याग करना होगा। शक्ति का वितरण ऐसी संरचना नहीं देगा। तर्कसंगत स्वार्थ और वैध सामाजिक उद्देश्य का कौन सा संयोजन ऐसा रोडमैप प्रदान कर सकता है, यह जांच के योग्य था। फिर भी, यथार्थवाद वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में शोषण की गतिशीलता को समझने

के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिमान बना हुआ है।

सामाजिक कमज़ोरी को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में राज्य की भूमिका

सामाजिक भेद्यता

वैश्वीकरण दो कारणों से धन और सामाजिक भेद्यता दोनों को बढ़ा सकता है। सबसे पहले, जैसे-जैसे देश बाहरी बाजारों पर अधिक निर्भर होते जाते हैं, मंदी, तेल के झटके और अन्य स्थानों पर लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न नीति विकल्पों के कारण अक्सर नौकरी छूट जाती है। यही कारण है कि स्कैंडिनेविया में अत्यधिक व्यापार पर निर्भर राज्यों में सबसे प्रभावी कल्याणकारी राज्य भी हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्वीकरण OECD देशों में काफी हद तक मजबूत कल्याणकारी राज्यों को खत्म करने में सक्षम नहीं है। दुनिया के अधिकांश सबसे अमीर देशों में कल्याण की राजनीति और नेटवर्क अपेक्षाकृत अच्छी तरह से स्थापित हैं। कुछ सुविचारित विवरणों के अनुसार, ये राज्य कराधान के मुद्दे पर शासकों और शासितों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पैदा हुए थे। विकासशील दुनिया की कहानी इसके बिलकुल उलट है। उपनिवेशवाद के बाद राज्य निर्माण उन संघर्षों से काफी अलग था जो पश्चिम में नागरिक और राज्य के बीच संघर्ष की विशेषता रखते थे। एक प्रेरक अंतर-राष्ट्रीय अध्ययन से पता चला है कि विकासशील दुनिया में कल्याणकारी राज्य का पतन हो रहा है। पश्चिम और पूर्व में लोकतंत्र और बाजारों का तर्क कैसे अलग हो सकता है? यदि शक्तिशाली ट्रेड यूनियन आंदोलनों के साथ सामाजिक लोकतंत्र, पश्चिम में विकास मॉडल की सफलता का एक प्रशंसनीय कारण प्रतीत होता है, तो क्या विकासशील दुनिया को भी ऐसे सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडल की आवश्यकता नहीं होगी?

दूसरा, बाजार, जो दक्षता और विकास उत्पन्न करते हैं, असमानताओं को भी बढ़ाते हैं। वे अक्सर हाशिए पर पड़े समूहों का ख्याल नहीं रख पाते जो बाजार के दायरे में नहीं आते। निजी पहल से प्रेरित भारत की दूरसंचार क्रांति शहरी क्षेत्रों में सफल रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में

उतनी नहीं। इससे पहले से मौजूद ग्रामीण-शहरी विभाजन और बढ़ सकता है। निजी अस्पताल तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। कृषि में उत्पादक निवेश में गिरावट आई है, लेकिन अमीर किसानों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी पर कोई अंकुश नहीं लगा है। प्राथमिक शिक्षा को और अधिक तेजी से फैलाने की जरूरत है।

राज्य को अक्सर अपनी स्वायत्तता का उपयोग कर प्रभावी ढंग से कर लगाने और पुनर्वितरण करने के लिए अमीर और गरीब के बीच सकारात्मक योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। समाज में गरीब और हाशिए के समूहों पर कर लगाने और पुनर्वितरण करने की भारतीय राज्य की क्षमता कम होती जा रही थी, लेकिन भारत में संपन्न और मध्यम वर्ग को लाभ प्रदान करने और खर्च करने की इसकी क्षमता निरंतर जारी रही। भारत की दूरसंचार कहानी से एक उदाहरण देने के लिए, स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी में वायरलेस को बुनियादी सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई थी क्योंकि यह माना जाता था कि वायरलेस तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को तार का उपयोग करने वाले पारंपरिक की तुलना में कम खर्चीली होगी। बुनियादी सेवा ऑपरेटरों ने शहरी क्षेत्रों में सेलुलर ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया, लेकिन अपनी ग्रामीण प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। आश्चर्य की बात यह थी कि नियामक और सरकार द्वारा बुनियादी सेवा ऑपरेटरों की ग्रामीण प्रतिबद्धताओं को किस तरह से नजरअंदाज किया गया। दूसरा, जिस तरह से केंद्र में विभिन्न दलों के तहत भारतीय राज्य ने एनरॉन के साथ सौदे पर बातचीत की, वह एक किराया-मांगने वाले राज्य की तरह अधिक था, जो बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रतिबद्ध था।

वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दौर में पीछे हटने वाला राज्य पूंजी और शक्तिशाली हितधारकों को अत्यधिक आवाज़ दे सकता है। वैश्विक आर्थिक एकीकरण के लिए राज्य को पूंजी के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत प्रति वर्ष 7% से 8% की दर से विकास करे। लेकिन मानव विकास के निम्न स्तरों पर पुनर्वितरण के बिना विकास, और न्यूनतम कल्याणकारी राज्य, पूंजी या श्रम के दीर्घकालिक हितों में नहीं हो

सकता। पूंजी और अमीर किसान लॉबी द्वारा भारतीय राज्य पर कब्ज़ा करने और कल्याण में गिरावट के बीच संबंधों की जांच करना ज़रूरी था।

क्षेत्रीय असमानता

आर्थिक उदारीकरण और कठोर बजट प्रतिबंधों ने राज्यों को संसाधन आवंटित करने में केंद्र की भूमिका को कम कर दिया है। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई है। निजी निवेश की बढ़ती भूमिका ने राज्यों को विकास की पहल करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की। औद्योगिक लाइसेंसिंग के उन्मूलन ने यह सुनिश्चित किया कि विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निजी निवेश उन राज्यों में जाएंगे जहां उत्पादकता में सबसे अधिक वृद्धि होगी। निवेशकों ने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक सभ्य कानूनी प्रशासनिक प्रणाली; बिजली, दूरसंचार और सड़कों के रूप में बुनियादी ढाँचा; और एक कुशल और अनुशासित कार्यबल की मांग की। निवेश को आकर्षित करने के लिए सुशासन आवश्यक था।

मोंटेक अहलूवालिया ने तर्क दिया है कि उन्होंने जिन 14 भारतीय राज्यों का अध्ययन किया है, उनमें सार्वजनिक निवेश के बजाय निजी निवेश राज्य-स्तरीय विकास दरों के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से सहसंबद्ध था। इसका तात्पर्य यह है कि अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संबंध में निजी निवेश के उच्च स्तर वाले राज्यों में तेजी से विकास होने की संभावना है। संसाधनों के उपयोग की अधिक दक्षता के कारण निजी निवेश विकास के साथ अधिक सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हो सकता है।

राज्य योजना व्यय का स्तर, जो निवेश का लगभग 10 प्रतिशत था, ने विकास पर कोई असर नहीं डाला। उड़ीसा, जिसका राज्य योजना-जीएसडीपी आवंटन सबसे अधिक (7.10 प्रतिशत) था, 3.25 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पश्चिम बंगाल, जिसका योजना-जीएसडीपी अनुपात सबसे कम (2.70 प्रतिशत) था, 6.90 प्रतिशत की दर से बढ़ा। राज्य योजनाओं में विशेष रूप से बिजली और सिंचाई के लिए खराब तरीके से लक्षित सब्सिडी ने बजटीय समस्याएं पैदा कीं।

1992 में राज्य बिजली बोर्ड का घाटा राज्य योजनाओं का लगभग 10 प्रतिशत था। 1999 में 25,000 करोड़ रुपये पर, वही आंकड़ा राज्य योजनाओं के 30 प्रतिशत तक बढ़ गया था। राज्यों में 1071 सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 247 ही लाभ कमा रहे थे। कृषि पर कर नहीं लगाया जा सकता था। शहरों में नागरिक सुविधाएं विफल हो रही थीं, जबकि उसी समय समस्या का समाधान करने के लिए नगरपालिका कर बढ़ाना कठिन था।

यदि हम 1980-90 और 1991-98 की अवधि पर विचार करें तो आर्थिक सुधारों ने राज्यों के बीच विकास के नेताओं और फिसड्डी राज्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य को बदल दिया। 1991 और 1998 के बीच जिन 14 राज्यों के लिए तुलनात्मक डेटा उपलब्ध थे, उनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल थे, सभी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष या उससे अधिक थी। मध्यम राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल थे, जो प्रति वर्ष 5.5 और 6 प्रतिशत के बीच बढ़े। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने सुधार अवधि के दौरान अपनी विकास दर में सुधार किया। राजस्थान की विकास दर 1980-1990 के दौरान 6.60 से मामूली रूप से घटकर 1991-98 की अवधि में 5.85 हो गई। विचाराधीन 14 राज्यों की लगभग एक तिहाई जनसंख्या वाले इन तीन राज्यों में गरीबों की संख्या भी सबसे अधिक है।

राज्यों के बीच असमानता के लिए गिनी गुणांक 1980 में 0.152 से बढ़कर 1991 में 0.175 और 1998 में 0.233 हो गया। सुधार अवधि के दौरान 14 राज्यों के भीतर असमानता बढ़ी। अच्छी खबर यह थी कि अगर सुधार से पहले और बाद की अवधि को एक साथ माना जाए तो 14 राज्यों में सबसे अमीर और बहुसंख्यक राज्यों के बीच असमानता में कमी आई थी। सुधार-पूर्व अवधि में पंजाब और हरियाणा सबसे अमीर राज्य थे। सुधार-पश्चात अवधि में उनकी वृद्धि दर क्रमशः 4.77 और 5.13 प्रतिशत तक धीमी हो गई। बुरी खबर यह थी कि तीन सबसे गरीब राज्य न केवल पंजाब और हरियाणा के संबंध में गरीब हो रहे थे, बल्कि बाकी के संबंध में भी गरीब हो रहे थे।

बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने भारतीय संघवाद के लिए चुनौती पेश की। भारत एक ही समय में विकासात्मक और शिकारी दोनों तरह से विकसित हो सकता है, जिससे असमानताएं बढ़ रही हैं और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम हो रहे हैं। जबकि चीन में, सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहे थे, भारत के लिए बिल्कुल विपरीत सच था।

क्षेत्रीय असमानताओं को रोकने के लिए केंद्र को हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने की आवश्यकता थी। राज्यों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली 46,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी, राज्यों को उनकी योजनाओं के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से अधिक है। क्या केंद्र सब्सिडी के लिए समर्थन कम कर पाएगा और बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के निरंतर पिछड़ेपन को कम करने के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान के रूप में निधियों को चैनलाइज़ कर पाएगा? ऐसी सहायता से, तीन सबसे पिछड़े राज्य बाकी ग्यारह के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

इसके लिए सशर्त निधियों की आवश्यकता होगी जो अविकसितता की राजनीति को बदल सकती हैं और इसे विकासवादी मार्ग की ओर ले जा सकती हैं। नीति-उन्मुख सामाजिक विज्ञान अच्छे शासन के पहलुओं की ओर इशारा कर सकता है जो उत्पादक राज्य निर्देशित निवेश के साथ सबसे गरीब राज्यों को गरीबी के जाल से बाहर निकलने में मदद करेगा। सबसे गरीब भारतीय राज्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक केंद्रीय हस्तक्षेप की प्रकृति और गुणवत्ता ने सुधार के बाद के भारत में सामाजिक विज्ञान के लिए एक चुनौती पेश की।

प्रशासनिक सुधार

निवेश आधारित वृद्धि का आधार सुशासन था। सरकारों को एक विश्वसनीय कानूनी प्रणाली, भौतिक अवसंरचना, बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सुविधाएँ और एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने की आवश्यकता थी जो लोगों को बाजार उन्मुख प्रणाली में व्याप्त सामाजिक

व्यवधान से सुरक्षित रखे। भारत में, राजनीतिकरण, स्थानांतरण, जवाबदेही की कमी और नागरिक-उन्मुख शासन की कमी निवेश अनुकूल माहौल बनाने के रास्ते में आड़े आई। एक महत्वपूर्ण शोध प्रश्न राज्यों में सुशासन और निजी निवेश के बीच संबंध था। एक संबंधित प्रश्न राज्यों में सार्वजनिक निवेश की उत्पादकता और सुशासन के बीच संबंध था।

नौकरशाही को राजनेताओं से कुछ हद तक अलगाव की आवश्यकता थी। अक्सर ऐसा करना आसान नहीं होता था क्योंकि मंत्रियों के पास निजी कारणों से सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरित करने की शक्ति होती थी। भारतीय राज्यों में अधिकारियों के तेजी से स्थानांतरण ने प्रशासनिक नेतृत्व से ज्ञान और अनुभव छीन लिया। जब कोई गारंटी नहीं होती कि वे उन्हें पूरा कर पाएंगे, तो सिविल सेवकों की अपनी नौकरी में हिस्सेदारी कम हो जाती। दूसरे, तेजी से स्थानांतरण ने राजनीतिक आकाओं को अधिकारी को अपनी मर्जी के मुताबिक झुकाने में सक्षम बनाया, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई। पांचवें वेतन आयोग ने दो से पांच साल के बीच की अवधि के लिए एक अधिकारी का कार्यकाल तय करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। मई 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर आम सहमति की कमी से यह स्पष्ट हो गया कि इस नीतिगत सिफारिश के पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी।

परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर अत्यधिक जोर देने से प्रशासन की गति धीमी हो गई। आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने नोट किया था कि सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों के बीच प्रत्येक मंत्रालय में शक्तियों का उचित वितरण और जिम्मेदारी का स्पष्ट चित्रण होना आवश्यक है। पांचवें वेतन आयोग ने किसी फाइल पर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए लेवल जंपिंग की सिफारिश की थी।

अंतर-मंत्रालयी मुद्दों में अक्सर जवाबदेही की कमी होती थी, क्योंकि नीतिगत विफलता को किसी विशेष मंत्री या अधिकारी से जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। अंतर-मंत्रालयी कार्यों का उचित प्रतिनिधिमंडल और जवाबदेही एक समस्या बन गई। कई बार प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा

निवेश निराशावाद के वर्षों के बाद दूरसंचार नीति को पटरी पर लाने की सफल पहल जैसे दुर्लभ अवसरों पर, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुरू किए गए टास्क फोर्स पर आधारित अंतर-मंत्रालयी समन्वय का एक मॉडल कारगर साबित हुआ। 1991 की नई दूरसंचार नीति, जो इस टास्क फोर्स के काम का परिणाम थी, को ध्यान देने योग्य सार्वजनिक नीति दस्तावेज के रूप में सराहा गया। यह समझना महत्वपूर्ण था कि अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सफल और असफल पहलों का क्या कारण था।

आर्थिक सुधारों के संदर्भ में सरकारी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग ने नागरिक चार्टर के विचार को प्रोत्साहित किया। इन चार्टरों का उद्देश्य सेवा वितरण के मानकों को निर्धारित करके जवाबदेही को बढ़ावा देना था। सेवा अभिविन्यास को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गईं। प्रत्येक मंत्रालय में लोक शिकायत निदेशक, कैबिनेट सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय और कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की एक स्थायी समिति होगी।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कुछ राज्यों ने लोक शिकायत निवारण के लिए लोकायुक्त या लोकपाल की स्थिति स्थापित की। लोकायुक्त को यह अधिकार था कि वह चाहे तो सीधे कार्यवाही शुरू कर सकता था। 4 करोड़ रुपये के बजट और पुलिस, तकनीकी, लेखा परीक्षा और सांख्यिकी विंग के 500 अधिकारियों के साथ कर्नाटक लोकायुक्त की स्थापना एक उल्लेखनीय विकास था। कर्नाटक लोकायुक्त के अधीन स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन, बैंगलोर विकास प्राधिकरण और पुलिस विंग के सतर्कता निदेशक थे। कर्नाटक लोकायुक्त की टीम स्वास्थ्य और शिक्षा में भ्रष्टाचार की जांच में सक्रिय थी। लोकायुक्त जैसी संस्थाओं और उनकी सफलता या विफलता में योगदान देने वाले कारकों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण था।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दहिसर सुविधा केंद्र ने अभिनव विचारों को लागू किया।

नागरिक के सामने एक मॉनिटर के साथ सहायता डेस्क ने उसे फॉर्म, दिशा-निर्देश और पिछले बिलिंग रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम बनाया। एक एकल खिड़की ने एक कारखाना या एक रेस्तरां खोलने के लिए आवेदन प्राप्त किए, अन्य एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी ली और 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किए। शिकायत ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पैकेज ने क्षेत्र और प्रकार के अनुसार शिकायत को परिभाषित किया, और प्रतिक्रिया समय दिया। पत्र और फ़ाइल ट्रैकिंग की एक एकल कम्प्यूटरीकृत प्रणाली ने 80 रजिस्ट्री के काम को बदल दिया।

बीएमसी ने प्रजा नामक एक एनजीओ के साथ मिलकर काम किया। प्रजा के नागरिक चार्टर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, परिवहन, जल कार्य, लाइसेंसिंग, पर्यावरण और सीवरेज जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण के बीएमसी के मानकों का सारांश दिया गया। इसने बीएमसी के प्रदर्शन का पहला सार्वजनिक सर्वेक्षण भी किया। इस सर्वेक्षण में जल कार्यों को उच्च दर्जा दिया गया, लेकिन लाइसेंस, सीवरेज और यातायात विभागों को नहीं। प्रजा ने ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने के लिए बीएमसी के साथ सक्रिय रूप से काम किया।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उत्तरदायी विकेंद्रीकृत शासन को सुगम बनाया जा सकता है। केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को कुछ वित्तीय शक्तियाँ सौंपी हैं। चीन का आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम आंशिक रूप से इसलिए सफल हुआ क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसे बाज़ार संरक्षण संघवाद कहा है। बाज़ार संरक्षण संघवाद सरकार के सबसे निचले स्तर पर निर्णय लेने की शक्तियों को सौंपने के सिद्धांत पर आधारित था। क्या पंचायती राज संस्थाएँ ऐसी विकेंद्रीकृत निर्णय लेने वाली भूमिका निभा सकती हैं? भारत में स्थानीयकृत निर्णय लेने की संभावना को किन कारकों ने बाधित किया?

भारत के सबसे गरीब राज्यों में निवेश और कुशल कर्मियों को आकर्षित करने के लिए सुशासन

आवश्यक था। प्रशासनिक सुधार एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी गहन विद्वत्तापूर्ण जांच की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रशासन में सुधार लाने के महान उद्देश्य को अधिक जवाबदेही और नागरिक अभिविन्यास प्रदान करके इस क्षेत्र में ठोस विद्वत्तापूर्ण समर्थन की आवश्यकता थी। चूंकि भारत का अधिकांश भाग सबसे गरीब राज्यों में रहता है, इसलिए प्रभावी शासन, विशेष रूप से सबसे गरीब राज्यों में, एक अनिवार्य आवश्यकता थी।

बढ़ानेप्रतिस्पर्धा

भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न उठने की संभावना है। क्या भारत के पास अच्छी सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पर्याप्त बिजली उत्पादन, कुशल दूरसंचार सेवा प्रावधान और एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक मानव पूंजी (शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं) हैं? क्या इसके पास बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने में पूंजी की सहायता करेगी? क्या देश में श्रम और पूंजी के बीच एक व्यावहारिक अनुबंध था जिसने सामाजिक सद्भाव और उत्पादकता के लिए परिस्थितियाँ बनाईं?

दूसरा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निजीकरण और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निजीकरण को अक्सर बड़े वित्तीय खिलाड़ियों द्वारा शिकार का सामना करना पड़ता है। शुरुआती चरणों में, इसका मतलब सरकारी स्वामित्व वाले मौजूदा खिलाड़ियों द्वारा शिकार हो सकता है। बाद के चरणों में, यदि निजीकरण सफल हो जाता है, तो निजी पूंजी प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बन सकती है। यदि प्रभावी नियामक इस समस्या का सामना नहीं करते हैं, तो बाजार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए काम नहीं करेंगे। समस्या यह थी कि सरकार अक्सर सरकारी नीति के प्रति उच्च स्तर की ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बाद नियामकों को प्रभावी स्वतंत्रता देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होती थी। यदि शिकारी व्यवहार प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक प्रभावों को कम नहीं करना था, तो प्रभावी विनियमन

के मुद्दे को संबोधित करने के लिए विद्वानों के शोध की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष

अध्याय 5

निष्कर्ष

वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया ने देश की औद्योगिक संरचना और सामाजिक संरचना को बदल दिया है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण परिवर्तन की गति तेज हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दुनिया भर में उत्पादन सुविधाओं का निर्माण करने के कारण, वैश्वीकरण ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की है। जैसे-जैसे सरकार वैश्विक स्तर पर उद्यमों का विस्तार करने के लिए बाधाओं को दूर करने और वैश्विक नियमों को लागू करने के लिए काम करती है, इसने भारत के लिए अवसर और समस्याएं प्रदान की हैं।

विश्व में देश की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, जिससे इसके राजनीतिक और आर्थिक कद में सुधार हुआ है। भारत को वैश्वीकरण की जटिलताओं से निपटने के दौरान किसी भी नकारात्मक दुष्प्रभाव को संबोधित करते हुए सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने वाली संतुलित रणनीति का पालन करना जारी रखना चाहिए। वैश्वीकरण ने आम तौर पर भारत को विश्व परिदृश्य में उछाल दिया है और कई क्षेत्रों में इसके भविष्य के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, लेकिन सख्त नियमन, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रणनीतिक निवेश के अवसर और बड़े उपभोक्ता और श्रम पूल तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। टेक फर्मों को वैश्वीकरण का लाभ उठाना चाहिए और भारत से प्रतिभाओं को काम पर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कुछ बेहतरीन तकनीकी कार्यबल देश से आते हैं। वैश्वीकरण ने भारत को काफी प्रभावित किया है, विकसित देशों ने व्यापार उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय निगमों की

वकालत की है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसका समर्थन करते हैं, उदारीकरण आर्थिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में गति पकड़ रहा है। तकनीकी नवाचार संचार को बेहतर बनाता है, दूरी के रिश्तों को कम करता है और पूंजीवादी गतिशीलता को समाप्त करता है। बहुराष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ते हैं, जिससे उभरते राष्ट्र वैश्विक रूप से समृद्ध होते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, इसकी संस्कृति, समाज, सरकार और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। इसने प्रौद्योगिकी, विशेष कौशल और एक बड़े उपभोक्ता बाजार तक पहुंच बढ़ाई है। इससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में प्रवेश करती हैं और दूरस्थ श्रमिकों की मांग करती हैं। प्रौद्योगिकी के उदय ने नौकरी के अवसरों में भी सुधार किया है, खासकर सेवा उद्योग में। हालाँकि, वैश्वीकरण चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि संसाधनों का गलत आवंटन, साइबर अपराध और पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय। कुल मिलाकर, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को बदल दिया है, इसकी संस्कृति, समाज, सरकार और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तन हुए हैं तथा इसका प्रभाव राष्ट्र और समग्र समुदाय की शहरी उपस्थिति पर भी पड़ा है।

इस शोधपत्र का मुख्य निष्कर्ष यह है कि 1991 के बाद की अवधि में भारत की वित्तीय प्रगति को एक मजबूत प्रेरणा मिली है। वैश्वीकरण के साथ आगे बढ़ते हुए, भारत लगभग हर पहलू में चमक रहा है। जीडीपी सुधार ने भारत की समग्र स्थिति को बेहतर बनाया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण ने वित्तीय दृष्टि से सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। वैश्वीकरण ने भारत के समग्र व्यापार को भी लगातार प्रभावित किया है, फिर भी भारत की समग्र व्यापार में हिस्सेदारी कम है। भारत को एक समग्र स्वीकृति मिल रही है और धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण वित्तीय और

राजनीतिक स्थिति बनने की ओर अग्रसर है। भारत को आर्थिक परिवर्तनों का एक 'क्षणिक समय' शुरू करने की आवश्यकता है और प्रगति को अगले बीस से पच्चीस वर्षों में भारत को एक समग्र वित्तीय प्रभाव में बदलने के समग्र व्यापार दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए।

विकासशील देशों के व्यापार पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। वैश्विक आर्थिक एकीकरण के आलोचक चेतावनी देते हैं कि (वाटकिंस, 2002, यूसुफ, 2001): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि औद्योगिक और कम औद्योगिक देशों के बीच और भीतर आय असमानताओं को बढ़ा रही है।

वैश्वीकरण के युग में अपने नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हैं। हमारी नीतिगत निहितार्थ आम आदमी के खिलाफ हैं। यह सरकार है जो वैश्वीकरण से लाभ उठा सकती है यदि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लोगों के पक्ष में नीतियों को तैयार और लागू करती है। चीन जैसे दक्षिण आसियान देशों जैसे कई विकसित और विकासशील देशों का उदाहरण है, जिन्होंने दुनिया भर में व्यापार करके वैश्वीकरण से बहुत लाभ कमाया है।

फोर्ब्स की सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की बढ़ती संख्या से यह साबित होता है कि हमारी नीतियाँ बड़े कॉर्पोरेट और अभिजात वर्ग से प्रभावित हैं। यहाँ तक कि हमारे चुनाव भी कॉर्पोरेट द्वारा वित्तपोषित होते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि सरकारी नीतियाँ कॉर्पोरेट द्वारा अपने निजी हितों को संतुष्ट करने के लिए बहुत अधिक प्रभावित हैं। यह चीन और रूस की नीतियाँ हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उपयोग करके आम जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। वैश्वीकरण के प्रति भारत को ऐसी नीतियाँ और दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल गरीब समर्थक नीतियाँ और नौकरी के लिए तैयार कार्यबल ही उन राज्यों के लिए लाभकारी होने जा रहे हैं जो ट्रिकल-डाउन प्रभाव के विचार पर विश्वास करते हैं। अब तक ट्रिकल-डाउन प्रभाव भारतीय लोगों द्वारा नहीं देखा गया है। भारतीय अभी भी अच्छे दिनों की उम्मीद कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश हो सकता है जो "वसुधैव कुटुम्बकम" में विश्वास करता

है और वैश्वीकरण इसका एक जीवंत उदाहरण हो सकता है। वैश्वीकरण के माध्यम से भारत ने कई लाभ प्राप्त किए हैं। भारत के व्यवसायी जो फैशनेबल व्यावसायिक रणनीतियाँ अपनाते हैं, वे वैश्वीकरण द्वारा प्रदान की जाती हैं। अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत भारत और उसके व्यापारिक घरानों के लिए अब तक का एक उत्कृष्ट सीखने का अनुभव रहा है।

भारत में वैश्वीकरण के परिणामों को समाप्त करने के लिए हम कहेंगे कि वैश्वीकरण ने देश के आर्थिक स्वरूप को बदल दिया है। वैश्वीकरण का प्रभाव देश के सामाजिक मोर्चे पर और इसलिए नियोक्ता की मानसिकता पर दिखाई देता है। अब नियोक्ता सबसे सरल प्रतिभा को भर्ती करने के लिए बेहतर वेतन प्रदान करता है। वैश्वीकरण की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिरता और विश्वास प्राप्त किया है और अब इसे ग्रह की एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है। लेकिन हम इसके लाभों का आनंद लेते हुए इसके नुकसानों पर भी नज़र रखना चाहेंगे।

इस अध्ययन में वैश्वीकरण के तहत भारतीय राज्य की स्थिति को समझने के लिए तीन प्रकार के शोध एजेंडे प्रस्तावित किए गए हैं। पहला समायोजन का प्रश्न है। क्या भारत आंतरिक सहमति के कारण अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समायोजन कर रहा है और इस तरह से जो भारत की बहुलतावादी राजनीति और आर्थिक स्थितियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है? या, क्या समायोजन दाता द्वारा संचालित और बाहरी रूप से प्रेरित है? क्या क्रमिकतावाद, राजनीतिक अवसरवाद और घरेलू दृष्टिकोण के ऐसे लाभ और लागत हैं जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारतीय राज्य के समायोजन को समझने के लिए केंद्रीय हैं?

दूसरा शोध एजेंडा अंतरराष्ट्रीय नियम निर्माण की प्रकृति को संबोधित करता है। अंतरराष्ट्रीय नियम निर्माण की गतिशीलता को उजागर करने से भारत को वैश्विक व्यवस्थाओं के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद मिल सकती है। क्या ये अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ़ कमज़ोर लोगों

का शोषण करने की मज़बूत शक्ति को दर्शाते हैं; या, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक सकारात्मक योग स्थिति जिसे पारस्परिकता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बिना नहीं समझा जा सकता है? या, क्या वे उपयुक्तता के तर्क के बारे में प्रेरक तर्कों को दर्शाते हैं जो अंतर-राज्यीय आचरण को नियंत्रित करना चाहिए? अध्ययन यह मामला बनाता है कि ये तीन प्रकार के कारणात्मक तर्क भारतीय राज्य के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को संबोधित करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ता है।

तीसरे प्रकार के प्रश्न वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को संबोधित करते हैं, जिन्हें भारतीय राज्य द्वारा हल किया जाना चाहिए। सबसे पहले, वैश्वीकरण सामाजिक भेद्यता को बढ़ा सकता है। कल्याण प्रदान करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, राज्य को कर लगाने और संसाधनों को पुनर्वितरित करने के लिए OECD देशों के उदाहरण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। दूसरा, उदारीकरण और कठोर बजट प्रतिबंधों ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ा दिया है। इससे अंतर-राज्य असमानता भी बढ़ सकती है। सुशासन, विशेष रूप से सबसे गरीब राज्यों में, इन राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सशर्त केंद्रीय वित्त द्वारा सुविधा प्रदान करना आवश्यक था।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार उसके भौतिक और मानवीय बुनियादी ढांचे में सुधार के बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है। भौतिक और मानवीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियमन को मजबूत करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना आवश्यक था।

तीन मुद्दे, जिनमें शामिल थे: क) अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समायोजन; ख) भारतीय राज्य के लिए एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने वाली भूमिका; और, ग) वैश्वीकरण के साथ सफल होने के लिए आंतरिक गतिशीलता का निर्माण करना, इन पर विद्वानों द्वारा

तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि आर्थिक वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता को कमजोर करता है, या एकाधिकार वाले राज्यों द्वारा अपने क्षेत्रों पर रखे गए अधिकार को कमजोर करता है। यह आर्थिक वैश्वीकरण के विभिन्न परिणामों के कारण है: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, और राज्य नियंत्रण से बाहर के स्थानों का विस्तार। हमने देखा है कि इन मूलभूत प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की राष्ट्र-राज्यों की क्षमता बहुत सीमित है और, परिणामस्वरूप, अन्य अभिनेताओं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने इस प्रक्रिया में नेतृत्व किया है। वर्तमान स्थिति इस बात को स्वीकार करने से इनकार करती है कि हिंसा का राज्य एकाधिकार, जो सदियों के युद्ध के बाद सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है, समाप्त हो रहा है। हालाँकि दुनिया भर में अभी भी कई हिंसक राज्यविहीन समाज हैं, लेकिन सबसे विकसित लोगों में एक तरह के राज्य हैं, जो क्षेत्रों और आबादी से विभाजित हैं। यह संगठन एक धीमी प्रक्रिया और विभिन्न पारलौकिक घटनाओं द्वारा विलीन हो गया है।

हमने देखा है कि राज्य प्रणाली, जो 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के समय महाशक्तियों की जरूरतों के लिए एक जैविक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई, उस अवधि की समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बन गई, लेकिन यह अपरिवर्तनीय नहीं है। आज, राज्य प्रणाली के क्षय के खिलाफ संस्थागत बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन दुनिया और राष्ट्रीय समाज को राज्यविहीन माना जा सकता है। उन पर ऐसे लोगों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है जो अपनी वास्तविकताओं का निर्माण करते हैं और राज्यविहीन संस्थाओं में जड़ें जमाते हैं। इस अध्ययन ने प्रदर्शित किया है कि आर्थिक वैश्वीकरण पर्यावरण, राज्य के एकाधिकार को कमजोर करता है, कि विभिन्न ताकतें इस पारंपरिक ढांचे को चुनौती देती हैं, और यह कि वर्तमान नियमों से परे एक विश्व व्यवस्था बनाने की आवश्यकता स्पष्ट है। अन्य अभिनेताओं के व्यवहार को अनुशासित करने के मानदंडों के विषय की 1960 के दशक से गहन जांच की गई है। यह

मूल्यांकन करना चाहता है कि क्या वैश्विक, उप-या सुपरनेशनल आदेशों का विस्फोट एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करता है जो पारंपरिक पदानुक्रमित और वेस्टफेलियन-केंद्रित राज्य प्रणाली से अलग है।

कोविड-19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित करके, पारस्परिक संपर्क और संचार को कम करके, और वैश्विक शासन और राजनीतिक बातचीत के महत्व को कम करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस अभूतपूर्व घटना ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, MNE के संचालन और FDI और व्यापार पैटर्न को बदल दिया है, और इसने संरक्षणवादी और सीमा नीतियों का पक्ष लिया है। इस बीच, यात्रा प्रतिबंधों और सामाजिक-दूरी के उपायों ने मानव गतिशीलता को कम कर दिया और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न की। कोविड-19 महामारी ने कई सरकारों को वैश्विक जुड़ाव, क्षेत्रीय वापसी और राष्ट्रीय अलगाव के बीच एक निश्चित संतुलन की तलाश करके वैश्वीकरण के संबंध में अपनी रणनीतियों का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, कोविड-19-प्रेरित डिजिटल परिवर्तन और भविष्य के बाहरी झटकों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के माध्यम से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यह अध्ययन कोविड-19 महामारी और इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक आर्थिक वैश्वीकरण पर प्रभावों पर गहराई से चर्चा करता है, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के लिए इसके प्रभावों को भी संबोधित करता है।

कोविड-19 के बाद के दौर में दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें आर्थिक तनाव और राजनीतिक संघर्ष, बढ़ती आर्थिक असमानता, घटता लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन का खतरा शामिल है। ऐसे में, इन चुनौतियों से निपटने और वैश्वीकरण विरोधी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन, समावेशिता और लचीलेपन पर आधारित एक "पुनः डिज़ाइन" वैश्वीकरण की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के लाभों के असमान वितरण के कारण, रॉड्रिक ने इस प्रक्रिया को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। रॉड्रिक के अनुसार,

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का अंतर्निहित उद्देश्य व्यवसायों को बढ़ाना है, इस अंतर्निहित धारणा के साथ कि समाज के विभिन्न वर्गों को लंबी अवधि में लाभ होगा। चूंकि श्रम मानदंड, मजदूरी और रोजगार सुरक्षा आमतौर पर इन समझौतों द्वारा सीधे संबोधित नहीं की जाती है, इसलिए रॉड्रिक ने कहा कि यह संभव है कि यह धारणा सही न हो। समानांतर में, ऐसमोग्लू एट अल ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि वे निगमों के प्रभाव को सीमित कर सकें और विभिन्न कौशल सेटों में रोजगार दरों को बढ़ावा देने वाली तकनीकों की ओर विकास को आगे बढ़ा सकें। इस तरह के परिवर्तन अंततः वैश्वीकरण को नया आकार दे सकते हैं और वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं को कम कर सकते हैं तथा कोविड-19 के बाद के युग में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं।

इस अध्ययन को अनुभवजन्य विश्लेषणों द्वारा पूरक बनाया जा सकता है जो विभिन्न वैश्वीकरण संकेतकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का अनुमान लगाते हैं और जो पारंपरिक अनुभवजन्य साहित्य के आधार पर सीमा प्रभावों और क्षेत्रीय/तरजीही व्यापार समझौतों के लिए कोविड-19 महामारी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करते हैं। वैश्विक एकीकरण की सीमा पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विविधताओं की जांच करके और राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं के बाद कोविड-19 के बाद के अनुमानों को संशोधित/अद्यतन करके इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अंत में, वैश्वीकरण के घटकों के बीच कोविड-19 के बाद की अंतः क्रियाओं की जांच करने और यह निर्धारित करने के बारे में और विस्तार से बताना फायदेमंद होगा कि क्या कोविड-19 के बाद वैश्वीकरण पैटर्न पर संरचनात्मक विराम हुआ।

संदर्भ

1. भट्टाचार्य, सी.ई. डॉ. सुमंत और सचदेव, भवनीत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इसका परिवर्तन और भविष्य के पहलू।

2. रसम, वसंती (2013)। वैश्वीकरण और भारत की राजनीतिक संस्कृति पर इसका प्रभाव। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। 10. 25-30।

3. साहू, सरबेश्वर. (2013). वैश्वीकरण और भारत में गरीबों की राजनीति. जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज. 49. 3-15. 10.1177/0021909612471785.

4. कुमार, सुरिंदर और सिंह, कुलविंदर। (2012)। वैश्वीकरण का प्रभाव: भारतीय अनुभव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड रिसर्च। 2. 1-10।

5. गोविंदराज, योगानंदम. (2023). विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव और आकलन.

6. अब्दुनैइमोवा, दिनारा. (2020). वैश्वीकरण, इसका सार, कारण और परिणाम. एकीकृत शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल. 3. 28-32. 10.31149/ijie. v3i9.583.

7. मन्हास, नीरज सिंह. (2020). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव. 5. 2455-670. 10.25215/2455/0502015.

8. हिली, डाल्टन. (2012). वैश्वीकरण की भूमिका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और उनके व्यापक आर्थिक और राजनीतिक माहौल पर इसका प्रभाव.

9. अब्दी, उमर और क़साये, मोहम्मद और मोहम्मद, उमर। (2024)। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंस एंड रिसर्च (IJSR)। 10.21275/SR231113213549।

10. अग्रवाल, अंकुर और कुमारी, मीनाक्षी. (2021). वैश्वीकरण और भारत में मीडिया प्रबंधन पर इसका प्रभाव. 20. 4150-4161. 10.17051/ilkonline.2021.01.458.

11. तुरान, सुएप और अवलेह, हनीफ़. (2022). मध्य पूर्व में राजनीति और संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव.

12. माहेश्वरी, हर्ष और सोनी, अर्पण (2023)। वैश्वीकरण और सामाजिक संरचना पर इसका प्रभाव।

13. खान, एस. (2015). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव. 2. 11-18.

14. भट्टाचार्य, एच. और कोनिग, लायन. (2015). भारत में वैश्वीकरण और शासन: समाज और संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ. भारत में वैश्वीकरण और शासन: समाज और संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ. 1-175. 10.4324/9781315722917.

15. साहू, विकास और पेढेकर (घारे), सुनंदा। (2024)। क्या वैश्वीकरण भारतीय समाज में एक प्रेरक शक्ति है? एक अवलोकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स। 12. 1190-1193। 10.56025/IJARESM.2024.1208241190।

16. पटजोशी, प्रमोद. (2019). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन.

17. रघुनाथ, (2017)। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च -ग्रंथालय। 5. 544-549। 10.29121/ग्रंथालय।v5.i6.2017.2071।

18. सिन्हा, सुबीर. (2024). वैश्वीकरण, मास मीडिया और भारत के सामाजिक परिवर्तन. एटीआरएएस जर्नल. 5. 265-264. 10.70091/एटीआरएएस/वॉल्यूम05नं.2.20.

19. फिशर, जस्टिना. (2013). वैश्वीकरण और राजनीतिक विश्वास.

20. पटजोशी, प्रमोद. (2019). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन. जर्नल ऑफ इनोवेटिव प्रोफेशनल साइंस एंड आईटी.

21. लाल, मैरी. (2013). भारत में नागरिकता पर वैश्वीकरण के प्रभाव: शिक्षा की बदलती भूमिका. 10.1007/978-3-642-34568-5_8.

22. मोंगा, ओपी और मोंगा, अनुभूति और मोंगा, अनुभव और मोंगा, ओम. (2016). भारत में वैश्वीकरण और शिक्षा: उच्च शिक्षा का मुद्दा. अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज. 14. 140-144.

23. धागे, वृषाली अनिल (2018). वैश्वीकरण और समकालीन भारतीय कला पर इसका प्रभाव.

24. राठी, अमित और सिंह, रणदीप. (2011). भारतीय आईटी उद्योगों पर वैश्वीकरण का प्रभाव-एक सर्वेक्षण.

25. गोविंदराज, योगानंदम और करीम, ए. अब्दुल (2023)। भारतीय समाज, सतत विकास और अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के परिणाम - एक मूल्यांकन। 13. 88-95।

26. डांग, जी.पी. (2016). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव।

27. मुथुसामी, मुरली. (2014). वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक शोध पुस्तक. 10.13140/2.1.5180.9923.

28. अधिकारी, किंगशुक. (2010). भारत में वैश्वीकरण और विकास - एक अवलोकन. एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल. 10.2139/ssrn.1624252.

29. पांडे, मनीषा. (2011). भारत में वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन: परिवर्तन का सिद्धांतीकरण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. 3.

30. गोविंदराज, योगानंदम. (2017). वैश्वीकरण और भारत में इसका प्रभाव - एक अध्ययन.

31. मोहपात्रा, हितेश (2017). भारतीय संस्कृति और वैश्वीकरण.

32. बागची, अमिया. (2019). भारत में नवउदारवाद और वैश्वीकरण. 10.1007/978-981-13-8269-7_2.

33. बिष्ट, रमीला और पिचफोर्थ, एम्मा और मरे, सुसान। (2012)। भारत को समझना, वैश्वीकरण और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का मानचित्रण। वैश्वीकरण और स्वास्थ्य। 8. 32. 10.1186/1744-8603-8-32।

34. उपाध्याय, राजीव. (2014). भारत में वैश्वीकरण का सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव. 2.

35. कक्यापदावु, निज़ार. (2022). भारत में उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण और विमर्श.

36. सिंह, जगदीप और कुमारी, डॉ. ममता। (2022)। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव: एक महत्वपूर्ण समीक्षा। विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 127-137. 10.48175/IJARSCT-5937।

37. अंबू, सेइलन. (2020). भारतीय व्यापार और संस्कृति में वैश्वीकरण का प्रभाव.

38. हक, एम. (2018). कॉर्पोरेट वैश्वीकरण और भारत में महिलाओं पर इसका प्रभाव।

39. गोंजालेज, बी. (2016). वैश्वीकरण: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे।

40. चटर्जी, मिनिया. (2012). राजनीति का वैश्वीकरण: मिस्र से भारत तक. सामाजिक आंदोलन अध्ययन. 12. 1-7. 10.1080/14742837.2012.698132.

41. वदित्य, वेंकटेश. (2019). भारत में वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा: प्रतिमान बदलाव. 10.13140/RG.2.2.25552.76806.

42. शर्मा, शिव. (2019). भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद पर वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव. जर्नल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. 15. 189-201. 10.1956/jge.v15i3.592.

43. शॉटली, जीवन्ता और झा, हिमांशु. (2023). भारत में वैश्वीकरण और शासन. 10.4324/9781003152347.

44. गुप्ता, शिखा और कुमार, नंद. (2021). भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की गतिशीलता. प्रबंधकीय और निर्णय अर्थशास्त्र. 42. 10.1002/mde.3313.

45. चौक्रौने, लीला. (2020). वैश्वीकरण और भारतीय राजनीतिक आधुनिकता. 10.1007/978-3-030-44058-9_34.

46. इस्लाम, रबीउल और अहमद, फखरोराज़ी और हुसैन, हार्टिनी और रेहान, एमडी (2019)। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रभाव। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान समीक्षाएँ। 7. 256-265. 10.18510/एचएसएसआर.2019.7130.

47. गोविंदराज, योगानंदम और करीम, ए. अब्दुल (2023)। भारत के विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला स्थानीयकरण, बाजार की सफलता, कौशल अंतराल, क्षेत्रीय सीमा शुल्क, विनियामक आवश्यकताओं और राज्य कल्याण पर वैश्वीकरण का प्रभाव - एक व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक मूल्यांकन।

48. बीसन, मार्क. (2017). वैश्वीकरण और शासन. 10.1057/978-1-137-58900-2_7.

49. मुखर्जी, राहुल. (2014)। भारत और आर्थिक वैश्वीकरण. 10.1057/9781137356642_5.

50. रॉय, तीर्थंकर. (2019)। निष्कर्ष। 10.1007/978-3-030-17708-9_8.

51. सिंह, डॉ. (2016)। भारत में उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव: मुद्दे, चुनौतियाँ और विकल्प। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। 3. 10.25215/0302.057।

52. प्रभु, एस.. (2020). भारतीय लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक अध्ययन. अनुसंधान विश्लेषण के लिए वैश्विक जर्नल. 1-2. 10.36106/gjra/5208805.

53. गोयल, कमलेश. (2018). भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने पर वैश्वीकरण का प्रभाव: सुधारों के बाद का विश्लेषण. 14. 234-240. 10.5958/2322-0430.2018.00063.X.

54. टेकबास, मूरत. (2021). आर्थिक विकास पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वैश्वीकरण का प्रभाव: ब्रिक्स-टी देशों से साक्ष्य*. गाजियांटेप यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज. 20. 57-71. 10.21547/jss.796472.

55. अरोड़ा, दिव्या. (2020). पीएम मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत की सरकार और वैश्वीकरण. इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. 4. 210-214. 10.56902/IRBE.2020.4.2.31.

56. के, अश्विनी और बी., श्रीया. (2020). चेन्नई के विशेष संदर्भ में वैश्वीकरण का प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन. 24. 2778-2783. 10.37200/IJPR/V24I4/PR201386.

57. एली, अली और विंटर, ग्रेगरी और मे, डेविड। (2011)। वैश्वीकरण: इसके प्रभाव। इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च जर्नल (IBER)। 6. 10.19030/iber.v6i1.3339।

58. अवेयर, विवेक (2019). वैश्वीकरण और राष्ट्र-राज्यों पर इसका प्रभाव.

59. वर्मा, और श्रीवास्तव, अमित (2018)। उदारीकरण के बाद के युग में भारत का वैश्वीकरण और आर्थिक विकास। 10.13140/RG.2.2.33276.87686।

60. कुमार, संजीव. (2023). भारत में वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा.

61. शोपिना, इरीना और ओलीनीक, ओलेना और फिनाहेयेव, वैलेरी। (2017)। वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव। बाल्टिक जर्नल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। 3. 457-461। 10.30525/2256-0742/2017-3-5-457-461।

62. ड्रैसी, पराश्केवी और कडियू, अर्जना। (2024)। वैश्विक समाज पर वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव। अनुसंधान और विकास के अंतःविषय जर्नल। 11. 254. 10.56345/ijrdv11n1s138।

63. पापानिकोस, ग्रेगरी. (2024). वैश्वीकरण का भविष्य. एथेंस जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. 10. 87-108. 10.30958/ajbe.10-2-1.

64. बर्लाकू, सोरिन और गुटु, कुथबर्ट और माटेई, एफओ. (2018). वैश्वीकरण - पक्ष और विपक्ष. गुणवत्ता - सफलता तक पहुँच. 19. 122-125.

65. विट, माइकल. (2019). डी-ग्लोबलाइजेशन: सिद्धांत, भविष्यवाणियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान के अवसर. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज. 50. 1053-1077. 10.1057/s41267-019-00219-7.

66. डियाज़, क्रिश्चियन और व्हाइट, अलास्डेयर। (2024)। शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव: एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 10.13140/RG.2.2.10491.73768।

67. एमपोलोमोका, डैनियल और चिसेबे, सिल्वेस्टर और मैडोडा, डेरिक और सैन, ज़ोहैब और गिल्बर्ट, मविला और चंदा, थेल्मा। (2024)। राष्ट्रीय शासन और विकास पर वैश्वीकरण का प्रभाव। 10. 1-19।

68. वेंकटेश, आर.. (2023). उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण: भारत के लिए निहितार्थ. मोरफाई जर्नल. 3. 64-71. 10.54443/morfai.v3i1.773.

69. कोएट्ज़ी, डर्क और व्हाइट, अलास्डेयर (2024)। विकासशील राष्ट्र और चौथी औद्योगिक क्रांति: वैश्वीकरण चुनौतियों की तुलना।

70. हाफ़िज़, डॉ. नुसरत और सबरीना, फ़रीन. (2023). विकासशील देशों में मानवाधिकारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव: सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में बिंदुओं को जोड़ना. समाज और स्थिरता. 5. 54-68. 10.38157/ss.v5i1.558.

71. सिद्दीकी, कलीम. (2020). (2020) वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकासशील देश. ईएफआर अगस्त सितंबर.

72. यिगित, पीएच.डी., मेहमत फतिह और तरमन, बुलेंट। (2013)। वैश्वीकरण, लोकतंत्रीकरण और सहभागी नागरिकता पर सोशल मीडिया का प्रभाव। जर्नल ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन। 12. 75-80। 10.4119/UNIBI/jsse-v12-i1-84।

73. भाटिया, श्वेता और पन्नीर, सिगमनी। (2019)। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा पर वैश्वीकरण और इसका प्रभाव: भारत का मामला। साउथ एशियन जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 6. 232209371983807. 10.1177/2322093719838076।

74. कोचचेवा, लाडा. (2013). उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वैश्वीकरण और पर्यावरण: बढ़ता असंतुलन, नई गति या गतिरोध?. न्यू ग्लोबल स्टडीज. 7. 10.1515/ngs-2013-007.

75. खान, अकबर और खान, आसिफ. (2019). औपचारिक, प्रेरक और रणनीतिक एचआरएम प्रथाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव: भारत से एक अनुभवजन्य साक्ष्य. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. 8. 3270-3276. 10.35940/ijrte.D8052.118419.

76. डेविड, सोलोमन अरुलराज (2014)। भारत में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम पुनर्गठन पर वैश्वीकरण का प्रभाव, केरल और तमिलनाडु में रुझानों की तुलना। भारतीय सामाजिक कार्य पत्रिका। 75. 553-572।

77. पांडे, अतुल. (2024). 21वीं सदी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को परिभाषित करने में वैश्वीकरण की भूमिका. 10.13140/RG.2.2.16863.06565.

78. , डॉ. अब्दाल और कुरैशी, सुमेरा और नरगिस, शमा। (2024)। वैश्वीकरण पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण: एक व्यापक अध्ययन। 10. 561-572। 10.5281/zenodo.10901882।

79. शर्मा, श्रीमती और शर्मा, डॉ. (2024). भारत में वैश्वीकरण, व्यापार और आर्थिक विकास: एक एआरडीएल दृष्टिकोण। 10.58532/nbennurch38.

80. मारलुसिद्दैया, एचएम और रमेशा, केजी. (2015). भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसर्च. 5. 119. 10.5958/2249-6270.2015.00009.4.

81. मेन्से, इवान और लेमोइन, पामेला और गैरेटसन, क्रिस्टोफर और रिचर्डसन, माइकल। (2018)। परिवर्तन की दुनिया में वैश्विक उच्च शिक्षा का विकास। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। 2. 47. 10.20849/jed.v2i3.529।

82. देसाई, प्रणव. (2023). भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का पुनरुत्थान. 846-850.

83. सुजंता, जी. और आनंद, एम. और वाज़, अनीश और गोमती, एस और वेनी, के. और माहेश्वरी, के.. (2024)। वैश्वीकरण और सहस्राब्दी के बाद के साहित्य पर इसका प्रभाव। जर्नल ऑफ एडवांस्ड जूलॉजी। 45. 125-129। 10.17762/jaz.v45iS1.3429।

84. शर्मा, अंशु और जोशी, अंकुर। (2019)। भारत में शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव: वैश्विक मानकों की ओर या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ओर? वैश्विक मुद्दे और अनुभव। 10.1007/978-981-13-1727-9_15।

Appendix 1

Paper 1

E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 07-07-2023
Accepted: 13-08-2023

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 1; Issue 2; 2023; Page No. 625-628

भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना

[1]Kumar Abhayaditya Subham and [2]Dr. Balram Singh

[1]Research Scholar, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Department of Political Science, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15546024

Corresponding Author: Kumar Abhayaditya Subham

सारांश

दुनिया में वैश्वीकरण पुराना है। हालाँकि, यह समय के साथ बदलता रहता है। वैश्वीकरण हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है क्योंकि यह एक देश से दूसरे देश में सूचना के तेज और आसानी से प्रवाहित होने के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। वैश्वीकरण को अधिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों और घटनाओं के तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आर्थिक वैश्वीकरण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं जैसे पोशाक, मशीनें, फिल्में, गीत आदि के व्यापार को सुगम बनाता है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया ने देश की औद्योगिक संरचना और सामाजिक संरचना को बदल दिया है।

मूलशब्द: भारतीय, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और वैश्वीकरण।

प्रस्तावना

वैश्वीकरण के प्रभाव दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देंगे। भारत उन देशों में से एक है जहाँ वैश्वीकरण के आगमन के बाद प्रतिस्पर्धा में बहुत वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को बेहतर और समय पर परिणाम देने के लिए नई व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया। वैश्वीकरण ने भारत को 1990 में प्रभावित किया, उस समय श्री मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे।

हम वैश्वीकरण को दुनिया भर के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आर्थिक शब्दों में, वैश्वीकरण को अक्सर विभिन्न देशों की अपनी सीमाओं से परे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परस्पर निर्भरता के रूप में वर्णित किया जाता है। वैश्वीकरण एक प्रतिस्थापन अवधारणा नहीं है। प्राचीन समय में भी व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करते थे। लेकिन उस समय पूरी प्रक्रिया लंबी और जोखिम भरी होती थी और अब कनेक्टिविटी ने देशों के लिए एक मंच पर वापस आना और अपनी तकनीकों और सेवाओं का आदान-प्रदान करना आसान बना दिया है।

वैश्वीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाएँ और समाज एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से एकीकृत हो जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रुझानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए, शब्द "वैश्वीकरण" समकालीन राजनीतिक और शैक्षणिक बहस के सबसे फैशनेबल चर्चाओं में से एक बन गया है। लोकप्रिय चर्चा में, वैश्वीकरण अक्सर निम्नलिखित घटनाओं में से एक या अधिक के लिए एक पर्यायवाची के रूप में कार्य करता है।

वैश्वीकरण को अधिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों और घटनाओं के तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विश्व दृष्टिकोण, उत्पादों, विचारों और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है। भारतीय उद्योग में वैश्वीकरण के विभिन्न लाभकारी प्रभाव यह हैं।

भारत में धार्मिक रूप से प्रेरित राजनीति (हिंदू और मुस्लिम दोनों) ने लैंगिक भूमिका, विवाह, तलाक आदि जैसे सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत की लोकप्रिय राजनीति ने समूह की पहचान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है न कि आर्थिक विकास के सवाल पर। पहचान की राजनीति में वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने का एक और तरीका भारत में विकासात्मक राज्य की वापसी के निहितार्थ का विश्लेषण करना है। वैश्वीकृत युग में, भारत में राजनीतिक दिमाग के स्थान के लिए दो तरह के एकात्मक

राष्ट्रवाद ने प्रतिस्पर्धा की। एक ओर, 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' थे, जो हमेशा हिंदू विश्व दृष्टिकोण को भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति के मूल में रखना चाहते थे। यह तर्क दिया गया कि भारत की एकता हिंदू धर्म की मजबूत शक्ति से प्राप्त हुई है। उन्होंने समान नागरिक संहिता और भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए आक्रामक रूप से दबाव डाला है। भारत में, वैश्वीकरण ने दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रचारित हिंदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साहित्य की समीक्षा

साहू, सरबेश्वर. (2013) [1]. यह शोधपत्र वैश्वीकरण साहित्य में दो बुनियादी सवालों को संबोधित करता है: (1) क्या वैश्वीकरण एक खतरा है या एक अवसर? और (2) बाजार की गहराई वास्तव में दुनिया में वास्तविक ठोस लोकतंत्र को किस हद तक प्रोत्साहित करती है? कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप असमानता और गरीबों का हाशिए पर जाना बढ़ गया है, जो लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। हालाँकि, भारत के मामले को ध्यान में रखते हुए, यह शोधपत्र तर्क देता है कि कल्याणकारी राज्य के पीछे हटने और विकासवाद के पतन ने वैश्वीकरण के अभिजात्य और शोषणकारी एजेंडे के खिलाफ जनता को लामबंद किया। परिणामस्वरूप, एक प्रति-आधिपत्यवादी जीवंत नागरिक समाज उभरा है।

कुमार, सुरिंदर एट अल. (2012) [2]. वैश्वीकरण एक नया शब्द है जो पिछली सदी के नब्बे के दशक से शीत युद्ध की समाप्ति और पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक प्रवृत्ति के साथ दुनिया पर हावी हो गया है। अपने पुराने समय में जिस तरह से वर्तमान में विकसित अर्थव्यवस्थाएँ विस्तारित हुईं और वैश्विक हो गईं, उसके विपरीत भारत में (कई अन्य विकासशील देशों की तरह) मुख्य सुधार पहल राजकोषीय और विदेशी मुद्रा संकट के बाद की गई थीं, जिसने इसे विदेशी ऋणों पर चूक के कगार पर ला दिया था। इस प्रकार, भारतीय वैश्वीकरण भीतर के पतन और बाहर से दबाव का परिणाम है। वैश्वीकरण के बाद के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव विदेशी क्षेत्र-विदेशी मुद्रा भंडार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी पूंजी का प्रवाह आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

गोविंदराज, योगानंदम। (2023) [3]। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल, सेवाएँ, धन और प्रौद्योगिकी को ले जाना संभव है, जो उद्यमों और समाजों का वैश्वीकरण है। सिल्क रोड इसकी सबसे प्रारंभिक अभिव्यक्तियों में से एक है, और यह प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क के दिनों से ही अस्तित्व में है। वैश्विक व्यापार और औद्योगिक क्रांति 15वीं शताब्दी में खोज के युग की शुरुआत में शुरू हुई थी। वैश्वीकरण व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ धन, विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित द्वितीयक स्रोतों और सूचनाओं का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जांच करता है।

अब्दुनैइमोवा, दिनारा. (2020) [4]. इस लेख में वैश्वीकरण की घटना की समीक्षा की गई है, इसके सार, विषय-वस्तु और कारणों का विभिन्न पहलुओं में विश्लेषण किया गया है। सांस्कृतिक पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है, विश्व संस्कृति की विविधता के वितरण और संस्कृति के वैश्वीकरण के कारणों और परिणामों पर समाजशास्त्रियों की राय का विश्लेषण किया गया है। वैश्विक भाषाओं का विषय और विभिन्न राष्ट्रों और लोगों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने की समस्या का भी खुलासा किया गया है।

मन्हास, नीरज सिंह. (2020) [5]. भारत का चौथा स्थान पूंजीकरण है। वैश्वीकरण के बाद से कृषि में सुधार नहीं हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17% है। भूमिहीन परिवारों की संख्या बढ़ी, आत्महत्या करने वाले किसान। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणामों के बावजूद, उभरते भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने और जल्दी विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा से एक त्वरित संदेश यह है कि एक राष्ट्र को जानबूझकर एक नीति संतुलन चुनना चाहिए जो उसे दुर्घटनाओं से बचने के साथ-साथ अवसर को जब्त करने में मदद करे।

अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण विदेशी निवेश को सुगम बनाकर किसी देश की आर्थिक वृद्धि को गति देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कौशल का उन्नयन होता है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार आदि में विकास और निरंतर वृद्धि जैसे तकनीकी विकास और नवाचार को भी प्रभावित करता है। हालाँकि, अर्थव्यवस्था का समतावादी विकास और असमानता अभी भी एक चुनौती है जो वैश्वीकरण के कारण कहीं अधिक प्रचलित है। विकासशील देशों में वस्तुओं और सेवाओं की अप्रतिबंधित आपूर्ति के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी ओर, विकसित वस्तुएं और सेवाएं समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के लिए वहनीय नहीं हैं।

राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

20वीं और 21वीं सदी में वैश्वीकरण ने राज्यों की भूमिका को नगण्य बना दिया है क्योंकि यह मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य से प्रभावित है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (WTO) आदि भू-राजनीतिक रूप से राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। IMF, विश्व बैंक और WTO द्वारा बनाए गए नियम अपने सदस्य राज्यों पर अपनी आर्थिक नीति को तर्कसंगत बनाने, वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार और टैरिफ पर प्रतिबंध को कम करने का नैतिक दायित्व डालते हैं जिससे राज्यों की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है।

वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने से विदेशी व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ गई है। इससे भारत की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में देश की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इससे भारत को वैश्विक मामलों में अधिक आवाज़ मिलती है। दूसरी ओर, इससे राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण भी हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (WTO)

और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में अधिक शक्ति प्राप्त हुई है।
वैश्वीकरण के कारण नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन भी उभरे हैं। ये संगठन सरकारी नीतियों और कार्यों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की वकालत कर रहे हैं। हालाँकि, वैश्वीकरण के लाभों के असमान वितरण के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है।

समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण एक राष्ट्र की सीमा के पार सूचना के मुक्त और सहज प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे विदेशी संस्कृति का तेजी से आयात होता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और तेज संचार प्रणाली के माध्यम से दुनिया के एक छोर के लोग दूसरे छोर के लोगों के समाज और संस्कृति से आसानी से परिचित हो सकते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण विदेशी वस्तुओं और सेवाओं जैसे पोशाक, मशीनें, फिल्में, गीत आदि के व्यापार को सुगम बनाता है, जिसके माध्यम से विदेशी संस्कृति का भी तेजी से आयात किया जा सकता है। हालाँकि, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की आसान पहुँच समाज की लोक और क्षेत्रीय संस्कृति और फैशन के लिए खतरा है।

वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति

एक निश्चित, महत्वपूर्ण अर्थ में, वर्तमान मानव दुनिया इतिहास के किसी भी पहले के बिंदु की तुलना में अधिक मजबूती से एकीकृत है। जेट विमान और सैटेलाइट डिश के युग में, वैश्विक पूंजीवाद के युग में, सर्वव्यापी बाजारों और वैश्विक जनसंचार माध्यमों के युग में, विभिन्न टिप्पणीकारों ने दावा किया है कि दुनिया तेजी से एक ही जगह बनती जा रही है। हालाँकि इस थोड़े अतिरंजित वर्णन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन शीत युद्ध के बाद की दुनिया का शायद इससे भी अधिक चौंकाने वाला पहलू पहचान की राजनीति का उभरना है - ऐसा लगता है कि हर जगह - जिसका स्पष्ट उद्देश्य जड़ परंपरा, धार्मिक उत्साह और/या जातीय या राष्ट्रीय पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की बहाली है। यह निस्संदेह सच है कि वैश्वीकरण एक व्यापक प्रवृत्ति है जो हर जगह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है - अमेज़न वर्षावन से लेकर जापानी शहरों तक।
यह अवधारणा हाल ही में एक फैशन बन गई है, और परिणामस्वरूप, इसका अर्थ अस्पष्ट होता जा रहा है। इसलिए, मैं वैश्वीकरण को उन सभी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के रूप में देखने का प्रस्ताव दूंगा जो दूरी को अप्रासंगिक बनाने में योगदान करती हैं। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम हैं, साथ ही साथ नैतिक निहितार्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में वैश्विक प्रक्रियाएं विशेष इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थितियों को प्रभावित करती हैं।
जिससे नए अवसर और भेद्यता के नए रूप बनते हैं। परमाणु बम और संभावित पारिस्थितिक आपदाओं के युग में जोखिम वैश्विक रूप से साझा किए जाते हैं। इसी तरह, विशेष इलाकों में आर्थिक स्थितियां अक्सर (कुछ लोग हमेशा कहेंगे) वैश्विक प्रणाली में कहीं और होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। यदि ताइवान में औद्योगिक उछाल है, तो अंग्रेजी मिडलैंड्स के शहर प्रभावित होंगे। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि तेल निर्यात करने वाली त्रिनिदाद की अर्थव्यवस्था के लिए मुक्ति और तेल आयात करने वाली बारबेडियन अर्थव्यवस्था के लिए आपदा।

वैश्वीकरण और राजनीति

राजनीति विज्ञान में वैश्वीकरण का अर्थ अलग-अलग राष्ट्रों, क्षेत्रों या यहाँ तक कि व्यक्तियों का एक व्यापक वैश्विक व्यवस्था में एकीकरण है। इसकी विशेषता लोगों और देशों के बीच संबंधों और जुड़ावों में वृद्धि और इन अंतःक्रियाओं के बारे में बढ़ती जानकारी है। यह एकीकरण प्रक्रिया अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज या संस्कृति को प्रभावित कर सकती है; यानी, प्रक्रिया की परिभाषा बहुत सामान्य है और यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक एकीकरण को संदर्भित कर सकती है। किसका एकीकरण किया जा रहा है, यह सवाल भी खुला छोड़ दिया गया है, हालाँकि राजनीति विज्ञान में यह ज़्यादातर देश ही होते हैं जो मुद्दे पर होते हैं। इस तरह के एकीकरण का संचालन करने का तरीका भी परिवर्तनशील है। साहित्य में वैश्वीकरण का सबसे आम रूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एकीकरण शामिल है, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी प्रवाह, श्रम आंदोलनों और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के माध्यम से।

वैश्वीकरण के कारण

बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैश्वीकरण कैसे विकसित हुआ है, और यह जिस तरह से विकसित हुआ है, वह क्यों हुआ है। यदि कोई वैश्वीकरण के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाता है, तो इसकी प्रगति को इस बात से समझाया जा सकता है कि तकनीकी परिवर्तन कितनी तेज़ी से होता है और फैलता है। ऐसे समय में जब ऐसा परिवर्तन बहुत तेज़ होता है और जब नए विचारों और तकनीकों को अपनाना तेज़ होता है, वैश्वीकरण तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कई लोगों को लगता है कि 19वीं सदी के मध्य और अंत में ऐसा ही हुआ था, जब भाप की शक्ति, रेलमार्ग और टेलीग्राफ जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों ने दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदल दिया था। सैन्य प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवादी नियंत्रण द्वारा आंशिक रूप से फैली इन तकनीकों ने दुनिया के दूरदराज के क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद की।
युद्ध के बीच की अवधि में तकनीकी परिवर्तन नहीं रुका, जब वैश्वीकरण पीछे हट रहा था; वास्तव में, युद्ध ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस अवधि में ऐसी तकनीकों का प्रसार बहुत सीमित था क्योंकि कई सीमाएँ बंद थीं और देश अपने नए रहस्यों की रक्षा कर रहे थे, जो अक्सर युद्ध लड़ने से जुड़े होते थे। परमाणु हथियारों का विकास इसका एक उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि को फिर से एक ऐसे दौर के रूप में देखा जाता है जब सरकारों द्वारा तेजी से तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया था, जब नई प्रक्रियाओं और उत्पादों का प्रसार बिना किसी बाधा के हुआ था, और जब कम से कम गैर-साम्यवादी देशों में नवाचारों को अपनाने को राज्यों द्वारा अपनाया गया था। इस प्रकार 1950 के बाद वैश्वीकरण में तेजी आई क्योंकि तकनीकी परिवर्तन में तेजी आई।

वैश्वीकरण के परिणाम

वैश्वीकरण के कारणों पर बहस के अलावा, इसके परिणामों के बारे में भी बहुत बहस है। साहित्य में कम से कम तीन अलग-अलग दृष्टिकोण हैं: (1) जबकि कुछ लोग इसके परिणामों को सभी पहलुओं में नकारात्मक मानते हैं, (2) अन्य लोग इसके प्रभावों को समग्र रूप से सकारात्मक मानते हैं, और (3) फिर भी अन्य लोग

दृढ़ता से बीच में खड़े हैं और इसे लागत और लाभ दोनों के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण के कई अलग-अलग प्रभाव होने की बात कही जाती है। यहाँ दृष्टिकोण उन प्रभावों में से कई को देखना और प्रत्येक पर विद्वानों की अलग-अलग राय को रेखांकित करना है। इस स्तर पर, इसके प्रभावों पर बहुत कम आम सहमति है।

इस बारे में पर्याप्त साहित्य मौजूद है कि क्या (और कैसे) वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास दर, गरीबी, असमानता, लोकतंत्र, संघर्ष, राज्य क्षमता, नीति और संस्थागत अभिसरण, सांस्कृतिक विविधता, अस्थिरता और संकटों का प्रसार, और पूंजी और श्रम के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करने का तात्पर्य है कि किसी को अन्य कारकों को स्थिर रखना चाहिए, जो एक कठिन कार्य है। चूंकि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इन सवालों के निश्चित उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से प्रत्येक परिणाम के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और साक्ष्य मौजूद हैं।

राजनीति और लोकतंत्रीकरण

वैश्वीकरण को राजनीति पर प्रभाव डालने का श्रेय भी दिया जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इसने लोकतंत्र को फैलाने में मदद की है और नेताओं पर लोकतंत्रीकरण के लिए दबाव डाला है। 1980 के दशक से निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ा है। लेकिन क्या यह वैश्वीकरण के कारण हुआ है? खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या आदर्श उद्यमियों द्वारा उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से वैश्वीकरण नेताओं को शासन के अधिक लोकतांत्रिक रूपों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि वे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के सदस्य बनना चाहते हैं। कुछ लोग इसके विपरीत तर्क देते हैं: कई देशों में नीतियों में बदलाव के लिए लोकतंत्रीकरण आवश्यक था जिसके कारण अधिक वैश्वीकरण हुआ।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्वीकरण से कौन से देश लाभान्वित होते हैं और कौन से खोते हैं, इस सवाल के अलावा, यह मुद्दा भी है कि कौन से समूह घरेलू स्तर पर लाभान्वित होते हैं और कौन से समूह खोते हैं। कई लोग वैश्वीकरण को पूंजी मालिकों और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के हाथ को मजबूत करने के रूप में देखते हैं, न कि श्रम मालिकों और वामपंथी दलों के। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जहां पूंजी अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है, यह घरेलू स्तर पर लाभप्रद हो जाती है। वैश्वीकरण व्यवसाय और श्रम के बीच शक्ति के घरेलू संतुलन को बदलता है। जब पूंजी के मालिकों को सरकार की नीति पसंद नहीं आती है या उन्हें डर होता है कि श्रम बहुत मजबूत हो गया है, तो वे अक्सर एक नए राजनीतिक वातावरण में चले जाते हैं जो अधिक अनुकूल होता है। यह प्रक्रिया तब दौड़-से-नीचे दबाव पैदा कर सकती है क्योंकि सरकारें अपने देश में पूंजी को बनाए रखने की कोशिश करती हैं और अधिक व्यापार-अनुकूल नीतियों को अपनाती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वैश्वीकरण ने श्रमिक संघों और श्रम बाजार संगठन के अन्य रूपों को कमजोर करने में मदद की है। यह प्रक्रिया तब राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया ने देश की औद्योगिक संरचना और सामाजिक संरचना को बदल दिया है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण परिवर्तन की गति तेज हो गई है। हम वैश्वीकरण को दुनिया भर के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आर्थिक शब्दों में, वैश्वीकरण को अक्सर विभिन्न देशों की अपनी सीमाओं से परे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए परस्पर निर्भरता के रूप में वर्णित किया जाता है। वैश्वीकरण एक राष्ट्र की सीमा के पार सूचना के मुक्त और सहज प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे विदेशी संस्कृति का तेजी से आयात होता है।

संदर्भ

1. साहू, सरबेश्वर। वैश्वीकरण और भारत में गरीबों की राजनीति। जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज। 2013;49:3–15. doi:10.1177/0021909612471785।
2. कुमार, सुरिंदर; सिंह, कुलविंदर। वैश्वीकरण का प्रभाव: भारतीय अनुभव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड रिसर्च। 2012;2:1–10।
3. गोविंदराज, योगानंदम। विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव और आकलन। 2023.
4. अब्दुनैइमोवा, दिनारा। वैश्वीकरण, इसका सार, कारण और परिणाम। एकीकृत शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2020;3:28–32. doi:10.31149/ijie.v3i9.583।
5. मन्हास, नीरज सिंह। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। 2020. p. 5. doi:10.25215/2455/0502015
6. हिली, डाल्टन। वैश्वीकरण की भूमिका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और उनके व्यापक आर्थिक और राजनीतिक माहौल पर इसका प्रभाव। 2012
7. अग्रवाल, अंकुर; कुमारी, मीनाक्षी। वैश्वीकरण और भारत में मीडिया प्रबंधन पर इसका प्रभाव। इल्कोग्रेटिम ऑनलाइन। 2021;20:4150–61. doi:10.17051/ilkonline.2021.01.458.
8. तुरान, सुएप; अवलेह, हनीफ़। मध्य पूर्व में राजनीति और संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। 2022.
9. माहेश्वरी, हर्ष; सोनी, अर्पण। वैश्वीकरण और सामाजिक संरचना पर इसका प्रभाव। 2023.
10. खान, एस. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। 2015;2:11–18।
11. भट्टाचार्य, एच.; कोनिग, लायन। भारत में वैश्वीकरण और शासन: समाज और संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ। भारत में वैश्वीकरण और शासन: समाज और संस्थाओं के लिए नई चुनौतियाँ। 2015. p. 1–175. doi:10.4324/9781315722917।
12. पटजोशी, प्रमोद। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन। 2019.
13. रघुनाथ। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च - ग्रंथालय। 2017;5(6):544–549. doi:10.29121/ग्रंथालय.v5.i6.2017.2071।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Paper 2

Online at: https://researchtrendsjournal.com **ISSN No:** 2584-282X



INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 6; 2024; Page No. 160-164

Received: 08-08-2024
Accepted: 17-09-2024

भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव

[1]Kumar Abhayaditya Subham and [2]Dr. Balram Singh

[1]Research Scholar, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Department of Political Science, P.K. University, Shivpuri, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15239437

Corresponding Author: Kumar Abhayaditya Subham

सारांश

शहरीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन हो रहा है। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित संरचना आर्थिक नीतियों से बहुत प्रभावित होती है। समाज में आय, बचत, निवेश और रोजगार के स्तर भी सरकार द्वारा बनाई और लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियों से बहुत प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण अलग-अलग जगहों पर महिलाओं के अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है। इस तरह की पहचान की राजनीति सिर्फ़ दलित और पिछड़े वर्ग के संगठनों तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्रमुख जाति और उच्च जाति समूह भी पहचान की राजनीति का सहारा लेते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, इसकी संस्कृति, समाज, सरकार और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।

मूलशब्द: भारतीय, समाज, वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था और भारत।

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया के अधिकांश विकासशील 5 देशों की तरह भारत भी बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज है। भारतीय समाज जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि की दृष्टि से एक बहुलवादी समाज है। भारत जैसे देश में जहां जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और समुदाय के आधार पर व्यापक विविधताएं हैं और कई तरह के सामाजिक उत्पीड़न हैं, पहचान की राजनीति उपजाऊ जमीन पाती है। भारत दुनिया के सर्वाधिक विविध समाजों में से एक है। कहा जाता है कि भारत के लोगों की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से निरंतर चली आ रही है। इसमें दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग रहते हैं - हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। हिंदुओं की आबादी लगभग 82 प्रतिशत है, लेकिन भारत में दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है, जो अनुमानित 149 मिलियन है।

इस तरह की पहचान की राजनीति सिर्फ़ दलित और पिछड़े वर्ग के संगठनों तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्रमुख जाति और उच्च जाति समूह भी पहचान की राजनीति का सहारा लेते हैं। पार्टियाँ समर्थन जुटाने और अपनी चुनावी ताकत बढ़ाने के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। उदाहरण के लिए, यूपी में भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसी सभी पार्टियाँ समर्थन जुटाने के लिए जाति और उपजाति सम्मेलन करती हैं। वे पहचान की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और जाति विखंडन की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया अनुसूचित जातियों की उप-श्रेणियों के भीतर विकसित होने वाली प्रतिस्पर्धा और संघर्षों में देखी जा सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश में माला-मडिगा संघर्ष। दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के मामले में नई पहचानों का उदय भी देखा जा सकता है। अब जबकि हमने भारत में पहचान की राजनीति के बारे में अपनी समझ को रेखांकित कर लिया है। आइए हम इस सवाल पर वापस आते हैं कि वैश्वीकरण से इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोग के पैटर्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत की पहचान और राजनीति में बदलाव के बुनियादी निर्धारक काफी हद तक घरेलू ही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान शताब्दी में पहचान की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय विकास से प्रभावित होती है। एक बहुलवादी या बहुसांस्कृतिक समाज में पहचान की राजनीति को कैसे समझा जाए और 21वीं सदी में भारत की पहचान की राजनीति की स्थायी विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करना बिल्कुल उपयुक्त है।

वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता,

जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी व्यापार और निवेश पर निर्भरता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और नियमों का पालन करने वाले देश वैश्वीकरण के एक समुदाय हैं। वैश्वीकरण ने देशों को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने और विदेशी कंपनियों को इसमें निवेश करने की अनुमति दी। वैश्वीकरण का प्रभाव अक्सर न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि देशों और उनके नागरिकों की संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक जीवन शैली पर भी देखा जाता है। वैश्वीकरण न केवल कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं को प्रभावित करता है।

साहित्य समीक्षा

सिंह, जगदीप एट अल. (2022) [1]. भारतीय इतिहास के दौरान, महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जैसे सामाजिक दबाव, जाति के आधार पर भेदभाव और अन्य प्रकार की सामाजिक बाधाएँ जैसे उत्पादक संसाधनों तक सीमित पहुँच, गरीबी, उन्नति के सीमित अवसर, लाचारी और बहिष्कार, इत्यादि। दूसरी ओर, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए कई तरह की नई परिस्थितियाँ सामने आई हैं, जिनका उनके जीवन के लगभग हर पहलू पर प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन में मीडिया की भूमिका, शिक्षा, सांस्कृतिक पहलुओं, राजनीति और महिलाओं की भूमिका, समाज में महिलाओं की भागीदारी और वैश्वीकरण के अन्य सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में महिलाओं के जीवन पर वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने की कोशिश की गई है।

अंबू, सेइलान. (2020) [2]. भारतीय व्यापार और संस्कृति में वैश्वीकरण का प्रभाव। व्यापार का वैश्वीकरण एक व्यापार दर्शन है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यापार को वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वैश्विक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ऐसे उत्पादों या सेवाओं की पेशकश की जाती है जो वैश्विक वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संतुष्ट कर सकें, वैश्विक मानकों के अनुपालन में गुणवत्ता बनाए रखें, वैश्विक कॉर्पोरेट नागरिकता की पहचान बनाएं और अंततः एक वैश्विक संगठनात्मक और व्यावसायिक संस्कृति को बढ़ावा दें।

हक, एम. (2018) [3]. कॉर्पोरेट वैश्वीकरण और भारत में महिलाओं पर इसका प्रभाव। क्या यह सच है, या कम से कम सैद्धांतिक रूप से संभव है, कि लोगों या राष्ट्र के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब राजनीतिक माहौल की मांग होती है कि हम-यहां तक कि हममें से सबसे परिष्कृत लोग-खुले तौर पर पक्ष लें? मेरा मानना है कि ऐसे समय हमारे सामने हैं। और मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में, बुद्धिजीवियों और कलाकारों को पक्ष लेने के लिए बुलाया जाएगा, और इस बार, स्वतंत्रता के संघर्ष के विपरीत, हमारे पास 'उपनिवेशवादी दुश्मन' से लड़ने की विलासिता नहीं होगी। हम खुद से लड़ेंगे" (रॉय 198) ।

गोंजालेज, बी. (2016) [4]. वैश्वीकरण: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे। वैश्वीकरण, एक अंतरराष्ट्रीय घटना के रूप में, नई सहस्राब्दी में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के विकास में योगदान दिया है या सहायता की है। पिछली आधी सदी से, वैश्वीकरण की ताकतें विकासशील और विकसित दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं। जबकि वैश्वीकरण या दुनिया को एक साथ बांधने वाले आर्थिक और सामाजिक संबंधों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, विद्वान और नीति-निर्माता इस बात पर जोरदार असहमत हैं कि क्या वैश्वीकरण अपरिहार्य है

चटर्जी, मिनिया. (2012) [5]. दुनिया ने 2011 के वसंत में एक चौंकाने वाली घटना देखी। कई देशों के नागरिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपनी सरकारों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए समान तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने एक-दूसरे से बहुत तेज़ी से सीखा। उन्होंने इस बारे में एक नई समझ साझा की कि सत्ता को कैसे संगठित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए कैसे किया जाना चाहिए, जिससे एक नई राजनीतिक व्यवस्था सामने आई जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार तेज़ी से फैल गई। शहरों में यह घटना कहीं और इतनी स्पष्ट नहीं थी, जो आम तौर पर लोगों, धन और विचारों के सीमा-पार प्रवाह के केंद्र बिंदु होते हैं, और जो बाहरी प्रभावों के संपर्क में आने वाले नागरिकों के एक निश्चित वर्ग का पोषण करते हैं। यह प्रोफ़ाइल दर्शाती है कि वैश्वीकरण नागरिकों के लिए ऐसी स्थितियाँ स्थापित करने में मदद करता है

संस्कृति का समरूपीकरण बनाम वैश्वीकरण

एक केंद्रीय तर्क यह है कि सभी संस्कृतियाँ समान हो जाएँगी, यानी एकरूप हो जाएँगी। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि संस्कृति के वैश्वीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक को स्थानीय के साथ मिलाना। यह पूरी तरह से स्वतःस्फूर्त नहीं है। न ही यह वैश्वीकरण के व्यावसायिक हितों से पूरी तरह अलग है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे अक्सर विदेशी कंपनियाँ स्थानीय परंपराओं से निपटते समय अपनी बाज़ार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनाती हैं। भारत में, हम पाते हैं कि स्टार, एमटीवी, चैनल वी और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टेलीविज़न चैनल भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड भी भारत में केवल शाकाहारी और चिकन उत्पाद बेचता है, न कि उसके गोमांस उत्पाद, जो विदेशों में लोकप्रिय हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान मैकडॉनल्ड शाकाहारी हो जाता है। संगीत के क्षेत्र में, 'भांगड़ा पॉप', 'इंडी पॉप', फ्यूजन संगीत और यहाँ तक कि रीमिक्स की लोकप्रियता में वृद्धि देखी जा सकती है।

इससे जुड़ी एक और घटना है जिसे ग्रोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है जिसे रिट्जर (2004) ने गढ़ा है। यह उस चीज को संदर्भित करता है जिसे वह "विकास की अनिवार्यताएं कहते हैं जो संगठनों और राष्ट्रों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने और वहां के स्थानीय भूगोल पर खुद को थोपने के लिए प्रेरित करती हैं"। रिट्जर के लिए, वैश्वीकरण 'ग्लोकलाइजेशन' और 'ग्रोबलाइजेशन' का योग है।

भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण अलग-अलग जगहों पर महिलाओं के अलग-अलग समूहों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है। एक तरफ यह महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अग्रणी बनने के नए अवसर पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ यह असेंबली लाइन उत्पादन या आउटसोर्सिंग के रूप में सस्ते रास्ते उपलब्ध कराकर नौकरी के अवसरों को छीन सकता है।

वैश्विक संचार नेटवर्क और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आगमन के साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता दिख रहा है, हालांकि यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। वैश्वीकरण ने वास्तव में महिलाओं के लिए समानता के विचारों और मानदंडों को बढ़ावा दिया है, जिससे जागरूकता आई है और समान अधिकारों और

अवसरों के लिए उनके संघर्ष में उत्प्रेरक का काम किया है।
हालाँकि, वैश्वीकरण पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ा सकता है, खासकर विकासशील देशों में। आर्थिक क्षेत्र में यह अनौपचारिक श्रम क्षेत्र में महिलाओं के हाशिए पर जाने या आय के पारंपरिक स्रोतों के नुकसान के कारण गरीबी की ओर ले जा सकता है। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को बढ़ाने में योगदान दिया है।

महिलाओं पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि - व्यापक संचार लाइनें खोली गईं और अधिक कंपनियों के साथ-साथ विभिन्न विश्वव्यापी संगठनों को भारत में लाया गया - इससे महिलाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हुए, जो कार्यबल का बड़ा हिस्सा बन रही हैं
- स्वतंत्रता और आत्मविश्वास - महिलाओं के लिए नई नौकरियों के साथ, उच्च वेतन के अवसर हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और स्वतंत्रता लाता है। इसके अलावा, बढ़ते शहरीकरण के कारण, शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गई हैं। यह अंतर-जातीय विवाह, एकल माताओं, लिव-इन रिलेशनशिप के माध्यम से प्रकट हुआ है।
- उद्यमशीलता के दृष्टिकोण का विकास - निम्न मध्यम वर्ग पारिवारिक संबंधों के तरीके में बदलाव का अनुभव कर रहा है। परंपरागत रूप से महिलाएँ घर पर रहकर घरेलू ज़रूरतों और बच्चों की देखभाल करती थीं। अब ज़्यादातर महिलाएँ जीविकोपार्जन के लिए अपने निजी स्थानों से बाहर निकल रही हैं। उदाहरण के लिए: भारत में स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) उन महिला मज़दूरों का संघ है जो कड़ी मेहनत करने और मिलने वाले किसी भी काम के अवसर को भुनाने के लिए तैयार हैं।

महिलाओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- रोजगार और कार्यस्थल से जुड़े मुद्दे - हालांकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे ज्यादातर कम वेतन वाली नौकरियों में ही व्यस्त हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा भी कम है। कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण एक नया मुद्दा बनकर उभरा है
- दोहरी जिम्मेदारी - महिलाओं को दो तरह से कष्ट उठाना पड़ रहा है। विकासशील देशों में महिलाएँ जैसे-जैसे कार्यबल में शामिल होती हैं, उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ कम नहीं होती हैं। महिलाएँ दो पूर्णकालिक नौकरियाँ करती हैं।
- महिलाओं का वस्तुकरण - वैश्वीकरण के साथ भारतीयों की पितृसत्तात्मक मानसिकता कायम रही है, जिसके कारण महिलाओं के लिए समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे महिलाओं का वस्तुकरण, महिलाओं को परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि।

भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण स्पष्ट आर्थिक अवसर और लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही पर्याप्त सामाजिक लागत भी आती है, जो अक्सर युवा लोगों को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि अनिश्चित और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक संदर्भ में उनकी स्थिति संक्रमणकालीन है।
भारत की अधिकांश आबादी युवा है। युवाओं के बीच जनसंख्या वृद्धि वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारतीय युवा वैश्वीकरण के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। वे वैश्वीकरण को ऐसे तरीके से अपना रहे हैं जिसकी पिछली पीढ़ी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

युवाओं पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव

- शिक्षा और उद्यम: छोटे से छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक के युवा भारतीयों की प्राथमिक महत्वाकांक्षा "अमीर बनना" है। युवा लोग उद्यम और शिक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे सबसे उच्च प्रतिष्ठित करियर उच्च तकनीक और मीडिया में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए रास्ता बना रहे हैं।
- वैश्विक किशोर बनना: भारत को प्रभावित करने वाली गतिशील, वैश्विक, आर्थिक शक्तियों के अलावा, वैश्वीकरण ने भारत की समृद्ध संस्कृति में भी बदलाव लाया है। युवा खुद को वैश्विक किशोरों के रूप में देखते हैं। वे जिस समुदाय में पैदा हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। युवा पीढ़ी पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति को अपना रही है और इसे अपनी भारतीय पहचान में शामिल कर रही है। पश्चिमी और भारतीय मूल्यों का एक सूक्ष्म और शक्तिशाली संकरण हो रहा है - जो विशेष रूप से भारतीय युवाओं में स्पष्ट है।

युवाओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- शहरी गरीबी में वृद्धि:आर्थिक वैश्वीकरण के कारण शहरी गरीबी बढ़ी है क्योंकि लोग अवसर की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरी प्रवासियों में युवा वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन शहरी केंद्रों में युवाओं को उच्च स्तर की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। युवा प्रवासियों को शहरों में धकेला जाता है और खींचा जाता है, लेकिन उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में तनाव का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अभाव में कई युवा दुर्लभ संसाधनों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होते हैं जो अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं। धार्मिक, नागरिक और जातीय संघर्ष भी शहरों में उपलब्ध आर्थिक समृद्धि को कमजोर करते हैं, जिसमें अक्सर युवा लोग सीधे तौर पर शामिल होते हैं।
- उपभोक्तावादी रवैया:उपभोक्तावाद ने भारतीय लोगों की पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं में घुसपैठ की है और उन्हें बदल दिया है। पारंपरिक भारतीय पोशाक में कमी आ रही है, खासकर शहरी युवाओं में, जो पश्चिम के नए फैशन के पक्ष में हैं। नवीनतम कारें, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फैशनेबल कपड़े खरीदना काफी लोकप्रिय हो गया है। युवा गरीब आबादी विशेष रूप से विज्ञापनों में देखे जाने वाले महंगे उत्पादों के आकर्षण के प्रति संवेदनशील है और जब वे इन विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं।

अवसाद और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि

वैश्वीकरण के कारण युवाओं में अनिश्चितता बढ़ी है; यह अंतर्निहित अस्थिरता उन तनावों और नियंत्रण की कमी को बढ़ा सकती है जो वे दैनिक आधार पर अनुभव करते हैं। अनिश्चितता पारंपरिक

मानदंडों के टूटने, परिवार और विवाह जैसे सामाजिक संबंधों के कमजोर होने, बाजार अर्थव्यवस्था के कारण करियर में अनिश्चितता के कारण है। इससे युवाओं में अवसाद और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन मिश्रित रूप में किया जाता है, जो अच्छा और बुरा दोनों है। आर्थिक वैश्वीकरण ने अध्ययन और नौकरी के अवसरों में सुधार किया है और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। लेकिन इसने गरीबों को और भी गरीब बना दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वीकरण से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। युवा आधुनिक, प्रगतिशील होने और समाज का हिस्सा बनने का अवसर पाकर खुश हैं।

परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव

परंपरागत रूप से भारत में समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज में जीवन के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं और हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण परिवार धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं ऐसे नेटवर्क हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की सोर्सिंग और आपूर्ति के उद्देश्य से कई महाद्वीपों और देशों में फैले हो सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में दुनिया भर में सूचना, प्रक्रियाओं और संसाधनों का प्रवाह शामिल होता है। कम लागत वाले देश की सोर्सिंग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है और इसका मतलब है कि उन देशों से उत्पादों और सेवाओं की खरीद करना जहां घरेलू देश की तुलना में कम श्रम दर और कम उत्पादन लागत है।

कोविड-19 संकट का उन निगमों और व्यवसायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिन्हें सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा समर्थित आर्थिक अंतर-निर्भरता से लाभ हुआ है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन आधार है और कई आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित है। इस कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से, चीन पर निर्भर होने वाली कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी सबसे कमजोर कड़ी। किसी भी स्तर पर कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, या पैकेजिंग में किसी भी बिंदु पर एक भी चूक मुख्य इकाई के पूरे उत्पादन को बाधित करती है। उदाहरण के लिए, भारत अपने सक्रिय फार्मा अवयवों का लगभग 70 प्रतिशत आयात करता है - जिसे चीन से थोक दवाओं के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी आपूर्ति महामारी के दौरान बंद हो गई थी, और भारतीय फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने में असमर्थ था, जबकि दुनिया भर में इसकी उच्च मांग थी।

कोविड-19 के संदर्भ में वैश्वीकरण

वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं और संस्कृतियों के पार उत्पादों, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों का प्रसार है। आर्थिक वैश्वीकरण में सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह, टैरिफ और व्यापार बाधाओं में कमी, आप्रवासन और सीमाओं से परे प्रौद्योगिकी और ज्ञान का प्रसार शामिल है। इसके उद्भव के बाद से, कई अध्ययनों में घरेलू संसाधनों के प्रभावी आवंटन, प्रौद्योगिकी के प्रसार, कारक उत्पादकता में सुधार और पूंजी के संवर्द्धन के माध्यम से विकास पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पाए गए हैं।

सामाजिक वैश्वीकरण पर COVID-19 महामारी के प्रभाव

कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद सीमा बंद होना, सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी उपाय गंभीर रूप से अंतर्राष्ट्रीय और देश के बाहर प्रवास और पर्यटन को प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने यात्रा के जोखिमों और यात्रा की चिंता की धारणाओं को बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए कोविड-19 महामारी के स्पष्ट प्रभावों को रेखांकित करते हैं। वैश्विक स्तर पर आगमन की संख्या 2019 में कुल 1465.5 मिलियन आगमन से घटकर 2020 में 405.2 मिलियन आगमन हो गई और 2021 में 426.9 मिलियन आगमन पर अपेक्षाकृत कम रही, जिसके बाद के वर्षों में इसमें सुधार हुआ। इस संदर्भ में, बिकले एट अल ने पाया कि अधिक वैश्विक देशों के मामले में यात्रा प्रतिबंध आम तौर पर अधिक स्पष्ट थे।

विभिन्न राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों के बीच प्रत्यक्ष पारस्परिक संपर्क पर परिणामी सीमाओं ने सामाजिक वैश्वीकरण की सीमा को सीमित कर दिया है। मेजबान देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों और विदेशी श्रमिकों पर असंगत रूप से प्रभाव पड़ा है; इन स्थितियों ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को सीमित करके, नौकरी के नुकसान का कारण बनकर और अपने मूल देशों में लौटने की आवश्यकता के कारण उनके कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

राजनीतिक वैश्वीकरण पर COVID-19 महामारी के प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने शुरू में संरक्षणवादी उपायों, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और विदेशी देशों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दिया, और इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और वैश्विक शासन के लिए चुनौतियां पेश की हैं। पारंपरिक वैश्विक राजनीतिक अंतर्क्रियाओं में बदलाव आया है, और शांति और सुरक्षा बनाए रखने और आर्थिक विकास और व्यापार खुलेपन को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र) की भूमिका को चुनौती दी गई है। लेवी [126] ने कहा कि वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को महामारी से पहले महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो लोकलुभावनवाद के उदय और उदारवाद के लुप्त होने से उपजी हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक शासन और राजनीतिक वैश्वीकरण के पाठ्यक्रम को और भी अधिक विचलित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक कोविड-19 संकट को कैसे प्रबंधित किया, इस बारे में आलोचकों की एक विस्तृत श्रृंखला रही है, जिससे सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और अधिक संदेह पैदा हुआ है। इस स्थिति के बीच, कई देशों (जैसे, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन [आसियान] के सदस्य देशों) ने महामारी संकट के प्रबंधन में क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर भरोसा किया, जिससे संभावित रूप से विश्व अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति में और अधिक क्षेत्रीयकरण की दिशा में एक मार्ग शुरू हुआ।

वैश्वीकरण के लिए COVID-19 महामारी के दीर्घकालिक निहितार्थ

वैश्वीकरण के पैटर्न और सरकारी प्रतिक्रियाएँ कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले, वैश्वीकरण की लहरों में कमी के कुछ संकेत थे, जैसा कि राष्ट्रीय संरक्षणवादी नीतियों और सीमा नियंत्रणों के प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण योजनाओं में ठहराव, विदेशी पूंजी प्रवाह में वैश्विक कमी और राष्ट्रवाद और लोकलुभावन आंदोलनों में वृद्धि के माध्यम से व्यक्त किया गया था। कोविड-19 से पहले की

ये स्थितियाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुईं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना (ब्रेक्सिट), और चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक/राजनीतिक तनाव। ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 महामारी ने निरंतर/उभरते आर्थिक/राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन और राजनीति और नीतियों में राष्ट्रवाद/लोकलुभावनवाद की और खुराक के साथ इन पैटर्न को बढ़ावा दिया है। इसने स्वास्थ्य, राजनीतिक और आर्थिक उपायों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभाजित करने में और योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य शुरू में वायरस के प्रसार को सीमित करना और राजनीति और समाज में राष्ट्रवादी/लोकलुभावन प्रवृत्तियों के सामान्यीकरण के माध्यम से था। ये स्थितियां वैश्वीकरण के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ दर्शाती हैं, और इस प्रकार, कोविड के बाद वैश्वीकरण का परिमाण संभवतः वैश्वीकरण के उस काल्पनिक स्तर से नीचे हो जाएगा जो महामारी की अनुपस्थिति में हुआ होता।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, इसकी संस्कृति, समाज, सरकार और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। इसने प्रौद्योगिकी, विशेष कौशल और एक बड़े उपभोक्ता बाजार तक पहुंच बढ़ाई है। इससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि हुई है, कुल मिलाकर, वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को बदल दिया है, इसकी संस्कृति, समाज, सरकार और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। वैश्विक संचार नेटवर्क और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आगमन के साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता दिख रहा है, हालांकि यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। वैश्वीकरण के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों का प्रसार हुआ है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिला है। शहरीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन हो रहा है। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित संरचना आर्थिक नीतियों से बहुत प्रभावित होती है।

संदर्भ

1. सिंह, जगदीप और कुमारी, डॉ. ममता। भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव: एक महत्वपूर्ण समीक्षा। विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।, 2022. p. 127-137. 10.48175/IJARSCT-5937।
2. अंबू, सेइलन. भारतीय व्यापार और संस्कृति में वैश्वीकरण का प्रभाव. 2020.
3. हक, एम. कॉर्पोरेट वैश्वीकरण और भारत में महिलाओं पर इसका प्रभाव।, 2018.
4. गोंजालेज, बी. वैश्वीकरण: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे। 2016.
5. चटर्जी, मिनिया. राजनीति का वैश्वीकरण: मिस्र से भारत तक. सामाजिक आंदोलन अध्ययन. 2012;12:1-7. 10.1080/14742837.2012.698132.
6. वदित्य, वेंकटेश. भारत में वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा: प्रतिमान बदलाव. 2019. 10.13140/RG.2.2.25552.76806.
7. शर्मा, शिव. भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद पर वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव. जर्नल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. 2019;15:189-201. 10.1956/jge. v15i3.592.
8. शॉटली, जीवन्ता और झा, हिमांशु. भारत में वैश्वीकरण और शासन, 2023. 10.4324/9781003152347.
9. गुप्ता, शिखा, कुमार, नंद. भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की गतिशीलता. प्रबंधकीय और निर्णय अर्थशास्त्र. 2021, 42. 10.1002/mde.3313.
10. चौक्रौने, लीला. वैश्वीकरण और भारतीय राजनीतिक आधुनिकता, 2020. 10.1007/978-3-030-44058-9_34.
11. इस्लाम, रबीउल और अहमद, फखरोराज़ी और हुसैन, हार्टिनी और रेहान, एमडी. वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रभाव। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान समीक्षाएँ।. 2019;7:256-265. 10.18510/एचएसएसआर.2019.7130.
12. गोविंदराज, योगानंदम, करीम ए अब्दुल. भारत के विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला स्थानीयकरण, बाजार की सफलता, कौशल अंतराल, क्षेत्रीय सीमा शुल्क, विनियामक आवश्यकताओं और राज्य कल्याण पर वैश्वीकरण का प्रभाव - एक व्यापक आर्थिक सैद्धांतिक मूल्यांकन।, 2023.
13. बीसन, मार्क. वैश्वीकरण और शासन, 2017. 10.1057/978-1-137-58900-2_7.
14. मुखर्जी, राहुल. भारत और आर्थिक वैश्वीकरण, 2014. 10.1057/9781137356642_5.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Appendix 2

Conference Certificate 1



IC-RU-RFI/2024/244

28 DEC 2024

International Conference On

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TOWARDS SUSTAINABILITY AND DEVELOPMENT BY UNLOCKING NEW OPPORTUNITIES IN THE WORLD OF CONSTANT DISRUPTION

Jointly Organized By

Renaissance University, Indore

RESEARCH FOUNDATION OF INDIA

Sponsored By

HERF ARGA

CERTIFICATE

This is to Certified that Prof./Dr./Mr./Ms./Mrs.

KUMAR ABHAYADITYA SUBHAM

Research scholar P.K. University vill.Thanra,(P.O.Dinara) Shivpuri,M.P

Participated in the International Conference On "A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TOWARDS SUSTAINABILITY AND DEVELOPMENT BY UNLOCKING NEW OPPORTUNITIES IN THE WORLD OF CONSTANT DISRUPTION" Jointly Organized by Renaissance University-Indore, RFI CARE & Research Foundation of India on 28 December, 2024 and Presented a Research Paper Titled

वैश्वीकरण के युग में भारतीय राजनीतिक संरचना में परिवर्तन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

in Technical Session: ||

CA Swapnil Kothari, Chancellor, Renaissance University, Indore

Prof. (Dr.) Rajesh Dixit, Vice-Chancellor, Renaissance University, Indore

Prof.(Dr.) Amit Kumar Hasija, Registrar, Renaissance University, Indore

Prof. (Dr.) Jayesh Shah, Organizing Chair, Renaissance University, Indore

Dr. Ajay Jain, National Coordinator, Research Foundation of India

Prof. Dr. Ashok Kumar Gupta, Chief Managing Director, Research Foundation of India, RFI-CARE

Dr. Sourabh Jain, Chairman & CEO, Research Foundation of India, Director, RFI-CARE

www.renaissance.ac.in www.care.researchfoundationofindia.com www.researchfoundationofindia.com

Conference Certificate 2



Appendix 3

Plagiarism Report

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language	Hindi

Submission Information

Author Name	कुमार अभयादित्य शुभम
Title	भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण का प्रभाव
Paper/Submission ID	5405431
Submitted by	library.pku@gmail.com
Submission Date	2026-03-31 15:54:20
Document type	Thesis Chapter

Result Information

Similarity **7%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

LIBRARIAN
P.K. University
Shivpuri (M.P.)